रूस में मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छी स्थिति में हैं तथा विश्व बड़ी भू-राजनीतिक हलचलों का सामना कर रहा है. द्विपक्षीय संबंधों के गहरे होने का अनुमान इस घोषणा से लगाया जा सकता है कि भारत वहां दो नये वाणिज्य दूतावासों को स्थापित करने जा रहा है. रूस में बसे और कार्यरत भारतीयों की एक सभा में इसकी सूचना देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के परस्पर संबंधों की महत्वपूर्ण धुरी है. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 65.70 अरब डॉलर हो गया, जो एक रिकॉर्ड है. भारत तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों, फर्टिलाइजर, खनिज, कीमती पत्थर, वनस्पति तेल आदि का रूस से आयात करता है तथा उसे दवाएं, रसायन, इलेक्ट्रिक मशीनरी, लोहा एवं इस्पात आदि का निर्यात करता है. रक्षा क्षेत्र में तो दोनों देशों का सहयोग दशकों से चल रहा है. भारत को एक सैन्य शक्ति बनाने में और अब रक्षा उत्पादन बढ़ाने में रूस का बड़ा योगदान रहा है. दोनों देशों ने 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. भारत और रूस के बीच अक्तूबर 2000 में रणनीतिक सहयोग समझौता हुआ था, जिसे दिसंबर 2010 में विशेष एवं विशेषाधिकार युक्त रणनीतिक सहयोग समझौता बना दिया गया. शीर्ष नेताओं की वार्षिक बैठक के साथ रक्षा एवं विदेश मंत्रियों की साझा बैठक की व्यवस्था भी है. दोनों देश ब्रिक्स समूह एवं शंघाई सहयोग संगठन के भी सदस्य हैं. मगर, भारत और रूस के संबंधों को केवल व्यापारिक आंकड़ों तथा लेन-देन के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है. प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही रेखांकित किया है कि हर भारतीय अपने हृदय में यह महसूस करता है तथा जब भी रूस का नाम आता है, तो हमारे मन-मस्तिष्क में यही भाव आता है कि रूस हमारा 'सुख-दुख का साथी' है. बीते एक दशक में परस्पर संबंधों को नयी गति एवं त्वरा मिली है. प्रधानमंत्री छह बार रूस जा चुके हैं तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 17 बार उनकी भेंट हो चुकी है. दोनों नेताओं के व्यक्तिगत समीकरण से द्विपक्षीय संबंधों को ठोस आधार मिला है तथा दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. दोनों को एक-दूसरे पर कितना भरोसा है, उसका अंदाजा इससे लग सकता है कि 2022 में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है तथा विवादों का निपटारा संवाद से होना चाहिए. रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य मामलों पर भारत के सकारात्मक रवैये की प्रशंसा रूस के साथ-साथ पश्चिम ने भी की है.

भारत और रूस के संबंधों को केवल व्यापारिक आंकड़ों तथा लेन-देन के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है. यह एक भावनात्मक संबंध है.

सवालों के घेरे में बाइडेन की उम्मीदवारी

जे सुशील
शोधार्थी
jey.sushil@gmail.com

अमेरिका से विशेष

डेमोक्रेट तबकों में भी मांग उठ रही है कि बाइडेन खुद ही पीछे हटें ताकि किसी नये उम्मीदवार को मौका मिले. अभी पार्टी सम्मेलन बाकी है और तकनीकी रूप से नया उम्मीदवार आ सकता है. उनकी उम्मीदवारी को लेकर बहुत समय से शंका जाहिर की जाती रही है. उनके बेटे हंटर बाइडेन को सजा सुनाये जाने के बाद भी पार्टी का एक तबका चिंतित था कि चुनाव में क्या होगा. पर अब मामला उम्र पर चला गया है, जिससे बाइडेन की रेटिंग खराब होती जा रही है.

अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से जो बाइडेन के हटने या हटाये जाने की चर्चाएं जोरों पर है. बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि वे दौड़ में बने हुए हैं और वे ही डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते हैं. उनके मित्र और हवाई के गवर्नर जॉस ग्रीन ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि अगर बाइडेन चुनाव नहीं लड़ते, तो वे यह काम उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सौंपेंगे. ओबामा प्रशासन में अधिकारी रह चुके मीडिया कमेंटेटर वैन जोंस ने कहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के बंद कमरों में यह चर्चा नहीं हो रही है कि बाइडेन को हटाया जाए या नहीं, बल्कि चर्चा यह हो रही है कि ऐसा कब किया जाए. अगर बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ते हैं, तो यह पहली बार होगा कि एक प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद किसी पार्टी ने उम्मीदवार बदला हो. अगर बाइडेन ही उम्मीदवार रहे, तो यह पहली बार होगा कि दोनों दलों के उम्मीदवार- डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन- 75 साल से ऊपर के होंगे. इससे पहले रोनाल्ड रीगन 69 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और 77 साल की उम्र में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था. बाइडेन 81 साल के हैं और ट्रंप 78 के. कुल अमेरिकी आबादी के 65 प्रतिशत हिस्से की उम्र 15 से 65 साल के बीच है और 65 साल से अधिक की आबादी 17 प्रतिशत है. उम्र के लिहाज से देखें, तो भी दोनों उम्मीदवार कहीं से भी प्रतिनिधि नहीं हैं. अमेरिका में औसतन 50-55 साल की उम्र में लोग राष्ट्रपति बने हैं, जिसमें उलिसस ग्रांट, जॉन कैनेडी, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा आदि कुछ राष्ट्रपति अपवाद रहे हैं, जो अपनी उम्र के 40वें दशक में राष्ट्रपति रहे. क्लिंटन 43 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे और अब वो 77 के हैं यानी ट्रंप और बाइडेन से छोटे.

हालांकि उम्र को अनुभव से जोड़ कर देखा जाता है, पर मसला सिर्फ अनुभव का नहीं है. पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाइडेन के बोलने, चलने और उनकी भाव-भंगिमाओं को देखकर लगता है कि अब वे अकेले न तो चल पाने में सक्षम हैं और न ही फैसले करने में. टीवी पर हुई प्रेसिडेंशियल बहस में लोगों ने देखा कि वे ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं. न्यूयॉर्कर के संपादक डेविड रेमनिक ने मार्क ट्वेन को उद्धृत करते हुए लिखा है कि हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है और बिखरना है, लेकिन बाइडेन दुनिया के सामने टीवी पर बिखर रहे हैं. बाइडेन को भी पता है कि वे बूढ़े हो चुके हैं, पर शायद सत्ता की चाह ऐसी ही होती है. डेमोक्रेट तबकों में भी मांग उठ रही है कि बाइडेन खुद ही पीछे हटें ताकि किसी नये उम्मीदवार को मौका मिले. अभी पार्टी सम्मेलन बाकी है और तकनीकी रूप से नया उम्मीदवार आ सकता है. उनकी उम्मीदवारी को लेकर बहुत समय से शंका जाहिर की जाती रही है. उनके बेटे हंटर बाइडेन को सजा सुनाये जाने के बाद भी पार्टी का एक तबका चिंतित था कि चुनाव में क्या होगा. पर अब मामला उम्र पर चला गया है, जिससे बाइडेन की रेटिंग खराब होती जा रही है.

लेकिन ऐसा क्या है कि पहले अमेरिका में उम्मीदवार अमूमन 50-60 के बीच हुआ करते थे, वहीं अब मामला 70 से अधिक के उम्मीदवारों पर आ गया है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मसलन युवाओं की राष्ट्रीय राजनीति में घटती दिलचस्पी, लोगों का पैसा और समृद्धि जुटाने पर फोकस तथा यथास्थिति कायम रखने की कॉरपोरेट नीति. ऐसा नहीं है कि अमेरिकी युवा राजनीति नहीं समझता है. ध्यान रहे कि पिछले दिनों ही बड़ी यूनिवर्सिटियों में गाजा को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे. पर राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के अलावा युवाओं की राजनीतिक भागीदारी कम दिखती है क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि उनके पास खूब पैसा हो. यह पैसा हर तरह के चुनाव से जुड़ा हुआ है. चंदा, प्रचार और प्रभाव बढ़ाने का हर तरीका पूंजीवादी रास्ते से होकर जाता है और युवाओं के पास इसके लिए समय नहीं है. जो राजनीति में जाना चाहते हैं, वे भी जानते हैं कि पहले खूब पैसा कमाना होगा. इसलिए अमेरिका युवा कॉलेज से निकलते ही किसी काम में लग जाते हैं. राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी युवा कानून, सेना या फिर स्थानीय राजनीति का रास्ता अपनाते हैं. अमेरिका के 32 राष्ट्रपति पूर्व में सेना में रहे, 27 राष्ट्रपति वकील रहे, जबकि 20 गवर्नर रहे. इनमें से कई पहले सीनेटर भी रहे या विदेश सेवा या अन्य सार्वजनिक पदों पर काम कर चुके थे. वहां भारत की तरह फुलटाइम राजनीति कम लोग कर पाते हैं क्योंकि किसी भी पद पर आने के लिए दिखाना पड़ता है कि आपने पहले क्या किया है.

सबसे महत्वपूर्ण कारण है कॉरपोरेट, जो प्रचार अभियान के लिए धन देते हैं. कंपनियां चाहती हैं कि बिजनेस के मामले में नीतियों में बहुत बदलाव न हो और अगर हो भी, तो उनके पक्ष में हो. इसे यथास्थिति बनाये रखना कहा जाता है. जब ट्रंप जीत कर आये, तो अपने रैडिकल फैसलों के कारण उन्होंने पारंपरिक कॉरपोरेट जगत को नाराज किया. मसलन, नाटो को खत्म करने की उनकी पहल, जो सफल नहीं हुई, संयुक्त राष्ट्र से प्रतिनिधि बुलाना, उत्तर कोरिया से दोस्ती, जलवायु समझौते से हटना आदि कई ऐसे कदम थे, जो पारंपरिक अमेरिकी राजनीति के अनुकूल नहीं थे. नतीजा, वे हार गये. अगर हम बाइडेन के कार्यकाल को देखें, तो एक तरह से पुरानी राजनीति बहाल हुई. उनके आते ही यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया और अमेरिकी हथियार लॉबी अपने हथियार बेच पाने में सफल होने लगी. ऐसा नहीं है कि अमेरिकी लोग यह सब नहीं समझते हैं. लोगों को पता है कि कॉर्पोरेट या बिग बिजनेस ही असली खिलाड़ी हैं. जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, तो कई लोगों को यह उम्मीद थी कि एक नयी सुबह होगी, एक नया अमेरिका बनेगा, जिसमें बेहतरी के लिए जगह होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ग्वांतानामो बे को बंद करने के अपने सबसे बड़े वादे से वे मुकर गये. उन्होंने सीरिया पर हमले किये और हर वह काम किया, जो पारंपरिक बिजनेस उनसे उम्मीद करता था. हेल्थकेयर की दिशा में ओबमाकेयर के नाम से जो नीति आयी, वह लगभग असफल रही क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा उद्योग को यह पसंद नहीं था. यह हो सकता है कि ओबामा के बाद अमेरिकी लोगों में एक निराशा घर कर गयी कि बदलाव संभव नहीं है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इस निराशा को भुनाया और 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' का नारा दिया. फिर आगे जो हुआ, वह हमारे सामने है. आम लोग यही कहते हैं कि हमें दो खराब नेताओं में से एक को चुनना है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

सुखद है भारतीय स्टार्टअप की घर वापसी

डॉ अश्विनी महाजन
राष्ट्रीय सह-संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच
ashwanimahajan@rediffmail.com

भारत की मजबूत वृद्धि घरेलू स्टार्टअप के रूप में 'रिवर्स फ्लिपिंग' की प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, जो कभी पूंजी तक पहुंच और कर लाभ के लिए विदेश जाते थे, अब घर लौट रहे हैं. विकास और तकनीकी विकास के साथ, कई अन्य कारण भी हैं, जो इस रिवर्स फ्लिपिंग को चलाते हैं.

ऐसी खबरें आयी हैं कि कई भारतीय स्टार्टअप, जो पहले विदेशों में फ्लिप कर गये गये थे, अब भारत लौट रहे हैं. किसी भारतीय कंपनी के फ्लिपिंग का मतलब है, एक ऐसा लेन-देन जिसमें प्रमोटर किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में अपनी कंपनी को पंजीकृत करता है, जिसे फिर भारत में स्टार्टअप कंपनी की होल्डिंग कंपनी बना दी जाती है. परिणामस्वरूप, भारतीय स्टार्टअप का अंतिम स्वामित्व विदेशी क्षेत्राधिकार में चला जाता है. इसलिए रिवर्स फ्लिपिंग का अर्थ है, वे स्टार्टअप जिन्होंने अपनी मालिकाना कंपनियों को विदेशी क्षेत्राधिकार में शामिल किया था, वे स्वामित्व को वापस भारत ला रहे हैं. जिन महत्वपूर्ण स्टार्टअप्स ने वापस फ्लिप किया है, उनमें फोन पे और ग्रो शामिल हैं. फ्लिपकार्ट के साथ ही जेप्टो और रेजर पे भी वापस फ्लिप करने का प्रयास कर रहे हैं.

फ्लिप करने वालों के पसंदीदा गंतव्य सिंगापुर, मॉरीशस, केमैन आइलैंड और ब्रिटेन थे. जबकि भारतीय स्टार्टअप फ्लिपिंग के माध्यम से भारत के विनियामक दायरे से बाहर हो गये थे, उन्होंने अब एक व्यावसायिक रणनीति के रूप में 'रिवर्स फ्लिपिंग' के माध्यम से भारतीय विनियामक ढांचे के तहत आना चुना है. फ्लिप करने वाले स्टार्टअप वे हैं जिनके प्रमोटर भारत से हैं और उन्होंने भारतीय संसाधनों- मानव, पूंजी और सरकारी सहायता से अपना कारोबार खड़ा किया. उनके फ्लिप करने का पहला कारण है कि वे भारतीय नियामक प्रणाली, भारतीय कर कानूनों और भारतीय अधिकारियों की जांच से बचना चाहते थे. दूसरा, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निवेशक उन कंपनियों को विदेश में फ्लिप करने के लिए मजबूर करते हैं जहां वे अपना पैसा लगाते हैं. तीसरा, अमेरिका, सिंगापुर जैसे कई देशों ने स्टार्टअप और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अनुकूल नीतियां बनायी हैं. चौथा, ये स्टार्टअप अपने शेयरों को विदेश में सूचीबद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभिनव विचारों को बेहतर मूल्यांकन मिलता है. स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी एक ऐसा मॉडल है जिसने कई स्टार्टअप को अपनी होल्डिंग कंपनियों को अमेरिका में सूचीबद्ध करने के लिए आकर्षित किया है. पांचवां, कराधान के मामले में भारतीय घरेलू निवेशकों के लिए समान अवसर की कमी, जिससे विदेशी निवेशकों ने भारतीय निवेशकों की तुलना में अधिक लाभ उठाया.

भारत से कंपनियों के फ्लिपिंग का पहला और सबसे बड़ा नुकसान संपत्ति और आय पैदा करने वाली संपत्ति का है. जब कोई भारतीय कंपनी विदेशी क्षेत्राधिकार में शामिल किसी कंपनी की सहायक कंपनी या एक विदेशी कंपनी बन जाती है, तो सरकार न केवल पूंजीगत लाभ कर राजस्व का अवसर खो देती है, बल्कि स्टॉक एक्सचेंजों पर कंपनी की लिस्टिंग से संभावित पूंजी निर्माण से भी वंचित हो जाती है. दूसरा, देश की बौद्धिक संपदा विदेशी देशों को हस्तांतरित हो जाती है और डेटा पर अधिकार भी विदेशियों को मिल जाता है. बौद्धिक संपदा में भविष्य की वृद्धि और विस्तार के सभी लाभ भी विदेशी देशों को हस्तांतरित हो जाते हैं. तीसरा, फ्लिप करने वाले स्टार्टअप भारतीय कर क्षेत्राधिकार और अन्य विनियामक ढांचे से बाहर हो जाते हैं और इस तरह वे अपने भारतीय समकक्षों पर बढ़त हासिल कर लेते हैं. चौथा, चूंकि फ्लिप किये गये स्टार्टअप का मुख्यालय विदेश में होता है, इसलिए उनके फंड के स्रोत को जानना मुश्किल हो जाता है. यह देश के लिए एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है. पांचवां, हमारे स्टार्टअप के फ्लिप करने का नुकसान यह भी है कि इससे भारतीय शेयर बाजार की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

सरकार का दावा है कि भारत की मजबूत वृद्धि घरेलू स्टार्टअप के रूप में 'रिवर्स फ्लिपिंग' की प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, जो कभी पूंजी तक पहुंच और कर लाभ के लिए विदेश जाते थे, अब घर लौट रहे हैं. विकास और तकनीकी विकास के साथ, कई अन्य कारण भी हैं, जो इस रिवर्स फ्लिपिंग को चलाते हैं. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पिछले एक दशक में महत्वपूर्ण परिपक्वता प्राप्त की है. अब उद्यमियों के लिए अधिक सहायक वातावरण है, फंडिंग, प्रतिभा और बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच है. सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी के लिए कई पहलें की गयी हैं. भारत अपने विशाल और बढ़ते उपभोक्ता बाजार के कारण तेजी से व्यवसाय शुरू करने और विस्तार करने के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है. भारत की उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी पारिस्थितिकी तंत्र भी काफी विकसित हुआ है, जो पूंजी की तलाश करने वाले स्टार्टअप के लिए फंडिंग के अवसर प्रदान करता है. पहले घरेलू वीसी के लिए समान अवसर की कमी थी क्योंकि वे विदेशी समकक्षों की तुलना में अधिक कर का भुगतान कर रहे थे. परंतु वित्त अधिनियम 2021-22 के माध्यम से सरकार ने भारतीय वीसी के लिए भी पूंजीगत लाभ पर अधिभार 37 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है. गिफ्ट सिटी की नीति से स्टार्टअप परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव आया है क्योंकि उन्हें अपने शेयरों को विदेशों में सूचीबद्ध करने के लिए फ्लिप नहीं करना पड़ता है. वे गिफ्ट सिटी के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

देश दुनिया

जापान-फिलीपींस के बीच हुआ ऐतिहासिक रक्षा समझौता

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के फिलीपींस पर आक्रमण और कब्जे के 70 वर्ष से अधिक समय बाद, दोनों देशों ने सोमवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये. दोनों देशों के बीच यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ा रहा है और फिलीपींस के साथ उसके संबंधों में लगातार तनाव बढ़ रहा है. रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट (आरएए) नामक यह समझौता जापानी सैनिकों और उपकरणों की फिलीपींस में तैनाती के लिए कानूनी इजाजत देता है. इसी तरह, फिलीपींस के सैनिक और साज-ओ-सामान भी जापान में तैनात किये जा सकेंगे. यह समझौता लड़ाकू प्रशिक्षण और आपदा प्रतिक्रिया में बढ़ते सहयोग का रास्ता खोलता है. आरएए के तहत दोनों देश एक-दूसरे से संयुक्त गतिविधियों के लिए सुविधाओं और क्षेत्रों तक 'पहुंच और उपयोग' का अनुरोध कर सकते हैं. हालांकि कुल मिलाकर नियंत्रण मेजबान देश का होगा. समझौते के अनुसार, दोनों को किसी अन्य देश की भूमि पर 'सैन्य सुविधाओं की स्थापना' का आधार नहीं होगा. जापान में 54,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. उसने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट किये हैं, परंतु एशिया में यह उसका पहला समझौता है. इसी तरह, फिलीपींस के भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह के समझौते हैं और फ्रांस के साथ भी ऐसा समझौता करने की योजना है. इसके अतिरिक्त, मनीला का वाशिंगटन के साथ एक अलग समझौता है जो अमेरिकी सैनिकों को फिलीपींस के नौ सैन्य ठिकानों पर तैनाती और रक्षा उपकरण तथा आपूर्ति जमा करके रखने की अनुमति देता है. फिलीपींस और जापान लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी हैं. अमेरिका एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इन देशों के जरिये अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके. यह बात चीन को नापसंद है और वह अक्सर अमेरिकी गतिविधियों की आलोचना करता रहा है.

Deutsche Welle

बोधि वृक्ष

सोच को ब्रह्म बनाओ

मनुष्य जब अपने को छोटा बनाता है, तो उसके विचार उसके आसपास ही घूमते हैं. वह देखता है कि पिता भी अपना नहीं हैं, माता भी अपनी नहीं है, सहोदर भाई-बहन भी अपने नहीं हैं. उसके बाद शरीर और प्राण भी एक नहीं लगेंगे. अंत में उसे लगेगा इस संसार में कोई अपना नहीं है. भीतर हाहाकार मचेगा. शांति नहीं रहेगी. मरने के पहले ही वह मर जायेगा. साधना 'मैं' पन को छोटा बनाने के लिए नहीं है, 'मैं' पन को बढ़ाते-बढ़ाते उसे अनंत कर देता है. साधना करने वाला जिधर देखेगा उधर ही उसे 'मैं' नजर आयेगा. सब में समदृष्टि, सब में आत्मदर्शन. और जैसे ही सोच को छोटा बनाओगे, वैसे सब कुछ पराया नजर आने लगेगा. यहां विखंडन शुरू हो जायेगा. अनेक को एक बनाते चलो, एक को अनेक नहीं. मनुष्य के लिए दुनिया मधुमय है और इस दुनिया के लिए यह मनुष्य भी मधुमय है. आत्मा सबके लिए मधुमय है और आत्मा के लिए भी हर वस्तु मधुमय है. हर चीज, वस्तु को जब देखोगे, उनकी आत्मा को देखने की चेष्टा करो, उनकी अनुभूति को समझने की चेष्टा करो. तुम्हारे लिए तुम्हारा 'मैं' पन जितना प्यारा है दूसरों के लिए उनका 'मैं' पन भी तो उतना ही प्यारा है. एक बार किसी कार्यालय का चपरासी मेरे एक परिचित व्यक्ति के पास आया. परिचित व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा नहीं, और चपरासी करीब आधे घंटे उसके पास खड़ा रहा. उसके बाद उसने कहा, 'बाबू, यह चिट्ठी आपकी है.' वे चिल्लाकर बोले- 'जाओ, चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो.' चपरासी कुछ नहीं बोला. उसके बाद एक कार्यालय में मेरे वही परिचित व्यक्ति एक बार एक चिट्ठी लेकर गये. इस टेबल से उस टेबल घूमते रहे, परंतु चिट्ठी नहीं दे सके. वह चपरासी उसी दफ्तर का था. उन्हें देखकर चपरासी ने कहा, 'बाबू, आइए, यह चिट्ठी फलां बाबू लेंगे.' बाबू समझ गये कि चपरासी वही था जिससे उन्होंने कहा था, 'जाओ-जाओ डिस्टर्ब मत करो.' इसलिए दूसरों से व्यवहार करते समय दूसरों के मन की भावना समझ लो. यह तभी संभव है जब सोच को ब्रह्म बनाओगे.

-श्री श्री आनंदमूर्ति

कुछ अलग

योग्यता के अनुसार ही अपना लक्ष्य बनाएं

डॉ कविता विकास
लेखिका
kavitavikas28@gmail.com

हर परिंदे की उड़ान में शोर नहीं होता. जो परिंदे जितनी सावधानी के साथ उड़ते हैं, वे दूर तक ऊंचाई में दिखते हैं और जो पंख फड़फड़ा कर अपने उड़ने की सूचना देते रहते हैं, वे निकट ही फुदकते रहते हैं. नयी उड़ान भरने वाले अधिकतर पंछी ऐसे ही होते हैं. अनुभवी बलशाली होते हैं और चुपचाप मंजिलें तय करते रहते हैं. यह आदत मनुष्य में भी देखने को मिलती है. दिखावा और डींगे हांकने वाले अंततः लुभावनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं और सुनने वाले को लगता है, यह तो बड़ा आदमी है. परंतु ऐसा कुछ नहीं होता है. कक्षा में भी ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो पढ़ाई छोड़ बाकी काम मुस्तैदी से करते हैं. जब तक परीक्षा का नतीजा नहीं आता, उन्हें कक्षा का सबसे स्मार्ट विद्यार्थी माना जाता है. एक श्रेणी बेपर परिंदों की भी होती है, यानी अभी पंख निकले ही नहीं और उड़ने लगे. जाहिर सी बात है कि इनके गिरने का डर सर्वाधिक होता है.

समाज वातावरण तैयार करता है, जिसमें अच्छे-बुरे, तेज-मंद, छोटे-बड़े सभी के लिए जगह होती है. सोच-विचार और देख-परख कर व्यवहार की प्रेरणा मिलती है. एक पुरानी कहावत है, 'अधजल गगरी छलकत जाए.' ज्ञान जितना छिछला होगा, उतना ही स्तरहीन होगा और स्वयं को ज्ञानवान बताने की होड़ मची रहेगी. गहरा ज्ञान, अध्ययन से उपजता है. यह आत्मबोध करवाता है. ज्ञानवान लोगों में विनम्रता होती है. वे विवेकशील व गंभीर होते हैं. अपने ज्ञान का परिचय इधर-उधर नहीं बांटते फिरते. इसलिए जब मन में अहंकार होने लगे, तो एक बार उन लोगों का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए जो हमसे भी बड़े हैं. हर विषय के ज्ञाता यहां मौजूद हैं और उनमें भी एक-दूसरे से श्रेष्ठतर तो मिल जायेंगे पर श्रेष्ठतम की जगह खाली ही रहेगी. इसी श्रेष्ठतम को पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं.

जीवन की प्रतियोगिता कोई दौड़ नहीं है, जिसमें कोई प्रथम आ जाए, कोई द्वितीय. यह तो निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रतियोगिता है जो कभी समाप्त नहीं होती. कोई नौकरी में सफल होता है, कोई परिवार के भरण-पोषण में. किसी क्षेत्र में हम विफल भी हो जाते हैं, पर दूसरे क्षेत्र की सफलता संतुलन बना देती है. इसलिए होड़ और हदस से भरे इस युग में अपने बच्चों को यह शिक्षा अवश्य दें कि एक क्षेत्र में यदि वे सफल नहीं होते हैं, तो मायूस न हों. कोई अन्य क्षेत्र उनके लिए अधिक उपयोगी हो सकता है. राह बदल कर देखिए, कोई और मंजिल इंतजार करती होगी. परंतु मनोनुकूल पथ न मिलने पर झूठ बोल कर छिपाना या जबरन श्रेष्ठ साबित करने की कवायद मूर्खता कहलायेगी. इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार ही लक्ष्य निर्धारण करें.

आपके पत्र

हाथरस मामले में हो निष्पक्ष कार्रवाई

हाथरस में हुए हादसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की प्राथमिकी में कथावाचक साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है. अलीगढ़ के आइजी शलभ माथुर से पूछा गया कि 'भोले बाबा' का नाम एफआइआर में क्यों नहीं है? इस पर शलभ माथुर ने कहा कि भगदड़ मचने के बाद आयोजनकर्ता भाग गये थे. इसलिए आयोजनकर्ताओं को आरोपित किया गया है. इधर, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने किहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सारी मुसीबत, फसाद और अपराध की जड़ बाबा है.

युगल किशोर राही, छपरा

ऑनलाइन हाजिरी बनाने में परेशानी

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को हर दिन ऑनलाइन हाजिरी बनाने का आदेश दिया है, लेकिन इसमें शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलने के कारण शिक्षक हाजिरी बनाने के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं. इस पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए. शिक्षकों का पूरा ध्यान हाजिरी बनाने पर ही लगा रहता है, जिसके कारण पठन-पाठन प्रभावित होता है. इसलिए हाजिरी बनानेवाले एप में सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे शिक्षकों को परेशानी नहीं हो.

शकील गौहर, पटना

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna@prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 124

किसानों को सक्षम बनाना

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को लेकर राष्ट्रीय मसौदा नीति जारी की। इसका लक्ष्य मौजूदा एफपीओ को मजबूत बनाना और नए एफपीओ के निर्माण और उन्हें प्रोत्साहन देने का काम करना है। एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने का इरादा है जहां बेहतर आय दिलाने वाली खेती और किसानों की समग्र बेहतरी के लिए काम किया जा सके। इस विचार का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे देश भर के करीब 2.5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। नीतिगत लक्ष्य यह है कि देश के कुल 7,256 ब्लॉक में से हर एक में प्राथमिक स्तर के 7-8 सक्रिय एफपीओ की स्थापना की जाए जिनमें से प्रत्येक के साथ औसतन 500 किसानों को जोड़ा जाए। इसका इरादा किसानों की शुद्ध आय को बढ़ाना है और ऐसा कृषि कारोबार को सहज बनाकर, किफायती उत्पादन को अपनाकर तथा बाजारोन्मुखी मूल्यवर्द्धन के माध्यम से किया जा सकता है।

अमूल ने जिस प्रकार दूध के लिए मूल्य श्रृंखला तैयार की है उसी तरह नीतिगत लक्ष्य खेती और बागवानी की उपज के लिए तीसरे स्तर का आपूर्ति श्रृंखला का मॉडल तैयार करने का है ताकि उनका मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और घरेलू तथा निर्यात बाजारों के लिए तैयार किया जा सके। इसका लक्ष्य एफपीओ के लिए ऋण और नकदी की पहुंच को सरल बनाना भी है। इसके लिए एफपीओ इक्विटी ग्रांट फंड और एफपीओ फॉर्मेशन फंड को जारी रखने की बात कही गई है। एफपीओ को कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत ब्याज राहत और ऋण गारंटी मिलनी जारी रह सकती है। इसके साथ ही नीति इन संगठनों में व्याप्त अक्षम प्रबंधन की पुरानी समस्या को भी हल करना चाहती है। इसमें अच्छे प्रबंधकों तक पहुंच, उन्हें आकर्षित करने और अपने साथ जोड़े रखने की दिक्कतें शामिल हैं।

भारत की कृषि लंबे समय तक छोटी जोत की समस्या से ग्रस्त रही है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के आंकड़े बताते हैं कि 85 फीसदी जमीन छोटे और सीमांत किसानों के पास है। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल भी सीमित है। इसके अलावा असंगठित किसानों को अपनी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। छोटे किसानों के पास मोलतोल करने की क्षमता नहीं होती है। उनके पास इतनी सुविधा भी नहीं होती है कि अपनी उपज को भंडारित करके रख सकें ताकि सामग्री की कमी वाले मौसम में उसे अच्छे दामों पर बेचा जा सके। छोटे उत्पादकों के पास इतना कच्चा माल या इतनी उपज नहीं होती है कि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के समान लाभ हासिल कर सकें। कृषि बाजार में बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला है जो अक्सर अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं जिससे ऐसे हालात बनते हैं जहां किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत का बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। इसकी वजह से किसानों की आय प्रभावित होती है।

एफपीओ यहां बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। हर एफपीओ में एक निर्वाचित निदेशक मंडल होता है और इसका स्वामित्व किसानों के पास होता है। इसका मुनाफा अंशधारकों के बीच बंटता है। नाबार्ड, सरकारी विभाग और अन्य वित्तीय संस्थान इन सहकारी समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराते हैं। ये एफपीओ ऐसी कई परतों को समाप्त करते हैं जो किसानों के खिलाफ जाती हैं। समेकन से किसानों को लाभ होता है। उन्हें अच्छी उपज भी मिलती है और अपनी उपज के बेहतर दाम भी हासिल होते हैं। उनके पास उपज के बड़े खरीदारों तथा कच्चे माल के बड़े आपूर्तिकर्ताओं के साथ मोलभाव करने की भी अच्छी क्षमता होती है। एफपीओ कच्चा माल खरीदते हैं, सदस्यों को बाजार से जुड़ी सूचनाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करते हैं और आमतौर पर उनके पास भंडारण और प्रसंस्करण की सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा वे ब्रांड बनाने, पैकेजिंग और बड़े खरीदारों के समक्ष उपज की मार्केटिंग में मदद करते हैं। किसान आमतौर पर उत्पादन तक सीमित रहते हैं और ज्यादातर मुनाफा उत्पादन में नहीं बल्कि प्रसंस्करण और वितरण में है जहां किसानों की भूमिका बहुत सीमित है। ऐसे में जरूरत यह भी है कि किसानों के बीच प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण को लेकर भी निवेश किया जाए।

बजट में दिखना चाहिए बदलाव का संकेत

बजट में जीडीपी के आंकड़ों की चकाचौंध से निकल कर रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाली दूर करने के उपाय भी होने चाहिए। बता रहे हैं अजय छिब्बर

लोकसभा चुनाव संपन्न हुए एक महीना हो गया है। कई सप्ताहों तक चली चुनावी जद्दोजहद के बाद नई सरकार को बिना समय गंवाए नए दृष्टिकोण के साथ देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी महीने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश होने वाला है। यह बजट सरकार के लिए यह बताने का अवसर है कि वह किस तरह चुनाव नतीजे से मिले संदेश को समझ चुकी है।

अब राज एवं अर्थव्यवस्था वैसे नहीं चलाई जा सकती जैसे पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, इसलिए इस बजट में बदलाव का संकेत स्पष्ट होना चाहिए। लोगों ने चुनाव नतीजों के माध्यम से बता दिया है कि वे रोजगार की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा संकट दूर करने पर सरकार को अधिक गंभीरता से काम करते देखना चाहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर निःसंदेह महत्त्वपूर्ण है, मगर इसी से संतुष्ट रहना काफी नहीं है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि की दशा-दिशा और गुणवत्ता भी मायने रखती हैं। लोग केवल भोजन और गैस सिलिंडर से ही खुश नहीं है, वे बेहतर एवं सम्मानजनक रोजगार भी चाहते हैं। जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी एक अपनी सीमा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष फरवरी में फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार चुनाव के बाद भूमि, श्रम, पूंजी और डिजिटल सार्वजनिक ढांचे पर विशेष ध्यान देगी। सीतारमण ने इन बातों का जिक्र कर एक अच्छा संकेत दिया था और अब देखना है कि वह आगामी बजट में इन मोर्चों पर किस तरह कदम बढ़ाती हैं। ये सुधार इन सवालों के उत्तर जानने के लिए जरूरी हैं कि हम उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले एक प्रमुख घटक श्रम का क्यों इतना अविवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं और भारत का आधारभूत ढांचा क्यों अत्यधिक पूंजी के इस्तेमाल पर आश्रित है। बजट में इस प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए कि भूमि की उपलब्धता सीमित होने के बावजूद क्यों इसका इस्तेमाल कम या न के बराबर लाभ देने वाले कृषि कार्यों और अनियोजित शहरी तंत्र तैयार करने में होता है। भारत का पूंजी बाजार भी पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाया है, क्योंकि जीडीपी के 8-9 प्रतिशत तक पहुंच चुके राजकोषीय घाटे की भरपाई करने में काफी आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। ये संसाधन निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध रहते तो इसके बड़े फायदे दिखते। सांविधिक तरलता अनुपात का प्रावधान खत्म किया जाना चाहिए। डिजिटल ढांचे में सुधार का और अधिक फायदा मिल सकता है।

भारत आने वाले समय में भी पूंजीगत व्यय जारी रखना चाहता है, मगर इसके साथ ही इसे राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में अब स्थिरता आ गई है और यह राजस्व का एक बड़ा जरिया बन चुका है। भविष्य के लिए विनिवेश भी एक बड़ा संभावित स्रोत साबित हो सकता है। विनिवेश की मौजूदा प्रणाली, जिसमें लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है, कारगर साबित नहीं हो रहा है। सरकार भी यह बात समझ चुकी है। सार्वजनिक लोक वित्त एवं नीति संस्थान में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर अपने एक अध्ययन के आधार पर मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगले पांच वर्षों में बड़े स्तर पर निजीकरण कार्यक्रम चलाया जाए, मगर यह बात काफी मायने रखेगी कि इसे किस तरह क्रियान्वित किया जाता है।

सार्वजनिक परिसंपत्तियों को रूस के तर्ज पर कुछ खास उद्योग समूहों को दे देना उचित रास्ता नहीं होगा। पारदर्शी प्रक्रिया, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली और श्रमिकों के मुआवजे के लिए कुछ रकम का अलग से प्रावधान करना रणनीतिक विनिवेश की सफलता के लिए अहम होंगे। परिपक्व बाजार वाले लोकतांत्रिक देशों में खुले बाजार में शेयरों की बिक्री का ढांचा मालिकाना नियंत्रण का दायरा बढ़ाने और विनिवेश में अधिक सार्वजनिक भागीदारी के लिए तैयार किया जा सकता है। उन कंपनियों में कर्मचारियों को भी शेयर (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना या ईसॉप्स) दिए जा सकते हैं, जो निजी प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इससे कर्मचारी बिक्री के खिलाफ नहीं जाएंगे।

पूंजी व्यय पर जोर (विशेषकर आधारभूत ढांचे पर) आर्थिक वृद्धि में सहायक रहा है, मगर इससे निजी निवेश में चिर प्रतीक्षित बढ़ोतरी का रास्ता नहीं खुल पाया है। कारोबारी खेमे उत्पादन प्रोत्साहन से जुड़ी योजनाओं की तरह दूसरी योजनाएं चाह रहे हैं, जिनमें उन्हें और सब्सिडी की गुंजाइश हो। मगर यह निजी क्षेत्र की अगुआई में अधिक रोजगार देने वाली आर्थिक वृद्धि के लिए टिकाऊ ढांचा नहीं होगा।

इसका कारण यह है कि मौजूदा 'ट्रिकल-डाउन इकनॉमिक मॉडल' पर्याप्त रोजगार सृजित नहीं करता है और न ही एक बड़े जन समूह के लिए अधिक आय सुनिश्चित कर पाता है, इसलिए उपभोग आधारित मांग कमजोर रहती है। कंपनी जगत को बैंकों से ऋण आवंटन कम रही है और निवेश में सुधार का असर भी नहीं दिख रहा है। बैंकिंग क्षेत्र ऋण आवंटित करने की गुंजाइश तो तलाश रहा है, मगर कंपनियों की तरफ से उधार लेने में सुस्ती को देखते हुए बैंक खुदरा उधारी पर दांव लगा रहे हैं। खुदरा ऋण आवंटन में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को आंख मूंदकर कर्ज बांटने से परहेज करने की हिदायत दी है।

सड़क एवं राजमार्ग व्यवस्थाओं में सुधार से भारत में माल परिवहन की स्थिति बेहतर हुई है, मगर इसका इस्तेमाल करना अब भी काफी महंगा है। पीएलआई का दायरा बढ़ाने (जैसा कि बड़े कारोबारी समूह चाहते हैं) के बजाय कारोबार करने पर लागत घटाने के अधिक फायदे दिखेंगे। बजट में यात्रियों को दूसरे तरीकों से लाभ देकर माल भाड़ा कम रखने, बिजली वितरण कंपनियों के नुकसान का वहन कर उत्पादकों को सस्ती बिजली देने और पेट्रोल एवं डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से सरकारी रकम का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा।

लोग चीन और दक्षिण कोरिया की सफलता देखकर सबक लेते हुए तर्क दे रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि आगे बढ़ाने के लिए भारत को एक अधिक गतिशील औद्योगिक नीति की जरूरत है। यह सच है, मगर उन देशों ने कई बुनियादी चीजों पर भी काम किया है, जिनसे उनके शानदार आर्थिक विकास की नींव तैयार हुई है। सार्वभौम शिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य पर उन देशों का अधिक जोर रहा है। दोनों देशों ने कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार कर अधिक उत्पादक कार्यों के लिए अधिक भूमि उपलब्ध कराई और कोरिया में तो भूमि सुधार की दिशा में भी कदम उठाए गए। दोनों ही देशों में तीव्र गति से शहरीकरण हुआ, मगर उन्होंने शहरों के लिए चिह्नित भूमि का उचित एवं विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया। भारत भी औद्योगिक नीति की दिशा में कदम बढ़ा सकता है, मगर इसका लक्ष्य निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना होना चाहिए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंत में, पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। भारत को एक समृद्ध विरासत मिली है और यहां पर्वत-पहाड़ सहित प्राकृतिक सौंदर्य की बहार है। मगर इनका समुचित लाभ उठाने के लिए भारत को अगले पांच वर्षों के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी होगी। इसमें महिलाओं को सुरक्षा, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा और 'इनक्रेडिबल इंडिया' को 'क्रेडिबल, सेफ इंडिया' में तब्दील करना होगा। इससे पर्यटक तो आकर्षित होंगे ही, साथ ही रोजगार में भी इजाफा होगा।

भारत में कुछ बड़े एवं साहसिक सुधार गठबंधन सरकार के समय में हुए हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे और सुधारों के जरिये भारत को अधिक समावेशी एवं टिकाऊ विकास के मार्ग पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो। बिना रोजगार मुहैया कराए जीडीपी के आंकड़ों से संतुष्ट रह जाना विकसित भारत का सपना साकार नहीं कर पाएगा। देश की दिशा बदलने का समय आ गया है और आगामी बजट इस बदलाव का स्पष्ट संकेत देने का अवसर प्रदान कर रहा है।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी सेंटर में विजिटिंग स्कॉलर हैं)

वायदा एवं विकल्प में कैसे लगे कयास पर अंकुश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच ने पिछले दिनों एक संवाददाता सम्मेलन में डेरिवेटिव खंड में कयास आधारित कारोबार में बेतहाशा बढ़ोतरी पर चिंता जताई थी। पिछले कुछ वर्षों के दौरान डेरिवेटिव खंड में कारोबार में भारी इजाफा हुआ है। इससे कयास आधारित कारोबार और बढ़ने की चिंता सिर उठाने लगी है। शेयर ब्रोकरेज कंपनी जीरोधा के संस्थापक नितिन कामत ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, 'विकल्प (ऑप्शन) खंड में कारोबार बेतहाशा बढ़ा है।'

सूचकांक विकल्प (इंडेक्स ऑप्शन) में 2018 में 4.6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था, मगर यह 2024 में बढ़कर 138 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इससे भी गौर करने वाली बात यह है कि खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गई है। इसे लेकर सेबी की प्रतिक्रिया देर से आई है और वह भी गलत दिशा में प्रतीत हो रही है। आइए, इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं।

कयास बनाम हेजिंग

सेबी इस बात को लेकर चिंतित है कि विकल्प कारोबार का एक बड़ा हिस्सा केवल अटकल या कयास पर आधारित है और हेजिंग से इसका सरोकार नहीं है। बाजार नियामक की चिंता उचित है, मगर हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो यह मुझे एक वाकये की याद दिलाता है, जो मुझे 25 वर्ष पहले एक तीसरी पीढ़ी के एक ब्रोकर ने बताया था। 1970 के दशक में शेयर बिचौलियों (ब्रोकर) के साथ बैठक में वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज (अब बीएसई) पर अटकलों का बाजार गर्म रहता है।

बैठक में मौजूद एक गुजराती ने कहा कि शेयर बाजार में कयास नहीं लगेंगे तो फिर कहां लगेगा? सेबी नकद बाजार और डेरिवेटिव बाजार के बीच जुड़ाव नहीं होने से भी चिंतित है।

मगर अधिकांश विकल्प कारोबारियों ने डिलिवरी लेने या देने के लिए विकल्प कारोबार नहीं किया है। वास्तव में, मुझे इसे लेकर आंकड़े नहीं मिले कि कितने विकल्प अनुबंध फिजिकल डिलिवरी में बदलते हैं। अगर कोई विकल्प कारोबार डिलिवरी में तब्दील होता है तो यह एक इत्तफाक होगा और यह संभवतः कारोबारी की गलती रही होगी, न कि हेजिंग स्ट्रैटजी (नुकसान से बचने या कम करने की रणनीति) का कोई हिस्सा। जब से शेयर विकल्प शुरू किया गया है तब से ऐसा देखने में आया है। सूचकांक विकल्प के लिए तो वैसे भी डिलिवरी का कोई खास मतलब नहीं रहता है।

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

सेबी प्रमुख ने यह भी कहा कि व्यापक आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो 'परिवारों की बचत का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे कारोबार में जा रहा है, जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद नहीं है। यह कयास आधारित गतिविधि है'। उन्होंने कहा कि यह रकम अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण पर खर्च नहीं हो रही है। यह सच भी है, मगर एम्सटर्डम में 1602 में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित होने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में शेयर कारोबार (कैश या डेरिवेटिव) से कभी उत्पादक गतिविधि साबित नहीं हुआ है।

व्यापक आर्थिक नजरिये से देखें तो द्वितीयक बाजार में शेयर कारोबार प्राथमिक बाजार को चलाने के लिए जरूरी खामी है। प्राथमिक बाजार के कारण ही लोगों की बचत उद्यमों में आती है, मगर यह (प्राथमिक बाजार) स्वयं अपने बूते नहीं टिक सकता, इसलिए इसके निवेशकों में पर्याप्त कारोबारी तरलता को लेकर विश्वास बहाल करने के लिए द्वितीयक बाजार की जरूरत होती है। तरलता पर्याप्त रहने से निवेशक अपनी सुविधानुसार निकल सकते हैं। निवेशकों को यह विश्वास दिलाना महत्त्वपूर्ण है ताकि उद्यम शेयर निर्गमों के माध्यम से निवेश आकर्षित करते रहें। संयोग से जिंस बाजार उद्यमों में लोगों की बचत खींचने नहीं खींच पाता और न ही वह विनिर्माताओं या किसानों को हेजिंग की सुविधा ही दे पाता है।

अब अगर डेरिवेटिव में अत्यधिक अटकलबाजी पर गंभीर चिंता सता रही है, मगर सवाल है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? आखिर, सेबी की अनुमति के बाद ही तो स्टॉक एक्सचेंजों ने विकल्प कारोबार शुरू किया था। एक्सचेंज अब लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं मगर सेबी का बाजार के सभी पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण है, जिनमें एक्सचेंजों के प्रमुखों एवं प्रबंधन स्तर के मुख्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी शामिल हैं।

सेबी के निर्देश के अनुसार जब कोई कारोबारी किसी ट्रेडिंग पोर्टल (कारोबारी पोर्टल) पर लॉग इन करता है तो उनके सामने स्क्रीन पर सेबी का एक अध्ययन सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि 'शेयर वायदा एवं विकल्प खंड में 10 में 9 लोगों को शुद्ध नुकसान उठाना पड़ा है। शुद्ध कारोबारी नुकसान के अलावा उन्हें शुद्ध नुकसान का 28 प्रतिशत लेनदेन पर आई लागत के रूप में चुकाना पड़ा।'

इन लेनदेन लागत के दूसरी तरफ कौन हैं? इनमें पांच इकाइयां हैं जिनमें ब्रोकर (ब्रोकर फीस), एक्सचेंज (फीस), सेबी (फीस), राज्य सरकार (स्टांप शुल्क) और केंद्र सरकार (प्रतिभूति लेनदेन कर) शामिल हैं। क्या ये इकाइयां कयास कम करने के लिए प्राप्त होने वाला राजस्व कमाना छोड़ सकते हैं? वास्तव में, नीति निर्धारकों के बीच भी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि डेरिवेटिव आय पर कैसे कर लगाया जाए। डेरिवेटिव वास्तव में कयास आधारित कारोबार ही हैं।

मगर आश्चर्य की बात है कि डेरिवेटिव कारोबार से प्राप्त मुनाफे को कयास आधारित आय नहीं बल्कि आयकर के लिहाज से कारोबारी आय के रूप में देखा जाता है!

जब डेरिवेटिव कारोबार की शुरुआत हुई थी तो विचारों में अंतर देखा जा रहा था। वर्ष 2001 में आधुनिक पूंजी बाजार की चिर-परिचित शख्सियत आर एच पाटिल ने कहा था, 'बदला लेनदेन की जगह देश में वायदा लाने का मुख्य मकसद सूचकांक वायदा, सूचकांक विकल्प और शेयर विकल्प शुरू करना था। शेयर आधारित वायदा से जुड़े पूरे मामले पर विचार करने वाली सेबी की समिति शेयर वायदा के पक्ष में नहीं थी। जिन देशों में शेयर वायदा का कारोबार होता है उनमें अधिकांश में कोई अकेला शेयर वायदा जगह नहीं पाता है और अगर पाता है तो भी उसमें बहुत अधिक कारोबार नहीं होता है।'

मगर उनके विचार पर ध्यान नहीं दिया गया और 'कयास' की शुरुआत हो गई।

कयास को दूसरा बड़ा समर्थन तब मिला जब सेबी ने 2029 में स्टॉक एक्सचेंजों को वीकली एक्सपायरी शुरू करने की अनुमति दे दी। सच्चाई यह है कि कोविड के बाद कारोबार में बेतहाशा बढ़ोतरी से पहले तक सेबी को डेरिवेटिव के साथ कोई दिक्कत नहीं थी। मगर अब एक खतरनाक ढांचा खड़ा करने के बाद सेबी को यह चिंता सताने लगी है कि बड़ी संख्या में लोग डेरिवेटिव कारोबार में शामिल हो रहे हैं। सेबी ने इस मामले की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना जरूर की है, मगर यह अटकलों पर अंकुश लगाना चाहता है तो उसे सबसे पहले शेयर विकल्प या सूचकांक विकल्प की वीकली एक्सपायरी को समाप्त करना होगा।

(लेखक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संस्थापक हैं)

https://epaper.bsmail.in

आपका पक्ष

सब्जियों के दाम में वृद्धि क्यों

बारिश होने पर सब्जियों के दाम में वृद्धि हो जाती है। अगर बारिश हो जाए तो भी सब्जियों के खराब होने के कारण दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका क्या हल निकाला जाए? देश के कुछ राज्यों में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। कभी प्याज तो कभी दूसरी सब्जियों के मूल्य आसमान छूने लग जाते हैं। कृषि प्रधान देश में सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी और किसानों की दयनीय दशा शर्मनाक और निंदनीय है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के जो मुख्य कारण हैं, उनमें इनके भंडारण के लिए सरकार का उचित प्रबंध न करना भी हो सकता है। किसानों ने सब्जियों की पैदावार कम की होगी कि अगर बिक्री समय पर न हुई तो ये सड़ जाएंगी और उन्हें नुकसान हो जाएगा। सब्जियां महंगी होने का कारण कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी या प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। सब्जियों की कीमतों में लगाम के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

देश के कुछ राज्यों में टमाटर, करेला, परवल, गोभी सहित कई सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं

उचित शहरी नियोजन जरूरी

बारिश से होने वाली तबाही की रोकथाम के लिए उचित शहरी नियोजन, पौधरोपण, वन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं (बांध, बैराज, तटबंध) का निर्माण, जल पुनर्भरण-संचयन प्रणाली का विकास, सतर्कता और पूर्वानुमान प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, आपदा प्रबंधन योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन, नदी-नालों की सफाई जरूरी है। इसके साथ ही आपदा से बचाव के लिए सामाजिक जागरूकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, पुल, बिजली तार आदि) सुधार और ड्रेनेज की नियमित मरम्मत आवश्यक है। अन्न संरक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में भंडारगृह बनें और विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ बंद होना चाहिए।

मोहित सोनी, कुक्षी

अलग से बने बजट

बारिश से तबाही रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए अलग से बजट बनना चाहिए। नदियों के किनारे आवास बनाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नदी-नालों का प्रवाह तंत्र नहीं रोका जाए। बाढ़ के स्थान चिह्नित रहने चाहिए। बारिश से पहले ही अलर्ट घोषित होना चाहिए। सूचना प्रणाली और त्वरित व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए। भवन कई मंजिल और मजबूत बनाने होंगे। अत्याधुनिक तंत्र से बाढ़ की तबाही रोकने का उपाय करना होगा। प्रशिक्षित लोगों की टीम हमेशा रिजर्व रखनी होगी।

प्रदीप गौतम सुमन, रीवा

ड्रेनेज के अवरोधों को दूर किया जाए

विगत तीन-चार दशकों के आंकड़ों का अध्ययन कर जल भराव वाले क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में बदलाव करना चाहिए। जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम की मॉनसून पूर्व ही जांच कर उनके अवरोधों को दूर किया जाना चाहिए। नदी-नालों के जलागम इलाके में किसी तरह की बसावट नहीं होनी चाहिए। एक नदी को कैसे दूसरी नदी से जोड़कर बाढ़ के संकट से निपटा जा सकता है, इस दिशा में ठोस पहल की आवश्यकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा काल में पर्यटन प्रतिबंधित होना चाहिए। पुल पर पानी की स्थिति में आवागमन पर रोक होनी चाहिए।

विमलेश पगारिया, बदनावर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कीर्ति चक्र विजेता शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इसके बाद वह शहीद स्मारक गए जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पौधरोपण किया।

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 10 जुलाई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मोदी की सफल रूस यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 और 9 जुलाई को दो दिन की रूस यात्रा पर थे। करीब पांच वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंधों को कुछ और प्रगाढ़ता मिली ही, इसके साथ ही वैश्विक राजनीति में यह बड़ा संदेश भी गया कि अब दुनिया एकध्रुवीय व्यवस्था के इर्द-गिर्द नहीं रहेगी, बल्कि बहुध्रुवीय समीकरणों से ही वैश्विक राजनीति संचालित होगी। भारत-रूस के बीच आखिरी वार्षिक शिखर वार्ता नयी दिल्ली में छह दिसंबर 2021 को हुई थी, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन भारत दौरे पर थे, 2020 में कोविड महामारी के कारण यह वार्षिक बैठक नहीं हो पाई थी। फिर यूक्रन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक श्री मोदी रूस दौरे पर नहीं गए थे। उनका आखिरी दौरा सितंबर 2019 में हुआ था। लेकिन इतने उतार-चढ़ाव के बावजूद दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और सौहार्द्र का रिश्ता कायम ही रहा।

9 जुलाई को रूस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी ने एक बड़ी मार्के की बात कही कि रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहला शब्द आता है, भारत का सुख-दुख का साथी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद से अब तक दुनिया के तमाम देशों में रूस ही वह देश रहा है जो हर मुकाम पर भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। भारत ने भी इस बीच आर्थिक, सामरिक या तकनीकी सहयोग के लिए दूसरे देशों से समझौते किए, संबंधों में नयी मजबूती दिखाई, लेकिन रूस के साथ भारत के संबंध जैसे पहले थे, अब भी वैसे ही हैं। यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस और भारत के संबंधों पर भी सबकी निगाहें बनी हुई थीं, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भारत ने रूस से तेल ख़रीदना जारी रखा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भारत की विश्वशांति की हिमायत शिखर वार्ता में की।

राष्ट्रपति पुतिन को श्री मोदी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बम, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती है। नरेन्द्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब यूक्रेन में एक अस्पताल पर रूस के हमले में बच्चों समेत 37 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस के इस हमले की अमेरिका, यूक्रेन और नाटो देश निंदा कर ही रहे हैं, इस बीच भारत ने रूस को यह नसीहत देकर बता दिया कि वह किसी भी तरह की हिंसा और युद्ध के खिलाफ ही है। इसलिए इस बात को केवल रूस तक सीमित न रखकर इसके व्यापक मायने समझने की भी जरूरत है। अमेरिका और यूक्रेन अगर रूस के हमलों की आलोचना कर रहे हैं, तो उन्हें इजरायल के गज़ा पर हो रहे हमलों पर भी वही रुख अख्तियार करना चाहिए। लेकिन अमेरिका अब भी फिलीस्तीन पर इजरायल की क्रूरता को नहीं रोक रहा, न ही एक बड़े नरसंहार के दाग से खुद को बचा पा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ऐसे वक्त पर हुई, जब अमेरिका में रूस-यूक्रेन संघर्ष को केन्द्रित करते हुए नाटो की बैठक थी। अमेरिका अब भी भारत को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश में लगा है। मोदी-पुतिन बैठक से पहले अमेरिकी विदेश विभाग का बयान था कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत, या कोई अन्य देश जब रूस के साथ बातचीत करेगा, तो 'यह स्पष्ट करेगा कि मॉस्को को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए'। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदीमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक की निंदा करते हुए इसे 'शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका' बताया।

भारत जानता था कि श्री मोदी के रूस दौरे पर उसे इस तरह के दबाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आजादी के बाद से ही भारत की विदेश नीति कुछ इस तरह तैयार की गई है कि वह किसी के दबाव या गुटबाजी में नहीं आता है। अपनी यात्रा में श्री मोदी ने एक तरफ यक्रेन को लेकर राष्ट्रपति पुतिन को नसीहत दी, तो वहीं पुतिन ने भी यूक्रेन संघर्ष के समाधान की कोशिशों के लिए भारत का आभार जताया। रूस के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए कजान और इकेतेरिनबुर्ग में कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय भारत ने लिया है। खबरें ये भी हैं कि श्री मोदी ने रूसी सेना में जबरन भर्ती किए भारतीयों का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया। जिस पर पुतिन ने आश्वासन दिया है कि वे सभी भारतीयों को बहाल कर देंगे। बताया जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बीच लगभग 40 भारतीय रूसी सेना में तैनात हैं, पिछले महीने 2 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे कठिन हालात में भारतीय प्रधानमंत्री की पहल से अगर रूसी सेना से भारतीयों को मुक्ति मिलती है, तो यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए।

इधर अमेरिका और उसके समर्थक देशों को यह सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भारत उनके इशारों या दबाव पर न चला है, न चलेगा, न ही अब वैश्विक व्यवस्थाएं उनके इशारों पर चलेंगी। ब्रिटेन और ईरान के बाद अब फ्रांस में भी जिस तरह दक्षिणपंथियों की राजनीति को जनता ने नकार दिया है, उससे साफ है कि जनता अमन चाहती है, जो सबके विकास के लिए जरूरी है। फ्रास में सबसे अधिक सीटें हासिल करने वाले वामपंथी धड़े न्यू पॉपुलर फ्रंट ने घोषणा भी कर दी है कि वह फिलीस्तीन को मान्यता देगा। यानी अब वैश्विक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर की चिंता

जम्मू और कश्मीर से लगातार जो खबरें आने लगीं यही वे चिंता से भी ज्यादा डर पैदा करती हैं। डर इस बात का नहीं है कि हमारी फौज के जवानों का हौसला पस्त होगा या हमारी सरकार ही कमजोर पड़ जाएगी और आतंकियों तथा उनके पीछे बैठे उनके पाकिस्तानी आकाओं का हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वे हमें लंबे समय तक भारी परेशान कर देंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह इतना तो बताता ही है कि आतंकियों ने हथियार नहीं डाला है, पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है, पाक मदद जारी है और हमारे अपने कश्मीरी समाज से आतंकियों को मदद मिले न मिले लेकिन हमारे खुफियातंत्र को उनसे जरूरी सूचनाएं नहीं मिल रही है। ऐसा जाना-बूझकर हो रहा है या फौजी उपस्थिति का दबदबा और खौफ ऐसा करा रहा है, यह मालूम नहीं है। लेकिन खुफिया सूचनाओं में फौजी तंत्र को पर्याप्त फ़ीड नहीं है, तभी हमले हो रहे हैं। कठुआ के बनडोटा गांव के पास आतंकियों ने जिस तरह घात लगाकर फौजी वाहन पर हमला किया और चार जवानों को मारने के साथ ही अनेक को घायल कर दिया उसमें उनको एक स्थानीय आतंकी के पूरा सहयोग मिलने की बात सामने आ रही है।

उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बार घाटी से भी ज्यादा वारदातें जम्मू इलाके में हो रही हैं। अकेले जून में ही चार बड़ी वारदातें जम्मू इलाके में हो चुकी हैं। बल्कि मई में तो वायु सेना के दो हेलीकाप्टरों तक को निशाना बनाया गया जिसमें एक जवान की मौत भी हुई। कठुआ के ही हीरन नगर में सेदा सोहल गांव में जब फौज और आतंकियों में मुठभेड़ हुआ तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान और दो आतंकी मारे गए थे। बनडोटा में कई जवान घायल हैं और लेख के लिखे जाने तक भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी थी। दो जवान गंभीर रूप से घायल थे और उनको बिलावर के अस्पताल में भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि जम्मू इलाके को अपेक्षाकृत शांत मानकर वहां से फौज की संख्या कम की गई थी और यह रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान से जिन 70 से 80 आतंकियों के घुसपैठ का अनुमान है उनमें से ज्यादातर अभी इसी इलाके में हैं। वे चार-चार, पांच-पांच की टोली बनाकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। और यह बताने का मतलब नहीं है कि वे घाटी को छोड़ गए हैं और जब बर्फ पड़ेगी तो घाटी वाली सीमा ही उनके लिए घुसपैठ का रास्ता बनती है। जम्मू-कश्मीर और खास तौर से जम्मू क्षेत्र को आतंकी क्यों वारदातों के लिए चुन रहे हैं इसको समझना मुश्किल नहीं है।

अरविन्द मोहन

> जम्मू इलाके को अपेक्षाकृत शांत मानकर वहां से फौज की संख्या कम की गई थी और यह रिपोर्ट भी है कि पाकिस्तान से जिन 70 से 80 आतंकियों के घुसपैठ का अनुमान है उनमें से ज्यादातर अभी इसी इलाके में हैं। वे चार-चार, पांच-पांच की टोली बनाकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। और यह बताने का मतलब नहीं है कि वे घाटी को छोड़ गए हैं और जब बर्फ पड़ेगी तो घाटी वाली सीमा ही उनके लिए घुसपैठ का रास्ता बनती है। जम्मू-कश्मीर और खास तौर से जम्मू क्षेत्र को आतंकी क्यों वारदातों के लिए चुन रहे हैं।

धारा 370 हटे और राज्य का विभाजन हुए पांच साल होने को आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सितंबर के पहले जम्मू और कश्मीर में चुनाव हो जाने चाहिए। राज्य में विधानसभा की सीटों के पुनर्गठन का काम भी पूरा हो चुका है और इसे लेकर भी हल्की नाराजगी है। आतंकवादियों की गतिविधियों से इस चुनाव का साफ रिश्ता है। हमने यह भी देखा है कि लंबा चले लोक सभा चुनाव में भी आतंकी घटनाएं बढ़ने लगी थीं। यहां हम लद्दाख क्षेत्र के चुनाव और राज्य का बंटवारा करने वाली पार्टी के प्रदर्शन की चर्चा नहीं करेंगे। जम्मू और कश्मीर घाटी में राज्य का बंटवारा मुद्दा था और उससे भी उल्लेखनीय खुद चुनाव था जिसमें लोगों की भागीदारी तो ठीक-ठाक हुई लेकिन स्थापित दलों की हालत खराब रही। बड़े-बड़े नेता ढेर रहे। नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन तथा पीडीपी के नेता तो चुनाव लड़े और हारे लेकिन भाजपा और उसके दुलारे गुलाम नबी आजाद की पार्टी तो घाटी के चुनाव मैदान में उतारने से डर गई और मैदान ही छोड़ दिया। लोगों ने मतदान में हिस्सा लेकर जिन्हे जिताया और जिन्हें हराया उन सबके माध्यम से अपना जनादेश साफ कर दिया।

केंद्र में बैठे नेताओं ने इस जनादेश को ठीक समझा हो ऐसा नहीं लगता। हार या जीत को सीधे फेस करने और चुनाव में हिस्सा लेकर जो संदेश दिया जा सकता था(राजीव-फारुख समझौते के बाद हुए चुनाव में अपनी पराजय के बाद राजीव गांधी ने बड़ी शालीनता से जनादेश को स्वीकार किया था) वह तो दूर, जाने क्या-क्या दावे किए जाते रहे। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तो यह बयान भी देते रहे कि पाक अधिकृत कश्मीर खुद ब खुद हमारी ओर आने वाला है क्योंकि हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं(और पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है) उसे देखकर ही कश्मीरी लोग लट्टू हो गए हैं। अभी तक राज्य में लाखों की संख्या में जवान तैनात हैं। निश्चित रूप से इसके कारण पहले की तुलना में हाल तक ज्यादा शांति रही है। उनके खर्च की बात छोड़ भी दें तो निवेश से लेकर शेष देश के जुड़ाव के जो सपने दिखाए गए थे, वे कहां हैं यह कोई भी पूछ सकता है? चुनाव में भी इस तरह के पिटे मोहरों और भगोड़े दस्तों पर लोग कितना भरोसा करेंगे कहना मुश्किल है। चुनाव कराने के क्रम में ऐसी सख्ती नहीं रखी जा सकती। आतंकी इस ताक में थे और हथियार-गोला-बारूद तथा प्रशिक्षण पा रहे थे। वारदातें बढ़ना उसी का प्रमाण है। और याद रखें कि अब सामान्य गैर-मुसलमान लोग या प्रवासी निशाने पर नहीं हैं। रियासी में तीर्थयात्रियों वाली बस को निशाना बनाने तक ऐसी रणनीति दिखती थी। अब तो सीधे फौज के लोग निशाने पर हैं।

एक थ्योरी यह चल रही है कि पाक अधिकृत कश्मीर में वहां के एक रिटायर ब्रिगेडियर और आईएसआई के आपरेटर आमीर हमजा समेत 21 कश्मीरी आतंकियों की रहस्यमय हत्या के बाद से ही ये वारदातें और घुसपैठ बढ़ी है। हमजा 2018 में सुनजवां सैनिक कैम्प पर हुए से जुड़ा था। उसकी और इन 21 लोगों की हत्या कुछ अनाम बंदूकधारियों ने कर दी थी। ये हत्यारे कौन थे, इसकी तरह-तरह की व्याख्या है पर न तो किसी ने इसका श्रेय लेने का दावा किया है न कोई पक्के प्रमाण ही सामने आए हैं। कहा जाता है कि इसके बाद से ही आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर सैफुला सज्जाद जट्टा, जो उसके एक दस्ते का नेतृत्व कर रहा है, को इसका बदला लेने का जिम्मा सौंपा है। घटनाएं इसी के कारण बढ़ी हैं। अब इस थ्योरी को मानने का मतलब पीओके में रा की गतिविधियों को बड़ा और सही मानना होगा पर बीच चुनाव में ऐसा होगा यह अविश्वसनीय लगता है।

भारत की धीमी औद्योगिक वृद्धि के पीछे कम एफडीआई प्रवाह ही मुख्य कारण

■ नन्तू बनर्जी

यह अजीब लग सकता है कि औद्योगिक महाशक्ति और एक प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखने वाले भारत को पिछले साल केवल 28अरब अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ, जबकि छोटे से सिंगापुर में 160अरब डॉलर और हांगकांग में 113अरब डॉलर के एफडीआई का प्रवाह हुआ। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के अनुसार, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत में एफडीआई प्रवाह में 43प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसमें दो प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 13खरब डॉलर रह गया है। भारत को वास्तव में मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए अगले 10 वर्षों में कम से कम 150-200बिलियन डॉलर की वार्षिक आवश्यकता होगी।

नयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को आने वाले वार्षिक बजट में देश में बड़े पैमाने पर एफडीआई प्रवाह के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद केवल 35.2खरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। इसके विपरीत, पड़ोसी चीन का सकल घरेलू उत्पाद 2023 में 1260.6खरब युआन था, जो 178.9खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

> नयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को आने वाले वार्षिक बजट में देश में बड़े पैमाने पर एफडीआई प्रवाह के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद केवल 35.2खरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है।

भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि का रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व के लक्ष्य से दूर है जिसमें चालू वित्त वर्ष के अंत में 50 खरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के निशान को छूने का लक्ष्य रखा गया था। भारत को अपनी गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए कई वर्षों तक दोहरे अंकों की वार्षिक आर्थिक वृद्धि की आवश्यकता है।

देश को अपनी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। अधिशेष धन वाले मुट्ठी भर घरेलू औद्योगिक निवेशक ऐसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। चीन का विशाल आर्थिक उत्थान देश में साल दर साल बड़े पैमाने पर एफडीआईप्रवाह द्वारा संभव हुआ है। 2021 में, चीन में एफडीआई प्रवाह 344 अरब डालर के शिखर पर पहुंच गया। दूसरी ओर, चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) द्वारा अन्य देशों में निवेश 2023 में पूरा हुआ। चीन से आउटबाउंड ग्रीन फील्ड एफडीआई 140अरब डालर से अधिक था, जिसने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

यह आउटबाउंड चीनी विलय और अधिग्रहण में गिरावट के बाद है क्योंकि पश्चिमी सरकारों ने प्रस्तावित चीनी विलय और अधिग्रहण सौदों की जांच तेज कर दी है। चीन स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में नये बाजारों में विस्तार कर रहा है। नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत का तेजी से विस्तार करने वाला अडानी समूह, जो सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का एक प्रमुख प्राप्तकर्ता है, ने अपनी महत्वाकांक्षी सौर विनिर्माण परियोजना में मदद के लिए आठ चीनी कंपनियों का चयन किया है। गुजरात में चीन से जुड़ी एमजी मोटर्स भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दे रही है।

संयोग से, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जो 2023 में कुल 341अरब डॉलर था। अमेरिका में एफडीआई प्रवाह 2015 और 2016 में क्रमश: 484अरब डॉलर और 480अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। हाल ही में अमेरिका में एफडीआई प्रवाह में काफी कमी आई है। शीर्ष-20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में, एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ी गिरावट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और भारत में दर्ज की गई।

भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी किये गये आंकड़ों में बताया गया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दरों और देश में विभिन्न क्षेत्रों में सीमित अवशोषण क्षमता जैसे बाहरी कारकों के कारण 2023-24 में एफडीआई पांच साल के निचले स्तर पर आ गया। विडंबना यह है कि भारत में एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो तेजी से बढ़ रहा है, वह है शेयर बाजार। शेयर बाजार में जुआ खेलने वाले उच्च उपभोक्ता मुद्रास्फीति के बावजूद सूचीबद्ध शेयरों की कीमतों में और उछाल देखने के लिए कम ब्याज दरों के लिए अभियान चला रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि रिजर्व बैंक और सरकार ऐसे अभियानों के झांसे में आ सकते हैं।

प्राथमिक बाजार में इक्विटी और ऋण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कुछ हद तक नगण्य है, फिर भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भारत के शेयर बाजार को अत्यधिक जीवंत और अस्थिर बनाने के लिए लुका-छिपी का खेल जारी रखते हैं, जिससे यह सट्टेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाता है। अधिकांश विदेशी सट्टेबाजों ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा (निचले सदन) चुनाव के बाद केंद्र में अस्थिर सरकार की संभावना के डर से बाजार से धन बाहर निकलना शुरू कर दिया था। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता में वापसी ने इन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को वापस लाना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले दो महीने तक शुद्ध निकासी के बाद, वे पिछले महीने खरीदार बन गये। जून में उन्होंने शेयरों की खरीद में लगभग 26,500 करोड़ रुपये और ऋण साधनों में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। पिछले हफ़्ते देश के शेयर बाज़ार के बेंचमार्क- 30 शेयरों वाला सेंसेक्स और निफ्टी-50 ने नये रिकॉर्ड बनाते हुए भारी बढ़त दर्ज की।

भारत में एफडीआई प्रवाह की खराब स्थिति को लेकर बहुत कम लोग चिंतित हैं। अभी तक, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी को छोड़कर बहुत कम ओईसीडी देश भारत में सीधे निवेशक हैं। निवेश मुख्य रूप से मॉरीशस और सिंगापुर जैसे देशों के ज़रिये होता है। अप्रैल 2000 से मई 2010 के बीच भारत में कुल एफडीआई प्रवाह में मॉरीशस का हिस्सा 25 प्रतिशत था। 2024 तक भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 24 प्रतिशत की गिरावट आयेगी, इसके बाद सिंगापुर और अमेरिका का स्थान है। पिछले वित्त वर्ष में मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, केमैनआइलैंड, जर्मनी और साइप्रस सहित सभी प्रमुख निवेशक देशों से भारत में एफडीआईइचिटी प्रवाह में गिरावट आई है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे एफडीआई निवेशक वास्तव में विदेशों में भारतीय संस्थाएं हैं जो छोटे देशों में शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश करती हैं। अब समय आ गया है कि सरकार एफडीआई इक्विटी प्रवाह को अत्यधिक आकर्षक और खुला बनाने के लिए कदम उठाये, जैसा कि उसने पिछले साल सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए किया था।

देश के आगामी राष्ट्रीय बजट 2024-25 में भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देना चाहिए। बड़े देश भारत में निवेश करने और भारत और उनके विदेशी निवेशकों दोनों के लिए लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। हालांकि, जब से यूएनसीटीएडी निवेशक सर्वेक्षणों ने एफडीआई गंतव्य के रूप में भारत में मजबूत रुचि की ओर इशारा किया है, तब से कुछ अदृश्य घरेलू हित आड़े आ रहे हैं। कई साल पहले, ए.टी. कियर्नी सर्वेक्षण ने भी भारत को 'एफडीआई के लिए दूसरा सबसे आकर्षक गंतव्य' बताया था। दुर्भाग्य से, इस पर अभी तक आवश्यक सरकारी कार्रवाई और नीतिगत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करके, बुनियादी ढांचे और नियामक बाधाओं को दूर करके अमल में नहीं लाया जा सका है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पावन प्रसंग

एकाग्रचित्त हो कठिनाइयों का करें सामना

जीवन में कठिन परिस्थितियों कभी बता कर नहीं आतीं हैं, इसीलिए मनुष्य को हर कठिन तथा विषम परिस्थिति के लिए सदैव सजग तथा सावधान रहने की आवश्यकता है। खुशियां तथा अवसाद हर मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन परिस्थितियों को किस तरह अपने जीवन में आत्मसात कर संतुलित करते हैं। जीवन एक गणित की तरह है कभी-कभी दो और दो चार तथा कभी दो और दो पांच भी हो जाते हैं। दो और दो पांच का मतलब विषम परिस्थितियों का सामना करना। वैसे भी जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए सदैव संघर्षरत रहना होता है। सिर्फ मानव प्रजाति में सोचने-समझने और मुस्कुराने की शक्ति होती है। मनुष्य की सर्व चेतनाओं से परिपूर्ण होता है। पत्थरों चेतनाशून्य होते हैं, पेड़ पौधे पल्लवित-पुष्पित होती है पशु-पक्षियों में चलायमान होते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें मस्तिष्क चिंतन मनन कर किसी समस्या का समाधान निकालता है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य का जीवन विभिन्न सामाजिक मानसिक संघर्षों का केंद्र होता है। मनुष्य ने सदैव मानसिक-शारीरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के बलबूते पर हर समस्या पर समय-समय पर विजय प्राप्त की है, और अपने लक्ष्य को बड़ी दृढ़ता के साथ प्राप्त किया है। मनुष्य के जीवन में जब उत्साह, ऊर्जा एवं अपनी क्षमताओं के उपयोग करने का पूर्ण रूप से आत्मविश्वास होता है तो वह परिस्थितियों का सामना बखूबी कर अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करता है। एक मानव प्रजाति ही ऐसी प्रजाति है जिसकी संकल्पशक्ति इतनी ऊर्जावान एवं महत्वपूर्ण होती है कि वह प्रगति की विविधताओं, विषमताओं एवं अपार शक्ति को भी आसानी से नियंत्रित कर लेता है। एवं उसका स्वयं के लिए. समाज के लिए. देश के लिए सकारात्मक उपयोग करने में भी सक्षम होता है। जीवन में मनुष्य को सदैव अपने आप को व्यस्त रख कार्यशील रहना चाहिए, क्योंकि व्यस्त व्यक्ति ही किसी कार्य को उसकी परिणति तक पहुंचा सकता है,खाली दिमाग सदैव शैतान का होता है एवं उसमें नकारात्मक विचार प्रवेश कर मन को मायूस कर देते हैं। आपका मन या मनोबल या संकल्प ही जब एकाग्रचित्त ऊर्जावान तथा शक्तिशाली होगा तो आपके सामने की कितना भी क्लिष्ट व कठिन लक्ष्य हो उसमें आप सफलता अवश्य पा सकेंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव कर्मरत रहना चाहिए। इसका यह भी अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने आपको सदैव स्वस्थ एवं व्यस्त रखना चाहिए।

मन में दृढ़ संकल्प रखकर हमारी दुनिया में लोगों ने ऐसे असंभव कठिन तथा दुरूह कार्यों को अपनी जड़ मानसिक शक्ति से संभव कर दिखाया है जिसकी हम कतई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की विपन्न स्थिति एवं आर्थिक कमी के बावजूद उन्होंने अपनी मानसिक दृढ़ता ,उच्च संकल्प शक्ति और संगठन क्षमता के दम पर भारत देश को आजाद कराया। इसमें निसंदेह महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल,जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मानसिक शारीरिक शक्ति तथा ऊर्जा के दमखम पर देश को अंग्रेजों के चंगुल से निकाल कर आजादी की हवा की सांस लेने का देशवासियों को मौका दिया है। हम उनका नमन करते हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति एवं संकल्प को आदर्श के रूप में लेकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। दुनिया में अपनी मानसिक शक्ति और संकल्प से अनेक असंभव कार्य को सफलतापूर्वक संचालित संपादित करते हुए अनेक उदाहरण मिलेंगे जो वाकई में इस दुनिया के और हम सबके आदर्श महान लोग हैं। व्यक्ति यदि सादगी, ईमानदारी और निरंतरता के साथ किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने का सार्थक एवं सर्वोच्च प्रयत्न करता है, तो निसंदेह सफलता उनके कदम चूमती है।

संजीव ठाकुर

आपके पत्र

मानसून की मनमर्जी

मानसून में होने वाली तेज बारिश अब बाढ़ में बदलने लगी है। विशेषज्ञों के अनुसार बारिश की मात्रा में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, किन्तु मानसून का पैटर्न बदल गया है। मानसून के आते ही देश के कई हिस्सों में बादल फटने, बाढ़ आने, बिजली गिरने व भूस्खलन जैसी घटनाएं होने से भारी तबाही होने लगी है। इन सब का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है जिसकी वजह से मौसम पैटर्न में बदलाव हुआ है, साथ ही ग्लेशियरों का पिघलना व समुद्र के जलस्तर का बढ़ना इत्यादि के कारण अब कम बारिश में भी बाढ़ आने की समस्या बढ़ती जा रही है।

'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के अनुसार भारत के 3290 लाख हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से 400 लाख हेक्टेयर से अधिक हिस्सा बाढ़ ढलान वाला है। हाल ही में देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही ला दी जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि देश के कुछ हिस्से में बारिश औसत से भी कम रहती है।

कई अध्ययनों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर के कई क्षेत्रों में बादल फटने की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की सबसे अधिक घटनाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में 'दशकीय तापमान वृद्धि' 'वैश्विक तापमान वृद्धि' की दर से अधिक है। हाल ही में किए गए एक मॉडलिंग अध्ययन से भी पता चला है कि भारत के पूर्वोत्तर में हवा में 'ब्लैक-कार्बन' की बढ़ती मात्रा बारिश बढ़ा रही है। इससे कुछ जगह कम तीव्रता वाली बारिश घट गई और मूसलाधार बारिश में वृद्धि हुई है। 'ब्लैक-कार्बन' एक तरह का वायु प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन, बायोमास और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से वायुमंडल में आता है। कार्बन डाई-ऑक्साइड के बाद ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों को बढ़ाने में यह भी जिम्मेदार है।

'नेचर क्लाइमेट चेंज' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के साथ-साथ चंद्रमा की कक्षा डगमगाने से भी पृथ्वी पर विनाशकारी बाढ़ें आने की संभावना है। अध्ययन में यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में 2030 के दशक में उच्च ज्वार के कारण बाढ़ के स्तर में बढ़ोतरी होगी। 'भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू' और 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर' के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में बताया है कि हाल के वर्षों में गंगा बेसिन में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ की आवृत्ति बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन और बांध बनाने जैसी मानव गतिविधियां गंगा को प्रभावित कर रही हैं।

भारत सरकार के 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' के अनुसार वर्ष 1901 से 2018 के बीच भारत में सतही हवा के तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है जिसके कारण वायुमंडलीय नमी में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 से 2015 के बीच हिन्द महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में भी करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। इस तरह से वायुमंडल में असामान्य बढ़ोतरी का प्रभाव मानसून के पैटर्न पर हो रहा है जो बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के रूप में देखने को मिल रहा है। बाढ़ आने की अन्य वजहें – नदियों को बाधित करना, प्राकृतिक जल-निकासी रास्तों को बंद करना, तालाबों के निर्माण की जगह पक्की सड़कों का निर्माण करना इत्यादि हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आई थी जिसमें करीब 6000 लोगों कि मौत हो गई थी।

भारी बारिश व बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए इससे बचने के लिए वर्षा जल की निकासी के कारगर उपाय करने चाहिए। नदियों पर होने वाले अतिक्रमण को रोकना व इनमें कूड़ा-कचरा डालकर इन्हें अवरुद्ध होने से बचाने जैसे उपाय बाढ़ को कम कर सकते हैं। पर्यावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर के पिघलने एवं समुद्र के जल स्तर को बढ़ने से रोका जा सकता है जिससे कि मौसम पैटर्न भी सही होगा एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में कमी हो सकेगी।

-सुदर्शन सोलंकी

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

फ्रांस की राजनीति

दक्षिणपंथ की पराजय

फ्रांस में दक्षिणपंथ को हाशिए पर रखने में सफलता मिली है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान द्वारा जल्दी में कराए चुनाव में धुर-दक्षिणपंथियों को उदारवादियों के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस में उदारवाद तथा सामाजिक प्रगतिशीलता का समृद्ध इतिहास है, पर इसके बावजूद हालिया वर्षों में देश में धुर-दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। लेकिन हालिया चुनावों तथा राजनीतिक आंदोलनों से संकेत मिलता है कि यहां प्रगतिशील मूल्यों का पुनर्जीवन हो रहा है। रविवार को दूसरे राउंड के चुनाव में 'टैक्टिकल वोटिंग' द्वारा वामपंथी संगठन ने फ्रांस की संसद में अधिकांश सीटों पर कब्जा करने में सफलता पाई जिससे मैरीन ले पेन की धुर-दक्षिणपंथी पार्टी को झटका लगा। लेकिन वामपंथ की विजय निर्णायक नहीं है। फ्रांस अब राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है क्योंकि किसी पार्टी को राष्ट्रीय असेम्बली में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान का दांव सफल रहा है जिन्होंने अपनी घटती लोकप्रियता के बाद त्वरित चुनाव का आदेश दिया था। उन्होंने मध्यमार्गी दृष्टिकोण की पैरोकारी की जिसमें उदारवादी आर्थिक नीतियों तथा प्रगतिशील सामाजिक सुधारों का मिश्रण है। उनके प्रशासन ने जलवायु परिवर्तन, जेंडर समानता को प्रोत्साहन तथा ज्यादा समावेशी समाज बनाने के प्रयास किए। विपरीत अनुमानों के बावजूद उनकी आश्चर्यजनक विजय से संकेत मिलता है कि दुनिया भर के लोग उदारवादी मूल्यों के पक्ष में झुक रहे हैं और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बजाय इनको प्रमुखता दे रहे हैं।

इस बदलाव के यूरोपीय संघ तथा उसके आगे भी दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से फ्रांस अभी केवल उन धुर-दक्षिणपंथियों को पराजित करने में सफल हुआ है जो चुनावों के बाद तोड़फोड़ पर उतर आई थीं क्योंकि परिणाम व्यापक अनुमानों के बावजूद उनके पक्ष में नहीं आए हैं। आने वाले समय में राष्ट्रपति मैक्रान की चुनौतियां बढ़ सकती हैं क्योंकि 577 सीटों वाले निचले सदन में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस प्रकार अब फ्रांस गठबंधन राजनीति के अस्थिर युग में प्रवेश कर रहा है। नई सरकार कोई स्थाई काम करने में सफल नहीं होगी जिससे दक्षिणपंथियों को इसे बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। राष्ट्रपति मैक्रान को अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना है। राजनीतिक रूप से उनको विभाजित परिदृश्य तथा अनेक पार्टियों के बीच से रास्ता निकाल कर जनता का विश्वास प्राप्त करना तथा बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लगाना होगा। आर्थिक रूप से असमानता, बेरोजगारी तथा भारी सार्वजनिक कर्ज से निपटते हुए सामाजिक खर्च बढ़ाने की मांगें पूरी करना जरूरी होगा। वर्तमान समय में फ्रांस अपनी अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने का प्रयास कर रहा है। अब तक 2024 में वार्षिक वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत है, जबकि 2023 की दूसरी छमाही में इसमें काफी सुस्ती आई थी। यह 2025 में बढ़ कर 1.3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। सामाजिक रूप से आप्रवासियों को समाहित करना, पेंशन सुधार तथा आवासों के संकट पर सावधानी से ध्यान देना होगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान को संवेदनशील सांस्कृतिक मुद्दों से भी निपटना होगा जिनमें सेक्युरवाद, धार्मिक स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय पहचान व बहु-सांस्कृतिकता संबंधी बहसें शामिल हैं। दक्षिणपंथी विचारधाराओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रपति मैक्रान को सामाजिक-आर्थिक असमानतायें घटाने पर विचार करना होगा तथा आर्थिक कठिनाइयों को संबोधित करना होगा क्योंकि ये समस्यायें अतिवाद को बढ़ावा देती हैं।

खैरातों का खामियाजा और कानून

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी निष्पक्षता पर खैरातों का प्रभाव उजागर करने के बावजूद राजनीतिक पार्टियां चुनावी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का प्रयोग कर रही हैं।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)

उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा प्रस्तुत महाराष्ट्र के 2024-25 के बजट में भाजपा नीत 'महायुति' ने 21 से 60 वर्ष की आयु वाली योग्य महिलाओं के लिए 1,500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता, औद्योगिक व गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में नौजवानों के लिए 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड, किसानों के लिए बिजली बिल माफी, आदि घोषणायें की हैं। स्पष्ट रूप से ये 'खैरातें', यानी राज्य द्वारा मुफ्त दिया जाने वाला धन है। इसका उद्देश्य इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में वोट बटोरना है। जुलाई, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरंार एवं अन्य में कहा था कि सभी लोगों को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार की खैरातों का वितरण 'स्वतंत्र एवं मुक्त चुनाव की जड़ों पर बड़ी सीमा तक प्रहार करता है।' इसके साथ ही उसने कहा था कि चुनाव घोषणापत्र में किए ऐसे वादों को लोक प्रतिनिधित्व कानून-आरपीए या किसी अन्य कानून के अंतर्गत 'भ्रष्ट व्यवहार' नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा खैरातों के वितरण को राज्य विधानसभा द्वारा पास किसी कानून के अंतर्गत रोका नहीं जा सकता है। इसी आदेश में उसने भारतीय निर्वाचन आयोग-ईसीआई को निर्देश दिया था कि वह 'ऐसे दिशानिर्देश बनाए जिनसे सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में उम्मीदवारों, बैठकों, प्रदर्शनों, मतदान के दिन, आदि में ऐसे व्यवहारों पर लगाम लागई जा सके।' न्यायालय ने कहा था कि 'इसे आदर्श आचार संहिता में-चुनाव घोषणापत्रों के लिए निर्देश के रूप में अलग से राजनीतिक पार्टियों व उनके उम्मीदवारों के लिए डाला जा सकता है।'

लेकिन निर्वाचन आयोग ने ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं दिया। निर्वाचन आयोग की इस निष्क्रियता के कारण राजनीतिक पार्टियां जो पहले अतीत में खैरातों को चुनाव घोषणापत्र के एक कोने में डालती थीं, अब उनको मुख्य रूप से प्रदर्शित करने लगीं। अब चुनाव जीतने में 'खैरातों' का प्रमुख स्थान है। फरवरी, 2020 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी-आप ने दिल्ली में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त या बहुत सस्ती बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त वाई-फाई, आदि का वादा किया। 2022 में पंजाब में आप ने प्रत्येक परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने, सभी बकाया बिल माफ करने तथा 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह देने, आदि वादे किए। पार्टी को राज्य में प्रबल बहुमत मिला।

2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने गरीब छात्रों को 20 मिलियन स्मार्टफोन, हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर, गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए 1,00,000 रुपये देने, आदि वादे किए। इस बीच यह मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका-पीआईएल के माध्यम से सुनवाई के लिए आया। 25 जनवरी, 2022 को उसने कहा, 'इस बात में कोई संदेह नहीं कि यह एक गंभीर मामला है। खैरातों के लिए बजट नियमित बजट से अधिक हो रहा है।' उसने जोर दिया कि 'इससे समान आधार की अवधारणा बाधित होती है।' 3 अगस्त, 2022 को उसने संकेत दिया कि निर्वाचन आयोग के अलावा यह संसद का काम है कि वह खैरातों पर लगाम लगाने के लिए पहल के रूप में एक कानून बनाए। उसने एक समिति गठित करने का सुझाव भी दिया जो इस 'भेदभावपूर्ण' मुद्दे पर विचार कर अपने सुझाव दे।

लेकिन इन सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, अपनी ओर से निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों को एक प्रश्नतालिका भेज कर कहा कि वे मतदाताओं से किए जाने वाले संभावित वादों के 'विशिष्ट' विवरण बताए तथा यह भी बताए कि इनका क्या वित्तीय प्रभाव होगा और इनके लिए फंड कहां से आएगा। लेकिन इसका कोई फालोअप नहीं हुआ। इस बीच 'खैरातों' की समस्या लगातार बढ़ती रही। मई, 2023 में कर्नाटक चुनाव में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने 'पांच गारंटियों'-गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, सखी कार्यक्रम, युवा निधि तथा अन्न भाग्य की धोषणा की। यह प्रवृत्ति नवंबर-दिसंबर, 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चुनावों में जारी रही। राजस्थान में कांग्रेस ने परिवार की प्रत्येक महिला प्रमुख को गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर साल 10,000 रुपये देने का वादा किया। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने 'लाडली बहना योजना' के अंतर्गत मिलने वाली 1,250 रुपये प्रति माह धनराशि को बढ़ा कर 3000 रुपये महीने करने की घोषणा की। इसके साथ ही इसी योजना के अंतर्गत भजपा ने विवाह होने तक लड़कियों को 200,000 रुपये देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में उसने विवाहित महिला को 'महतारी वंदन योजना' के अंतर्गत हर साल 12000 रुपये देने का वादा किया। तेलंगाना में कांग्रेस ने सबको पीछे छोड़ते हुए विवाह के समय महिलाओं को 100,000 नकद के साथ 10 ग्राम सोना देने का वादा भी कर दिया। आम चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 23 दिसंबर, 2023 को 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना'-पीएमजीके के अंतर्गत 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज योजना जारी रखने की घोषणा की।

कांग्रेस ने अप्रैल, 2024 में जारी अपने घोषणापत्र- 'न्याय पत्र' में दस गारंटियों का वादा किया। इस बीच दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 18 वर्ष से अधिक आयु वाली सभी महिलाओं को 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना'-एमएमएसवाई के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये देने का वादा किया। इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियां 'खैरातों' की और बड़ी खेप देने की तैयारियां कर रही हैं। महाराष्ट्र में भाजपा नीत 'महायुति' ने अच्छे पैकेज की घोषणा कर दी है। हरियाणा और झारखंड में सभी पार्टियां इसी रास्ते पर चलेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जनवरी, 2022 को जोर दिया था कि 'खैरातों का बजट सामान्य बजट से ऊपर जा रहा है।' यह बात जमीनी स्तर पर सही सिद्ध हो रही है। दिल्ली में इनके कारण खजाने पर हर साल 12,500 करोड़ रुपये से अधिक बोझ पड़ रहा है और पंजाब में इसका प्रभाव लगभग 20,000 करोड़ वार्षिक होगा। कर्नाटक में पहले से ही राजकोषीय घाटे का सामना कर रहे राज्य पर 'पांच गारंटियों' का बोझ 60,000 करोड़ रुपये से अधिक है। कांग्रेस के 'न्याय पत्र' की सभी गारंटियों को लागू करने का अर्थ केन्द्र सरकार पर भारी भरकम 46,00,000 करोड़ रुपये का खर्च होता। महाराष्ट्र में प्रत्येक योग्य महिला को 1,500 रुपये महीने देने का खर्च 46,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। ऐसे में सवाल है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने 'खैरातों' को खराब कहा है तो वह इन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देता है। लेकिन इस संबंध में जुलाई, 2013 का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश बाधा का काम कर सकता है जिसमें कहा गया था कि 'इसे भ्रष्ट व्यवहार नहीं कहा जा सकता है।'

लोक प्रतिनिधित्व कानून-आरपीए की धारा 123-1ए के अनुसार रिश्वत को उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले किसी उपहार, प्रस्ताव या वादे के रूप में किया गया है जो उम्मीदवार या उसका एजेंट किसी व्यक्ति को उम्मीदवार को वोट देने के लिए ललचाने के रूप में प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य मतदाता द्वारा उम्मीदवार को लाभ पहुंचाना होता है। विडंबना है कि जब कोई उम्मीदवार अपनी जेब का पैसा मतदाता को रिश्वत देने के लिए प्रयोग करता है तो इसे 'भ्रष्ट व्यवहार' माना जाता है, लेकिन जब अपने चुनाव निशान पर चुनाव लड़ने वाली कोई पार्टी 'सार्वजनिक धन' का प्रयोग करते हुए मतदाताओं को रिश्वत देती है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे भ्रष्ट व्यवहार नहीं मानती है। केन्द्र सरकार के वित्तीय निष्ठा के मानकों के अनुसार कोई अधिकारी अपने आदेश से ऐसे परोक्ष या प्रत्यक्ष खर्च की अनुमति नहीं दे सकता है जिससे किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लाभ हो।

इस प्रकार 'खैरातों' पर करदाताओं के पैसे का बेरहमी से खर्च कोई नीति या परंपरा नहीं है, न किसी अदालत ने इसकी अनुमति दी है। चुनावी लाभ के लिए मतदाताओं को सार्वजनिक धन से रिश्वत देना बेशर्म वित्तीय अनियमितता है। इसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को अपना दृष्टिकोण बदलते हुए संसद को 'खैरातों' के खिलाफ कानून बनाने का स्पष्ट निर्देश देना चाहिए।

शिक्षा और परीक्षा राजनीति का विषय नहीं

> " दुर्भाग्यपूर्ण है कि कतिपय राजनीतिक दल अपनी राजनीति को धार देने के लिए परीक्षा एवं शिक्षा को राजनीति का मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। "

कामेश्वर नाथ सिंह
(लेखक, दक्षिण बिहार केंद्रीय विवि गया के कुलपति हैं)

जलते हुए अंगारों पर राख का जमाव आग की स्वाभाविक प्रकृति है, परन्तु आग जलाये रखने वालों का यह दायित्व? बनता है कि, राख के जमाव को फूंक-फूंक कर उड़ाते रहे, ताकि आग जलती रहे। प्रकृति का उक्त स्वभाव किसी किसी संस्थाफ, संगठन या समूह पर भी लागू होता है। किसी तंत्र, संस्था, संगठन या समूह की सक्रियता एवं सफलताओं में काल के प्रवाह में विकृति आ सकती है।

परन्तु संस्था , तंत्र, संगठन या समूह के संचालकों का यह दायित्वक बनता है कि किसी विकृति या विकार की आहट पाकर, वे अपने अंगों, उपांगों की कार्य पद्धति की समीक्षा करें एवं समय रहते उसमें सुधारात्मक कार्य करें। किसी भी तंत्र, समूह, संस्थाा या संगठन के संचालकों की यह जिम्मेदारी बनती है, वे समसामयिक चुनौतियों को रेखांकित करें एवं खामियों को दूर करके तंत्र को चुस्तर दुरुस्त करें। यह तथ्यं एन.टी.ए. यानि नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी पर भी शत प्रतिशत लागू होता है।

विलंब से ही सही, परन्तुत सरकार ने नीट परीक्षा एवं अन्यक परीक्षाओं में कतिपय समाज विरोधी तत्वों द्वारा संभावित एवं घटित कदाचार को लेकर जो तात्कालिक कार्यवाही किया है, वह सवर्था स्वा गत योग्य कदम है। ज्ञातव्यं है कि 'एक देश एवं एक परीक्षा' के राष्ट्रीय हित वाले प्रयास को कार्यरूप देने के लिए नवम्बर 2017 में एन.टी.ए. का गठन हुआ था।

एन.टी.ए. ने अपनी कार्य प्रणाली में कई सफलताएं एवं उत्कृष्टता भी हासिल किया है। सी.यू.ई.टी. यानि कॉमन यूनिवर्सिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षा परिणाम घोषित होना एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित होना इसका उदाहरण है, जिसमें अभी तक कोई कमी नहीं पाई गई। इस प्रवेश परीक्षा के चलते एक शुल्क पर कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक आधार पर देश के किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है। इससे पूर्व अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग आवेदन देना पड़ता था एवं अलग अलग शुल्क भी देय होता था। इस व्यवस्था के चलते अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है, साथ ही देश के विश्वपविद्यालय के छात्रों की अंतरप्रांतीय विविधता बढ़ी है।

नीट की परीक्षा के पीछे भी यह भावना है कि एक शुल्क पर किसीभी संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सके, साथ ही योग्यता के अनुसार अभ्येर्थी यथोचित संस्थाीन में प्रवेश पा सके। यू.जी.सी.-जे.आर.एफ. एवं नेट परीक्षा के लिए एकीकृत परीक्षा के पीछे भी उद्देश्य यही है कि एक शुल्क पर किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के लिए कोई भी अभ्यवर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता हेतु परीक्षा में भाग ले सके। चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे जे.आर.एफ.-नेट परीक्षा हो या सी.यू.ई.टी. की परीक्षा हो, उन्हें सम्पादित कराने में एन.टी.ए. ने काफी हद तक सफलता भी पाई है।

परन्तु काफी हद तक सदप्रयासों के बावजूद विगत दिनों में नीट की परीक्षामें कतिपय सम्भावित अनियमितताओं के प्रकाश में आने एवं यूजीसी-नेट एवं जे.आरए.एफ. की परीक्षा में अनियमितता के संभावना के कारण स्थगन के चलते आम नागरिक में इन परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता को लेकर एक संदेह की स्थिति उत्पषन्नश हुई है।

नि:सन्देह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं के प्रति विश्वणसनीयता एवं प्रमाणिकता को पुर्नस्थातपित करने के तात्का लिक रूप में जो निर्णय लिया है, वह स्वाकगत योग्या है और मंत्रालय इस सक्रिय निर्णय के लिए साधुवाद का पात्र है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने तात्कामलिक निर्णय लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टखर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटाकर श्री प्रदीप सिंह खरोला को उनके जगह पर नया डी.जी. बना दिया है। मंत्रालय ने नीट प्रकरण के प्रकाश में आने पर उसने पारदर्शी बनाने तथा निष्पाक्ष एवं निर्विवाद परीक्षा सम्पाउदित करने हेतु विभिन्नक उपागमों को जानने के लिए भारतीय अन्तरिक्ष शोध संस्थापन के पूर्व अध्यनक्ष डा.के. राधा कृष्ण न की अध्ययक्षता में एक उच्च स्तसरीय समिति का गठन कर दिया है। देश के उच्च स्तरीय संस्थानों के सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों एवं प्रशासकों को उक्त समिति का सदस्य बनाया है। यह उच्च स्तरीय समिति परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने एवं अनियमितताओं के निदान एवं निराकरण के लिए सुधारात्मयक संस्तुतियां देगी। इस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है एवं दो माह के अंदर अपनी संस्तुतियां मंत्रालय को देगी।

इसी तरह मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सुत्रों से यू.जी.सी.- नेट 2024 की परीक्षा में अनियमितता के संदेह पर तात्कालिक प्रभाव से उक्त- परीक्षा को निरस्त कर दिया एवं सीबीआई को उक्त प्रकरण की जांच सौंप दिया है। सरकार ने नीट 2024 में अनियमितताओं की जांच भी सौंप दिया है। सरकार ने अनियमितता एवं लापरवाही करनेवाले लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी सजा देने का निर्णय लिया है। इससे भी आगे बढ़कर सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम भी लागू कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम के द्वारा परीक्षाओं में शामिल आरोपियों को दस साल तक जेल एवं एक करोड़ रुपये दण्ड का प्रावधान है।

नि:सन्देह परीक्षाओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के लिए सरकार ने सक्रिय एवं सकारात्मदक कदम उठाया है, एवं इसके परिणाम निर्णायक होंगे परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि कतिपय राजनीतिक दल अपनी राजनीति को धार देने के लिए परीक्षा एवं शिक्षा को राजनीति का मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं, और शिक्षा एवं परीक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं। राजनीतिज्ञों का उक्त प्रयास युवा विरोधी, समाज विरोधी एवं राष्ट्रहित विरोधी है। राजनीति के हजार विषय हो सकते हैं, परन्तु शिक्षा एवं परीक्षा राजनीति का विषय कदापि नहीं है।

आप की बात

मोदी की रूस यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय रूस यात्रा भारत के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत-रूस के बीच हर साल होने वाली शिखर वार्ता कोरोना वैश्विक महामारी के कारण चार साल बाद हो रही है। इससे भारत-रूस संबंध और मजबूत होने के साथ ही लगातार बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी भारत को सहायता मिल सकती है। मोदी के लगातार तीसरी बार चुनाव जीत कर प्रधानमंत्री बनने के बाद होने वाली यह यात्रा दुनिया भर में मोदी और उनके नेतृत्व में भारत के बढ़े कद का प्रमाण है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जहां रूस पश्चिमी देशों व अमेरिका से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं भारत ने इनकी अनदेखी कर रूस से संबंध मजबूत करने तथा उससे कच्चा तेल खरीदने की पहल की है। उम्मीद है कि मोदी की यात्रा से भारत-रूस रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। रूस और चीन की बढ़ती निकटता को देखते हुए नरेन्द्र मोदी भारतीय सीमाओं पर चीन की बढ़ती आक्रामकता पर अपना दृष्टिकोण रखेंगे। इसके साथ ही मोदी रूस-यूक्रेन युद्ध के राजनयिक समाधान तथा नाटो व रूस के बीच बढ़ते टकराव को घटाने के तरीके भी सुझा सकते हैं। भारत-रूस संबंध भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की रणनीति की भी परीक्षा हैं। मोदी की यात्रा से ये और मजबूत होंगे।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

नए ईरानी राष्ट्रपति

ईरान में नए सुधारवादी राष्ट्रपति चुन लिए गए। इससे लोगों ने बहुत उम्मीदें पाल रखी हैं, लेकिन उनका हकीकत बनना बहुत कठिन है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे कम सिर्फ40 फीसदी मतदान से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मसूद पेजेशकियन ईरानी राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम के साथ सहज बातचीत करने, देश के कठोर हिजाब कानून को नरम बनाने और 2015 का परमाणु समझौता बहाल कराने का वादा किया है। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से अधिकांश मामलों में देश के सर्वोच्च धर्मगुरु के आधीन होते हैं। ईरानी सेना, पुलिस तथा क्रांतिकारी इस्लामी गार्ड सीधे वर्तमान सर्वोच्च धर्मगुरु अली खामनेई के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऐसे में देखना होगा कि पेजेशकियन को काम करने की कितनी छूट मिलती है। इसके पहले उदारवादी ईरानी राष्ट्रपति के नेतृत्व में ईरान का अमेरिका से नाभिकीय समझौता हुआ था जिसकी गारंटी सुरक्षा परिषद के सभी स्थाई सदस्यों ने दी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी जिद के चलते खारिज कर ईरान को कट्टरपंथ के दलदल में धकेल दिया। ऐसे में पेजेशकियन की सफलता बहुत कुछ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणामों पर भी निर्भर करेगी।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

बेलगाम नाबालिग

मुंबई में सत्तारूढ़ दल के नेता-पुत्र की बीएमडब्लू कार ने एक दोपहिया को टक्कर मारी जिससे पीड़ित 100 मीटर तक घिसटती रही। यह बेलगाम नाबालिग रईसजादों की एक और करतूत है। कुछ ही दिनों पहले पुणे में ऐसी ही घटना में जज महोदय ने आरोपी को निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया था। इस बार और अधिक शक्तिशाली नेता-पुत्र ने यह कारनामा किया है। जाहिर है उसे कठोर सजा देने के बजाय प्रशासन यथासंभव बचाव के प्रयास करेगा। देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में लाखों लोग मारे जाते हैं इस बारे में सख्त कानून होने के बावजूद कई लोग रिहा हो जाते हैं या उनको बहुत कम सजा दी जाती है। कानून स्वाभाविक रूप से नाबालिगों को मामूली सजा देकर उनको सुधरने का मौका देता है। लेकिन अपने नाबालिग बच्चों को खुली छूट देने और गरीब जनता को भेड़-बकरी समझने वाले अमीरों को इतनी कठोर सजा दी जानी चाहिए कि वे भविष्य में अपने नाबालिग बच्चों को ऐसी खतरनाक हरकतों से रोकने को प्राथमिकता दें। बच्चों को बनाने व उन्हें आम लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी माता-पिता की होती है। बच्चों के कम से कम बालिग होने तक वे अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं चुरा सकते हैं।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

हरियाली का संदेश

हर्ष की बात है कि हरियाली और खुशहाली लाने, प्रदूषण कम करने व आबोहवा बेहतर करने के लिए इंदौर में 51 लाख और पूरे मध्यप्रदेश में 5 करोड़ पौधे रोंपे जाएंगे। इंदौर वैसे भी सफाई में 6 बार देश में प्रथम आ चुका है। अगर ऐसा ही जूनून इंदौर की अवाम और स्थानीय प्रशासन में रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाली आच्छादन में भी वो देश में अव्वल नंबर प्राप्त कर लेगा। तेजी से विकसित होते महानगर में 51 लाख पौधे रोंपे जाने हैं जिससे पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही, देश के अन्य नगरों को भी इससे अपने यहाँ हरियाली बढ़ाने व पर्यावरण शुद्ध रखने का सन्देश जाएगा। इससे पूरे देश में वृक्षारोपण आंदोलन तेज किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माँ के नाम एक पौधा लगाने का आह्वान किया है। इसका सभी प्रदेशों के नेताओं तथा आम जनता ने व्यापक स्वागत किया है। वैसे पिछले एक दशक में भारत का वनाच्छादन व यहां हरियाली पहले की तुलना में बढ़ी है, पर जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए इसे और बढ़ाने तथा लगाए गए पेड़-पौधों की सुरक्षा पहले के किसी भी समय की तुलना में आज ज्यादा जरूरी है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

समृद्ध जीवन की राह

आजादी के 77 वर्षों के बाद भी भारत के लोग आज अपने लिए ऐसी उद्यम नीति की तलाश में हैं जो न केवल उन्हें सक्रिय रख सके बल्कि वे देश को विकास पथ पर ले जाने में भी अपने आप को सफल मान सकें। देश में उपलब्धि और सफलता के उत्सव होते रहते हैं। अगर पीछे मुड़कर देखें तो उसमें बहुत-सी कमियां नजर आती हैं। बेकारी को दूर करने का संकल्प अनुकम्पा के उदार वितरण में नजर आता है। महंगाई का नियंत्रण एक ऐसा छद्म लगने लगता है जिसमें आंकड़े तो कहते हैं कि थोक ही नहीं बल्कि खुदरा सूचकांक भी नीचे गिर गया। खाद्य वस्तुओं की बाजार कीमतें आकाश छूती रहती हैं। देश आश्वस्त हो चुका है कि वह दो-तीन साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है।उम्मीद करते हैं कि उस समय हम दुनिया में आर्थिक सामर्थ्य के लिहाज से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये तिलिस्मी बातें जिनकी चकाचौंध में हम अपने आप को दुनिया की किसी भी प्रमुख शक्ति से कम नहीं मानते। लेकिन जितनी उद्यमहीनता और दृष्टिहीनता भारत के आम लोग महसूस करते हैं, उतनी शायद किसी भी अन्य देश में नहीं है। यह निष्कर्ष लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के एक अध्ययन में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन बताता है कि हमारे देश में 50 फीसदी लोग शारीरिक सक्रियता से भागते हैं। दुनिया में लोगों की औसत उम्र बढ़ रही है। भारत में कुपोषण और पर्याप्त रोजी-रोटी के अभाव में हम स्वास्थ्य के न्यूनतम मापदंडों पर भी खरे नहीं उतर रहे हैं। यह बात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही है। लोगों के बीच एक ऐसी संस्कृति पनप रही है जो यह कहती है कि मुफ्त में जो हाथ लग सके, वही बेहतर है। जब बैंक खातों में बिना श्रम किए पैसे आ जाने के नेताई वादे हों तो भला लोग परिश्रम क्यों करें? किसी उद्यम नीति की तलाश क्यों करें? आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2000 में 22 फीसदी वयस्क शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं थे। 2010 में यह आंकड़ा बढ़कर 34 फीसदी हो गया और अब 50 फीसदी है। यह औसत महिलाओं में 57 फीसदी और पुरुषों में 42 फीसदी लोग सक्रिय नहीं हैं। सवाल उठता है कि महिलाएं तो घर को संभालती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, उनको निष्क्रिय कहेंगे? नौजवान जवान होते ही बाप-दादा के साथ खेतों में या दुकानों में काम करने लगते हैं, क्या इनको निष्क्रिय कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन यह कहता है कि अगर कोई वयस्क प्रति सप्ताह 150 मिनट की मध्यम या 75 मिनट की तीव्रता गति वाली शारीरिक गतिविधि नहीं करता, तो वह निष्क्रिय है। ऐसी इस युवा देश की आधी जनसंख्या है। आंकड़े कहते हैं कि भारतीय महिलाओं की निष्क्रियता बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से भी निचले स्तर पर है। इस निष्क्रियता के चलते उनमें कई गंभीर बीमारियों का विस्तार होता जाता है। सरकार ने चाहे आयुष्मान योजना का लाभ पूरी आबादी तक कर दिया है लेकिन बीमारों का अनुभव है कि निजी क्षेत्र के अस्पताल उन्हें दाखिल नहीं करते या उनकी परिचर्या नहीं करते क्योंकि वे कहते हैं कि सरकार से उन्हें उचित समय पर भुगतान नहीं मिलता। इस पर विचार करने की जरूरत है। सरकार के साथ - साथ समाज भी इसपर चिंतन करे।

भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप हो इस वर्ष का बजट

प्रह्लाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्णकालिक बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारतीय संसद में 23 जुलाई 2024 को पेश किया जा रहा है। वर्तमान में भारत सहित विश्व के लगभग समस्त देशों में पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण करते हुए अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। परंतु, हाल ही के वर्षों में पूंजीवादी नीतियों के अनुसरण के कारण, विशेष रूप से विकसित देशों को आर्थिक क्षेत्र में बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह देश इन समस्याओं का हल निकाल ही नहीं पा रहे हैं। नियंत्रण से बाहर होती मुद्रास्फीति की दर, लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ, प्रौढ़ नागरिकों की बढ़ती जनसंख्या के चलते सरकार के खजाने पर बढ़ता आर्थिक बोझ, बजट में वित्तीय घाटे की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आदि कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिनका हल विकसित देश बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इन देशों का सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न हो गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चूंकि व्यक्तिवाद हावी रहता है अतः स्थानीय समाज में विभिन्न परिवारों के बीच आपसी रिश्ते केवल आर्थिक कारणों के चलते ही टिक पाते हैं। अन्यथा शायद विभिन्न परिवार एक दूसरे से रिश्तों को आगे बढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखते हैं।

कई विकसित देशों में तो पति-पत्नि के बीच तलाक की दर 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। अमेरिका में तो यहां तक कहा जाता है कि 60 प्रतिशत बच्चों को अपने पिता के बारे में जानकारी ही नहीं होती है एवं केवल माता को ही अपने बच्चे का लालन-पालन करना होता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है एवं यह बच्चे अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समाज में हिंसा की दर बढ़ रही है तथा वहां की जेलों में कैदियों की संख्या में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। इन देशों के नागरिक अब भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं एवं उन्हें उम्मीद है कि उनकी आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का हल भारतीय सनातन संस्कृति में से ही निकलेगा। अतः इन देशों के नागरिक अब भारतीय सनातन संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं।

भारत में वर्ष 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ हद तक वामपंथी नीतियों का अनुसरण करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया था। परंतु, वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों ने बहुत फलदायी परिणाम नहीं दिए अतः बहुत लम्बे समय तक यह नीतियां आगे नहीं बढ़ सकीं। हालांकि बाद के खंड काल में तो वैश्विक स्तर पर वामपंथी विचारधारा ही धराशायी हो गई एवं सोवियत रूस कई टुकड़ों में बंट गया। आज तो रूस एवं चीन सहित कई अन्य देश जो पूर्व में वामपंथी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना रहे थे, ने भी पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित आर्थिक नीतियों को अपना लिया है।

भारत का इतिहास वैभवशाली रहा है एवं पूरे विश्व के आर्थिक पटल पर भारत का डंका बजा करता था। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत के आसपास बनी रही है। उस समय पर भारतीय आर्थिक दर्शन पर आधारित आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया जाता था। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ऋण का बोझ, वित्तीय घाटा, बुजुर्गों को समाज पर बोझ समझना, बच्चों का हिंसक होना, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होना आदि प्रकार की समस्याएं नहीं पाई जाती थीं। समाज में समस्त नागरिक आपस में भाईचारे का निर्वहन करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे।

प्राचीन काल में भारत के बाजारों में विभिन्न वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जिसके चलते मुद्रा स्फीति जैसी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे जहां खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता रहती थी, कभी किसी उत्पाद की कमी नहीं रहती थी जिससे वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ते थे। बल्कि, कई बार तो वस्तुओं की बाजार कीमत कम होती दिखाई देती थी क्योंकि इन वस्तुओं की बाजार में आपूर्ति, मांग की तुलना में अधिक रहती थी। वित्त मंत्री को भी देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजारों में उत्पादों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए न कि ब्याज दरों को बढ़ाकर बाजार में वस्तुओं की मांग को कम किए जाने का प्रयास किया जाए। विकसित देशों द्वारा अपनाई गई आधुनिक अर्थशास्त्र की यह नीति पूर्णत असफल होती दिखाई दे रही है और इतने लम्बे समय तक ब्याज दरों को ऊपरी स्तर पर रखने के बावजूद मुद्रास्फीति की दर वांछनीय स्तर पर नहीं आ पा रही है। भारत को इस संदर्भ में पूरे विश्व को राह दिखानी चाहिए एवं आधुनिक अर्थशास्त्र के मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत को बाजार में वस्तुओं की मांग कम करने के स्थान पर वस्तुओं की आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए अर्थात आपूर्ति पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे मुद्रास्फीति तो कम होगी ही परंतु साथ ही अर्थव्यवस्था में विकास की दर भी और तेज होगी क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ते रहने से विनिर्माण इकाइयों में गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर निर्मित होंगे। परंतु यदि वस्तुओं की मांग में कमी करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास होंगे तो उत्पादों की मांग में कमी होने के चलते उत्पादों का निर्माण कम होने लगेगा, विनिर्माण इकाइयों में गतिविधियां कम होंगी एवं देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। मांग में कमी करने के प्रयास सम्बंधी सोच ही अमानवीय है।

इसी प्रकार, प्राचीन भारत में ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के साथ ही कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कई ग्रामों को मिलाकर हाट लगाए जाते थे, इन कृषि उत्पादों के साथ ही इन कुटीर एवं लघु उद्योगों में निर्मित उत्पाद भी बेचे जाते थे। अतः ग्रामीण इलाकों से शहरों की पलायन नहीं होता था तथा नागरिकों को रोजगार के अवसर ग्रामीण इलाकों में ही उपलब्ध हो जाते थे। आज की परिस्थितियों के बीच कृषि क्षेत्र तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार के अधिक से अधिक अवसर निर्मित हो सकें।

जनता पर करों के बोझ को कम करने के सम्बंध में भी विचार होना चाहिए। भारत के प्राचीन शास्त्रों में कर सम्बंधी नीति का वर्णन मिलता है जिसमें यह बताया गया है कि राज्य को जनता पर करों का बोझ उतना ही डालना चाहिए जितना एक मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है। अर्थात, जनता को करों का बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाने बजट में भी आवश्यक वस्तुओं पर लागू करों की दरों को कम करने के प्रयास होने चाहिए। साथ ही, मध्यमवर्गीय परिवारों को भी करों में छूट देकर कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनकी उत्पादों को खरीदने के क्षमता बढ़े। इससे अंततः अर्थव्यवस्था को ही लाभ होता है। मध्यमवर्गीय परिवारों की खरीद की क्षमता बढ़ने से विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था का चक्र और अधिक तेजी से घूमने लगता है। यदि किसी देश में अधिक से अधिक आर्थिक व्यवहार औपचारिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था का चक्र भी तेज गति से घूम रहा है तो ऐसी स्थिति में करों के संग्रहण में भी वृद्धि दर्ज होती है। अतः कई बार करों की दरों में कमी किए जाने के बावजूद कर संग्रहण अधिक राशि का होने लगता है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री जी के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बजट के रूप में एक अच्छा मौका है कि भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुरूप आर्थिक नीतियों को लागू कर पूरे विश्व को पूर्व में अति सफल रहे भारतीय आर्थिक दर्शन के सम्बंध में संदेश दिया जा सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

सांसद ही कर रहे संसदीय गरिमा पर आघात

उमेश चतुर्वेदी

लाइव प्रसारण के चलते अब जनता तक वे सारी बातें भी पहुंच रही हैं, जो तथ्यहीन हैं, और जिन्हें संसदीय कार्यवाही से निकाल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण को रखा जा सकता है। उन्होंने अग्निवीर, फसलों पर एमएसपी आदि पर तथ्यहीन बातें कीं। चूंकि लाइव प्रसारण के कारण उन्हें संसद के लाइव प्रसारण देखने वाले सभी लोगों ने देखा और सुना। इसके बाद भले ही उनकी बातों को कार्यवाही से हटा दिया गया हो, लेकिन जनता के बीच संदेश तो पहुंच ही गया। इसी तरह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने कई बार टोका, लेकिन नहीं मानने पर उनके भाषण के हिस्सों को एक्सपंज किया जाता रहा। यह कोई पहला मौका नहीं था, जब लाइव प्रसारण के दौरान सांसदों के ऐसे कई बयान देखे-सुने गए। अब ऐसे वाकये अक्सर होने लगे हैं। दिलचस्प है कि जब सांसदों को रोका जाता है, तो वे इसे अपने प्रति दुर्भावना बताते हैं। आरोप लगाते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया।

हाल की कुछ घटनाओं के चलते संसदीय कार्यवाही के लाइव टीवी प्रसारण पर सवाल उठने लगे हैं। संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बचाए-बनाए रखने वाले तबके में इसकी मांग उठने लगी है। इस वर्ग का मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो संसद की गरिमा घटेगी। अपने आचरण के चलते सांसदों का एक वर्ग लोगों की नजर में अपनी प्रतिष्ठा तो खो ही चुका है। लाइव प्रसारण के जरिये उनके मुखारविंद से जो शब्द संसद में झड़ रहे हैं, उससे स्थितियां उलझी हैं।

इसे बिडबंना कहें या उलटबांसी कि जिस ब्रिटेन के हम करीब दो सौ साल तक गुलाम रहे, हमारा संसदीय लोकतंत्र भी उसी ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह है। वैसे शासन प्रणाली जो भी हो, अगर उसे अपना लिया, तो उसकी उच्च परंपराएं, उसकी गरिमा और मयार्दा को भी स्वीकार करना होगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल कहा करते थे कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। यानी महान परंपराओं और गरिमा को स्वीकार किए बिना कोई भी शासन सफल नहीं हो सकता।

अगर लोक का भरोसा शासन प्रणाली से खत्म हो गया, तो उस प्रणाली पर सवालिया निशानों की झड़ी लग जाती है।

ब्रिटिश संसद में एक परंपरा है कि संसदीय कार्यवाही से हटाए गए शब्दों को न तो कभी उद्धृत किया जा सकता है और न ही उसे रिपोर्ट किया जा सकता है। जाहिर है कि हटाए गए शब्द अमर्यादित, तथ्यहीन और गरिमा के विरुद्ध होते हैं। जब तक टेलीविजन नहीं था, पत्रकारों को संसदीय इम्बार्गो और कार्यवाही की रिपोर्टिंग के मायने गहराई से समझाए जाते थे। संसद या किसी संसदीय समिति के बयान की जानकारी होने के बावजूद उसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, जब तक कि संसद या संसदीय समिति द्वारा तय की गई समय सीमा खत्म न होती थी। मियाद पूरी होने के बाद ही वह अखबार में छपता था। अखबारों के रिपोर्टर संसद की रिपोर्टिंग करते हुए सांसदों की उन बातों को भी सुनते ही थे, जिन्हें कार्यवाही से हटा दिया जाता था। लेकिन उनका उल्लेख वे अपनी रिपोर्टों में नहीं करते थे। इसका उद्देश्य था कि लोगों तक वही बातें पहुंचे, जो मर्यादित एवं तथ्यात्मक रूप से ठीक हों।

लाइव प्रसारण के चलते अब जनता तक वे सारी बातें भी पहुंच रही हैं, जो तथ्यहीन हैं, और जिन्हें संसदीय कार्यवाही से निकाल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण को रखा जा सकता है। उन्होंने अग्निवीर, फसलों पर एमएसपी आदि पर तथ्यहीन बातें कीं। चूंकि लाइव प्रसारण के कारण उन्हें संसद के लाइव प्रसारण देखने वाले सभी लोगों ने देखा और सुना। इसके बाद भले ही उनकी बातों को कार्यवाही से हटा दिया गया हो, लेकिन जनता के बीच संदेश तो पहुंच ही गया।

इसी तरह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पदेन सभापति जगदीप धनखड़ ने कई बार टोका, लेकिन नहीं मानने पर उनके भाषण के हिस्सों को एक्सपंज किया जाता रहा। यह कोई पहला मौका नहीं था, जब लाइव प्रसारण के दौरान सांसदों के ऐसे कई बयान देखे-सुने गए। अब ऐसे वाकये अक्सर होने लगे हैं। दिलचस्प है कि जब सांसदों को रोका जाता है, तो वे इसे अपने प्रति दुर्भावना बताते हैं। आरोप लगाते हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण से हटाए गए शब्दों को रखने की मांग की है। मौजूदा दौर में हर सांसद चाहता है कि वह संसद में जो भी बोले, उसका प्रसारण हो, ताकि उसके वोटरों के बीच यह संदेश जाए कि उसका सांसद दमदार है और जनता के मुद्दों को संसद में उठाता है।

संसद की कार्यवाही का पहला प्रसारण 20 दिसंबर, 1989 को दूरदर्शन पर शुरू हुआ, तो शुरू में चुनिंदा संसदीय कार्यवाही को ही टीवी पर दिखाया गया। लेकिन 18 अप्रैल 1994 से लोकसभा की पूरी कार्यवाही को फिल्माया जाने लगा। उसी साल अगस्त में, कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया गया। तीन नवंबर, 2003 को डीडी न्यूज लॉन्च होने पर दोनों सदनों के प्रश्नकाल का प्रसारण डीडी चैनलों पर एक साथ होने लगा।

संसदीय कार्यवाही के लाइव प्रसारण के इतिहास में दो घटनाएं बहुत याद की जाती हैं। जब अक्टूबर, 1990 में भाजपा द्वारा समर्थन वापसी के बाद वीपी सिंह सरकार अल्पमत में आ गई, तो उन्होंने संसद में विश्वास मत प्रस्तुत किया था। उस पर दो दिनों तक चली बहस का दूरदर्शन ने लाइव प्रसारण किया था। 'अंतरात्मा की आवाज' पर वीपी सिंह का सांसदों से समर्थन मांगना बेहद चर्चित रहा। दूसरी घटना तेरह दिन की वाजपेयी सरकार के विश्वास मत पर हुई चर्चा से संबंधित है। विश्वास मत पर चर्चा का जवाब देते हुए वाजपेयी ने जो भाषण दिया, उसे उनके कालजयी भाषणों में से एक माना जाता है। इससे उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी। इसके बाद से ही संसदीय बहसों में शामिल होते ही सांसद लाइव प्रसारण में दिखने की इच्छा पालने लगे।

साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की पहली सरकार आई। तब लोकसभा अध्यक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ चटर्जी बने। उन्होंने संसदीय कार्यवाही के प्रसारण के लिए दो चैनलों का विचार दिया। दिसंबर, 2004 में दोनों सदनों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए एक अलग समर्पित सैटेलाइट चैनल की स्थापना की गई। 2006 में लोकसभा टीवी ने निचले सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू किया। लेकिन राज्यसभा टीवी की शुरूआत उस दौर के नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच मतभेदों के चलते नहीं हो पाई। जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने, तो 2011 में राज्यसभा टीवी के लिए अलग से चैनल की शुरूआत हुई। एक मार्च, 2021 को लोकसभा और राज्यसभा-दोनों चैनलों को एक करके संसद टीवी बना दिया गया। जब से संसद टीवी बना है, तब से कुछ ज्यादा ही विवाद उठ रहे हैं।

लोकसभा टीवी अपने प्रसारण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखता है कि वह जीवंत लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को निष्पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तथ्यों से रहित वक्तव्यों के प्रसारण को निष्पक्षता के दायरे में रखा जा सकता है! संसदीय बहसों के संदर्भ में मीडिया निरपेक्षता संभव नहीं है। ऐसे में क्यों न संसदीय बहसों की पहले रिकॉर्डिंग हो और फिर संसदीय मयार्दाओं के लिहाज से उन्हें संपादित करके प्रसारित किया जाए ?

यूएमएल का नेपाली कांग्रेस के साथ नया गठबंधन

नेपाल में पिछले तीन-चार दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए उनके नतीजे सोमवार की आधी रात को सामने आए। इस नाटकीय घटनाक्रम में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में शामिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) ने नेपाली कांग्रेस के साथ नया गठबंधन बनाने को लेकर समझौता कर लिया। समझौते के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउबा बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। इन दोनों नेताओं ने सरकार बनाने के संबंध में अर्धरात्रि को जो समझौता किया इससे जाहिर होता है कि वे दिन के उजाले में नेपाल की समकालीन राजनीति के साथ फरेब वाला समझौता करने से भयभीत थे। देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों और उनके दो कद्दावर नेताओं ने नई गठबंधन सरकार बनाने को लेकर जिस तरह का निर्णय लिया वह नेपाल की लोकतांत्रिक राजनीति को ढलान की ओर ले जाता है। संविधान और लोकतंत्र के नाम पर किए गए इस राजनीतिक समझौते से देश का राजनीतिक भविष्य एक बार फिर अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। समझौते के मुताबिक, पहले ओली डेढ़ साल के लिए प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे और उसके बाद देउबा के लिए अपना पद छोड़ेंगे। लेकिन नेपाल के राजनीतिक उतार-चढ़ाव को देखकर कहना मुश्किल है कि ओली समझौते के मुताबिक अपने वादे को निभाएंगे। ओली और देउबा के बीच में सत्ता के लिए जो समझौता हुआ है, वह कितने दिन तक चल पाएगा अभी से कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों नेता जिन दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे वैचारिक रूप से धुर विरोधी हैं। इसलिए इसका जाना चाहिए कि कपड़ों की तरह गठबंधन का सहयोगी बदलने के पीछे कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि सत्ता की चाह काम करती है। हालांकि सत्ता के इस उलटफेर के भी कुछ सकारात्मक संदेश हैं। नेपाली संसद की कुल 275 सीटों में से 88 नेपाली कांग्रेस और 79 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के पास हैं। मात्र 32 सीटें वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी सेंटर) के नेता प्रचंड जोड़-तोड़ करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ओली और देउबा के समझौते से इस तरह की प्रवृत्ति को धक्का पहुंचा है। इसे नेपाली राजनीति के लिए शुभ कहा जाना चाहिए।

सोशल मीडिया पर बाबाओं का विवाद

जब से सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से व्यापक हुआ है, तब से समाज का हर वर्ग यहां तक कि गृहणियां भी 24 घंटे सोशल मीडिया पर हर समय छाए रहते हैं। इसके दुष्परिणामों पर काफी ज्ञान उपलब्ध है। सलाह दी जाती है कि यदि आपको अपने परिवार या मित्रों से संबंध बनाए रखना है, अपना बौद्धिक विकास करना है और स्वस्थ और शांत जीवन जीना है तो आप सोशल मीडिया से दूर रहें या इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करें। पर विडंबना देखिए कि समाज को संयत और सुखी जीवन जीने का और माया मोह से दूर रहने का दिन-रात उपदेश देने वाले संत और भागवताचार्य आजकल स्वयं ही सोशल मीडिया के जंजाल में कूद पड़े हैं। विशेषकर ब्रज में ये प्रवृत्ति तेजी से फैलती जा रही है। पिछले ही दिनों वृंदावन के विरक्त संत प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच सोशल मीडिया पर श्री राधा तत्व को लेकर भयंकर विवाद चला। ऐसे ही पिछले दिनों वृंदावन में नवस्थापित भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के वक्तव्य भी विवादों में रहे। इसी बीच बरसाना के विरक्त संत श्री रमेश बाबा द्वारा लीला के मंचन में राधा स्वरूप धारण कर बालाकृष्ण से पैर दबवाने पर विवाद हुआ। ये सब ब्रज की विभूतियां हैं। हर एक के चाहने वाले भक्त लाखों-करोड़ों की संख्या में हैं। जैसे ही कोई विवाद पैदा होता है, इनका चेला समुदाय भी सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय हो जाता है। ठीक वैसे ही राजनैतिक दलों की ट्रोल आर्मी, जो बात का बतंगड़ बनाने में मशहूर है, सक्रिय हो जाती है। यह सब सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने का एक तरीका बन गया है। अब प्रेमानंद जी वाले विवाद को ही लीजिए, कितने ही कम मशहूर भागवताचार्य भी इस विवाद में कूद पड़े जिनके फॉलोवर्स चार-पांच सौ ही थे पर जैसे ही वे इस विवाद में कूदे तो उनकी संख्या 20 हजार पार कर गई यानी बयानबाजी भी फायदे का सौदा है। परंपरा से शास्त्र ज्ञान का आदान-प्रदान गुरुओं द्वारा निर्जन स्थलों पर किया जाता था जहां जिज्ञासु अपने प्रश्न लेकर जाता था और गुरु की सेवा कर ज्ञान प्राप्त करता था। यही पद्धति भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताई थी। भगवद् गीता के चौथे अध्याय का चौंतीसवां श्लोक इसी बात को स्पष्ट करता है। 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।।4.34।। परंतु सोशल मीडिया ने आकर ऐसी सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब धर्मगुरु चाहें न चाहें पर उनके शिष्य, उनके प्रवचनों का सोशल मीडिया पर प्रसारण करने को बेताब रहते हैं और फिर अलग-अलग गुरु ओं के शिष्य समूहों में आपसी प्रतिद्वंद्विता चलती है कि किस गुरु के कितने चेले या श्रोता हैं। जिस संत के फॉलोवर्स की संख्या लाखों में होती है।

असुविधा की सड़कों का टोल-टैक्स ज्यादती है

आरती कुमारी

बेहतर सेवाओं के नाम पर सरकारें कई तरह के शुल्क वसूलती है, इसमें कोई आपत्ति एवं अतिश्योक्ति नहीं है। लेकिन सेवाएं बेहतर न हो फिर भी उनके नाम पर शुल्क या कर वसूलना आपत्तिजनक एवं गैरकानूनी है। यह एक तरह से आम जनता का शोषण है, धोखाधड़ी है। राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर बेहतर एवं सुविधाजनक सड़कों के नाम पर एजेंसियां द्वारा टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन विडम्बना एवं त्रासदी यह है कि टूटी-फूटी सड़कों के नाम पर भी टोल वसूला जाता है, जो अन्यायपूर्ण एवं आपत्तिजनक है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयान में जनता के इस बड़े होते दुःख, धोखाधड़ी एवं शोषण पर न केवल दुःख जताया बल्कि ऐसी जबरन की जा रही वसूली को रोकने के लिये अधिकारियों को चेताया है। अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले नितिन गडकरी ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि यदि सड़कें अच्छी हालत में न हों और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो राजमार्ग पर एजेंसियों द्वारा टोल टैक्स वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स वसूलने से पहले हमें अच्छी सेवाएं देनी चाहिए। लेकिन हम अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये टोल टैक्स वसूलने की जल्दी में रहते हैं। रोड टैक्स का उपयोग राज्य के भीतर सड़कों के रखरखाव और विकास के लिए किया जाना चाहिए न कि सरकार की आमद को बढ़ाने के लिये। ऐसे अनेक उदाहरण है कि बिना सुविधा एवं आवश्यकता के भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है। राज्य सरकारें भी स्वतंत्र रूप से टोल वसूलती है। दूसरी ओर, टोल टैक्स एक उपयोगकर्ता शुल्क है जिसे वाहन मालिकों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या निजी ठेकेदारों को कुछ टोल सड़कों, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, पुल और सुरंगों का उपयोग करने के लिए देना पड़ता है। जो अन्य सड़कों की तुलना में इन सड़कों को उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की माना जाता है। निश्चित रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क-क्रांति की है बल्कि व्यवस्था की खामियों को सुधारने के भी सराहनीय प्रयास किये हैं। किसी देश को विवेकपूर्ण, बेहतर सुविधाओं एवं विकास के नये मानकों के साथ चलाने के लिए सरकार को पात्र नागरिकों से बेहतर सुविधाओं के लिये कर एकत्र में कोई ऐतराज नहीं है; लेकिन सड़कें हो या अन्य सुविधाएं, अच्छी नहीं होने पर भी टोल टैक्स या अन्य टैक्स वसूलने पर उपभोक्ता स्वयं को ठगा हुआ एवं शोषित महसूस करता है, जिसके कारण टोल टैक्स या अन्य टैक्स वसूलने वाली एजेन्सियों के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही है। टोल टैक्स प्रणाली सरकार या निजी ठेकेदारों के लिए राजस्व सृजन का स्रोत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के लिए बेहतर और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध कराने का साधन होनी चाहिए। निश्चित तौर पर गुणवत्ता की सेवा दिए बिना कोई टैक्स वसूलना उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी एवं अन्याय है। यह बात हर सरकारी व निजी महकमे पर भी लागू होती है। लेकिन यथार्थ में ऐसा होता नहीं है और बेहतर सेवा के बिना टैक्स वसूलने की स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही है। इन स्थितियों को लेकर आम जनता एवं उपभोक्ताओं में विरोध एवं विद्रोह पनप रहा है, इसलिये सरकार एवं ऐसी एजेन्सियों के खिलाफ लोग लोक अदालतों से लेकर विभिन्न अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहते हैं। किसी भी विभाग को अपनी खामियों पर पर्दा डालने के बजाय सेवा में सुधार की पहल करनी चाहिए। अब चाहे मामला राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यरत एजेंसियों का हो या फिर बिजली-पानी जैसे मूलभूत जरूरतों वाले विभागों का, अधिकारियों को उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशील एवं जिम्मेदार होना चाहिए। नियंत्रण से बाहर होती हमारी व्यवस्था हमारे लोक-जीवन को न केवल अस्त-व्यस्त कर रही है, बल्कि आहत, पीड़ित एवं परेशान भी कर रही है। ऐसी अनेक सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा जनता के लिये उपलब्ध कराई जाती है, इसके लिये सरकार टैक्स वसूलती है। लेकिन बिना सुविधा के भी टैक्स वसूलने की स्थितियां सरकार पर बदनुमा दाग है और ऐसे दाग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल बात राजमार्गों पर वसूले जा रहे गैर वाजिब टोल टैक्स के बढ़ने की चिन्ता का है, जो एक त्रासदी है। इसी त्रासदी को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री ने स्वीकारा और कहा कि सड़कें अच्छी नहीं होने पर तमाम शिकायतें हमें मिलती हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। सही मायनों में गुणवत्ता की सड़क प्रदान करने पर ही हमसे टोल वसूलने का अधिकार मिलता है। जाहिर सी बात है कि गड्ढों व कीचड़ वाली सड़कों पर टैक्स वसूलने पर पब्लिक की नाराजगी स्वाभाविक रूप से सामने आएगी। निस्संदेह, परिवहन मंत्री की स्वीकारोक्ति एक अच्छा कदम एवं स्वागतयोग्य कदम है और हर विभाग के मंत्री को अपने अधीनस्थ विभागों की ऐसी कारगुजारियों एवं ज्यादतियों पर नजर रखनी चाहिए। जरूरत इस बात की भी है कि ऐसी शिकायत दर्ज करने और शिकायतों के तुरंत निवारण हेतु एक स्वतंत्र तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। कई स्थानों पर सड़कों की गुणवत्ता में कमी, सड़कों के निर्माण में तकनीकी खामियों का उजागर होना, गैरवाजिब टोल टैक्स वसूला जाना, उपभोक्ताओं को परेशान करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स चुकाने के लिये घंटों लाइन में लगना भी एक बड़ी समस्या है, भले ही इस समस्या से मुक्ति के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं, फास्टैग व्यवस्था के लागू करने से लाइनें छोटी हुई है। आज 98 प्रतिशत वाहनों में स्मार्ट टैग के माध्यम से निर्बाध यात्रा की जा रही है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे आदि के बनने से यात्रियों का आवागमन सुविधाजनक हुआ है, पेट्रोल-डीजल में बचत हुई है एवं यातायात सुगम बना है। मोदी सरकार ने सड़कों को सुविधाजनक बनाया है। आने वाले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली को अंजाम देने की तैयारी में है। जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल गेटों की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर टोल प्लाजा पर गाड़ी धीमी करने व रोकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसे देश में चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यह व्यवस्था सड़क-क्रांति को एक नई दिशा देगा। दरअसल, यह नया सिस्टम न केवल सही ट्रैकिंग कर पाएगा बल्कि यह राजमार्ग पर उपयोग की गई दूरी के आधार पर सटीक टोल गणना भी करेगा। बहुत संभव है आने वाले वर्षों में कार निर्माता कंपनियां अपने वाहनों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाएं। प्रारंभ में इस सिस्टम को प्रमुख हाईवे व एक्सप्रेस-वे पर लागू किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार के लिये यह जरूरी है कि वह सड़कों की गुणवत्ता को बनाये रखे एवं गुणवत्ता वाली सुविधा की सड़कों पर ही टोल वसूले। राजमार्गों पर यात्रा करने के दौरान आपके बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से पैसा कट जाता है। इसमें भी गलत तरीके से पैसे कटने की शिकायतें बढ़ती जा रही है। किसी व्यक्ति के फास्टैग से बिना टोल से गुजरे टोल टैक्स काट लिया जाता है या ज्यादा टोल वसूल लिया जाता है, जो उपभोक्ताओं के लिये परेशानी का सबब है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़क निर्माण और रखरखाव के अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रहा है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि एचएचआई ने टोल अनुबंधों को आकार देने और निगरानी के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है और टोल सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। रिपोर्ट में टोल संग्रह प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी और दोषपूर्ण टोल प्लाजा, ओवरचार्जिंग और लंबी कतारों के कारण सड़क उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी और असुविधा पर भी प्रकाश डाला गया है। इन सभी हालातों को देखते हुए भारत में राजमार्गों एवं सुविधा की सड़कों के नाम पर हो रही टोल टैक्स वसूली को औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत बनाने की अपेक्षा है। सुविधा के नाम असुविधाओं, असुरक्षा एवं धोखाधड़ी की बढ़ती स्थितियों को गंभीरता से लेना होगा।

23 जुलाई आगामी बजट – फिर जागी सीनियर सिटीजन की उम्मीदें

अशोक भाटिया, मुंबई

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से सीनियर सिटीजंस को काफी उम्मीद हैं। वित्तमंत्री 23 जुलाई को लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेंगी। इस साल 1 फरवरी को पेश बजट में वित्तमंत्री ने सीनियर सिटीजंस के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। इसलिए सीनियर सिटीजंस को आने वाले बजट से ज्यादा उम्मीदें हैं,ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बटुए में और ज्यादा पैसे आएंगे या नहीं। इनकम टैक्स क़ानून के अनुसार, सीनियर सिटिज़न्स को दो समूहों में बांटा गया है – सीनियर सिटिज़न्स और सुपर सीनियर सिटिज़न्स। इनमें से प्रत्येक समूह के लिए टैक्स सम्बन्धी क़ानून भी अलग-अलग हैं। सीनियर सिटिज़न्स यानी 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए 3 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ़ है। सुपर सीनियर सिटिज़न्स यानी 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ़ है। रिटायर्ड लोग चाहते हैं कि यह अंतर ख़त्म हो जाए क्योंकि कई लोगों के पास, पेंशन और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर इनकम का कोई अन्य साधन नहीं है। उनका मानना है कि सबके लिए 5 लाख रुपये की छूट सीमा तय की जानी चाहिए ताकि सभी सीनियर सिटिज़न्स पर टैक्स का बोझ कम हो सके।मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार, सीनियर सिटिज़न्स को अलग-अलग रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजंस को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। अभी 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन की इजाजत है। बुजुर्गों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड की महामारी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम काफी बढ़ गया है। इसलिए सरकार को 50,000 रुपये के डिडक्शन को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये कर देना चाहिए। इससे उन पर टैक्स का बोझ घटेगा । सीनियर सिटिज़न्स पर महंगाई का ज्यादा असर पड़ता है। उनके इनकम के साधन सीमित और अक्सर निश्चित होने के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण सीधे तौर पर उनकी खरीदने की ताकत कम हो सकती है। उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए अपने इनकम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं भी हो सकता है। इसलिए, सरकार उन्हें अधिक से अधिक, महंगाई को मात देने वाले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने के बारे में सोच सकती है। वर्तमान में, सीनियर सिटिज़न्स सेविंग्स स्कीम में 30 लाख रुपये तक इन्वेस्ट किया जा सकता है जिस पर 8.2 % प्रति वर्ष की दर से सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाने, ज्यादा रेट ऑफ़ रिटर्न देने और एक कम लॉक-इन फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए । इससे सीनियर सिटिज़न्स की खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी और उन्हें बेहतर लिक्विडिटी मिल पाएगी। कई सीनियर सिटीजन की मांग है कि उन्हें चालू ब्याज से 2 प्रतिशन अतिरिक्त ब्याज मिलना चाहिए । वैसे इस समय एफ़डी ब्याज दरों की बात करें तो डीसीबी बैंक में सीनियर सिटीजन को एफडी पर 8.6% का ब्याज मिल रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक में सीनियर सिटीजन को एफ़डी पर 7.9% का ब्याज दे रहा है। ज्यादातर बैंक सीनियर सिटीजन को अधिकतम 7.75 फीसदी का ब्याज दे रहे हैं। इसमें एसबीआई, HDFC, ICICI Bank आदि शामिल हैं। अगर सरकार 2 फीसदी तक ब्याज बढ़ता है तो सीनियर सिटीजन को मिलने वाला ब्याज 10 फीसदी तक जा सकता है।जिससे उनके बुढ़ापे की गाड़ी आसानी से चल सकती है । वसई पूर्व सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी आनंद बोंगिरवार के अनुसार सरकार वरिष्ठ नागरिको का बँक मे जमा पूँजी की पुरी राशी की सुरक्षा की गॅरंटीकरें इसे 5 लाख की सीमा में लॉक अप न किया जाय । देश में चल रहे सभी विमान सेवा नागरिकों को 50% डिस्काउंट प्रदान किया जाये , विमान सरकारी हो यां गैर सरकारी।इस समय पारिवारिक पेंशन के लिये 65 लाख लोग पेन्शन के लिये लगातार संघर्ष कर रहे है सभी वरिष्ठ नागरिक को पेन्शन प्रदान किया जाय क्योकि उन्होंने अपने जीवन काल मे बहुत ही कम पैसे मे गुजर किया था और महंगाई बढ़ने पर उनकी जमा पुंजी मे कमी हो गई हैं।इसी प्रकार सीनियर सिटीजन को दांतो की बीमारी के लिए इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। नकली दाँत बनवाने, और दांतों का इलाज करने की इनकम टैक्स में छूट दी जावे। दांतो के इलाज़ में एक बड़ी धनराशि ख़र्च होती है।मोदी सरकार ने चुनाव के पहले वायदा किया था कि 70 वर्ष से ऊपर के हर वर्ग के सीनियर सिटीजन को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा इस वायदे को इस बजट में मोहर लगाई जाय व उम्र सीमा घटा कर70 से 60 वर्ष की जाय । कोविड से पहले तक सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट दी जाती थी लेकिन ये छूट कोविड के समय खत्म कर दी गई। कोविड का डर देश और दुनिया में खत्म होने के बाद भी सरकार ने इस छूट को फिर से शुरू नहीं किया है। अब सीनियर सिटीजन बजट में ट्रेन टिकट पर 50 फीसदी तक की छूट दिये जाने की डिमांड कर रहे हैं। वह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें ये छूट फिर से देना शुरू करेंगे।गौरतलब है कि आईआरसीटीसी सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी केटेगरी में रियायती किराए ऑफर करता था। आईआरसीटीसी साल 2019 के अंत तक 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिला बुजुर्ग यात्रियों को दुरंतो, शताब्दी, जन शताब्दी, राजधानी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के ट्रेन टिकटों पर किराए में छूट देता था। जहां पुरुष वरिष्ठ नागरिक 40 प्रतिशत की रियायत के पात्र थे, वहीं महिला वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकती थी।साल 2019 के अंत तक सीनियर सिटीजन को ट्रेनों की टिकट की कीमत पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट मिली थी। अगर राजधानी का फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपये है तो सीनियर सिटीजन को 2,000 या 2,300 रुपये में मिलता था। फिर साल 2019 के अंत और साल 2020 की शुरुआत में कोविड देश और पूरी दुनिया में फैल गया जिसके बाद IRCTC की टिकट बुकिंग विंडो पर ये सर्विस मिलनी बंद हो गई। अब सीनियर सिटीजन उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में उन्हें ये खास छूट फिर से मिलेगी। सीनियर सिटीजंस का कहना है कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनका अपना घर नहीं है। वे किराया के घरों में रहते हैं। उन्हें हर महीने मकानमालिक को किराया चुकाना पड़ता है। रेगुलर इनकम नहीं होने से उन्हें दिक्कत आती है। सरकार को ऐसे सीनियर सिटीजंस को घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है। इससे बुजुर्गों पर टैक्स का बोझ कम होगा। उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बार बजट में उनकी यह मांग पूरी करेंगी। वर्तमान में, मूल कर छूट सीमा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 3 लाख रुपये और बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 5 लाख रुपये है। यह वह सीमा है जिस तक वरिष्ठ नागरिक की आय पर कर नहीं लगता है। अब, मांग यह है कि बजट में नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए मूल कर छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए, जो कि बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के समान है। वरिष्ठ नागरिक आगामी 2024 बजट में संभावित बोनस योजनाओं और कर प्रोत्साहनों को लेकर आशान्वित हैं। यह उम्मीद बुजुर्ग आबादी के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर आधारित है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किए गए बोनस धन का सीधा इंजेक्शन प्रदान कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, दैनिक जीवन और अन्य आवश्यक खर्चों से जुड़ी बढ़ती लागत को संबोधित करने में मदद मिलेगी। इससे न केवल वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता मिलेगी। तो, ये वित्त वर्ष 2024-25 के आगामी केंद्रीय बजट के लिए वरिष्ठ नागरिकों की कुछ सामान्य उम्मीदें हैं। वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके, सरकार बुजुर्ग समुदाय को सशक्त और उत्थान कर सकती है, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के वर्षों के दौरान अधिक सम्मानजनक और आरामदायक जीवन सुनिश्चित हो सके। हालांकि, चूंकि यह बजट 'वोट ऑन अकाउंट' है, इसलिए ये उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, इसका खुलासा 23 जुलाई 2024 को होगा।

गरजते मेघ उफनती नदियां कहर बनती बाढ़ खतरे में जिन्दगी!

मनोज कुमार अग्रवाल

बरसात का सीजन आते ही देश के कई राज्यों में हालात काफी बिगड़ने लगे हैं। एक ओर कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो पहाड़ी राज्यों की अवस्था काफी खराब होती जा रही है। चट्टानें खिसकने चटकने, पहाड़ दरकने और भूस्खलन से हालात काफी खराब होते जा रहें हैं। अतिवृष्टि और बाढ़ की चपेट में आकर कई राज्यों में जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, असम में नदियां उफान पर हैं और महाराष्ट्र गुजरात में मानसूनी बारिश में स्थिति काफी दयनीय दिख रही है। राजस्थान में इस बार भी बारिश आफत बनकर टूटी है। विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में हालात काफी खराब होती जा रही है। यहां की नदियां उफान पर हैं, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। असम के 30 जिलों में करीब 24.5 लाख लोग इस बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में अब तक बाढ़ से 52 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बारिश की वजह से हुए भूस्खलन और तूफान में भी 12 लोगों की जान गई है। विनाशकारी बाढ़ की वजह से अब तक 114 जंगली जानवरों की भी मौत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हो चुकी है। इधर उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। इसी प्रकार जम्मू में पूरी रात हुई भारी बारिश की वजह एक 30 वर्षीय महिला की डूबने से मौत हो गई है। हालात को देखते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने टेलीफोन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा को भी केंद्रीय मदद का भरोसा दिया है। भारी बारिश से हिमाचल में 150 से अधिक सड़कें बाधित हुई हैं। इनमें मंडी की 111, सिरमौर की 13, शिमला की नौ तथा चंबा और कुल्लू की आठ-आठ सड़कें शामिल हैं। भारी बारिश से उत्तराखंड में पहाड़ दरकने लगे हैं। उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो रहा है। यहां बारिश में पहाड़ों का मलबा आने से, पेड़ गिरने की वजह से कई सड़कें बंद हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन ने चारधाम यात्रा भी 2 दिनों के लिये स्थगित कर दी है। खराब मौसम का असर देखते हुए चार धाम यात्रा पर रोक लगाई गई है। पहाड़ों पर कुदरत ना जाने क्या ठानकर बैठी है. आसमान से ऐसी तबाही बरस रही है कि जमीन पर सबकुछ ध्वस्त हो रहा है. पहाड़ तिनके की तरह बिखर रहे हैं. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला की ओर जाने वाली एक सड़क पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर ऐसे गिरा कि सड़क बंद हो गई और सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं. पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते हादसे का खतरा बना हुआ है. काली नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। उत्तरकाशी में हिमखंड टूटने से गंगा के बहाव में अचानक तेज़ी आ गई।गौमुख में पुल बह जाने से 2 कांवड़िए पानी के तेज बहाव के साथ बह गए. बाकी बचे कांवड़ियों को एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया. केदारनाथ मंदिर के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर एवलांच की तस्वीर 2013 की त्रासदी की याद दिलाती है. पहाड़ों पर बर्फ का गुबार नजर आने लगा, जिसके बाद केदानगरी में हलचल मच गई। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड की सबसे बड़ी पर्यटन नगरी नैनीताल की ओर जाने वाली सड़कें बेहाल हो गई हैं. नैनीताल पर बारिश आफत बनकर आई. रेलवे ट्रैक पर पानी और मलबा भर गया. जो सैलानी बरसाती मौसम का मजा उठाने आए थे, लौटने को मजबूर हो गए. शहर की सड़कें वीरान पड़ी हैं. सैलानी होटल खाली कर अपने-अपने ठिकानों को लौट रहे हैं और स्थानीय लोग भी भूस्खलन के डर से सहमे हुए हैं।जगह-जगह पहाड़ दरक रहे हैं. भूस्खलन की वजह से भवाली-कैंचीधाम को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया है. लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। उधर नेपाल में हो रही बारिश के कारण एक बार फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल का पहाड़ी क्षेत्रों की अवस्था भी काफी खराब है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन की चपेट में आने से पिछले कई दिनों से बंद है। इससे यातायात में काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही कई घर भूस्खलन की चपेट में आ जाते हैं। साथ ही तीस्ता के रौद्र रुप के कारण समतल के जलपाईगुड़ी जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह हाल तब है, जबकि अभी मानसून शुरू हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बारिश अचानक आयी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी। लेकिन शायद राज्य सरकारों के द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हकीकत यह कि अपने देश के कुछ राज्यों में हर साल की बाढ़ आती है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों का एक बड़ा इलाका लगभग हरेक साल ही बाढ़ की त्रासदी झेलता है। मगर दुर्भाग्य से हमारी सरकारें इस मद में बजटीय आवंटन को लेकर जितनी उत्सुक दिखती हैं, इस समस्या से स्थायी छुटकारे को लेकर उनके प्रयास उतने दिखाई नहीं पड़ते। अगर देखा जाए तो देश में हर साल बारिश और बाढ़ से करीब 7 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। पिछले 65 सालों से हर साल औसतन बाढ़ में 2130 लोग मारे जाते हैं। एक लाख 20 हजार जानवर मरते हैं। 82.08 लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद होती है। एक रिसर्च के अनुसार भूस्खलन की जो घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती थीं, वो 2004 से 2010 के बीच 22 मिमी प्रति वर्ष की रफ्तार से होती थी, लेकिन 2022-23 में ही भारी बरसात के कारण ये 32 मिमी प्रतिवर्ष की रफ्तार से हुई। इस बार भी हिमाचल और उत्तराखंड में जिस तरीके से बरसात हो रही है, उससे भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड जैसे हालात बने हुए हैं. पहाड़ी से अचानक मलबा गिरने से हिमाचल टूरिज्म की बस और कई गाड़ियां फंस गईं. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद हो रही लैंडस्लाइड से कई सड़कें ध्वस्त हो गई हैं. पार्किंग में खड़ी गाड़ियां को मलबे के नीचे दब गईं। पहाड़ तिनके की तरह बिखर रहे हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा दूसरी तरफ प्रशासनिक कुव्यवस्था जिसमें पुल के पुल ढहे जा रहे हैं. ये पुल नहीं गिर रहे, ये बिहार में सरकारी तंत्र पर भरोसा गिर रहा है. ये पुल नहीं टूट रहे लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं. 17 दिनों में 12 पुल गिर गए. बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि पुल गिरते ही जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो और कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक शोध के अनुसार पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं पिछले 20 सालों में काफी बढ़ी हैं। साफ है कि पिछले कुछ वर्षों में कुदरत का कहर बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं कि मौसम संबंधी गतिविधियों में आ रहे बदलाव का बड़ा कारण जलवायु संकट है। और ऐसा सिर्फ भारत या एशियाई क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पूरी धरती पर देखने को मिल रहा है। इसलिए जब तक हम जलवायु संकट से निपटने के उपायों पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक इससे निजात मिलना संभव नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में मौसम विभाग का आकलन भी दुरुस्त हुआ है। समय रहते भारी बारिश, खासतौर से तटीय राज्यों में समुद्री तूफान आदि के बारे में सटीक सूचना भी मिल जाती है। इससे लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा देना संभव हो गया है। मगर समस्या यह है कि हम पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते। देश के अधिकतर राज्यों में बाढ़ आती है और व्यापक तबाही होती है। लोगों की जानें जाती है और फसलों को काफी नुकसान होता है। बाढ़ आने से लोगों का सब कुछ यह जाता है और बाढ़ खत्म होने के बाद उनको फिर से नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है। सवाल है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ठोस योजनाएं क्यों नहीं बनाई जातीं? आजादी के 75 साल बाद भी राज्यों के पास ठोस आपदा प्रबंधन प्रणाली नहीं है। वरना लोग जैसा संकट झेलने को मजबूर हैं वैसा शायद नहीं होता। बारिश के मौसम में बारिश होगी और जो धरती के लिए जरूरी भी है। कब तक आधी आबादी बारिश और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भगवान के भरोसे रहेगी? सरकार के तमाम प्रयास अभी तक नाकाफी साबित होते रहे हैं तकनीक के इस युग में भी हम बाढ़ और बारिश से मुकाबला करने में इतना अक्षम बने हुए हैं यह तरक्की और तकनीकी विकास के दावों का खोखला चेहरा उजागर करता है जरूरत है कि आपदा प्रबंधन को नए सिरे से खड़ा किया जाए और इसके लिए एआइ जैसे आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल किया

शब्द सामर्थ्य -113

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं
1. रूचिकर लगने वाली, रूचि के अनुकूल, चुनी हुई 3. राजाओं के बैठने का आसन 6. श्रमिक 7. कार्य, काज 9. वाद्ययंत्र आदि बजाने वाला 10. सहारा, सहायक वस्तु 11. शर्म, लाज, हया 12. मक्खन, माखन 14. श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं 15. चंद्रमा, रजनीश, चांद 18. पुस्तक 20. अवधि, समय 21. तर्क वितर्क और कहा-सुनी, जबानी झगड़ा 22. सूरत, आकार 23. झुका हुआ, नत।

ऊपर से नीचे
1. पंद्रह दिन का समय, शुक्ल या कृष्ण पक्ष 2. आग बुझाने की मशीन 3. हिंदु विवाहित स्त्री के मांग में भरने का लाल चूर्ण 4. पराजय, माला 5. मुंह ढकने का कपड़ा, घुंघट 8. चंदन, दक्षिण का एक पर्वत 10. व्यवस्थित करना, सजाना, स्वभाव आदि का परिष्कार, शुद्ध संबंधी कृत्य 12. विशालता, बड़प्पन, महान होने का भाव 13. अड़चन, रुकावट 15. जमीन के अंदर गहरा और लंबा रास्ता, अच्छे रंग का 16. बेवकूफ, मूर्ख, अहमक 17. औसत के हिसाब से 18. कृषक 19. अधिक, ज्यादा।

1		2	■	3	4		5	■
	■	6				■	7	8
9			■		■	10		
	■	11		■	12		■	
■	13	■	■	14			■	■
15		16		■		■	■	17
	■		■	18		19	■	
	■	20			■	21		
■	22		■	23			■	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 112 का हल

ज	ल	■	आ	वा	जा	ही	■	■
मा	■	खू	ब	■	दू	र	स्थ	■
ना	दा	न	■	सा	ग	■	ल	क्ष्य
■	न	ख	■	त	र	ल	■	■
■	वी	रा	न	■	■	च	ट	क
■	र	ब	■	आ	ज	क	ल	■
■	■	■	आ	ग	■	दा	ना	■
■	अ	ग	र	म	ग	र	■	क्रो
भा	भी	■	ती	न	■	■	व	ध

सूडोकु नवताल- 7122

★☆☆☆☆ सरल

3				8				9
		8	6		9	5		
6	5			4			7	1
	4						2	
1	2			6			9	8
		6	4		5	8		
9				1				7

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7121 का हल

8	2	4		9	7	5	1	6
3	5	6	1	4	2	7	8	9
1	9	7	6	5	8	2	3	4
9	6	2	5	8	3	1	4	7
5	3	1	4	7	9	8	6	2
4	7	8	2	1	6	9	5	3
2	8	3	9	6	1	4	7	5
6	1	5	7	2	4	3	9	8
7	4	9	8	3	5	6	2	1

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुभाषित *त्यागके बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेनेके लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है।* ❐ **स्वामी विवेकानन्द**

नीटकी पुन: परीक्षा सम्भव

सर्वोच्च न्यायालयने स्पष्टत: कहा है कि नीट यूजी परीक्षाके प्रश्नपत्र लीक हुए हैं और इसमें अनियमितताएं बरती गयी हैं। शीर्ष न्यायालयने इस प्रकरणपर कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी कहा है कि परीक्षामें पवित्रता प्रभावित हुई तो दोबारा परीक्षा करानेका आदेश भी सम्भव है। सोमवारकोइस प्रकरणसे सम्बन्धित ३० याचिकाओंपर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़के नेतृत्ववाली पीठ कर रही है, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र भी शामिल है। पीठका यह भी कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यदि परीक्षा प्रश्नपत्र टेलीग्राम, ह्वाट्सएप और अन्य माध्यमोंसे फैला है तो यह जंगलमें आग जैसा है। यदि दोषियोंकी पहचान नहीं कर पाते हैं तो पुन: परीक्षाके आदेश दिये जा सकते हैं। शीर्ष न्यायालयका यह भी कहना है कि पेपर लीकका प्रभाव कितना था, इसी आधारपर दोबारा परीक्षा करानेका निर्णय होगा। न्यायालयने सरकारको भी कटघरेमें खड़ा करते हुए कहा कि परीक्षाको लेकर क्या कुछ हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। सरकार परीक्षा रद नहीं कराना चाहती है, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होनेके बाद इसका लाभ लेनेवालोंकी पहचान सरकार कैसे करेगी? यह बड़ा प्रश्न है, जिसका समुचित उत्तर मिलना कठिन है। परीक्षाकी पवित्रता सुनिश्चित करनेके लिए केन्द्र सरकारको विशेषज्ञोंकी एक टीम गठित करनी होगी जिससे कि भविष्यमें ऐसी घटनाएं नहीं होने पाये। नीट यूजीमें इस बार लगभग २४ लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। प्रश्नपत्र लीक होनेसे परीक्षाकी पवित्रता प्रभावित हुई है। केन्द्र सरकार और एनटीए परीक्षा रद करानेका विरोध कर रही है और इसके पक्षमें यह दलील दी जा रही है कि इससे २४ लाख परीक्षार्थियोंका भविष्य जुड़ा है। परीक्षा रद करनेसे बड़ा संकट उत्पन्न हो जायगा। इसलिए परीक्षाएं रद नहीं होनी चाहिए। पेपर लीकको लेकर पूरे देशमें काफी आक्रोश है। यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इसकी जांच सौंप दी गयी है लेकिन अभी जांचकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थितिमें एक ओर सर्वोच्च न्यायालय और दूसरी ओर एलटीए और सरकार आमने-सामने है। यदि परीक्षाएं रद नहीं होती हैं तो हम परीक्षाकी शुचिताकी बात कैसे कर सकते हैं। गलत तरीकेसे सम्पन्न हुई परीक्षाओंके परिणामोंपर भरोसा करना कठिन है और यह न्यायसंगत भी नहीं है। मामलेकी अगली सुनवाई गुरुवारको होनी है। अब देखना है कि शीर्ष न्यायालयका रुख कैसा रहता है।

घर खरीदारोंको राहत

देशभरमें बिल्डर और सम्पत्ति खरीदारोंके बीच समझौताको लेकर सर्वोच्च न्यायालयकी एक नियम बनानेकी सलाह उचित और घर खरीदनेवालेको राहत पहुंचानेवाली है। इससे घर खरीदनेवाले जहां धोखाधड़ीसे बचेंगे, वहीं समझौतेमें पारदर्शिता आयेगी। बिल्डर और सम्पत्ति खरीदारोंके बीच समझौतेमें अलग-अलग नियमोंको लेकर चिन्ता जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालयने कहा है कि सम्पत्ति खरीदनेके लिए पूरे देशमें एक नियम तय किया जाना चाहिए जिससे लोगोंके साथ धोखाधड़ी न हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चन्द्रचूड़की अगुवाईवाली बेंचने यह टिप्पणी समान बिल्डर खरीददार समझौते तैयार करनेके लिए दायर जनहित याचिकापर सुनवाई करते हुए की है। आम तौरपर जब खरीदार घर खरीदता है तो बिल्डर उससे एक एग्रीमेंटपर साइन करवाता है। यह एग्रीमेण्ट बिल्डर खुद एकतरफा तैयार करता है। बादमें जब भुगतान या देरीसे जुड़े किसी विवादपर बिल्डर और खरीदारके बीच कोई विवाद होता है तब खरीदारको पता चलता है कि एग्रीमेण्टमें तो यह क्लाज है ही नहीं। हर राज्यमें अलग-अलग तरहके बिल्डर वायर एग्रीमेण्ट है और कुछ राज्योंमें इसका कोई माडल भी नहीं है। इसी कारण कोर्टमें बहुत सारी जनहित याचिकाएं दायर की गयी थीं। केन्द्र सरकारने अब सर्वोच्च न्यायालयके निर्देशपर माडल एग्रीमेण्ट कोर्टमें दाखिल कर दिया है। इसमें घर खरीदारोंकी सुरक्षाको ध्यानमें रखा गया है। अब घर खरीदार बिल्डरके मनमाने और एकतरफा एग्रीमेण्टसे खुदको बचा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालयने जनवरी २०२२ में भी केन्द्र सरकारको निर्देश दिये थे कि नेशनल माडल बिल्डर-वायर एग्रीमेण्ट होने चाहिए। स्टैण्डर्ड फार्म तैयार कर हाउसिंग एग्रीमेण्टके दौरान भरा जाय। माडल बिल्डर-वायर एग्रीमेण्ट और माडल एजेण्ट-वायर एग्रीमेण्टसे रियल एस्टेटमें पारदर्शिता आयेगी और घर-फ्लैट खरीदारोंको धोखाधड़ीका सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम देरसे ही सही लेकिन यह घर खरीदारोंको राहत देनेवाला है।

लोक संवाद

हाथ मिलानेकी परंपरा

महोदय,-यह एक महत्वपूर्ण अवसर था जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षके नेता राहुल गांधीने संसदमें एक-दूसरेसे हाथ मिलाया। यह पिछले सप्ताह स्पीकर ओम बिरलाके चुनावके बाद हुआ था। हाथ मिलानेकी परंपरा देशके राजनीतिक विकासका प्रतीक है। यह परंपरा एक महत्वपूर्ण क्षणको चिह्नित करती है। यह संसदके शुरुआती दिनोंसे चली आ रही है। उनके वैचारिक मतभेदोंके बावजूद, यह सत्तापक्ष और सत्तारूढ़ पार्टीके बीच अपेक्षित सहयोगको प्रदर्शित करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने विपक्षके नेताके रूपमें राहुलकी औपचारिक मान्यताको दर्शाया। कांग्रेस पार्टीके भीतर नयी गतिशीलता होगी और अपनी नयी भूमिकामें राहुलके लिए चुनौतियां होंगी। मोदीके शासनके दस साल बाद, लोकसभामें विपक्षका नेता है। राहुल गांधीने कांग्रेस पार्टीका नेतृत्व फिरसे संभाल लिया है और मोदीकी भाजपाके खिलाफ शीर्ष राजनीतिक दावेदारके रूपमें खड़े हैं। यह पार्टीके लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसमें कायाकल्पकी उच्च उम्मीदें हैं। वह एक एकीकृत विपक्षका निर्माण कर रहे थे, जो मोदीकी भाजपाके लिए अधिक मजबूत चुनौती पेश कर सकता है। एक अनिच्छुक नेतासे एक विपक्षके नेताके रूपमें राहुलका परिवर्तन उनके राजनीतिक विकासको दर्शाता है। दो महीनेकी भारत जोड़ो पद यात्रा शुरू करनेके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गयी, जिसके कारण कांग्रेसने २०२४ में २०१९ में जीती गयी सीटोंसे दोगुनी सीटें हासिल कीं। इसका उद्देश्य लोगोंसे जुड़ना था। इसके बाद उन्होंने एक और यात्रा की। राहुल गांधीकी राजनीतिक यात्रा, जो २००४ में अमेठीसे सांसद बननेके साथ शुरू हुई, उनके लचीलेपनका प्रमाण है। पिछले दो दशकोंमें उन्होंने कई चुनौतियों, आलोचनाओं और छूटे हुए अवसरोंका सामना किया है। उन्होंने कुछ वर्षोंतक पार्टी अध्यक्षके रूपमें भी काम किया। उनकी राजनीतिक यात्रा उनके नेतृत्व गुणोंके बारेमें संदेह और आलोचनासे भरी रही। हालांकि वे मजबूत और दृढ़ बने रहे और पीएम मोदीके विश्वसनीय प्रतिद्वंद्वी बन गये। महत्वपूर्ण पदोंपर रहनेके बावजूद, राहुल महत्वपूर्ण समयपर गायब हो जाते हैं। उन्होंने यूपीएके दस वर्षोंके दौरान कैबिनेट मंत्रीके रूपमें काम नहीं करनेका फैसला किया, इसके बजाय पार्टीपर ध्यान केंद्रित किया। ५४३ सदस्योंवाले सदनमें एनडीएके २९२ सदस्योंकी तुलनामें विभिन्न विपक्षी दलोंके गठबंधन इण्डी गठबंधनमें २३४ सदस्य और तीन स्वतंत्र सांसदोंका समर्थन है। अपर्याप्त संख्याके कारण कांग्रेस विपक्षी दलका दर्जा हासिल नहीं कर सकी। राहुलके अपरिपक्व बयानोंने पूरे देशवासियोंको झकझोर दिया। पहले सत्रके अंतमें प्रधान मंत्रीने राष्ट्रपतिके अभिभाषणके धन्यवाद प्रस्तावका जवाब दिया। विपक्षके नेताके रूपमें राहुल गांधीके पास अब नयी जिम्मेदारियां हैं जो भारतीय राजनीतिको महत्वपूर्ण रूपसे प्रभावित कर सकती हैं। उनकी भूमिकाके लिए उन्हें संसदीय नियमों और विनियमोंमें निपुणता हासिल करनी होगी और विपक्षका प्रभावी ढंगसे प्रतिनिधित्व करनेके लिए व्यावहारिक संचार कौशल विकसित करना होगा। इन जिम्मेदारियोंका भार महत्वपूर्ण है और यह भारतीय राजनीतिके भविष्यको आकार देगा। वह लोक लेखा समितिके प्रमुख भी बन सकते हैं, यह पद आम तौरपर संसदमें विपक्षको दिया जाता है। इससे उन्हें अन्य संसदीय समितियोंके लिए सदस्योंका चयन करने और भारतके कुछ सबसे प्रभावशाली सिविल सेवकोंको चुननेमें भाग लेनेका अवसर मिलेगा। विपक्षके नेताके रूपमें राहुलने संसदमें हिमदुओंके विरोधमें जो बयानबाजी की, वह ग्राह्य नहीं कहा जायेगा। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षके बीच चल रही लड़ाई संसदीय सत्रोंसे परे भी जारी रहनेकी उम्मीद है। यह लड़ाई संसदके अंदर और बाहर दोनों जगह होगी। राहुल संसदमें पहले पन्नेपर ध्यान खींचनेमें कामयाब रहे हैं और उन्होंने गलत शुरुआत की है। **-कल्याणी शंकर, वाया ईमेल।**

पर्यटन क्षेत्रसे अपार संभावनाएं

इन दिनों वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तैयार किये जा रहे वर्ष २०२४-२५ के बजटके तहत देशके घरेलू और विदेशी पर्यटनको मजबूत करनेके लिए प्रभावी बजट आवंटनकी संभावना दिख रही है। नये बजटके माध्यमसे सरकार पर्यटनसे आय बढ़ाकर अर्थव्यवस्थाको मजबूत करनेकी संभावनाओंको आगे बढ़ा सकती है।

❐ **डा.जयंतीलाल भंडारी**

इन दिनों प्रकाशित हो रही भारतमें पर्यटन संबंधी रिपोर्टोंमें कहा जा रहा है कि भारतमें घरेलू और विदेशी पर्यटन तेजीसे बढ़ रहा है और भारतमें पर्यटन सेक्टर बढ़नेकी असीम संभावनाएं हैं। ऐसेमें भारत अपने बेजोड़ पर्यटन स्थलोंपर सुविधाएं और सुन्दरता निर्मित करके पर्यटन सेक्टरकी ऊंची संभावनाओंको साकार करके पर्यटनसे आयको कई गुना बढ़ा सकता है। हिमाचल प्रदेशमें भी घरेलू और विदेशी पर्यटनकी असीम संभावनाओंको मुट्ठीमें लेकर हिमाचल प्रदेशकी अर्थव्यवस्थाको मजबूती दी जा सकती है। हालमें पर्यटन मंत्रालयके द्वारा प्रकाशित रिपोर्टके मुताबिक जनवरीसे अप्रैल २०२४ के दौरान भारत आनेवाले विदेशी पर्यटकोंकी कुल संख्या ३४७१८३३ रही जो एक साल पहलेकी समान अवधिमें ३१३३७५१ थी। इन चार महीनोंमें न केवल भारत आनेवाले विदेशी पर्यटकोंकी संख्या बढ़ी है, वरन इन चार महीनोंमें पर्यटनसे विदेशी मुद्रामें आय सालाना आधारपर २७.१८ प्रतिशत बढ़कर ९०६०० करोड़ रुपये हो गये है। ऐसेमें अब पर्यटन सेक्टरको मजबूत आधार देकर पर्यटनसे विदेशी मुद्राकी कमाई बढ़ायी जा सकती है। विदेशी पर्यटकोंसे होनेवाले आर्थिक लाभका अनुमान इस बातसे लगा सकते हैं कि एक विदेशी पर्यटकसे औसतन दो लाख रुपयेकी कमाई होती है।

इस समय विश्वमें भारतीय पर्यटक विदेशी पर्यटनके लिए क्रम दसवां है, जबकि वर्ष २०२७ तक भारतके पर्यटकोंका विदेशोंमें भ्रमणके लिए दुनियामें पांचवें क्रमपर होंगे। निश्चित रूपसे जहां एक ओर भारतीयोंका विदेश यात्रा करनेकी तरफ तेजीसे बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटनके मद्देनजर हानिकी तरह है, वहीं देशके विदेशी मुद्रा कोषको घटानेवाला भी है। उम्मीद है कि प्रधान मंत्री मोदीके तीसरे कार्यकालमें वित्तमंत्री घरेलू और विदेशी पर्यटनको तेजीसे बढ़ाने और मजबूत आधार देनेके लिए अभूतपूर्व प्रावधानोंके साथ आगे बढ़ेंगी और नयी पर्यटन नीतिसे भारतको अतुल्य बनायेंगी।

साथ ही पर्यटकोंका खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्थामें पुन: निवेशका काम करता है। पर्यटकों की संख्या बढ़नेसे रोजगार और पर्यटनसे जुड़े विभिन्न उद्योग-कारोबार भी बढ़ते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत पर्यटन सेक्टरको बढ़ानेवाले विभिन्न मापदंडोंके मद्देनजर लगातार प्रगति कर रहा है। गौरतलब है कि हालमें वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरमने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) २०२४ जारी किया है। ११९ देशोंके इस सूचकांकमें भारत ३९वें स्थानपर है। इसके पहले टीटीडीआई सूचकांक २०१९ में भारत काफी नीचे ५४वें स्थानपर था। नये टीटीडीआई सूचकांकमें भारत पर्यटनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण संसाधन मापदंडोंपर प्रमुख पर्यटन प्रधान देशोंकी सूचीमें शामिल है। प्राकृतिक मापदंडपर भारत छठे, सांस्कृतिक, कारोबार, चिकित्सा और शिक्षाके लिए यात्रा मापदंडोंपर भारत नौवें क्रमपर है। कुछ और ऐसे प्रमुख पर्यटन मापदंड हैं, जिनमें भारत उभरकर दिखाई दे रहा है। इनमें कीमत प्रतिस्पर्धात्मकताके मामलेमें भारत १८वें, हवाई यातायातकी प्रतिस्पर्धात्मकताके मामलेमें २६वें और जमीनी एवं बंदरगाह बुनियादी ढांचेके मामलेमें २५वें स्थानपर है। इस पर्यटन सूचकांकके विश्लेषणसे यह भी मालूम होता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्यए पर्यावरण सततता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्यटनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडोंपर भी भारतने प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि दुनियामें सबसे अधिक विदेशी पर्यटक प्रमुखतया फ्रांस, स्पेन, अमेरिका, चीन और इटलीमें जाते हैं। इन प्रमुख वैश्विक पर्यटन देशोंके अलावा सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, मलयेशिया और संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) जैसे देश भी अपनी कुछ विशिष्टताओंसे विदेशी पर्यटकोंको आकर्षित करनेके मामलेमें भारतसे बहुत आगे हैं।

लेकिन अब भी दुनियाके विदेशी पर्यटकोंकी कुल संख्याका कोई दो फीसदीसे भी कम हिस्सा ही भारतके खातेमें आ रहा है। यद्यपि पर्यटन उद्योग भारतके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब छह फीसदीका योगदान करता है, लेकिन इसमें सिर्फ आठ करोड़ लोगोंको ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीकेसे रोजगार मिला हुआ है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारत अपने बेजोड़ पर्यटन स्थलोंकी शक्तिके दमपर दुनियाके सबसे अधिक पर्यटकोंको आकर्षित करनेकी संभावनाएं रखता है। लेकिन भारत इस डगरपर बहुत पीछे है। भारतके कई ऐसे अनोखे पर्यटन स्थल हैं, जो देशमें टूरिज्मके विभिन्न आयामोंको चमकीली पहचान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतकी संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खान-पानसे लेकर नैसर्गिक सुन्दरता हमेशासे देशी-विदेशी पर्यटकोंको आकर्षित करती रही हैं।

भारत एक ऐसा देश है जिसके पास हिमालयका सबसे अधिक हिस्सा, विशाल समुद्री तट रेखा और रेतका रेगिस्तान, कच्छमें सफेद नमक रेगिस्तान, लद्दाखमें ठंडे रेगिस्तान, देशके कोने-कोनेमें टाइगर रिजर्व और यूनेस्कोंके द्वारा चिह्नित धरोहर स्थलों समेत अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसी प्राकृतिक विविधताएं हैं। देशके विभिन्न भागोंमें तटीय पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपनी चिर-परिचित पहचान बनाये हुए हैं और सभी प्रकारके पर्यटकोंको आकर्षित करनेकी अपार संभावनाएं रखते हैं। इनके अलावा रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, अयोध्यामें राम मंदिर, उज्जैनमें महाकाल लोक और वाराणसीमें काशी विश्वनाथ धाम जैसे आस्था केन्द्रस्थल देश एवं दुनियाके धार्मिक पर्यटकोंके कदमोंको असाधारण रूपसे आकर्षित कर सकते हैं। नि:संदेह इस समय जहां एक ओर विदेशी पर्यटकोंके कदम भारतकी ओर धीमी गतिसे बढ़ रहे हैं, वहीं भारतीय पर्यटकोंके कदम विदेशोंमें पर्यटनके लिए छलांगे लगाकर बढ़ रहे हैं। ४ दिसंबर २०२३ को सरकारने लोकसभामें बताया कि वर्ष २०२२ में भारत यात्रापर आये विदेशी पर्यटकोंकी संख्या ८५.९ लाख थी, जबकि पिछले वर्ष २०२२ में करीब दो करोड़ भारतीय पर्यटकोंने देशसे बाहर भ्रमण किया। २३ मई २०२४ को प्रकाशित रिजर्व बैंककी रिपोर्टके मुताबिक भारतीय पर्यटकोंने वर्ष २०२३-२४ में विदेश घूमनेपर १७ अरब डालर यानी करीब १.४१ लाख करोड़ रुपये खर्च किये हैं, जो कि इसके पूर्व वर्ष २०२२-२३ में विदेश घूमनेपर किये गये व्ययकी तुलनामें अधिक हैं।

इस समय दुनियामें भारतीय पर्यटक विदेशी पर्यटनके लिए क्रम दसवां है, जबकि वर्ष २०२७ तक भारतके पर्यटकोंका विदेशोंमें भ्रमणके लिए दुनियामें पांचवें क्रमपर होंगे। निश्चित रूपसे जहां एक ओर भारतीयोंका विदेश यात्रा करनेकी तरफ तेजीसे बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटनके मद्देनजर नुकसानकी तरह है, वहीं देशके विदेशी मुद्रा कोषको घटानेवाला भी है। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि भारतीयोंके द्वारा विदेश भ्रमणमें किये जा रहे भारी-भरकम व्ययकी तुलनामें भारत आनेवाले विदेशी पर्यटकोंसे भारतकी आमदनी बहुत कम है। हम उम्मीद करें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीके तीसरे कार्यकालके वर्ष २०२४-२५ के बजटके तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण घरेलू और विदेशी पर्यटनको तेजीसे बढ़ाने और मजबूत आधार देनेके लिए अभूतपूर्व प्रावधानोंके साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। साथ ही नयी गठबंधन सरकार नयी पर्यटन नीतिसे पर्यटनके लिए भारतको अतुल्य बनानेकी डगरपर भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। उम्मीद करें कि नयी सरकार भारतमें वर्ष २०३० तक विदेशी पर्यटकोंसे ५६ अरब डालरकी विदेशी मुद्रा अर्जित करनेके लक्ष्यके साथ वर्ष २०४७ तक भारतको एक लाख करोड़ डालरकी पर्यटन अर्थव्यवस्था बनानेकी डगरपर तेजीसे आगे कदम बढ़ायेगी।

सरकारी अस्पतालोंमें सुधार जरूरी

सरकारी अस्पतालोंकी दयनीय हालात किसीसे छिपी नहीं है। आजादीके ७६ साल बाद भी सरकारी अस्पतालोंकी हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। देशके ८० फीसदी सरकारी अस्पताल मापदण्डपर खरे नहीं उतरते हैं।

❐ **अखिलेश आर्येन्दु**

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयके मुताबिक भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) का उपयोग बुनियादी ढांचे, कर्मचारियोंकी तादाद, दवाओंका भंडारण, प्रयोगशाला क्षमता और स्वास्थ्यके लिए संसाधनके लिए किया जाता है। सरकारी एजेंसीके जरिये ४०,४५१ सरकारी अस्पतालोंकी पड़ताल जो २००७ और २०२२ में संशोधित मानकोंके आधारपर की गयी। इसके आधारपर तैयार की गयी रिपोर्टके मुताबिक ३०,३६२ अस्पतालोंको सौमेंसे ८० से भी कम अंक हासिल हुए। इनमेंसे १७,१९० अस्पतालोंको ५० से भी कम अंक हासिल हुए। संसाधनोंके मामलेमें सिर्फ ८,०८९ अस्पताल ८० से ज्यादा अंक हासिल कर मानकोंपर ठीक पाये गये। स्वास्थ्य मानकोंके लिए ८० से ज्यादा अंक लाना जरूरी है, जिसमें पड़तालके दौरान बनायी गयी डाटा किटके लिए २५ अंक राज्यस्तरीय मूल्यांकनके मिलते हैं। मरीजोंकी प्रतिक्रियाके आधारपर पांच अंक दिये जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओंपर दस अंक। पांच अंक प्रयोगशाला जांच सुविधाओं और दवाओंके भंडारणके लिए दस अंक दिये जाते हैं। इस तरह अस्पतालका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिसमें ८० से अदिक अंक लेना जरूरी होता है। पड़तालकी रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रोंके अस्पतालोंमें बहुत अंतर है। मसलन ग्रामीण क्षेत्रोंके स्वास्थ्य केन्द्रोंपर टीकाकरण। कैंसर स्क्रीनिंग, खूनकी जांच जैसी तमाम सुविधाओंका अभावके साथ बिजलीकी समस्या आम है। वहीं शहरी इलाकोंके अस्पतालों विस्तरोंका अबाव और दवाओंके भंडारणकी सुविधामें कमी पायी गयी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रोंमें चिकित्कों और नर्सोंका कमी एक बड़ी चुनौती है। देशके आठ हजारसे ज्यादा सरकारी अस्पतालोंमें १४ उन जांचोंकी भी सुविधा नहीं है जो नियमके मुताबिक होनी ही चाहिए।

सरकारी अस्पतालोंकी समस्याएं और उनकी दयनीय हालातके मद्देनजर केन्द्र सरकारने कुछ ठोस कदम उठाये हैं। इसके लिए राज्योंको सरकारी अस्पतालोंकी दशा सुधारने और बेहतर सेवा मुहैया करानेके लिए राज्योंको पत्र लिखा गया है। पत्रमें लिखा गया है सरकारी अस्पतालोंके साथ-साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरोंको मानक प्रमाण पत्र हासिल करनेके लिए सहयोग दिया जायेगा। गोरतलब है कोरोना महामारीके दौरान हासिल आभासी मूल्यांकनके अनुभवके आधारपर आयुष्मान आरोग्य मंदिरके लिए एक मॉडल विकसित किया है, जिसे वर्चुअल रूपसे इस्तेमाल किया जाना है। इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकारके राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक को सौंपी है। आजादीके ७६ सालोंमें मुल्कके तकरीबन सात लाख गावोंमें स्वास्थ्य सुविधाओंकी आज भी भारी कमीके अलावा डाक्टरोंकी नियुक्ति जरूरतसे बहुत कम है। महज तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां गांवोंमें स्वास्थ्य सेवाओंको कुछ संतोषजनक कहा जा सकता है। राज्योंने कुछ साल पहले गांवोंमें डाक्टरोंकी कमीको पूरा करनेके लिए सख्त कानून बनाये थे, बावजूद गांवोंमें सेवा देनेसे ज्यादातर नये डाक्टर मना करते रहे हैं। विडम्बना ही कही जायगी कि नौकरीके लिए डाक्टरों द्वारा भरे गये बांडको तोड़नेके लिए हर साल करोड़ों रुपये उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, लेकिन गांवोंमें सेवा देनेसे वे मना करते रहे हैं। अकेले राजस्थान एवं महाराष्ट्रमें पिछले एक दशकमें दस हजारसे ज्यादा डाक्टरोंने गांवमें सेवा देनेसे मना कर दिया।

भारतमें चीनकी अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रोंमें महज ३१०० मरीजोंपर एक बेड है। वहींपर बिहारमें १८,००० ग्रामीणोंपर एक बेड है। उत्तर प्रदेशके गांवोंमें ३९०० मरीजपर एक बेडकी व्यवस्था है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रोंमें २६००० की आबादीपर एक एलोपैथिक डाक्टर हैं जबकि विश्व स्वास्थ्य संघटनका कहना है कि हर १००० लोगोंपर एक डाक्टर होने चाहिए। भारतमें तकरीबन दस हजारकी आबादीपर बमुश्किल सात डाक्टर हैं। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) के यहां पंजीकृत एलोपैथिक डाक्टरोंकी कुल संख्या लगभग एक करोड़ है। राज्योंमें डाक्टरोंकी उपलब्धताके मामलेमें पश्चिम बंगालकी स्थिति सबसेसे खराब है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइलके मुताबिक पश्चिम बंगालके ग्रामीण क्षेत्रोंमें महज ९०० डाक्टर हैं। आबादीके हिसाबसे ७०,००० लोगोंपर एक डाक्टर है। बिहार और झारखंडमें ५०,००० की आबादीपर सिर्फ एक डाक्टर है। गौरतलब है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओंकी बुनियाद प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओंपर टिकी है, लेकिन यह बुनियाद ही बेहद कमजोर है। गांवोंमें डाक्टरोंकी भारी कमीकी वजहसे ग्रामीणोंको मजबूर होकर नीम-हकीम खतरे-जान यानी झोला छाप डाक्टरोंसे काम चलाते हैं। इससे आये दिन हजारों लोग बेहतर इलाजके अभावमें दम तोड़ देते हैं। आंकड़े बताते हैं गांवोंमें एलोपैथीके अलावा होमियोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सकोंकी भी कमी है।

केन्द्र सरकार आयुर्वेद और योगको बढ़ावा देनेके लिए करोड़ों रुपये हर साल उपलब्ध कराती है। लेकिन सवाल महज धन मुहैया करानेका ही नहीं है। सवाल गांवोंमें आयुर्वेद और योग-केन्द्रोंकी स्थापना और वहां सेवा देनेके लिए योग्य चिकित्सकोंकी कमीका भी है। इसलिए एमबीबीएसके अलावा बीएमएस और आयुर्वेदिक चिकित्सकोंकी बड़े पैमानेपर नियुक्ति की जानेकी जरूरत है।

गांव स्तरपर होमियोपैथी और आयुवैदिक स्वास्थ्य केन्द्रोकी जो कमी है। यदि उसपर जल्द कदम उठाये जायं तो गांवोंमें डाक्टरोंकी कमीके बावजूद हलाकानीसे लोगोंको बचाया जा सकता है। देशमें एमबीबीएस डाक्टरोंकी कमीको पूरा करनेके लिए विशेषज्ञों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये हैं। इनमें जनरल मेडिसिनमें एनडी या फैमिली मेडिसिन डिप्लोमा इन जनरल मेडिसिन और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामें स्नातक करना शामिल है। इन तीनों सुझावोंपर कारगर ढंगसे आगे बढ़नेपर गांवोंमें बड़े स्तरपर चिकित्सकोंकी कमीको दूर किया जा सकता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयने गांवोंमें स्वास्थ्य सेवाओंकी कमीकी समस्याको दूर करनेके लिए एक व्यावहारिक कदम उठानेकी बात सालोंसे कहता आया है। यह फार्मूला है पांच सालकी एमबीबीएसकी पढ़ाई पूरी करनेके बाद छात्रोंको एक सालका विशेषज्ञता कोर्स कराया जाय जिससे ग्रामीण क्षेत्रोंमें उनकी तैनातीपर ऐसे डाक्टर बिना किसी हिचकके ग्रामीण क्षत्रोंमें अपनी बेहतर सेवाएं दें सकें, लेकिन इससे बात नहीं बनी। फिर केन्द्र सरकारने एक दूसरा फार्मूला तैयार किया। इसके तहत एमबीबीएस डिग्रीधारी डाक्टरोंको परास्नातक यानी एमएस या एमडीमें दाखिला तभी मिलेगा जब गांवोंमें तैनातीकी अनिवार्य अवधिके लिए वे हलफनामा लिखकर देंगे। सरकारने एक बात इसमें और जोड़ दी कि जो एमबीबीएस डिग्रीधारी छात्र हलफनामा लिखकर देंगे यदि उनके नम्बर कम भी होंगे, तब भी उन्हें एमएस या एमडीमें प्रवेश दे दिया जायगा। लेकिन केन्द्र सरकारके इस लुभावने फार्मूलेके बाद भी गांवोंमें सेवाएं देनेवाले डाक्टरोंमें कोई खास रुचि नहीं दिखाई दे रही है। ऐसेमें अब एक सवाल यह उठता है कि इन तमाम कवायदोंके बावजूद जब एमबीबीएस डॉक्टरोंमें गांवोंमें सेवा देनेकी रुचि नहीं बन पा रही है तो अब कौन-सा फार्मूला अपनाया जायगा जिससे ग्रामीण इलाकोंमें बदतर स्वास्थ्य सेवाओंमें सुधार हो सके?

आत्मचिंतन

❐ **श्रीराम शर्मा**

यदि तुम विद्वान बननेकी चेष्टा कर रहे हो तो निराशा निकालकर यह उम्मीद रखो। तुम अनुभव करो कि मेरी विद्वतामें निरन्तर अभिवृद्धि हो रही है। तुम्हारा व्यवहार, आचरण पूर्ण विश्वास युक्त हो, निराशाका नामोनिशान भी न हो। अपने इस विश्वासपर तुम्हें पूरी दृढ़ताका प्रदर्शन करना उचित है। यह अभिनय करते-करते एक दिन तुम स्वयमेव अपने कार्यको पूर्ण करनेकी क्षमता प्राप्त कर लोगे। जिस वस्तुको हमें प्राप्त करना है उसके लिए जितनी मानसिक क्रिया होगी, जितना उसकी प्राप्तिका विचार किया जायगा, उतनी ही शीघ्रतासे वह वस्तु हमारी ओर आकर्षित होगी। प्रत्येक वस्तु पहले मनमें उत्पन्न की जाती है फिर वस्तु जगतमें उसकी प्राप्ति होती है। तुम अपने विषयमें अयोग्यताकी भावना रखते हो अत: उसी प्रकारकी अंत:करणकी सृष्टि होती जाती है। भयकी कल्पनाएं ही मनमें निराशाके काले बादलोंकी सृष्टि कर रही है। मन:स्थितिके ही अनुसार अन्य व्यक्ति तुमसे द्वेष अथवा प्रेम करते हैं। जब तुम निश्चय कर लोगे कि मेरा निराशासे जीवनका कोई संबंध नहीं होगा। मुझे नाउम्मीदोंसे कोई सरोकार नहीं है, मैं अबसे निराशाका कोई चिह्न भी न रहने दूंगा मैं पूर्ण शक्ति और मनोरथ सिद्धिमें प्रवृत्त होउंगा, निराशापूर्ण वातावरणसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो अपनी प्रवृत्ति ही उत्तम पदार्थोंकी ओर कर दी है। लता और मनोरथ सिद्धि मेरे बाएं हाथका खेल है मुझे संसारकी कठिनाई अपने श्रेयके मार्गसे विचलित नहीं कर सकती तब याद रखो तुम्हारे हृदयमें एक दिव्य शक्ति शासनकर्ता शक्ति प्रसन्न होगी। डर तभी हो सकता है जब हृदय कमजोर हो। हृदय कमजोर करनेवाली एक ही वस्तु है संसारमें चाहे उसे अविश्वास, अपघात, धोखेबाजी, बेईमानी कह लो अथवा पाप। मुख्य बात यह है कि हमें किसीसे भय न हो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम किसीके साथ क्षुद्रता न करें। जब कोई बुरी बात मनमें आती है तभी मन:स्थिति कमजोर होती है और छिपानेका स्थान ढूंढ़ना पड़ता है। हमारे मनमें उठनेवाली भावनाएं पवित्र हों योजनाएं और विचार धाराएं ऐसी हों जिनसे जीवन सुव्यवस्थित बनता हो, प्रगति होती हो, हमारे कार्य इतने स्वच्छ हों कि कभी किसीको। अंगुली उठानेका अवसर न मिले तो फिर डर भी किस लिए होगा। डरका घर नहीं रहेगा तो वह बसेगा कहां। संसारमें सब मित्र ही नहीं होते शत्रु भी होते हैं। विसंगतियां प्रत्येक क्षेत्रमें पायी जाती हैं। आप अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी भावनाएं सदैव दूसरोंका कल्याण चाहती हैं परोपकार, परमार्थ और पुण्यको जीवनका लक्ष्य मान कर चलने वाले लोगोंके साथ भी खरपेंच लगानेवालोंकी कमी नहीं रहती।

ढोंगी बाबाओंका फैलता साम्राज्य

❐ **डा.सुरेश शर्मा**

आम व्यक्ति ढोंगी बाबाओं तथा अंधविश्वासोंके चंगुलसे कब मुक्त होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी बाबा ढोंगी होते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि बहुतसे लोग धर्म, मत तथा आस्थाके नामपर अपना धंधा चला रहे हैं। वहीं, बहुतसे लोग, गैर-सरकारी संघटन मानव कल्याणके लिए बहुत ही सराहनीय कार्य भी कर रहे हैं। बहुतसे मामलोंमें लोग ढोंगी बाबाओंसे गुमराह ही होते हैं। अशिक्षा, अज्ञान तथा अन्धविश्वास ही इसका मुख्य कारण है। लोकतांत्रिक व्यवस्थामें कोई भी अपना संघटन खड़ा कर सकता है, अपना विचार फैला सकता है तथा अपने अनुयायियोंकी फौज खड़ी कर कहीं भी सत्संग, समारोह तथा समागम आयोजित कर सकता है। उत्तर प्रदेशके हाथरस जिलेमें सिकंद्राराऊ क्षेत्रमें हालमें एक समागम कार्यक्रममें बाबाकी चरण रज प्राप्त करनेके चक्करमें १२१ लोग भगदड़में मारे गये।

इस समागम कार्यक्रममें प्रशासनसे ८० हजार लोगोंके शामिल होनेकी अनुमति ली गयी, जबकि करीब अढ़ाई लाख श्रद्धालु कार्यक्रम स्थलपर पहुंचे। कार्यक्रमके पश्चात भोले बाबाके नामसे मशहूर बाबाके चरणोंकी धूल प्राप्त करने तथा बाबाके निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा धक्के देनेके फलस्वरूप भगदड़ मचनेसे १२१ बेकसूर तथा नासमझ लोगोंकी जान चले जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आश्चर्य तथा खेदजनक है कि इन मृतकोंमें ११४ महिलाएं शामिल हैं। कुछ मृतकोंकी पहचान नहीं हो पायी है। बहुतसे गम्भीर रूपसे घायल लोगोंका आगरा, अलीगढ़ तथा हाथरसके अस्पतालोंमें ईलाज चल रहा है। मौतकी ऐसी भयावह त्रासदी कोई पहली घटना नहीं है। धर्मस्थलोंमें भीड़ इकट्ठी होने, भगदड़ मचने, धक्का-मुक्की होने, पुल टूट जाने, गाड़ियोंकी दुर्घटना होने, आयोजन स्थलपर आगजनी होनेसे टैंट तथा शामियाने जलने, शार्ट सर्किट होने जैसे कारणोंसे अनेकों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। दु:खद यह है कि हर बार कुछ दिनोंके अफसोस, पुलिस केस, जांच समिति गठित होने तथा न्यायालयके मुकद्दमोंके अतिरिक्त हम कोई सीख नहीं ले पाये हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, बाबाओंके चमत्कारों तथा आडंबरोंके चक्करमें न जाने कितने बेकसूर लोग असमय मौतका शिकार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिसमें कभी आरक्षक रहे सूरज पाल यादवको अचानक आध्यात्मिक ज्ञान हो गया। वर्ष १९९७ में सूरज पालने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनेके बाद अपने घरको ही आश्रमका रूप देकर प्रवचन देनेसे अपना धंधा शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षोंमें सूरज पाल भोले बाबा तथा चमत्कारी बाबाके नामसे प्रसिद्ध हो गये। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब आदि राज्योंमें अनेकों भक्तोंके बाबा बन गये। भोले बाबाके लिए सत्संगमें लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगे, हाथसे छूकर भी बीमारियां दूर होनेका चमत्कार होने लगा। बाबाकी मार्किट बनती रही। चमत्कारको नमस्कार होने लगा। हैरानीकी बात है कि न केवल आम आदमी, बल्कि प्रसिद्ध व्यवसायी, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, फिल्मी सितारे तथा वीवीआईपी लोग भी लाभ लेनेके लिए इन बाबाओंके चक्करमें रहते हैं।

इनके प्रभाव तथा भेड़चालमें आम व्यक्ति इस प्रकारके हादसोंका शिकार हो जाते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यक्ष प्रश्न यह है कि हम कबतक अशिक्षा, अज्ञान तथा अंधविश्वासके प्रभावमें रहेंगे। कबतक ये बाबा लोग सामान्य जनकी भावनाओंसे खिलवाड़ कर अपना धंधा चलाते रहेंगे। कबतक प्रशासन, व्यवस्थाएं तथा सरकारें बेफिक्र होकर सोई रहेंगी। कबतक समाज वास्तवमें शिक्षित तथा जागरूक होगा। ऐसी घटना घटित होनेके बाद कुछ दिनोंतक आंखें खुली रहनेके पश्चात् हम फिरसे ऐसी घटनाओंके लिए तैयार हो जाते हैं। फिलहाल अब सूरज पाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, सत्संग कार्यक्रमके आयोजक देव प्रकाश माथुर तथा अज्ञात लोगोंके खिलाफ भारतीय न्याय संहिताकी धारा १०५, ११०, १२६, २२३ तथा २३८ के तहत मामला दर्ज हो चुका है और इसके बाद गिरफ्तारी, जांच-पड़ताल, आपराधिक मामले, न्यायालयके मुकदमोंके पश्चात फिर कोई सबक न लेकर किसी और समय तथा स्थानपर इस प्रकारकी किसी मिलती-जुलती घटनाके लिए तैयार हो जायंगे। यह दु:खद घटनाक्रम निरंतर तथा अनवरत रूपसे चल रहा है।

हाथरस जिलामें सूरज पाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबाके इस समागममें यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना होनेके पश्चात अब प्रशासन द्वारा बाबाका इतिहास खंगाले जानेसे यह पता चल रहा कि उपरोक्त बाबा यौन शोषण सहित अनेकों आपराधिक मामलोंमें शामिल है। भोले बाबाके नामपर अनेक आपराधिक मामले, जादुई चमत्कार, अंधविश्वास फैलाने, जादू-टोना तथा जमीन कब्जानेके मामले दर्ज हो चुके हैं। बाबाको कई मामलोंमें गिरफ्तार किया जा चुका है। विडंबना है कि ऐसी घटनाएं सामने आनेके बाद ही इन बाबाओंके संगीन अपराधोंकी परतें खुलती हैं तथा सामान्य रूपमें प्रशासन तथा राजनीतिक व्यवस्थाओंकी छत्रछायामें इनका धंधा चलता रहता है। बाबाके चरणोंकी धूल लेने तथा उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा धक्का-मुक्कीके फलस्वरूप भगदड़ मच जानेसे बेकसूर लोगोंकी जान चली गयी। आवश्यक यह है कि ऐसे आयोजनोंमें भीड़ इकट्ठी होनेसे पूर्व आयोजकों तथा प्रशासन द्वारा सुरक्षित तथा पुख्ता इंतजाम किये जाने चाहिए। मामलेमें सख्त काररवाईकी आस है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

सच न बोलना राजनीति की मजबूरी बन चुकी है

किसी देश में 123 लोग भगदड़ में मर जाएं, लेकिन दशकों से ऐसे आयोजनों के नायक (नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा) पर सरकार न तो एफआईआर करे, ना ही किसी राजनीतिक दल की हिम्मत हो कि बाबा के खिलाफ एक शब्द भी बोले, तो इसे क्या कहेंगे? यूपी सरकार बाबा के प्रति पहले ही दिन से उदार है! वह अपराध न्याय-प्रक्रिया में एक नया शब्द 'आयोजकों' ईजाद कर छोटे-मोटे लोगों को असली दोषी मानकर तलाश रही है। मजा तो यह है कि इस भोले बाबा ने भी एक वीडियो जारी कर घटना पर चिंता जताई, अपने आप को घटना के समय अनुपस्थित बताया और कहा कि भगदड़ करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। बाबा पर हाथ डालने की हिम्मत न करने का कारण है करीब 15 जिलों के दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर उसका जादुई प्रभाव। लिहाजा सत्तापक्ष का डर तो छोड़िए, प्रदेश के प्रमुख विपक्ष के नेता का भी उसके साथ फोटो और बाबा के प्रति उपास्य-भाव वाला सम्मान चर्चा में है। कांग्रेस के नेता ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया लेकिन बाबा की दोष-युक्तता के बारे में सवाल आया तो कहा कि 'घटना की गंभीरता पर ध्यान दीजिए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इस पर प्रशासन से सवाल कीजिए।' यानी सत्तापक्ष हो या विपक्ष, सबको एक कमजोर गर्दन की तलाश है और जाहिर है वह है- प्रशासन और उसमें सबसे नीचे का अधिकारी। यानी यह बाबा जो दशकों से अपने हैंडपंप के पानी से बीमारी ठीक करने का दावा करता रहा, अशिक्षित-अतार्किक-अवैज्ञानिक सोच को बढ़ाते हुए अपनी चरणरज से व्यक्तिगत दुःख दूर करने का स्वांग करता रहा, वह इतनी बड़ी घटना के बाद भी लोगों को धोखा देता रहेगा और अपनी 'भक्त-शक्ति' के चुनावी लाभ या हानि से राजनीतिक वर्ग को नतमस्तक होने को मजबूर करता रहेगा।

प्रेरणा

जीवन स्वयं को खोजना नहीं, बल्कि स्वयं को बनाना है। - जॉर्ज बर्नार्ड शॉ

सुर्खियों से आगे • बिहार में चाहे जिसकी सरकार रही हो, सब की सब कामचलाऊ ही रहीं...

पुल बनते हैं, ताकि नदियां नीचे से निकल सकें

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

पुल-पुलिया बनाने के मामले में बिहार एक अलग और अनोखा प्रदेश है।

शेष देश में पुल इसलिए बनाए जाते हैं कि लोग और वाहन उनके ऊपर से निकल सकें।

बिहार में पुल इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि नदियां उनके नीचे से निकल सकें!

चूंकि तमाम पवित्र नदियां जैसे गंगा, गंडक, महानंदा बिहार में हैं, इसलिए नदियों को दण्डवत करना जरूरी होता है। पुल भी दण्डवत प्रणाम करते रहते हैं, यानी चरणों में गिर जाते हैं। कौन-सी हैरत की बात है? बाकी देश के लोग फोकट ही हल्ला मचाते फिरते हैं!

दरअसल, बिहार एक अलग देश जैसा है। यहां कांग्रेस की सरकार रही हो, या लालू प्रसाद यादव की या बाद में नीतीश कुमार की, सब की सब कामचलाऊ ही रहीं। किसी तरह समय बिताना और ज्यादा से ज्यादा साल तक सरकार में रहने का रिकॉर्ड बनाना!

नीतीश बाबू ने तो सत्ता में रहने के लिए राजनीति के तमाम नियम-कानून खीसे में डाले और केवल अपनी गद्दी की चिंता की। बिहार के विकास के नाम पर केवल सड़कें बनवा दीं, जिससे लालू यादव के जमाने का जंगल राज खत्म होने का लोगों को भ्रम हो गया। नीतीश बाबू चल गए। चलते रहे। कभी लालू के सहारे, कभी उनके बेटे के सहारे और ज्यादातर भाजपा के सहारे।

दरअसल भाजपा को भी जिस बिहार में कभी अकेले सत्ता नहीं मिल पाई, वहां उसे नीतीश कुमार के रूप में एक दिव्य आड़ मिल गई। कांग्रेस हो, लालू हों, नीतीश कुमार हों या उनकी ज्यादातर सहयोगी रही भाजपा हो, निर्माण कार्यों में क्वालिटी की तरफ किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। वजह एक ही है- सरकार चलाने के सिवाय इनका कोई उद्देश्य नहीं रहा।

आगे की पढ़ाई के लिए यहां के युवा हमेशा दिल्ली जाते रहे। वहां जाकर इन युवाओं ने खूब मेहनत की। जो सफल हुए, वे आईएएस या आईपीएस बन गए और कई बार की कोशिशों के बावजूद जो सफल नहीं हो पाए, वे पत्रकार हो गए। कोई प्रिंट मीडिया में, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में।

सरकारें बिहार में अपनी जगह बनी रहीं। उनका ढर्रा न कभी बदला और न ही किसी ने बदलना चाहा। एक जय प्रकाश नारायण के बाद यहां किसी ने सरकारों के खिलाफ आंदोलन भी नहीं किया। युवा लोगों के पास आंदोलन में उलझने के बजाय अपना भविष्य बनाने के लिए दिल्ली कूच करने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा। समय की मांग और तकाजा भी यही था।

क्वालिटी नहीं, कॉस्ट पर जोर

बिहार में निर्माण कार्य का उद्देश्य क्वालिटी नहीं, बल्कि कॉस्ट होती है। यानी अच्छा निर्माण नहीं, बल्कि सस्ता निर्माण ही यहां की मूल नीति है। जो जितना सस्ता निर्माण करने की गारंटी देता है, ठेका उसी को मिलता है।

जहां सरकारें ही अपहरण उद्योग चलाती रही हों, वहां प्रदेश से कूच करने के सिवाय कोई उपाय ही कहां रह जाता है?

जहां तक घटिया पुल-पुलिया निर्माण का सवाल है, इसका कारण बाकी देश से कुछ अलग ही है। बिहार में निर्माण कार्य का उद्देश्य क्वालिटी नहीं, बल्कि कॉस्ट होती है। यानी अच्छा निर्माण नहीं, बल्कि सस्ता निर्माण ही यहां की मूल नीति है। जो जितना सस्ता निर्माण करने की गारंटी देता है, ठेका उसी को मिलता है।

इसके ऊपर इंजीनियरों और ठेकेदारों का गठजोड़। पैसे दो, निर्माण पास करवाओ। बिल भी पैसे देकर ही पास होते हैं। कच्चे निर्माण के कारण ये पुल-पुलिया बार-बार टूटते-गिरते हैं। बार-बार टेंडर होते हैं। फिर बार-बार ये बनाए जाते हैं और मोटी रकम बार-बार अफसरों, इंजीनियरों की जेब में जाती है।

सरकारों को इससे कोई मतलब न कभी रहा, न अब है। उन्हें तो दल बदलने, सत्ता में बने रहने के रिकॉर्ड बनाने और नए-नए गठजोड़ करने से ही फुर्सत नहीं है।

पुल चाहे गंगा में बहें या गंडक में, सरकारों को इससे क्या लेना-देना?

बच्चे आज भी टूटी-फूटी नावों में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। बरातें तक नावों में गंगा पार कर रही हैं। कभी पूरी बरात हिलोरे खा रही है तो कभी दूल्हा-दुल्हन डूब में समा रहे हैं।

सरकार नीरो की तरह चैन की बंसी बजा रही है।

बिहार रोम की तरह जल रहा है। आज भी। अब भी।

इस आलेख पर सुझाव एवं प्रतिक्रिया देने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

उदासी से बचने के लिए जल्दी उठने की आदत डालें

क्या कोई भी काम करने के पहले आपके भीतर एक उदासी छा जाती है? काम करते हुए आप बेचैनी महसूस करते हैं। अपने काम पेंडिंग रखने की आदत पड़ गई है। क्या भूलने अधिक लगे हैं। फिर अपनी भूल छिपाने के लिए झूठ बोलने लगे हैं। क्या अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए कुतर्क करने लगे हैं। दूसरों पर शक करना, बातचीत करते हुए चिल्लाना, बदला लेने की वृत्ति बन जाना, अगर आपके भीतर ये आदतें उतर रही हैं, तो मानकर चलिए कि आप इसके परिणाम में निकम्मे होने जा रहे हैं। निकम्मेपन के दो मतलब हैं। पहला काम न करना और दूसरा वही और वैसा काम करना, जिसको आपने सही मान लिया है। ये भी एक नए तरह का निकम्मापन है जो आज लोगों में उतर आया है। और यदि इस पर सही समय पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो देर हो जाएगी और लोगों की नजर में आपकी छवि खराब होगी। इससे बचना हो तो दो काम किए जा सकते हैं। रात को समय पर सो जाएं ताकि सुबह सूर्योदय के साथ उठ सकें। और जब सूर्य उग रहा हो तो उसकी लालिमा के साथ उस पर जल चढ़ाएं। आपके जल की धारा से सूर्य का प्रकाश आपके भीतर उतरेगा। और आपके शरीर में जो आंतरिक परिवर्तन होंगे, वो इतने पॉजिटिव होंगे कि आप इन निगेटिव बातों से मुक्ति पा जाएंगे। • Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • भाजपा पहले की तरह काम करना चाहती है तो विपक्ष उसे अपनी ताकत दिखाने पर आमादा है...

जनादेश पर सरकार और विपक्ष की समझ में अंतर है

अभय कुमार दुबे
अम्बेडकर विवि, दिल्ली में
प्रोफेसर abhaydubey@aud.ac.in

सारी दुनिया इस समय भारत के मतदाताओं की राजनीतिक बुद्धि की प्रशंसा कर रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जनादेश दिया है, उससे भारतीय लोकतंत्र का खोया हुआ संतुलन लौट आया है। 2014 के बाद से विपक्ष कभी इतना मजबूत होकर नहीं उभरा। किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण केंद्र में गठजोड़ सरकार बनी। लेकिन वह भी कमजोर न होकर राजनीतिक स्थायित्व की संभावनाओं से भरपूर है। जाहिर है कि मतदाताओं ने अपना काम बखूबी किया। लेकिन क्या राजनीतिक दल इस जनादेश को सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं? क्या वे बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से अपनी राजनीति के विन्यास को नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सत्तारूढ़ एनडीए का नेतृत्व कर रही भाजपा और विपक्षी इंडिया का नेतृत्व कर रही कांग्रेस के पिछले एक महीने में सामने आए रवैए पर गौर करके इन सवालों का कुछ-कुछ जवाब पाया जा सकता है।

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस राजनीतिक रणनीति को लागू किया जा रहा है, उसके केंद्र में अंग्रेजी का शब्द 'कॉन्टिनुइटी' (निरंतरता) है, जिसे उसके पैरोकारों द्वारा बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है। वे आग्रहपूर्वक बताना चाहते हैं कि कुछ नहीं बदला है। वही प्रधानमंत्री हैं। थोड़े से मंत्रियों को छोड़कर वही मंत्री हैं। वही उनके मंत्रालय हैं। वही दावेदारियां हैं। सरकार का वही एजेंडा है, जो पिछले दस साल से चल रहा था। ऐसा लगता है जैसे भाजपा के लिए 4 जून का जनादेश घटित ही नहीं हुआ है। पार्टी के वैचारिक पितामह संघ ने महीने भर में कई बार बुलंद आवाज में उसे राजनीतिक परिस्थिति में हुए परिवर्तन का अहसास दिलाने की कोशिश की है। यह असंभव है कि भाजपा ने संघ की आवाज न सुनी हो। लेकिन वह दिखा यही रही है कि कुछ नहीं बदला है।

भाजपा के इस रवैए के पीछे एक समझ काम रही है। इसके मुताबिक उसकी सीटों में आई गिरावट का मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि चुनाव में हुई राजनीतिक बदइंतजामी है। अगर टिकटों के बंटवारे में कुछ होशियारी बरती जाती, अगर कार्यकर्ताओं की तरफ से सुस्ती न दिखाई जाती, कुछ नेताओं ने नासमझी वाले बयान न दिए होते और अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी को नियंत्रित कर लिया जाता तो 2019 के चुनाव परिणाम को दोहराया जा सकता था। अर्थात मोदी सरकार के खिलाफ किसी तरह की उल्लेखनीय एंटी-इनकम्बेंसी नहीं थी, इसलिए किसी विशेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है। राजनीतिक प्रबंधन को दुरुस्त करने से सब ठीक हो जाएगा।

दरअसल यही समझ उत्तर प्रदेश समेत उन प्रदेशों की पड़ताल-कमेटियों के काम में देखी जा सकती है, जिन्हें भाजपा ने सीटें कम हो जाने के कारणों का पता लगाने के लिए नियुक्त किया है। राजस्थान के वरिष्ठ नेता किरोड़ीमल मीणा के प्रदेश सरकार से इस्तीफे को इसी प्रबंधनमूलक रवैए के खिलाफ असंतोष के रूप में देखा जाना चाहिए।

रवैए पर गौर करना होगा...

क्या राजनीतिक दल जनादेश को सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं? क्या वे बदली हुई परिस्थिति के हिसाब से अपनी राजनीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा और कांग्रेस के पिछले एक महीने में सामने आए रवैए पर गौर करने पर इन सवालों का जवाब मिल सकता है।

वहीं कांग्रेस के रवैए पर विचार करने से पहली नजर में लगता है कि उसने बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को अपने नजरिए से समझकर विपक्ष की दावेदारी के लिए एक नई रणनीति बनाई है। ऐसा लगता है कि इस रणनीति के दो चरण हैं। पहले दौर में वह देश के सामने अपनी बढ़ी हुई ताकत का मुजाहिरा करना चाहती है। नई लोकसभा के पहले सत्र में उसने अपना दबदबा बनाकर दिखाया। अपनी बात एक के बाद एक भाषणों में (राहुल, महुआ, राजा, अखिलेश, बिमोल अकोईजम) असरदार तरीके से सुना दी, और प्रधानमंत्री जब बोले तो विपक्षी सांसद लगातार मणिपुर के लिए नारेबाजी करते रहे।

दूसरे चरण में विपक्ष अपनी संसदीय एकता को सड़क पर किए गए राजनीतिक हस्तक्षेपों से जोड़ेगा। यह प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नीट पर्चा-लीक के सवाल पर युवकों-छात्रों के साथ विपक्ष की आंदोलनकारी जुगलबंदी इसका प्रमाण है। अभी इस तरह के कई मौके आने वाले हैं। खुद सरकार अपनी अक्षमताओं और विफलताओं के कारण प्लेट पर रखकर इस तरह के अवसर विपक्ष को देने वाली है। अग्निवीर योजना और पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर मध्यवर्ग के आर्थिक असंतोष का सिलसिला कभी भी शुरू हो सकता है। खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान पश्चिमी यूपी के साथ मिलकर एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं।

बदले हुए हालात में केंद्र की नई सरकार को दो ऐसे मुकामों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो उसके भीतर ही मौजूद हैं। इनमें पहला है संघ परिवार, जिसके संगठनों ने कथित रूप से सरकार को अपना मांग-पत्र दे दिया है कि अगले बजट में वे क्या-क्या चाहते हैं। ऐसा दस साल में पहली बार हुआ है। खास बात यह है कि विपक्ष ने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, संघ के मांग-पत्र में कमोबेश वे सभी मुद्दे हैं।

दूसरा भीतरी मुकाम है जदयू और टीडीपी। इन दोनों ने प्रस्ताव पास करके हजारों करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संसद में जिस समय विपक्ष भाजपा और मोदी पर हमले कर रहा था, उस समय ये दोनों सहयोगी दल न विचलित लग रहे थे, और न ही उन्होंने तत्परता से सरकार का बचाव किया। वे मौजूदा सरकार में सहयोगी हैं। लेकिन अतीत की दो भाजपा सरकारों के कामों की जिम्मेदारी लेने के मूड में वो फिलहाल तो नहीं हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

वेब भास्कर

फ्रेंच पॉलीनिज़ा में दिखती है दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइल्डलाइफ

समुद्र की दुनिया में सबसे खूबसूरत वाइल्डलाइफ निहारने के ठिकाने चुनिंदा ही हैं। उनमें से एक है फ्रेंच पॉलीनिज़ा का यह इलाका। हर साल गर्मियों की पहली पूर्णिमा में हजारों की संख्या में लोग, पॉलीनिज़ा के इस फकारवा इलाके में डेरा जमा लेते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में शार्क मूंगे की चट्टानों के आसपास मंडराती हैं। कई तरह के समुद्री जीव दिखाई देते हैं। पारदर्शी और साफ पानी, खूबसूरत लैगून (पानी के उथले इलाके) इस जगह को और सुंदर बना देते हैं। प्रसिद्ध फोटोग्राफर पॉल ने यह तस्वीर मैक्सिको से तहीती जाते हुए अपने ड्रोन से खींची थी।

• तस्वीर साभार : Paul Nicklen

क्लाइमेट • इसकी मार खेती और उद्योगों पर पड़ेगी...

इकोनॉमी को खतरे में डालने लगा है बदलता पर्यावरण

अम्बिका हीरानंदानी
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
से एम-फिल
ambikahira9@gmail.com

भारत इस समय गंभीर आर्थिक चुनौती से जूझ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का साया उसके परिदृश्य पर गहराता जा रहा है। कभी-कभी होने वाली परेशानी का सबब बनने वाली हीट-वेव का अब लगातार आना एक बढ़ते खतरे को बता रहा है, जिसने न केवल पर्यावरण, बल्कि अर्थव्यवस्था के जटिल ढांचे को भी नया आकार दे दिया है। हाल के वर्षों में भारत ने भीषण गर्मी की घटनाओं को देखा। इसने कृषि, उद्योग और सामाजिक ताने-बाने पर अमिट निशान छोड़े हैं। 'नेचर' जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि जलवायु-परिवर्तन से प्रेरित घटनाओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को वर्ष 2050 तक 19% की आय की हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भी भारत को 22% की आय हानि का पूर्वानुमान है। क्लाइमेट-चेंज की तबाही अब दूरदराज के कोनों तक ही सीमित नहीं रह गई है; यह देश की आर्थिक जीवन-रेखा तक पहुंच गई है।

कृषि क्षेत्र- जो अक्सर जलवायु-परिवर्तन का सबसे पहला शिकार होता है- इस संकट में सबसे आगे है। भारत के किसान पहले ही मौसम की अनिश्चितताओं से परेशान थे और अब तो वे बढ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 2022 की हीट-वेव 122 साल के रिकॉर्ड में सबसे गर्म थी, जिसने गेहूं सहित अन्य प्रमुख फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया। ये नुकसान न केवल खाद्य-उपलब्धता को कमजोर करते हैं बल्कि कीमतों में भी वृद्धि करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। चावल, चीनी और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूती हैं, जिससे पहले से ही महंगाई से जूझ रहे परिवारों पर बोझ पड़ता है। 2022 में, भारत में 42.86 प्रतिशत वर्कफोर्स कृषि में जुड़ी थी, इसलिए हीट-वेव भारत की लगभग आधी आबादी की आजीविका को सीधे प्रभावित करती है।

लेकिन आर्थिक दुष्प्रभाव खेतों से कहीं आगे तक फैले हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे स्थिर-परिस्थितियों पर निर्भर उद्योग इससे तेजी से कमजोर होते हैं। मैकिन्से के अध्ययन के अनुसार, गर्मी से संबंधित व्यवधानों से उत्पादकता में भारी नुकसान हो सकता है। इससे आउटडोर वर्किंग-ऑवर्स के नुकसान से भारत को 2030 तक 250 अरब डॉलर या जीडीपी के 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। पहले ही तनाव में चल रही फैक्ट्रियों की क्षमताओं में कमी देखी जा रही है, क्योंकि गर्मी का तनाव श्रमिकों और मशीनरी दोनों पर समान रूप से असर डाल रहा है। भारत के विकास-पथ के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा-गहन क्षेत्र, बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग में वृद्धि और पहले से ही कम संसाधनों पर दबाव के कारण और अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भारत के विकास-एजेंडे की एक अहम कड़ी ऊर्जा-क्षेत्र ऐसे में खुद को एक दोराहे पर पाता है। अक्षय ऊर्जा में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, कोयले पर हमारी निर्भरता जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं के प्रति इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। भारत अपने बिजली-उत्पादन के लगभग 75% के लिए कोयले पर निर्भर है और हम अगले कई दशकों तक कोयले के खनन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वैसे-वैसे बिजली की खपत भी बढ़ती है, जिससे ऐसी स्थितियों के लिए तैयार न होने वाले पुराने बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ता है। बिजली की कमी औद्योगिक उत्पादन को पटरी से उतारने के साथ ही रोजमर्रा के जीवन को भी बाधित करती है, जिससे संकट और बढ़ जाता है।

भारत पर जलवायु-परिवर्तन का आर्थिक प्रभाव अब केवल दूर की बात नहीं, बल्कि कठोर वास्तविकता बन चुका है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत को इस चुनौती का सामना करने का संकल्प भी लेना होगा।

तात्कालिक आर्थिक व्यवधानों से परे, जलवायु-परिवर्तन के व्यापक निहितार्थ तो और भयावह हैं। बढ़ते तापमान से पानी की कमी दोहरा खतरा पैदा करती है। इससे एक तरफ कृषि-उत्पादकता को नुकसान पहुंचता है तो दूसरी तरफ शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ता है। कंपनियां इन जोखिमों से अवगत हैं, इसलिए घाटे को कम करने और काम जारी रखने के लिए उन्नत कूलिंग तकनीकों में निवेश करने के लिए बाध्य हो रही हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

नजरिया • आचरण व कार्यों का आत्मनिरीक्षण करके ही नकारात्मकता से बच सकते हैं

बाहरी शोर में अंतरात्मा की आवाज को अनसुना न करें

नंदितेश निलय
वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक
एवं लेखक
nanditeshnilay@gmail.com

'मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन किया है..' यह बात तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 15 जनवरी 2009 को दिए अपने विदाई भाषण में कही थी। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने एक प्रसिद्ध भाषण 'अ पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्शन्स' में अंतरात्मा को जगाने का आह्वान किया था और अपने भाषण का समापन कुछ यूं किया था, 'तो आइए हम खुद को एक नई तरह की राजनीति के लिए समर्पित करें- अंतरात्मा की राजनीति।'

अब अमेरिका की मौजूदा राजनीति में चल रहे आरोप-प्रत्यारोप को देखें। निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रम्प को गली में घूमने वाली लावारिस अनैतिक बिल्ली कह डाला तो ट्रम्प ने बाइडेन को बचकाना, कमजोर और बोलने में अक्षम करार दिया। भारतीय संसद में भी आक्षेप-पटाक्षेप की कमोबेश ऐसी ही स्थित ही। यह प्रश्न सब जगह उभर आता है कि क्या आज की दुनिया अंतरात्मा की आवाज समझती है? क्या नागरिकों के स्तर पर भाव को सुनने-समझने की शक्ति बची है?

हमारे आसपास ऐसी बहुत-सी घटनाएं घट रही हैं, जो हमसे कुछ कह रही हैं। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिसमें लोग अभी भी अंधविश्वास के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। नीट विवाद पर संस्थाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं तो लीक पेपर्स की फेहरिस्त भी लंबी है। प्रश्न यह है कि सिर्फ कानून बनाने से ही चीजें सुधरती हैं? क्या कोई कानून या संविधान ही यह निर्धारित करेगा कि मनुष्य कैसे बनें? वो 'वॉइस ऑफ कॉन्शन्स' (अंतरात्मा की आवाज) कुछ नहीं होती, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने कई बार किया। चलिए पहले यह समझ लें कि आखिर कॉन्शन्स होता क्या है? यह मनुष्य की एक तरह की आंतरिक क्षमता है जो अपरिवर्तनीय, जन्मजात और अविनाशी है और हम सभी के अंदर मौजूद है। दूसरे शब्दों में, कॉन्शन्स मनुष्य का सच्चा स्व है और मार्गदर्शन की एक किरण है। यह एक हमारा सच्चा भरोसेमंद साथी है और यह हमें आवाज देता है। यह आवाज महान दार्शनिक इमैनुएल कांट के शब्दों में 'रैशनल अथॉरिटी' और 'मोरल ऑब्लिगेशंस' की आवाज होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विवेक या अंतर्मन से कोई संदेश या सलाह सुनता है, महसूस करता है, तो उसे विवेक या अंतरात्मा की आवाज कहा जाता है।

लेकिन चुनौती यह है कि आज के व्यक्ति के आस-पास शोर बहुत है। वह सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा होता है और पैसा कमाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। वह भ्रम, अज्ञानता, स्वार्थ, लालच, विश्वास, धारणा, धर्म, जाति, अभिमान, शक्ति, हठधर्मिता, पालन-पोषण, दबाव और अन्य प्रलोभनों के शोर में बहरा हो चुका है और उस शोर के बीच में व्यक्ति को अंतरात्मा की आवाज बिलकुल ही नहीं सुनाई पड़ रही है। उसे 'क्राइसिस ऑफ कॉन्शन्स' है ही नहीं। वह अपने आपको नैतिक दुविधाओं में नहीं पा रहा है। वह सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास चाहता है और विकास के नाम पर असंवेदनशीलता के गर्त में जा चुका है।

तो आगे क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमने खुद के लिए कैसी छवि बनाई है या बनाने की इच्छा रखते हैं? राजनीतिक जिम्मेदारी हो या पारिवारिक, अंतरात्मा की आवाज सुनने की शक्ति तभी बढ़ती है जब व्यक्ति द्वारा गलत आदतों के चुनाव में कमी आती है। हमें अपने व्यवहार, अपने कार्यों का आत्मनिरीक्षण, चिंतन और मूल्यांकन करने के लिए कुछ समय चाहिए और यहां हमारा विवेक ही हमें मार्गदर्शन देता रहेगा। बशर्ते हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहें।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 10 जुलाई 2024

सबको सही संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय रूस यात्रा से न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिली है, युद्ध के खिलाफ और शांति के पक्ष में भारत का स्पष्ट रुख भी एक बार फिर प्रभावी ढंग से रेखांकित हुआ है।

दुनिया की नज़रें | पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर दुनिया भर में कितनी उत्सुकता थी इसका अंदाजा विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं से भी मिलता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस यात्रा पर अपनी निराशा जाहिर करते हुए इसे शांति प्रयासों को झटका तक बता चुके थे। अमेरिका ने भी यात्रा को लेकर अपनी चिंता जता दी। खुद पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति पूतिन के साथ बातचीत में इसका जिक्र किया कि उनके रूस आने पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।

पूतिन-मोदी : बेहतरीन केमिस्ट्री

स्वतंत्र विदेश नीति | मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखें तो यह कोई अचरज वाली बात भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का जोर इस बात पर रहा है कि भारत रूस से अपनी करीबी खत्म करे। भारत ने शुरू से ही यह स्पष्ट कर रखा है कि वह अपने राष्ट्रहित पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहेगा।

रूस में संदेह | इसके बावजूद यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम रूस नहीं गए थे। दोनों देशों के बीच होने वाली सालाना द्विपक्षीय शिखर बैठक भी 2022 के बाद से नहीं हो पाई थी। इससे रूस के कुछ हलकों में यह धारणा बनने लगी थी कि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रभाव में रूस से दूरी बनाए रखना चाहता है। पीएम मोदी की इस यात्रा के पीछे जहां द्विपक्षीय रिश्तों को संदेहों और अविश्वासों से मुक्त करने की बात थी, वहीं अंतरराष्ट्रीय हलकों में यह स्पष्ट संदेश भेजना था कि भारत को किसी तरह के दबाव के जरिए इस या उस पक्ष में झुकाना संभव नहीं है।

युद्ध हल नहीं | इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने के समझौते तो हुए ही, पीएम मोदी ने पूतिन के साथ बातचीत में पूरी बेबाकी से कहा, 'युद्ध के मैदान से कोई हल नहीं निकलता।' यह पीएम मोदी का वैसा ही बयान है जैसा दो साल पहले समरकंद में पूतिन से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया था कि 'यह युद्ध का दौर नहीं है'। यह खबर भी सुकून देने वाली है कि रूस ने भारत के आग्रह पर न केवल रूसी सेना के सपोर्ट स्टाफ के रूप में भारतीयों की नियुक्ति रोकना स्वीकार कर लिया है बल्कि नियुक्त किए जा चुके युवाओं को स्वदेश भेजने पर भी मान गया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की यह यात्रा सफल कूटनीति के एक उत्तम उदाहरण के रूप में याद रखी जाएगी।

इन दिनों

डॉलर का रेला

मृत्युंजय राय

चीन अपने विकास की यात्रा में जहां पहुंचा है, उसमें प्रवासी चीनियों की बड़ी भूमिका रही है। इन लोगों ने विदेश में जो कमाई की, उसका एक हिस्सा अपने वतन भेजते रहे। चीन में इससे निवेश हुआ, जिससे विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिली। बेशक, चीन की आर्थिक तरक्की के इसके अलावा और भी कई कारण हैं, मसलन- चीन सरकार की आर्थिक नीतियां, वहां के सरकारी बैंकों से उद्योगों को मिला रियायती कर्ज, विश्व व्यापार संगठन में उसकी एंट्री, लेबर कॉस्ट का कम होना और चीनी प्रांतों के बीच ग्रोथ तेज करने की प्रतिस्पर्धा। फिर भी चीन की ग्रोथ में प्रवासियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।

भारतीय प्रवासी भी देश में पैसे भेजने में सबसे आगे हैं। वित्त वर्ष 2024 में विदेश में रहने वाले भारतीयों ने अपने परिजनों के पास रेकॉर्ड 107 बिलियन डॉलर भेजे। यह लगातार दूसरा वित्त वर्ष है, जब उन्होंने 100 बिलियन डॉलर से अधिक रकम देश भेजी है। यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के जरिये 54 बिलियन डॉलर आए थे। प्रवासी जो पैसे भेजते हैं, उससे इकॉनमी में निवेश तो होता ही है, विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर भी बढ़ते हैं। वहीं, अगर विदेशी मुद्रा भंडार अच्छे स्तर पर होता है तो उससे रुपये को सहारा मिलता है।

ऐसी सूरत में वैश्विक हलचल बढ़ने के बावजूद संबंधित देश की मुद्रा में बड़ी गिरावट नहीं आती। इससे कच्चे तेल के आयात पर खर्च नियंत्रण में रहता है। कुछ साल पहले हम देख चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध के वक्त तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को किस तरह से प्रभावित किया था। आपको 2013 का वह वक्त भी याद ही होगा, जब रघुराम राजन को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था। उस वक्त रुपये में गिरावट की वजह से गंभीर चुनौती खड़ी हो गई थी। तब राजन ने अच्छे रिटर्न की पेशकश कर प्रवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा जुटाई और इस तरह से रुपये में गिरावट को रोकने में कामयाब हुए, जिससे इकॉनमी को स्थिरता मिली। अच्छी बात यह भी है कि प्रवासी भारतीयों से आने वाले फंड का स्रोत भी बदला है। पहले जहां इसमें खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों का योगदान अधिक होता था, वहीं अब अमेरिका इसका सबसे बड़ा जरिया बन गया है। वहां से आने वाली रकम की देश के कुल रेमिटेंस में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

बड़ी बात यह भी है कि दुनिया में प्रवासियों से सबसे अधिक रेमिटेंस पाने वाले देशों की लिस्ट में भारत पहले नंबर पर है। इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आने वाले वर्षों में भारत इस सिलसिले में नए रेकॉर्ड बनाए और इस तरह से प्रवासी देश की तरक्की में अपना योगदान करते रहें।

एकदा

सही रास्ता

एक बार शिष्य मोग्गल्लान ने बुद्ध से पूछा, 'भगवन क्या आपके सभी अनुयायी संसार के सभी दुखों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे?' बुद्ध ने कहा, 'वत्स! तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरा एक सीधा सा प्रश्न है- क्या, तुम राजगृह का रास्ता जानते हो?' मोग्गल्लान ने कहा, 'हां भगवन, मैं राजगृह का रास्ता जानता हूं, क्योंकि मैं राजगृह जा चुका हूं। मैं राजगृह में जाकर घूमा हूं और अच्छी तरह से परिचित भी हूं। यह जो सड़क यहां से जा रही है, राजगृह ही तो जाती है। चलते चलेंगे, तो आगे एक जंगल आएगा। जंगल खत्म होते ही राजगृह के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाएंगे।' यह सुनकर बुद्ध बोले, 'मोग्गल्लान! संभव है कि तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर कोई राही राजगृह पहुंच जाए और कोई राह भटक भी जाए और राजगृह तक न पहुंच सके।' बुद्ध की बातें सुनकर मोग्गल्लान ने कहा, 'गुरुदेव! मेरा काम तो बस राजगृह जाने का रास्ता बताने का था, सो मैंने बता दिया। अब जो उस रास्ते पर चलेगा, वह राजगृह अवश्य पहुंचेगा। बीच में ही जो भटक जाएगा, उसका क्या कर सकता हूं।' बुद्ध मुस्कराए और बोले, 'तुम्हारे प्रश्न का भी यही उत्तर है वत्स! सभी शिष्य, सभी अनुयायी संसार के दुखों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे अगर राह नहीं भटकेंगे। गुरु का काम सिर्फ रास्ता दिखाना है।' मोग्गल्लान को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह गदगद होकर बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वास्तव में गुरु और शिष्य के इस वार्तालाप का मतलब यही है कि कौन किस मंजिल को पाता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। गुरु के बताए मार्ग पर श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ने वाले को मुक्ति अवश्य मिलेगी।

Subrata Dhar

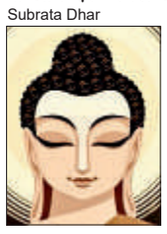

संकलन : **सुभाष चंद्र शर्मा**

विपक्ष को सम्मान दिए बगैर कोई भी संसदीय लोकतंत्र अपनी कामयाबी की कहानी नहीं लिख सकता

एतराज़ की राजनीति से नहीं बनेगी बात

अनिल सिन्हा

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब मणिपुर में थे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंच चुके थे। यह मौका भारतीय लोकतंत्र की दुनिया भर में बेहतर तस्वीर भी पेश कर सकता था, लेकिन विडंबना ही कहिए कि जहां कांग्रेस लोगों को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए बीजेपी के एक बहुचर्चित विज्ञापन की याद दिला रही थी, वहीं BJP राहुल के मणिपुर दौरे को राजनीतिक पर्यटन का उदाहरण करार दे रही थी।

गहराता संकट | यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के गहरे संकट की ओर इशारा करती है। पिछले पूरे दशक में टकराव की राजनीति इस तरह हावी रही है कि यह बुनियादी समझ ही लोगों के जेहन से निकल गई लगती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की अपनी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं।

विपक्ष की ज़िम्मेदारी | इस बार के चुनाव परिणामों ने विपक्ष को सिर्फ बुलंद आवाज में अपनी बात रखने लायक संख्याबल ही नहीं दिया है, बल्कि नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने वाले विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद भी दिया है। पिछले 10 साल से विपक्ष इस ताकत से मरहूम था। इससे स्वाभाविक ही उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। लेकिन टकराव की जैसी स्थिति स्थिति बन चुकी है, वह संवाद कायम होने में बड़ी बाधा साबित हो रही है।

कौन करेगा पहल | चुनाव के बाद संसद के पहले ही सत्र में जिस तरह का टकराव दिखा, उससे यह अंदेशा गहराता है कि दोनों पक्षों की दूरी और बढ़ती ही न जाए। मौजूदा हालात को बदलने के लिए एक बड़ी राजनीतिक पहल की जरूरत है। कायदे से यह पहल सत्ता पक्ष को करनी चाहिए। लेकिन वह इसके लिए भी तैयार नहीं दिखता कि विपक्ष की तरफ से सौहार्द्र के संकेत ग्रहण कर सके। वैसे विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को ऐसी पहल के लिए प्रेरित करने लायक कोई बड़े संकेत नहीं दिए हैं।

सोच बदलनी होगी | विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हाथरस के हादसा पीड़ितों या मणिपुर के हिंसा पीड़ितों से मिलने जाने को लेकर सत्ताधारी BJP का ऐतराज भी एक संकीर्ण सोच का उदाहरण है। लोकतंत्र में सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। आदर्श लोकतंत्र की कल्पना यही है कि किसी भी फैसले में हर नागरिक की हिस्सेदारी हो। और राहुल गांधी तो अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। उन्हें पूरे विपक्ष की आवाज बनने की संवैधानिक जिम्मेदारी मिली हुई है। वह भारत सरकार का हिस्सा हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में, अगर वह मणिपुर में शांति स्थापना का प्रयास करते हैं तो इसे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर से की गई एक पहल के रूप में क्यों नहीं देखा जा सकता? सत्ता पक्ष का इस सोच से निकलना जरूरी है कि विपक्षी पार्टियों का विरोध देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश होती है।

AI Images

पक्ष-विपक्ष में टकराव

- संसद में दोनों पक्षों में संवाद की कमी
- हर बात पर एतराज करने की प्रवृत्ति
- बजट सत्र पर लगी हैं सबकी निगाहें

लोकतंत्र पर असर | यह समझना जरूरी है कि विपक्ष को नकारने से लोकतंत्र के स्वरूप पर क्या असर होता है। हम इसे पिछली लोकसभा में देख चुके हैं। करण चाहे जो भी हो , लेकिन यह तो तथ्य है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री का बयान पाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा। ऐसी स्थितियां लोकतंत्र को विकृत करती हैं। अगर हालात टकराव वाले नहीं होते तो यह काम संसद में एक प्रस्ताव से हो सकता

उम्मीदों पर चोट | क्या संवादहीनता की स्थिति खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं बची है? इस सवाल पर जाने से पहले यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। चाहे जैसे भी हालात हों, सभी पक्ष ठान लें तो किसी भी पल हालात बेहतर होने शुरू हो सकते हैं। लेकिन व्यवहार में फिलहाल इस तरह के आसार नहीं दिखाई दे रहे, यह मानना ही होगा। संसद सत्र की शुरुआत ही तू-तू मैं-मैं से हुई है। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका भी विपक्ष की आलोचना के दायरे में आ चुकी है। ऐसे में उनके बीच-बचाव करके रास्ता निकालने की गुंजाइश भी कम ही है।

तालमेल की ज़रूरत | इसी 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। सरकार को बेरोजगारी, महंगाई से लेकर देश की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर ध्यान लगाना है। कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। ऐसे में, सत्ता पक्ष और विपक्ष विरोध के बीच भी कुछ संवेदनशील मसलों पर आपसी तालमेल दिखाएं तो देश के लिए कई बड़ी चुनौतियों से जूझना आसान हो सकता है।

अतीत से सबक | अच्छी बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र का गौरवपूर्ण अतीत ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जब दोनों पक्षों ने देश हित से जुड़े मसलों पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने का माद्दा दिखाया है। दोनों पक्षों -सत्ता पक्ष और विपक्ष- की ओर से बड़ा दिल दिखाने के ऐसे कई उदाहरण यहां भी गिनाए जा सकते हैं। दिक्कत यह है कि वे सारे उदाहरण पहले के हैं। पिछले एक दशक के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जिसे निर्विवाद रूप से राजनीति के बड़प्पन की मिसाल के रूप में पेश किया जाए। क्या बजट सत्र हमें चौंकाएगा? जवाब के लिए बजट सत्र का ही इंतजार करना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी साल

2024 वैश्विक चुनावी वर्ष है। इस साल दुनिया के 78 देशों में 83 चुनाव हो रहे हैं। इनमें दुनिया की 60 फीसदी आबादी रहती है। ऐसा संयोग फिर 2048 में बनेगा। इन चुनावों में कई रुझान दिख रहे हैं तो कई तरह की चिंताएं भी। आइए समझते हैं कि कैसे ये दुनिया का रास्ता बदल रहे हैं :

लहर और मूड

- अपवादों को छोड़कर सरकार दोबारा लाना लोग नुकसानदेह मान रहे हैं।
- सत्ता में बैठे नेताओं के प्रदर्शन से लोग खुश नहीं।

लोग बुनियादी जरूरतों के लिए सरकारों से जवाब चाहते हैं।

आर्थिक मुद्दे लोगों का मूड बदल रहे।

लोकतंत्र की चिंताएं

दुनिया के प्रमुख देशों में दक्षिणपंथी हावी।

जलवायु समस्या नेताओं और मतदाताओं के अजेंडे से गायब।

भारत-अमेरिका सबसे अधिक चुनावी खर्च करने वाले देश।

चुनावी मुद्दे

युद्ध, विस्थापन और शरणार्थी।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन।

रोजगार और आर्थिक स्थिरता।

इन पर है नज़र

अमेरिका

- अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में होना है।
- अभी तक रुझानों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे।
- यह चुनाव दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

फ्रांस

दूसरे चरण के चुनाव में वामपंथी गठबंधन को अभूतपूर्व बढ़त मिल गई।

पहला चरण 20.7% मैक्रों की पार्टी

33.1% नैशनल रैली 28% वामपंथी गठबंधन

पहले चरण में आगे थी दक्षिणपंथी पार्टी

(स्रोत-IDEA, प्यू रिसर्च, BBC, Al jazeera, रशिया टुडे, Time, NPR)

कंटेंट: राहुल पाण्डेय
ग्राफिक्स: अर्जुन सिंह

प्रमुख देशों की चुनावी लिस्ट

दक्षिण अफ्रीका **मई-अगस्त** 60.7M

अल्जीरिया **दिसंबर** 46M

मोजाम्बिक **अक्टूबर** 34.4M

वेनेजुएला **दिसंबर** 29.1M

घाना **दिसंबर** 34.4M

उज्बेकिस्तान | अक्टूबर-दिसंबर | 35.4M

जनसंख्या

चुनाव यहां हो चुके

ब्रिटेन

- 4 जुलाई को लेबर पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। 14 साल का कंजर्वेटिव शासन समाप्त।
- महंगाई और आर्थिक मंदी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे।

पाकिस्तान

- इमरान खान की पार्टी चुनाव से दूर रही, पर समर्थकों को जनता ने पसंद किया।
- सेना की मदद से नवाज की पार्टी ने बहुमत हासिल किया।

भारत

- बीजेपी की अगुवाई में NDA की सरकार बनी।
- मोदी के आलोचक अब जोर-शोर से आवाज उठा रहे हैं।

रूस

- रिकॉर्ड 87.97% वोट के साथ व्लादिमीर पूतिन फिर से जीते।
- यूक्रेन के कब्जा किए इलाके में भी चुनाव जीते पूतिन।

लोकतंत्र के खतरे

- मतदाता लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति से नाखुश।
- अमेरिका समेत 11 देशों में चुनावी निष्पक्षता पर संदेह।
- जमकर चल रहा डीपफेक। लगभग सभी देशों पर असर।
- नेताओं को लेकर बने फेक मीम और एआई से बनी फर्जी तस्वीरें डाल रही हैं असर।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

किसी को जानने के लिए उसकी हंसी काफी है

निर्मल जैन

हंसते हुए जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उनका गुणगान हर तरफ होता है। जीवन की कठिन राहों पर गाते-गुनगुनाते गुजरना उन्हें बेहतर ढंग से आता है। ऐसे लोग गुलाब के फूलों की तरह कांटों के बीच भी मुस्कुराना जानते हैं। तभी तो संत कबीर कह गए हैं, *'ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोवे।'* हर समय हमारा प्रयास यही रहे कि मुश्किल पलों को हंसी और आल्हाद के सुनहरे पलों में बदलते रहें। हंसने, मुस्कुराने की कोई उम्र नहीं होती और न ही इसके लिए कोई अवसर होता है।

अक्सर देखा गया है, एक साधारण-सा मजदूर मेहनत-मशक्कत करता हुआ हंसी का असीमित भंडार आसानी से समेटता रहता है। हंसी न खरीदने-बेचने की वस्तु है, न किसी से दान में प्राप्त की जा सकती है। इसे उपासना करके भी नहीं हासिल किया जा सकता है और न ही संतों के उपदेश में यह मिलती है। हंसी का फव्वारा हमारे अंदर ही फूटता है। जिस तरह से सूर्य की किरणों से कमल खिल उठता है, वैसे ही सहज और स्वाभाविक शांत मन में हंसी का झरना फूटता है। किसी विद्वान ने खूब कहा है कि अगर आप किसी इंसान की आत्मा के अंदर झांकना चाहते हैं और उसे जानना चाहते हैं, तो आप उसे हंसते हुए देखें। आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। अगर वह अच्छी तरह हंसता है, तो वह एक अच्छा इंसान है।

निश्चित रूप से जीवन जीना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है हंसते हुए जीना। जो खुलकर हंसता है वह दीर्घायु होता है। वह अपने नजरिए से हर तरफ अच्छाई ही देखा करता है। निष्काम हंसी कड़वाहट का मैल धोकर सुगंधित वातावरण का निर्माण करती है। प्रसिद्ध जीवन शास्त्री लिन यू तंग का कहना है, यह जिंदगी संघर्षों से भरी हुई है। उसमें एक के बाद एक खींचतान लगी रहती है। वे क्षण बहुत कीमती होते हैं जो जीवन को गुदगुदा दें और हंसने पर मजबूर कर दें, क्योंकि हंसना खुशियों का खजाना है। वह आदमी निर्धन नहीं है, जो खुलकर हंस सकता है। संसार में रुदन तो सबके पास है। यदि दूसरों को कुछ देना चाहें तो हंसी से बड़ा दान कुछ नहीं है।

अगर हमें हंसना नहीं आता तो हमारा चेहरा पेड़ की डाली पर उस कली की तरह है, जो फूल बनने से पहले ही मुरझा जाती है। कोई कैसे भी हमें अपमानित क्यों न करे, अगर हमारे पास हास्य का माधुर्य घोलने की कला है, तो हम दुख के क्षणों को भी सहज आनंद में बदल सकते हैं। सात्विक हंसी अंतरंग की सही पहचान हुआ करती है। निर्दोष हंसी ठीक वैसी ही है, जैसे अस्थिदान करते समय दधीचि के अधरों पर रही होगी, विष का प्याला पीते हुए सुकरात के चेहरे पर खेलती होगी। बुद्धि सदा ही हृदय पर भारी पड़ती रही है। इन दिनों हम जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान हो गए हैं, तभी तो उन्मुक्त हंसी जैसे अनुपम खजाने से वंचित होते जा रहे हैं।

हंसें अवश्य, पर ध्यान रहे कि वह कैकयी और मंथरा की कुटिल हंसी न हो, अहंकार में चूर किसी का अपमान करने वाली हंसी न हो। अलग-अलग भाषा, संस्कृति के साथ जीने पर भी पूरा विश्व एक जैसा ही हंसता है। इसकी वजह है कि हंसी सब जगह एक ही है। हंसी एक दवा है। जब हम अपने दिल की गहराई से खुश होकर हंसते हैं, तो ईश्वर को भी प्रसन्नता होती है।

क्या हुआ कि चांदी इस कदर भाव खाने लगी

मधुरेन्द्र सिन्हा

सोने ने अपनी चमक दिखाई और सारी दुनिया को चकाचौंध किया। अब बारी है चांदी की। इसकी डिमांड सदियों से रही है भारत में। वक्त के साथ चांदी की कद्र कम हो गई और सोना मुख्य धातु बन गया। लेकिन, बढ़ते दामों ने गोल्ड को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया, जबकि चांदी उसका सहारा बनी रही। हालांकि अब चांदी भी एक लाख रुपये प्रति किलो की ओर जा रही है। दिल्ली के सर्राफा बाजारों में इसका रेट टैक्स सहित 90 हजार रुपये प्रति किलो हो गई है।

खरीदारी हुई कम | इस समय खुदरा ग्राहक नहीं आ रहे। इसका मुख्य कारण है कि कीमत पहले की तुलना में ज्यादा है, शादी-ब्याह का सीजन नहीं है और ग्राहकों की रुचि भी नहीं है। दिल्ली के सदर बाजार सर्राफा असोसिएशन के चेयरमैन कैलाश चंद खंडेलवाल बताते हैं कि पहले गरीब से गरीब आदमी भी दिवाली पूजन वगैरह के लिए चांदी ले जाता था, लेकिन पिछले तीन वर्षों से यह क्रम टूट गया है।

औद्योगिक इस्तेमाल | दिल्ली के कूचा महाजनी सर्राफा असोसिएशन के महासचिव सुशील जैन चांदी के बढ़ते दामों पर कहते हैं कि हाल के बरसों में इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। स्मार्टफोन, टैबलेट्स, फोटोवोल्टेक सेल, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों से लेकर मोबाइल फोन, गुटका, तंबाकू - सभी में इसका इस्तेमाल होता है। कुछ मेडिकल उपकरणों में भी चांदी यूज हो रही है। इन उद्योगों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि 2024 के पहले चार महीनों में ही भारत ने 2023 के बराबर यानी 4,172 मीट्रिक टन चांदी का आयात कर लिया।

सटोरियों का खेल | कैलाश चंद खंडेलवाल कहते हैं कि सोने की तरह चांदी भी बाहर से आती है, इसलिए इसकी कीमतों पर कोई अंकुश नहीं है। विदेश में बैठे बड़े सटोरिये इसकी कीमतें ऊपर-नीचे करते रहते हैं। जियोजीत फाइनैंशल सर्विसेज के हेड हरीश वी कहते हैं कि बड़े खिलाड़ियों द्वारा चांदी की आक्रामक खरीदारी जारी रहेगी, जिससे कीमतें और बढ़ सकती हैं।

अभी सुधार नहीं | इस समय राजधानी ही

AI Image

कॉमन रूम

नहीं, देश के अन्य भागों में भी चांदी की बिक्री में ग्रहण लग गया है। सुशील जैन कहते हैं कि दिल्ली के सबसे बड़े सर्राफा बाजार कूचा महाजनी में चांदी की दुकानों पर सन्नाटा है। यह हालत पिछले कुछ महीनों से है। ग्रामीण मांग भी फिलहाल ठहर गई है। बिक्री में अभी तुरंत सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती, क्योंकि डर है कि चांदी एक लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है।

ज्यादा खरीद से बचें | बाजार में हर चीज तेज है तो चांदी कैसे पीछे रह सकती है। ग्राहक सोने की तरह भविष्य के लिए चांदी खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि एमसीएक्स में इसके दाम ऊपर-नीचे जा रहे हैं। इसकी कीमतें अस्थिर हैं और कल क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। चांदी सभी तरह के मेटल में कीमतों की दृष्टि से अस्थिर है। फिर भी एक्सपर्ट मानते हैं कि यह अभी तुरंत गिरेगी नहीं। फिलहाल कीमतें ऊपर हैं। ऐसे में ज्यादा खरीदारी नुकसानदेह भी हो सकती है। अतीत में एक बार ऐसा हो चुका है कि सोने-चांदी के दाम एक ही दिन में धड़ाम हो गए, जिससे कारोबारियों को भारी घाटा उठाना पड़ा और कइयों का तो दिवाला निकल गया था।

चीन फैक्टर | चांदी की कीमतें बढ़ने का एक बड़ा कारण है चीन। दुनिया के सबसे बड़े इस औद्योगिक देश में चांदी का इस्तेमाल जमकर हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हों अथवा ईवी की बैटरी या फिर सोलर लाइट्स। इसलिए चीन पिछले पांच वर्षों से हर महीने औसतन 390 टन चांदी खरीद रहा है। इससे भी विश्व बाजार पर काफी असर पड़ा है। चीन में जो लोग गोल्ड नहीं खरीद पा रहे, वे भी चांदी ले रहे हैं। गोल्ड खरीदने के मामले में भी चीन दुनिया में नंबर वन है।

(लेखक सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं)

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 10 जुलाई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

आलस्य वह रोग है, जिसका रोगी कभी नहीं संभलता।
-मुंशी प्रेमचंद

नीट पर 'सुप्रीम' सुनवाई

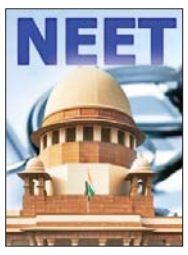

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 की शुचिता 'नष्ट' हो गई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एक बात स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नीट-यूजी अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस बीच, सोमवार को सीबीआई ने नीट-यूजी में कथित हेरफेर करने के आरोप में महाराष्ट्र के लातूर में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी को जांच की स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई के दिन अदालत के समक्ष पेश करने को भी कहा है। सीबीआई कदाचार, 'ओएमआर' सीट में हेरफेर, अभ्यर्थी के बदले किसी अन्य के परीक्षा देने और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रही है। नीट-यूजी परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितता उजागर होने के बाद अभ्यर्थी और उनके परिजन सड़क पर उतर आए और उन्हें कुछ राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। वे री-नीट की मांग कर रहे थे यानी नये सिरे से परीक्षा कराने की मांग पर अड़ गए। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच गया। उसके बाद विरोध प्रदर्शनों का शोर थमा लेकिन छिटपुट प्रदर्शन होते रहे। सभी को उम्मीद बंध गई थी कि शीर्ष अदालत उनके साथ न्याय करेगी। अब जिस प्रकार से शीर्ष अदालत ने सवाल किए हैं, और रिपोर्ट तलब की हैं, उससे लगता है कि शीर्ष अदालत दोटूक फैसला देने से पहले हर पक्ष और पहलू को जान लेना चाहती है। शीर्ष अदालत ने पुनः परीक्षा के आदेश की बाबत कानून स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच करनी होगी कि क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ है, क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित किया है और क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां उल्लंघन पूरी परीक्षा को प्रभावित करता है और लाभार्थियों को दूसरों से अलग करना संभव नहीं है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना आवश्यक हो सकता है। चूंकि पेपर लीक जंगल की आग की तरह फैला है, इसलिए लाभार्थियों और दोषियों की पहचान आसान नहीं होगी। अब अगली सुनवाई पर अदालत के रुख पर सभी की नजरें हैं।

आतंकवाद के विरुद्ध

जम्मू के कठुआ में सोमवार को सेना के गश्ती दल पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें पांच जवान शहीद हो गए। एक महीने के भीतर कठुआ में दूसरी बार आतंकी हमला हुआ है जो सरकार, सुरक्षा बल और प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। पिछली कुछ आतंकी घटनाओं का ट्रेंड बता रहा है कि दहशतगर्दों ने अपनी रणनीति में बदला किया है। अब जम्मू और विशेषकर कठुआ आतंक का नया गढ़ बनता दिख रहा है। हालांकि जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के शुरुआती दिनों में यह इलाका आतंकवादियों का अच्छा खासा ठिकाना बन गया था। लेकिन सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान चलाकर कठुआ और उसके आसपास के इलाके को आतंक से मुक्त करा लिया था। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन बहाल हो रहा था लेकिन जब से विधानसभा चुनाव की आहट तेज हुई है, अचानक आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं। हाल के महीनों में आतंकियों ने सीमावर्ती जिले पूंछ, राजौरी, डोडा और रियासी में एक के बाद एक हमले किए हैं। अब आतंकी घाटी की ओर से जम्मू की ओर रुख करने लगे हैं। इसकी बड़ी वजह कठुआ की प्रकृति और बनावट है। यह क्षेत्र पहाड़ियों और घनघोर जंगलों से भरा-पूरा है और इसके एक ओर पाकिस्तान की सीमा लगती है और दूसरी ओर पंजाब और हिमाचल है। सीमा पार से आने वाले आतंकवादी वारदात को अंजाम देकर जंगलों के रास्ते पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। इस जिले की जनसांख्यिकी भी कश्मीर घाटी से अलग है। यहां हिन्दुओं की आबादी अधिक है। ऐसा हो सकता है कि चुनाव से पहले सांप्रदायिक माहौल खराब करना भी पाक प्रायोजित आतंकवादियों का एक राजनीतिक लक्ष्य हो। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि रियासी में इसी इरादे से श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया गया हो। यह कहा जाता है कि आतंकवाद की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। देखा गया है कि कभी-कभी यह एक समय बाद स्वतः ही खत्म हो जाता है। लेकिन कश्मीर में जारी आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान की बड़ी भूमिका से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। शायद इसलिए भी यहां आतंकवाद लंबे समय से जीवित है। अब यह देखने वाली बात होगी कि यहां आतंकवाद के विरुद्ध जारी निर्णायक युद्ध में केंद्र सरकार का पाकिस्तान के प्रति क्या रुख रहता है।

हिन्दी का विस्तार/प्रमोद भार्गव

बिहार और एमबीबीएस की पढ़ाई

बिहार सरकार हिन्दी में चिकित्सा शिक्षा में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम अगले सत्र से शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद इस तरह की पहल करने वाला बिहार दूसरा राज्य है। हिन्दी को वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करने में ऐसे उपाय लाभदायी होंगे। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि बिहार में हिन्दी माध्यम से पढ़ाई कराने वाले जो 85 हजार सरकारी विद्यालय हैं, उनसे पढ़ कर आने वाले छात्रों को चिकित्सा शिक्षा हासिल करने का अवसर मिल जाए।

एमबीबीएस की हिन्दी माध्यम से पढ़ाई सामाजिक न्याय के साथ समाज को भाषायी धरातल पर उन्नत और विकसित करने की बड़ी पहल है। विश्व के ज्यादातर देश अपनी मातृभाषाओं में चिकित्सा, अभियांत्रिकी एवं अन्य विज्ञान विषयों की पढ़ाई कराते हैं। रूस, चीन, यूक्रेन में जाकर जो बच्चे एमबीबीएस करके आते हैं, उन्हें पहले एक वर्ष इन देशों की मातृभाषा ही पढ़ाई जाती है। जापान और जर्मनी में भी यही पद्धति लागू है। जिस तरह से दूसरे विकसित देशों में ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में शोध एवं आविष्कार अपनी भाषाओं के माध्यम से होते हैं, भारत में भी कालांतर में यह स्थिति बन जाएगी। अभी तो हालात ये हैं कि एमबीबीएस और इंजीनियरिंग में जो छात्र मातृभाषाओं में पढ़कर आते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आने के कारण मानसिक प्रताड़ना की ऐसी स्थिति से गुजरना होता है कि वे आत्महत्या करने तक को विवश हो जाते हैं। दिल्ली एम्स में अनिल मीणा नाम के एक छात्र ने सुसाइड नोट में यह लिख कर आत्महत्या की थी कि मेरी समझ में अंग्रेजी नहीं आती है, और शिक्षक और मेरे सहपाठी मेरी मदद भी नहीं करते हैं।

आईआईटी जैसे संस्थानों में भी कस्बाई इलाकों से आने वाले छात्रों को ऐसे ही हालात से दो-चार होना पड़ता है। अतएव देर आयद, दुरुस्त आयद कहावत चिकित्सा शिक्षा में भी लागू होती है। वैश्वीकरण के दौर में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की अवधारणा महत्त्वपूर्ण है। अक्सर कहा जाता है कि हिन्दी के पास शब्द सामर्थ्य कम है जबकि हकीकत यह है कि हिन्दी के शब्दकोश में सात लाख शब्दों का भंडार है, और संस्कृत में बीस लाख शब्दों का।

सतर्क रहें निवेशक

सेंसेक्स में उछाल

प्रो. लल्लन प्रसाद

बीएसई सेंसेक्स पहली बार पिछले सप्ताह 80,000 के पार पहुंचा, 5,000 अंकों की बढ़त में मात्र 57 दिन लगे। 1990 से शुरू हुए सेंसेक्स में तीसरी बार इतनी बड़ी बढ़त हुई है जिसे लेकर जहां शेयर धारकों में उल्लास का वातावरण है वहीं सेबी के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। इस वर्ष सेंसेक्स में अब तक 10% की तेजी हो चुकी है, 29 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये के ऊपर चला गया है। देश में अब कुल 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक मार्केट कैप वाली 101 कंपनियां हैं, 2023 में इनकी संख्या 74 थी।

सेंसेक्स में इतनी बड़ी तेजी को लेकर मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ ने कहा है कि ऐसी घटनाएं नियामक प्राधिकरणों के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती हैं कि जीत के जश्न के बीच हर कोई अपना संतुलन और धैर्य बनाए रखे। बाजार नियामकों -सेबी (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड) एवं सैट (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण) को सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि इनकी नींव की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। विगत वर्षों में शेयर बाजार में लेन-देन में भारी बढ़त होने के कारण सेबी और सैट, दोनों के कार्यभार बढ़े हैं। साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी। सैट के और नये पीठ खोलने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। निवेश के लिए स्थिर और विश्वसनीय माहौल राष्ट्रीय महत्त्व का विषय है। जब निवेशक आश्वस्त महसूस करते हैं कि उनका निवेश कानून द्वारा संरक्षित है, और विवादों के समाधान के लिए प्रभावी तंत्र है, तो पूंजी बाजार में निवेश की अधिक संभावना होती है जो इस समय देखी जा रही है।

सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं-वही शक्तियां जो दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं। सेबी तीन श्रेणियों के आवश्यकता की पूर्ति करता हैः 1) ऐसा बाजार उपलब्ध कराना जिसमें निवेशक अपना वित्त बढ़ा सकें, 2) बाजार के बारे में सही और सटीक जानकारी सुनिश्चित करना, तथा 3) बिचौलियों के लिए प्रतिस्पर्धा और पेशेवर बाजार को सक्षम करना। बाजार अपराधियों से भरा होता है। इसके चलते सख्त कार्रवाई और गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। वैधानिक प्रवर्तन शक्तियां, जो सेबी को दी गई हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में भी अधिक हैं ताकि आर्थिक क्षति के लिए दंड की व्यवस्था प्रभावी हो।

सैट भी वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत सेबी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और

निपटारे के लिए की गई है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील भी सैट में की जा सकती है। 1997 से अब तक सैट ने 67,000 अपीलों पर अपने निर्णय दिए हैं, 1,028 अपील अभी लंबित हैं।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य घटना है, जो होती ही रहती है। कभी-कभी बढ़ोतरी या गिरावट बहुत तीव्र होती है, जो निवेशकों को तेजी से आकर्षित करती है, या उनकी पूंजी डुबो देती है। इसके अनेक कारण हैं-देश की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति, सरकार एवं केंद्रीय बैंक की अर्थ एवं वित्त नीति, कंपनियों में लगी पूंजी और लाभ, जीडीपी, मुद्रास्फीति, व्याज दर, बेरोजगारी, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाए गए कदम, युद्ध, सप्लाई श्रृंखला में बाधा, अराजकता आदि सभी शेयर बाजार को प्रभावित करते हैं। इन पर सेबी का कोई नियंत्रण नहीं होता। बड़े निवेशकों एवं बिचौलियों द्वारा हेराफेरी जब शेयर मार्केट को प्रभावित करती हैं, तब सेबी की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप एवं बिजनेस न्यूज चैनलों पर स्टॉक टिप्स सहित सूचनाओं की लगातार बमबारी हो रही है, सीधे-साधे निवेदक कभी-कभी इससे खतरनाक जाल में फंस जाते हैं, और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। शेयर बाजार में भारी संख्या में निवेशक घाटे में रहते हैं। पेनी स्टॉकों में निवेश कराने, इंट्रा ट्रेड और कम समय वाले कारोबार में शामिल कराने, जल्दबाजी में निर्णय कराने, अफवाह फैलाने जैसे हथकंडे बिचौलियों द्वारा अपनाए जाते हैं, जिन पर नियंत्रण आवश्यक है। शेयर धारकों की बेसब्री भी उनके लिए महंगी पड़ती है, गिरते बाजार में बिना सोचे-समझे भारी बिकवाली इसका एक उदाहरण है। कई बार बहुत थोड़े समय में बाजार में फिर से तेजी आ जाती है। ऐसी स्थिति में शेयर धारक अपने निर्णय पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कोरोना महामारी के शुरू होते शेयर बाजार तेजी से नीचे आया किंतु 11 महीनों के बाद ही फिर ऊंचाइयां छूने लगा। गिरते बाजार में जिन लोगों ने भारी खरीदारी की बाद में उनकी पूंजी में खूब वृद्धि हुई, जिन लोगों ने जल्दबाजी में बेच दिया घाटे में रहे।

विश्व के महानिवेशक वारेन बुफे का कहना है कि शेयर बाजार बेसब्री से सब्र करने वालों को धन हस्तांतरित करने का एक उपकरण है। समय-समय पर शेयर बाजार में बड़े घोटाले के समाचार आते हैं। भारतीय शेयर बाजार का कुल मार्केट कैप 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है जहां इतना पैसा रोज एक दूसरे के पास आता जाता है, लालच, घोटाले, धोखाधड़ी करने वाले को अवसर मिल ही जाता है। हर्षद मेहता, केतन पारिख, सत्यम आदि घोटाले बड़े पैमाने पर निवेशकों को चूना लगा चुके हैं। बाजार नियामकों-सेबी, सैट आदि की सतर्कता और हस्तक्षेप ऐसी स्थितियों को कुछ हद तक नियंत्रण में ला सकते हैं। शेयर बाजार के बारे में सही समाचार निवेशकों तक पहुंचें और बिचौलिये निवेशकों को गुमराह न कर सकें, इसके लिए सेबी प्रयत्नशील रही है। फिर भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सैट द्वारा अपीलों का निपटारा भी कम समय में हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, सैट की पीठों की संख्या बढ़ाई जाए, तथा उन्हें और सक्षम किया जाए।

हर्षद मेहता, केतन पारिख, सत्यम आदि घोटाले बड़े पैमाने पर निवेशकों को चूना लगा चुके हैं। बाजार नियामकों-सेबी, सैट आदि-की सतर्कता और हस्तक्षेप ऐसी स्थितियों को कुछ हद तक नियंत्रण में ला सकते हैं। शेयर बाजार के बारे में सही समाचार निवेशकों तक पहुंचें और बिचौलिये निवेशकों को गुमराह न कर सकें, इसके लिए सेबी प्रयत्नशील रही है। फिर भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सैट द्वारा अपीलों का निपटारा भी कम समय में होना चाहिए

तेजी से बढ़ रहा है 'ऑफिस पीकॉकिंग' का चलन

- कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बाद कर्मचारियों को संस्थान में बनाए रखने और उन्हें कार्यालय में वापस लाने के लिए कई कंपनियां 'ऑफिस पीकॉकिंग' का सहारा ले रही हैं
- 'ऑफिस पीकॉकिंग' में कार्यालयों में आकर्षक फर्नीचर, सजावट, आरामदायक कार्यस्थल, प्राकृतिक रोशनी, खानपान की अच्छी व्यवस्था आदि जैसे उपाय किए जाते हैं
- पिछले दो-तीन वर्षों में 'ऑफिस पीकॉकिंग' के चलन में खासी वृद्धि हुई है, और बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद जैसे महानगरों में इसका चलन अधिक है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

सैटेलाइट से ली गईं तस्वीरों से पता चलता है कि चीन पैंगांग लेक क्षेत्र में युद्ध में सहायक निर्माण कर रहा है। इनसे यह भी पता चलता है कि लद्दाख से अरुणाचल तक भारतीय सीमा से सटे क्षेत्र में वह युद्ध में सहायक हो सकने वाले भूमिगत निर्माण भी कर रहा है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

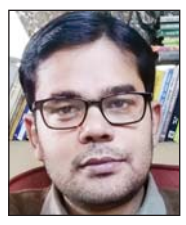

जनजागरण के रहे प्रतीक

भिखारी ठाकुर | पंकज चौबे

भिखारी ठाकुर को याद करने का यह सही समय है। समाज कई तरह के बदलावों के दौर से गुजर रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हम सशक्त हुए हैं, जिसमें नैतिकता का नितांत लोप दिखाई पड़ता है। हमारे रचनाकार, कलाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने तरीके से समाज को रास्ता दिखाने का प्रयास करते रहे हैं। इसके लिए विद्वता का होना जरूरी नहीं है। अपनी परंपराओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। साहस से रचते हैं। इसी परंपरा के लोक कलाकार हैं भिखारी ठाकुर।

लोक कवि भिखारी ठाकुर ने अपनी रचनाओं को जन जागरण का हथियार बना दिया। वे तुलसीदास को अपना गुरु मानकर उनकी शैली अपनाते हैं तो कबीर की तरह सामान्य जन की भाषा अपना कर अंतिम जन तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करते हैं। सही मायने में भिखारी ठाकुर आधुनिक भोजपुरी पुनर्जागरण के दूत थे। उनकी सामाजिक चेतना पर भोजपुरी क्षेत्र के साथ-साथ बंगाल का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से पड़ा। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती-प्रथा उन्मूलन कानून बनाया, जिसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर व्यापक रूप से पड़ा। राजा राममोहन राय समाज के नायक बन कर उभरे। राय ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को उठाया। लोक में व्याप्त कलाओं में निहित आस्तिकता और आध्यात्मिकता को वाचिक परंपरा से प्राप्त भक्ति साहित्य की आस्तिकता और आध्यात्मिकता से मिला कर भिखारी ठाकुर ने अपने यथार्थ को रचा जो उनकी रचनात्मकता आधार था।

भारत में पुनर्जागरण के ज्यादातर पुरोधा सामाजिक रूप से ऊपरी तबके से थे, जबकि भिखारी ठाकुर नाई जाति में पैदा हुए थे और पढ़े-लिखे नहीं थे। भिखारी को अपार लोकप्रियता मिली। किंचित इसके पीछे 'तमाशा' के उस माध्यम का भी हाथ रहा जिनके जरिए उन्होंने अपनी बात कही और जीते जी किंवदंती बन गए। भिखारी ठाकुर के प्रतीकीकरण की प्रक्रिया बाद में हुई। इस प्रक्रिया में बिहार के राजनीतिक समीकरणों और वहां के नेताओं ने भी प्रमुख भूमिका निभाई। एक समाज चेता प्रतीक के रूप में भिखारी ठाकुर और मजबूती से उभरे।

भिखारी ठाकुर व्यक्तिगत आचार व्यवहार तथा सामाजिक आदान-प्रदान में सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते थे परंतु वर्ण-व्यवस्था की त्रासदी को स्वयं भोगते हुए भी वे उनके खिलाफ उग्र प्रतिक्रिया की जगह रचनात्मक

समाधान की उम्मीद रखते थे। यह उनकी रचनाओं में साफ दिखता है और उसमें पूर्ण विश्वास करते थे। शोषित, दलित, नारी और गरीब पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंतित दिखाई पड़ते हैं। हाशिये पर गुजर-बसर कर रहे इस समाज की मुक्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करते रहे। अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति का माध्यम नाटकों को बनाया। तमाशा और नाच के जरिए उन्होंने तत्कालीन समस्याओं और समाज की विद्रूपताओं पर साहसपूर्ण तरीके से विवेचना की। साहित्य में भिखारी ठाकुर के प्रतीकीकरण के प्रसंग और महत्त्व को समझने के लिए भोजपुरी साहित्य के इतिहास, उसकी धाराओं और उसकी प्रवृत्तियों को समझना जरूरी है।

भोजपुरी साहित्य का लंबा इतिहास रहा है। वैसे तो कुछ जानकार कबीर को भोजपुरी साहित्य के आदिकवि के रूप में देखते हैं, लेकिन कइयों ने इसकी जड़ें विक्रमशिला के सिद्ध साहित्य और शाहाबाद के ईशानचंद्र की कविताओं में ढूंढी हैं। ये आध्यात्मिक और संस्कार गीत भोजपुरी साहित्य की सुदीर्घ लोक परंपरा को चरितार्थ करते हैं। दूसरी तरफ, अगर हम भोजपुरी साहित्य में प्रकाशन की परंपरा को देखें तो यह लगभग 140 वर्ष पुरानी है। इसकी शुरुआत 1885 में तेग अली के बदमाश दर्पण के प्रकाशन के साथ होती है। उल्लेखनीय है कि यद्यपि तेग अली बनारस के भारतेंदु मंडल के संपर्क में आए थे, और उन्हीं के प्रोत्साहन से बदमाश दर्पण प्रकाशित हो पाया था, लेकिन अली स्वयं कोई साहित्यकार या विद्वान नहीं थे। पहलवानी करते थे और पेशे से लठैत थे। भोजपुरी की सबसे पहले प्रकाशित पुस्तक के रचनाकार का पेशा इस बात की ओर इशारा करता है कि प्रिंट के आने के बाद भी भोजपुरी साहित्य में लोक संस्कृति का हस्तक्षेप व्यापक रहा है।

अपनी बहुचर्चित किताब 'जोरालिटी एंड लिटरेसी दी टेक्नोलोजइजिंग ऑफ दी वर्ल्ड' (1982) में वॉल्टर जे ऑग कहते हैं कि प्रिंट के आने से हमारे विचार पद्धति, सोच और संस्कृति में व्यापक परिवर्तन आए। लोक संस्कृति किताबों में कहीं गुम सी हो गई और अनूठी बौद्धिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन भोजपुरी साहित्य की धाराओं पर नजर डालें तो पाएंगे कि आंग का सूत्रीकरण शायद पूरी तरह से सटीक नहीं है। प्रिंट के आने के बाद भी भोजपुरी साहित्य सिर्फ मनोरंजन के ही नहीं, बल्कि भोजपुरी साहित्य और समाज के बौद्धिक विन्यासों के भी प्रतीक हैं। भिखारी ठाकुर विरले रचनाकार हैं जिनकी कला और रचना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता था। लोग उनके मंचन के बाद रोते-बिलखते और अपनी सामाजिक कुरीति को खत्म करने की सामूहिक प्रतिज्ञा लेते थे। महात्मा गांधी जो काम अपने रचनात्मक कार्यक्रम के जरिए कर रहे थे वही काम भिखारी ठाकुर अपनी कला के माध्यम से कर रहे थे। भिखारी पूरे भोजपुरी इलाके के सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं।

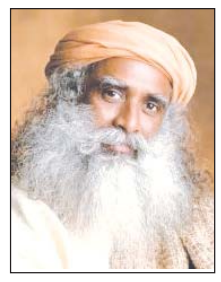

जल | सद्‌गुरु

इस संस्कृति में हम जिन लोगों की पूजा करते हैं, चाहे शिव हों, राम हों या कृष्ण, वे उन सभी परेशानियों और मुश्किलों से गुजरे, जिनसे ज्यादातर इंसान गुजरते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हालात चाहे जो भी रहे हों, चाहे उन्हें जीवन में कैसी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, वे अपनी भीतरी प्रकृति से कभी नहीं भटके। हम उन्हें इसलिए पूजते हैं क्योंकि वे उन परिस्थितियों से अछूते रहे। नदी कई तरह से ऐसी ही होती है। चाहे कैसे भी लोग उसे छुएं, बहने की प्रकृति के कारण वह हमेशा शुद्ध रहती है। इस संस्कृति में हमने नदियों को सिर्फ जल-भंडार की तरह नहीं देखा। हमने उन्हें जीवनदायी देवी-देवताओं के रूप में देखा। तर्क की सीमाओं में बंधे विचारशील मन को यह बात मूर्खतापूर्ण या आदिम लग सकती है। 'नदी तो सिर्फ नदी है, देवी कैसे हो सकती है?' अगर ऐसे व्यक्ति को आप किसी कमरे में तीन दिन तक बिना पानी के कैद कर दें और फिर उसे एक गिलास पानी दिखाएं, तो वह उसके आगे सिर झुकाएगा। नदी के सामने नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी के आगे। पानी, हवा, भोजन और जिस धरती पर हम चलते हैं, ये सब वस्तुएं नहीं हैं। हमने कभी नदियों को भौगोलिक इकाई की तरह नहीं देखा। उन्हें जीवन को बनाने वाले सामान की तरह देखा क्योंकि हमारे शरीर का 70 फीसद हिस्सा भी जल है। जब भी हम जीवन की खोज करते हैं, तो सबसे पहले एक बूंद पानी ढूंढते हैं। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो इसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज यह दिखाने के लिए काफी वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि पानी में जबर्दस्त याददाश्त होती है। आप पानी से कैसे पेश आते हैं, यह याददाश्त उसमें लंबे समय तक रहती है। इसलिए हमारे शरीर को छूने से पहले हम पानी के साथ कैसे पेश आते हैं, उससे हमारे शरीर में सारी चीजों की गुणवत्ता बदल जाती है। अगर हम अपने शरीर के जल को शुद्ध रखते हैं, तो सेहत और खुशहाली कुदरती तौर पर आती है। इंसानी जीवन से परे जाने या उसे रूपांतरित करने के मूलभूत विज्ञान को भूत शुद्धि कहते हैं। भूत शुद्धि का मतलब है पंचतत्वों की शुद्धि।

रीडर्स मेल

भीड़तंत्र और भेड़चाल से बचना है

आधुनिक भारत के डिजिटल इंडिया एवं कंप्यूटर के युग में रहने के बावजूद कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद, आडंबर, जादू-टोने और तांत्रिकों के चक्कर में समाज जकड़ा हुआ प्रतीत होता है। हम धार्मिक रहें, आस्थावान रहें और निष्ठावान रहें लेकिन भीड़तंत्र और भेड़चाल से तो बचना ही है। नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। सरकारी तंत्र और सत्संग तथा धार्मिक आयोजन करने वालों के समन्वय और संवाद में भारी कमी दिखाई देती है। यह भी कड़वा सच है कि देश के नामी-गिरामी लोग इन बाबाओं के दरबार में जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, और आशीर्वाद लेते हैं। राजनेता भी आसानी से देखे जाते हैं, और चुनाव के दौरान यह संख्या बढ़ जाती है। इससे जनता भी भ्रमित होती है और उसकी आस्था भी इन बाबाओं के प्रति बढ़ जाती है। श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, सत्संग पीछे छूट जाता है। हाथरस भगदड़ कांड में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते क्षेत्र के सीईओ, एसडीएम और तहसीलदार समेत सात अधिकारियों को निलंबित किया है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और 12 जुलाई को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। देश में हमें ऐसा माहौल बनाना होगा, जहां हम सत्संग भी करें, ज्ञान प्राप्त भी करें और हमारी आस्था भी बन रहे।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

विवेकवान बना रहे विपक्ष

यदि विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझा और राहुल गांधी कुछ विवेकवान बने रहे तो विपक्ष इस सरकार को मजबूर सरकार में तब्दील कर सकता है। संसद के पहले रोज जिस तरह इंडिया गठबंधन के सदस्य संविधान की प्रतियां लहराते हुए लोक सभा में पहुंचे, उस आरंभ से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा पर अगली ही चाल में सत्ता पक्ष ने आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव लाकर उसके दांव में पलीता लगा दिया। कहना होगा कि विपक्ष जितना अधिक वैचारिक संकट पैदा करेगा, सत्ता में उतनी अधिक बेचैनी बढ़ेगी। विपक्ष की संख्या खासी प्रभावी है, इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमें शह और मात का खेल देखने को मिलता रहेगा।

मनोज श्रीवास्तव, सुलतानपुर

कब रुकेंगे आतंकी हमले

पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों ने देश को यह सोचने पर फिर से मजबूर कर दिया है कि आखिर, वहां आतंकी हमले कब रुकेंगे? हालांकि हमारे सैनिक आतंकवाद का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और कुछ सैनिक देश की सुरक्षा की खातिर शहीद भी हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी लेकिन यह फिर भी यह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सवाल उठता है कि आखिर, आतंकवाद अभी भी यहां समस्या क्यों बना हुआ है? आतंकवाद बेशक, आज विश्वव्यापी समस्या बन चुका है, लेकिन भारत को अपने यहां आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए खुद ही गंभीर होना पड़ेगा। भारत को चाहिए कि वह पाकिस्तान को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के उपाय करे, आर्थिक कमजोरी भी पाकिस्तान की बर्बादी का कारण बन सकती है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 326
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

फ्रांस का त्रिशंकु जनादेश

फ्रांस में हुए संसदीय चुनाव में भारी उलटफेर देखने को मिला। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट (एनएफपी) ने सबसे अधिक 182 सीटें हासिल की हैं, जबकि मैक्रों के गठबंधन को 168 सीटें मिलीं। नेशनल रैली और सहयोगी दलों को 143 सीटें मिली हैं। फ्रांस के चुनाव परिणाम हैरान कर देने वाले हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और त्रिशंकु संसद के चलते राजनीतिक अनिश्चितता भी शुरू हो गई है। फ्रांस में गठबंधन सरकार का कोई इतिहास नहीं रहा है। अब की बार हुई अधिक वोटिंग का अर्थ यही है कि देश की जनता राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व से खुश नहीं है और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। जून में हुए यूरोपीय संसद के चुनाव में फ्रांस में मध्यमार्गियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें दक्षिणपंथी पार्टियों को भारी जीत मिली थी। 9 जून को नतीजे आए और उसी दिन राष्ट्रपति मैक्रों ने संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी थी। उन पर इस बात का नैतिक दबाव था। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था लेकिन समय से पहले संसद भंग कर चुनाव कराने का फैसला उल्टा पड़ा।

फ्रांस में राष्ट्रवाद की आंधी चलने के बाद इमैनुएल मैक्रों सत्ता में आए थे लेकिन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साबित किया कि राष्ट्रवाद की आंधी बार-बार सफल नहीं होती। फ्रांस यूरोप क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ हफ्ते बाद ही पैरिस में ओलिम्पिक खेलों की शुरूआत होने वाली है। त्रिशंकु संसद ने बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर दी हैं। हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री गैब्रियल ने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस में अति दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को सत्ता में आने से रोकने के लिए दूसरे चरण के चुनाव में मैक्रों की रेनेसां पार्टी और उसमें शामिल गठबंधन दलों और वामपंथी पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट ने गठबंधन कर लिया था। इसके तहत दोनों समूहों ने 217 उम्मीदवार मैदान से हटा लिए थे। देश की जनता को धुर दक्षिणपंथियों के सत्ता में आने से अशांति फैलने का डर था। इसलिए लोगों ने उसे वोट नहीं डाले।

फ्रांस में गठबंधन सरकार का कोई इतिहास नहीं रहा है। अब की बार हुई अधिक वोटिंग का अर्थ यही है कि देश की जनता राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व से खुश नहीं है और लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है। जून में हुए यूरोपीय संसद के चुनाव में फ्रांस में मध्यमार्गियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसमें दक्षिणपंथी पार्टियों को भारी जीत मिली थी। 9 जून को नतीजे आए और उसी दिन राष्ट्रपति मैक्रों ने संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी थी। उन पर इस बात का नैतिक दबाव था। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था लेकिन समय से पहले संसद भंग कर चुनाव कराने का फैसला उल्टा पड़ा।

अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। हालांकि मैक्रों ने पहले ही यह कह दिया था कि चाहे कोई भी जीत जाए वह राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। राष्ट्रपति मैक्रों अगले प्रधानमंत्री के नाम पर कोई और निर्णय लेने से पहले नेशनल असैम्बली के नए स्वरूप का इंतजार करेंगे। फ्रांस के सामने अब दो विकल्प होंगे जो कि फ्रांस के इतिहास में पहले कभी नहीं दिखे हैं। मैक्रों हमेशा एक जैसी सोच रखने वाली पार्टियों के बीच गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन इसके लिए न्यू पॉपुलर फ्रंट को अलग होकर राष्ट्रपति के पीछे अपने कट्टरपंथी एजेंडे और उसूलों के बिना फिर से संगठित होना होगा। वामपंथी नेता जीन-ल्यूक मेलेंचन ने मैक्रों से वामपंथी न्यू पापुलर फ्रंट गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर मैक्रों एक टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नामित कर सकते हैं जो राजनीतिक उथल-पुथल के दौर को पाट सके। समाधान के तौर पर इन दोनों ही विकल्पों का मतलब संभवत: एक कमजोर सरकार होगी। जिसे कोई भी सार्थक बिल या कानून पारित करने में परेशानी होगी और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उसका प्रभाव भी कम होगा।

न्यू पॉपुलर फ्रंट ईंधन और खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर कैपिंग चाहता है। वह न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 1600 यूरो प्रतिमाह करना चाहता है। इसके अलावा वह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना चाहता है और वह वैल्थ टैक्स भी लगाना चाहता है। दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन की पार्टी ने नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावनाओं को खत्म करने का मुद्दा बनाया था लेकिन फ्रांसीसी समाज में कई लोग अभी भी इस पार्टी के फ्रांस प्रथम रुख और बढ़ती लोकप्रियता को चिंता के साथ देखते हैं। यह पार्टी मुस्लिमों की कट्टर विरोधी मानी जाती है। इससे भी उसकी वोटिंग पर असर पड़ा।

स्पष्ट है कि नया गठबंधन बनाने के लिए मध्यमार्गी मैक्रों की पार्टी और वामपंथी पार्टियों के बीच सौदेबाजी चल सकती है। गठबंधन का स्वरूप क्या होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। गठबंधन के चलते क्या फ्रांस में मजबूत सरकार बन पाएगी जो कोई भी बिल कानून आदि पारित करने में समक्ष हो सके। फ्रांस के लोगों ने महंगाई, अपराध, आव्रजन और मैक्रों सरकार की शैली सहित अनेक शिकायतों को लेकर मतदान में अपना गुस्सा निकाला है। मैक्रों ने हमास के साथ युद्ध में इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का वादा किया था लेकिन उनकी नीतियां स्पष्ट नहीं रहीं। इसी बीच वामपंथी नेता ज्यां ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि उनका गठबंधन फिलिस्तीन को मान्यता देने की दिशा में काम करेगा। यूरोप के चार देश स्पेन, नार्वे, आयरलैंड और स्लोवानिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। फ्रांस में पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ कि जिसने राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। फ्रांस का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका जवाब ढूंढने के लिए अभी वक्त लगेगा। सात साल पहले जब मैक्रों सत्ता में आए थे तब से राजनीतिक ताकतों में बिखराव देखने को मिल रहा है। फ्रांस की जनता अब वामपंथी, धुर दक्षिणपंथी , मध्यमार्गी और इसके साथ ही मध्य दक्षिणपंथी विचारधारा में बट चुकी है। इन पक्षों के भीतर भी अलग-अलग प्रतिस्पर्धाएं और पार्टियां हैं। कुल मिलाकर मैक्रों कमजोर हुए और वह आने वाले दिनों में सुलह-समझौतों की बात करेंगे। अगर मैक्रों किसी मध्यमार्गी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने में सफल हो जाते हैं तो यह उनकी बेहतर रणनीति होगी लेकिन वामपंथी दलों की ताकत को देखकर ऐसा सम्भव नहीं लगता। देखना होगा कि फ्रांसीसी सियासत में किसका दमखम रहता है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

जिसमें भेंट चढ़ गयी है, इंसानियत...

कोई धमकियां भेज रहा है परमाणु वार की,
अनसुनी कर रहा है चीखें, युद्धों में तबाह परिवार की,
ये दास्तां है ताकतनुमा मुल्कों के अहंकार की,
जिसमें भेंट चढ़ गयी है, इंसानियत और अहिंसा के विचार की !!

गीता पाढा

दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतेखाब !

फिरोज बख्त अहमद

जो लोग कहते हैं कि रोम की ईंट-ईंट पर इतिहास लिखा है, शायद नहीं जानते कि दिल्ली के कण-कण पर इतिहास की छाप है। दिल्ली आठ बार उजड़ी और आठ बार बसी। यहां से शहर देखने से दिमाग में कुछ बिंब उभरते हैं जैसे पहला महाकाव्य का शहर, दूसरा सुल्तानों का शहर, तीसरा शाहजहांनाबाद और चौथा नई दिल्ली से आज की दिल्ली तक।

क्या ख़ूब कहा है, मीर तकी मीर ने दिल्ली के इतिहास पर :

"दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतेखाब,
रहते थे यहां मुंतखिब ही रोजगार के,
इसको फ़लक ने लूट के पामाल कर दिया,
हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के!"

अपनी इस शायरी में मीर ने दिल्ली को आलम में इंतेखाब अर्थात विश्व का सबसे विलक्षण शहर बताया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि समय समय पर दिल्ली बर्बाद हुई है। वैसे असली दिल्ली पुरानी दिल्ली है, जिसका इतिहास इंद्रप्रस्थ से लेकर शाहजहांनाबाद तक का है न कि नई दिल्ली का। "दिल्ली को सभी ने एक तवायफ की तरह निचोड़ा, मगर उसका अधिकार उसे नहीं दिया!" अक्सर कहा करते थे, जगप्रवेश चंद्र, दिल्ली के पूर्व चीफ़ एग्जिक्यूटिव काउंसलर।

वास्तव में दिल्ली इतना सुंदर और लुभावना शहर था कि इसके आगे बगदाद, काबुल, तेहरान, इस्फाहान आदि सभी पानी भरते थे। इन्हीं खूबसूरत आधारों को देख एक अन्य विख्यात शायर और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की आजादी का बिगुल बजाने वाले, शहंशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद, उस्ताद शेख मुहम्मद इब्राहीम ज़ौक ने दिल्ली के कूचों, कटरों, फाटकों और आहतों के बारे में कहा था :

दिल्ली के कूचे न थे,
औराक़-ए-मुसव्विर थे,
जो शक्ल नज़र आई,
तस्वीर नज़र आई!

जिस जिंदादिली से दिल्ली वाले अपन जीवन व्यतीत करते हैं, वह विश्व में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इनकी दिनचर्या मंदिरों में पूजा और मस्जिदों में दिल्ली का इतिहास, शहर की तरह ही रोचक है। इस शहर के इतिहास का सिरा महाभारत तक जाता है, जिसके अनुसार, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था। दिल्ली का सफर लालकोट यानी दिल्ली क्षेत्र का पहला निर्मित नगर, किला राय पिथौरा, सिरी, जहांपनाह, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, दीनपनाह, शाहजहांनाबाद से होकर नई दिल्ली तक जारी है। रायसीना की पहाड़ी पर बने राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर बारस्ता इंडिया गेट नजर आने वाला पुराना किला, वर्तमान से स्मृति को जोड़ता है।

हिंदू-मुस्लिम एकता का भी इतिहास रहा है दिल्ली में। वैसे फ़ारसी में दिल्ली का इतिहास लिखने वाले मिर्ज़ा संगी बेग का मानना है कि सदा से ही अंतर्धर्म सद्भाव और संभाव की नगरी रही इस दिल्ली का क्षेत्र फल लाल क़िले से महरौली तक था, जिसे कहा जाता था, "किला-ए-मुल्ला ता महरौली"। जब मुस्लिम नमाज़ी, मस्जिदों से नमाज़ पढ़ कर बाहर आते थे तो बिरादराना-ए-वतन, यानि हिंदू अपने बीमार बच्चों को स्वस्थ कराने के लिए उन से दम कराया करते थे, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि क़ुरान की आयतों में सेहत अता करने की ईश्वरीय शक्ति है। दिल्ली की ऐतिहासिक हवेलियों में हिंदू-मुस्लिम, नवाब, लाला, मुंशी, मनसबदार आदि ऐसे मिल जुल कर रहते थे और कभी भी एक-दूसरे से नहीं रूठते थे, अलग नहीं होते थे, जैसे गोश्त से नाखून। इन्हीं हवेलियों में कई हवेलियों का जीर्णोद्धार कराया गया है, जिस में पुरानी दिल्ली के वेजिटेरियन भोजन मिलते हैं और जहां देश-विदेश के सैलानी जाकर खानों के चटखारे तो लेते ही हैं, हवेली की पुरानी शाहजहानाबादी वास्तुकला से भी लुत्फ अंदोज होते हैं।

चांदनी चौक बाज़ार जो लाल क़िले से शुरू होता है, उसमें दिगंबर जैन लाल मंदिर है, औरंगजेब की मदद से बना अप्पा गंगाधर (औरंगजेब का सबसे विश्वासपात्र सेनापति) मंदिर, जिसे गौरी शंकर मंदिर कहा जाता है और जहां सबसे भव्य आरती होती है, सुनहरी मस्जिद, जिसके नीचे तैमूर लंग ने सैकड़ों दिल्ली वाले काट डाले थे, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, आर्य समाज मंदिर, कटरा नील का शिव मंदिर और मस्जिद फतेहपुरी, इस बात का प्रमाण हैं कि दिल्ली या भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का यह अंतर्धर्म सद्भाव का मात्र अनूठा बाज़ार है।

आहा ! खान-पान में तो पुरानी दिल्ली का जवाब नहीं। यह तो खान-पान की जन्नत है। खाने चाहे वेज हों या नॉन वेज, विश्व में इसकी टक्कर के व्यंजन कहीं नहीं। चाहे परांठे वाली गली के परांठे हों, 'जलेबी वाला' की रसदार जलेबियां हों, चाहे 'नटराज दही भल्ला' के दही भल्ले हों या तरह-तरह की वर्षों पुरानी चर्चित मिठाई की दुकानें व मिठाईयां हों अथवा 'दौलत की चाट' हो, ये सभी लाजवाब हैं। सीता राम बाजार की वो चाट पकोड़ी की दुकानें, हलवा नागोरी, बाज़ार हौज क़ाज़ी, लालकुआं में इदरीस की पूड़ी, कौचड़ी सब्ज़ी का क्या कहना। और हां, कूचा पातीराम में रबड़ी की दुकानें, कुल्हड़ की कुल्फी का मज़ा लेने पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं।

फ़सील बंद दिल्ली अर्थात् 'वॉल्ड सिटी' के सब से ख़ूबसूरत और भव्य बाज़ार, चांदनी चौक में एक समय, कंधार के अनार, काबुल के मेवे, इस्फाहान की इमली, बेल्जियम के झाड़ फानूस, फ्रांस की सुगंधियां, ब्राज़ील की कॉफी, अमेरिका के पारकर पैन, जर्मनी के झिंगन क्लॉक, ग्लौस्टर की कॉटन, साइप्रेस के रसीले आड़ू, ढाका के जूट के मोंढे आदि बड़े कम दामों में मिल जाया करते थे। ऐसे फल भी मिल जाया करते थे जिनके बारे में आज के बच्चों को तो क्या बूढ़ों को भी पता नहीं होगा, जैसे -कसेरू चकोतरा, फीरनी, जलेबा आदि। दिल्ली पर राज तो सभी राजनीतिक दलों ने किया, मगर जिस प्रकार से इसे दुल्हन बना सकते थे, किसी ने नहीं किया। गालिब ने क्या ख़ूब कहा है कि यदि भारत शरीर है तो दिल्ली इसकी आत्मा।

पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कुचलना होगा

राजेश माहेश्वरी

जम्मू-कश्मीर में सख्ती के बाद आतंकवादियों ने जम्मू क्षेत्र को अपना नया निशाना बना लिया है। वहां के जम्मू क्षेत्र को शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में आतंकवादियों के ताबड़तोड़ कई हमलों से यह क्षेत्र सहम गया है। ये हमले सीमावर्ती जिले पुंछ, राजौरी, डोडा और रियासी में हुए। पिछले कुछ समय से जम्मू क्षेत्र में ऐसे हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। जून से लेकर अब तक यहां पर कम से कम 8 ऐसे हमले हुए जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकवादियों का सामना हुआ। पिछले कुछ महीनों से आतंकियों की सक्रियता के पीछे जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू होना माना जा रहा है। आतंकी हमलों और मुठभेड़ के बढ़ते मामलों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आतंकियों की घुसपैठ भी हो चुकी है और वे मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देने में लगे हैं।

पाकिस्तान जब आमने-सामने की लड़ाई में हमेशा भारत से हारता रहा तो उसने आतंकवाद रूपी छद्म युद्ध या फ्रॉक्सी वार शुरू किया। इन आतंकियों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर बरगलाया जाता है तथा पैसे और हथियार देकर आतंकवादी हमला करने भेजा जाता है। पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें प्रशिक्षण देती है और लांचिग पैड से इन्हें सीमा पार कराया जाता है। ये आतंकी गुप्त सुरंगों, नालों या जंगल के रास्ते से होकर जम्मू-कश्मीर में दाखिल होते हैं।

भारत ने बालाकोट में बड़े आतंकी प्रशिक्षण शिविर को सर्जिकल स्ट्राइक कर नष्ट किया था। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने और आल इंडिया हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं को हवाला के जरिए मिलने वाली फंडिंग को रोक दिए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगी थी। जो नेता आतंक को बढ़ावा देकर आए दिन कश्मीर में हड़ताल और सुरक्षा बलों पर पथराव कराते थे उन्हें जेल भेजा गया। जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद ऐसे शरारती तत्वों के हौसले पस्त हो गए थे। पाकिस्तान ने भी भारत में ऐसी सख्त सरकार देखी जो आतंकियों को घर में घुसकर मारने की इच्छाशक्ति और क्षमता रखती थी। अन्यथा एक ऐसा भी समय था जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराना टेढ़ी खीर था। यह सारा माहौल बदला और अलगाववादी तत्वों की शरारत पर अंकुश लगा। इतने पर भी बौखलाए हुए आतंकवादी अपनी चुनी हुई जगह व समय पर अचानक हमले को अंजाम देते हैं।

सुरक्षाबलों की सख्ती के चलते कश्मीर तो फिर भी शांत है, लेकिन जम्मू दहशतगर्दों का नया ठौर बनता दिख रहा है। वे नागरिकों, तीर्थयात्रियों समेत सेना पर भी घात लगाकर हमले कर रहे हैं। ताजा हमला कठुआ में हुआ। जम्मू के कठुआ जिले में 8 जुलाई को सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में पांच जवान शहीद हो गए। घात लगाकर किए गए अटैक के बाद से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। तीन दिनों के भीतर यह सेना पर दूसरा हमला है।

कठुआ वही इलाका है, जो कश्मीर के सबसे अस्थिर दौर में आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ था लेकिन ऐसा क्या हुआ है, जो आतंकी एक बार फिर जम्मू की तरफ मुड़ रहे हैं। जम्मू, खासकर कठुआ आतंक का नया केंद्र है, जो 90 के दशक में भी टैररिस्ट्स का ठिकाना हुआ करता था। अब एक बार फिर ऐसा दिख रहा है कि दहशतगर्दों ने कठुआ को अपना ठिकाना बना लिया है। दरअसल इस जिले की बनावट ऐसी है कि यहां छिपना-छिपाना आसान है। जंगलों से सटे क्षेत्र में हमले के बाद आतंकी गायब हो सकते हैं, जैसा ताजा केस में दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी वजह और भी है, जो है इसकी जिओग्राफी। जिले के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा सटती है, तो दूसरी तरफ हिमाचल और पंजाब हैं। कठुआ उधमपुर, सांबा और डोडा जिलों से भी लगा हुआ है।

नब्बे के दशक में कठुआ सुरक्षा बलों का बेस भी हुआ करता था ताकि आतंक पर रोक लगाई जा सके। साफ दिख रहा है कि कश्मीर में तो शांति है, लेकिन आतंकवादी जम्मू को घेर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी में सुरक्षाबल भारी संख्या में बना हुआ है। वहां सेंध लगाना बेहद मुश्किल है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान स्थित आतंकी जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश में हैं। साल 2023 में भी ऐसी कोशिश हुई थी, जब जम्मू में 43 टेरर अटैक दर्ज किए गए। वहीं बरसात में मामला और संवेदनशील हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तेज बारिश के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर होता है, जैसे फेंसिंग और इंफ्रारेड लाइट्स कमजोर या खराब हो जाती हैं। इसका फायदा आतंकी उठाते हैं और सीमा पार से आकर आतंक मचा जाते हैं।

गत माह रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमले ने भी यह साबित किया कि आतंकी क्षेत्र में खौफ पैदा करना चाहते हैं। वे सेना के शिविरों पर भी हमले कर रहे हैं। जम्मू में अचानक हिंसा बढ़ने के पीछे एक वजह सीमा पार आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं को भी माना जा रहा है। बता दें कि सीक्रेट किलर्स ने कुछ समय में आईएसआई के आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी। हमजा फरवरी, 2018 को जम्मू के सुंजवान कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। मुख्य आतंकी की मौत के बाद से पाकिस्तान काफी बौखलाया हुआ था। सुरक्षाबल वैसे तो काफी चैकन्ना हैं लेकिन जम्मू की यही जिओग्राफी परेशान करने लगी है। यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्स घने जंगलों जहां कोई आता-जाता नहीं, वहां भी चेकपॉइंट्स बना रही है।

घाटी में कई टैररिस्ट गुट एक्टिव हो चुके हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं दिखता। यानी वे हाल ही में बने और खुद को इंडिपेंडेंट बताते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ), जम्मू- कश्मीर गजवनी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स और पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट इन्हीं में से हैं। टीआरएफ का अस्तित्व धारा 370 हटाने टीआरएफ, जम्मू-कश्मीर गजवनी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स और पीपल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट इन्हीं में से हैं। टीआरएफ का अस्तित्व धारा 370 हटाने बाद संगठन कई दूसरे बड़े आतंकी गुटों के साथ मिला हुआ दिखा। वैसे ये जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी है, यानी उसे कवर करने का काम करता है।

हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के साथ जम्मू-कश्मीर में भी शीघ्र विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय भी जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव करवाने के निर्देश दे चुका है। यहां विधानसभा चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग भी गंभीर है। लेकिन आतंकी हमलों की बढ़ती वारदातों के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखना और क्षेत्र की जनता को यह संदेश देना जरूरी है कि वह बेखौफ होकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती है।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की समस्या दशकों पुरानी है। इसके पीछे स्पष्ट रूप से पाकिस्तान है। पाकिस्तान में चुनाव के बाद बनी नई सरकार ने भारत के साथ संबंध सुधारने की इच्छा तो जताई है लेकिन कश्मीर मुद्दे पर अपना पुराना राग नहीं छोड़ा है। इसलिए यह आशा करना व्यर्थ है कि पाकिस्तान का रवैया बदलेगा। इसलिए भारत को सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने के साथ देश के भीतर सक्रिय आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने पर ही ध्यान देना होगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी जदयू में शामिल

पटना, (पंजाब केसरी): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वासपात्र माने जाने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मनीष कुमार वर्मा मंगलवार को जदयू में शामिल हो गए। वर्मा ने मुख्यमंत्री के साथ रहने के लिए सिविल सेवा में अपना बेहतर करियर कुछ साल पहले छोड़ दिया था।

तीन साल पहले वीआरएस लेने वाले वर्ष 2000 बैच के आईएएस अधिकारी रहे वर्मा का पटना स्थित जदयू मुख्यालय में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बड़े धूमधाम से स्वागत किया गया। पूर्व नौकरशाह का पार्टी में स्वागत करते हुए झा ने कहा, हमारी पार्टी बिहार से बाहर अपने आधार का विस्तार करने के बारे में गंभीरता से सोच रही है। हमें यकीन है कि वर्मा का समृद्ध प्रशासनिक अनुभव जदयू के लिए बहुत काम आएगा।

● मनीष कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री के साथ रहने के लिए सिविल सेवा में अपना बेहतर करियर कुछ साल पहले छोड़ दिया था

इस अवसर पर कुमार के गृह जिले नालंदा से ताल्लुक रखने वाले वर्मा ने अपने संरक्षक की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री असाधारण व्यक्तित्व, सच्चे समाजवाद के प्रतीक और वादों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं, जो राजनेताओं में दुर्लभ है।

आईआईटी दिल्ली के छात्र रहे वर्मा को आईएएस में शामिल होने पर ओडिशा कैडर सौंपा गया था और वहां 12 साल तक सेवा देने के बाद, उन्होंने पिता के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने गृह राज्य में प्रतिनियुक्ति की मांग की थी। वर्मा ने कहा, मैं नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि मेरी प्रतिनियुक्ति पर उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण कार्यभार दिया। मैंने पटना के जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया और राज्य की बिजली कंपनियों का नेतृत्व किया। 2021 में मेरी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो गई और मुझे अपने कैडर में वापस जाना पड़ा। लेकिन मैंने बिहार में ही रहकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना चुना। हालांकि, पार्टी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है की वर्मा को जदयू के भीतर क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

महाराष्ट्र विधानसभा में 94,889 करोड़ की अनुपूरक मांगें पेश

मुंबई, (पंजाब केसरी): महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में 94,889.46 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का भी प्रभार संभालने वाले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने ये अनुपूरक मांगें सदन में पेश कीं। अनुपूरक मांगों के जरिये बजट में किए गए आवंटन से अधिक धनराशि की मांग की गई है।

पवार ने 28 जून को 6,12,293 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें महिलाओं, युवाओं और किसानों सहित अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई थीं।

अनुपूरक मांगों में 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपये, युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए 5,555 करोड़ रुपये, किसानों को 7.5 एचपी क्षमता तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,930 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 4521200,
प्रसार विभाग : 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य ★ सार्थक ★ सदैव

दोषियों को दंड मिले

हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जिस तत्परता से अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके आलोक में जिस त्वरित गति से एसडीएम समेत छह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस हादसे में 120 से अधिक मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और उनके परिजनों को जीवन भर का दर्द मिल गया है। ऐसे में, हर तरफ से जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही थी और राज्य सरकार ने बिना देरी किए जांच दल गठित की थी। अब एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपकर एसआईटी ने इंसाफ की प्रक्रिया को गति दी है। अमूमन ऐसी रिपोर्टें तब आती हैं, जब संबंधित घटनाएं लोगों के जेहन से उतर चुकी होती हैं और ऐसे में उन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई हुई, यह लोगों को पता भी नहीं चल पाता और अक्सर लीपा-पोती हो जाती है। मगर हाथरस हादसे की गहरी टीस अब भी लोगों के भीतर बनी हुई है। यही कारण है कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जहां 12 जुलाई को इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी।

एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया है और साफ-साफ कहा है कि उन्होंने प्रशासन को धोखे में रखकर इजाजत ली। स्थानीय प्रशासन से तथ्य छिपाए गए और इतनी विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे। बल्कि बाबा नारायण साकार तक लोगों के पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं थी और जब भगदड़ मची, तो आयोजक घटनास्थल से फरार हो गए। ये तमाम बातें तो 2 जुलाई से ही कही जा रही हैं, मगर एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से एसडीएम की लापरवाही का जिक्र किया गया है, उससे हमारे प्रशासनिक अमले में पैठ आई काहिली का ही उद्घाटन होता है। क्या एसडीएम को बाबा नारायण साकार के सत्संगों में उमड़ने वाली भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने आयोजन स्थल का दौरा किए बगैर ही इसकी अनुमति दे डाली? उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों तक को सूचित नहीं किया। इसलिए उनके साथ-साथ अन्य संबंधित अधिकारियों का निलंबन बिल्कुल जायज है। सत्संग के आयोजकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई आयोजन जानलेवा न बन सके।

हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट में जिस तरह से एसडीएम की लापरवाही का जिक्र है, उससे हमारे प्रशासनिक अमले में पैठ आई काहिली का ही उद्घाटन होता है।

विशेष जांच दल ने 'किसी बड़े षड्यंत्र' की आशंका को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया है और इसकी गहन तफ्तीश की आवश्यकता पर बल दिया है। उम्मीद है, राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेगी। मगर धर्मगुरुओं के लिए भी इस हादसे में एक बड़ी सीख है कि वे कहीं भी सत्संग के लिए जाएं, तो अपने तईं भी आयोजकों से इंतजामों के बारे में दरयाफ्त करें। आखिर श्रद्धालु उनके आकर्षण में जुटते हैं, इसलिए उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भारत धर्मपरायण समाजों का देश है और यहां हरेक दिन हजारों जगहों पर छोटे-बड़े आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में, बड़े आयोजनों के बारे में जो तय दिशा-निर्देश हैं, उनमें किसी किस्म की शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए। हमारे तंत्र को पेशेवराना तेवर की जरूरत है और यह तेवर तभी आएगा, जब निचले स्तर पर नियमित प्रशिक्षण और उच्च स्तर पर लापरवाह अधिकारियों को दंडित करने की व्यवस्था होगी। जाहिर है, प्रशासन यदि किसी के प्रभाव में आएगा, तो वह पेशेवर बन ही नहीं सकेगा। इसलिए इस मामले के दोषियों की सजा एक नजीर बननी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
10 जुलाई, 1949

अशांत संसार

प्रथम महासमर के पश्चात् जिस भीषण आर्थिक संकट ने समस्त विश्व को अपने चंगुल में जकड़ लिया था, उसकी काली छाया एक बार फिर अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर दिखाई देने लगी है। ... ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक भिन्न-भिन्न देशों ने जो रक्षात्मक युक्तियां की थीं, वे पारस्परिक सहयोग के अभाव के कारण छिन्न-भिन्न होती जा रही हैं। सम्भवतः इसी स्थिति को दृष्टि में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के अर्थ विभाग ने संसार के समस्त राष्ट्रों से अपील की है कि वे अपने यहां बेकारी न उत्पन्न होने दें, आर्थिक विकास की योजनाओं को प्रोत्साहन दें और सम्भावित मंदी को रोकने के लिए समीचीन युक्तियां करें।

बात यह है कि द्वितीय महायुद्ध ने विश्व की अधिकांश आर्थिक शक्ति अमरीका के हाथों में केन्द्रित कर दी है। आर्थिक दृष्टि से इस समय संसार दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है- डालर क्षेत्र और स्टर्लिंग क्षेत्र। अर्थात् कुछ देश ऐसे हैं जहां स्वर्ण-मुद्रा का चलन है और कुछ ऐसे जहां चांदी की मुद्रा चलती है। अमरीका, कनाडा आदि स्वर्ण-मुद्रा के क्षेत्र हैं, जबकि ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल तथा यूरोप के विभिन्न देश रजत-मुद्रा के क्षेत्र में हैं। दुर्भाग्यवश रजत-मुद्रा क्षेत्र के सभी प्रदेशों में अन्न, उपभोक्ता पदार्थों तथा मशीन आदि की कमी है। इनमें रूस सम्मिलित नहीं किंतु वह अपने उत्पादित पदार्थों को अधिकतः अपने यहां ही रखता है और उनसे दूसरे देश बहुत ही कम लाभान्वित हो पाते हैं। स्वभावतः उन्हें अमरीका का मुंह देखना पड़ता है, जो अन्न, मशीन आदि सभी पदार्थों से सम्पन्न है। किंतु कठिनाई यह है कि अमरीका अपनी वस्तुओं के मूल्य-स्वरूप केवल स्वर्ण-मुद्रा लेना चाहता है, जिसकी अमरीका को छोड़कर प्रायः सभी देशों में भारी कमी है। पता चला है कि इस समय अमरीका के पास २४,४६,५९,२३,००० डालर है जो कि समस्त विश्व की स्वर्ण-मुद्रा का ३।५वां भाग है। इसके विपरीत अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन में, जो कि रजत-मुद्रा क्षेत्र के समस्त देशों का महाजन है, स्वर्ण और स्वर्ण-मुद्रा की बड़ी कमी हो गई है। कहा जाता है कि रजत-मुद्रा वाले देशों की आर्थिक मर्यादा की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन के पास ५० करोड़ पौंड मूल्य की स्वर्ण-मुद्रा होनी चाहिए, जबकि वहां इससे १० करोड़ पौंड कम हैं। यह निस्संदेह एक विश्वव्यापी अर्थसंकट का द्योतक है।

भारत-रूस संबंधों की नई इबारत

यहां स्कैन करें

पंकज सरन | रूस में रहे भारतीय राजदूत

अमेरिका में हमारे पांच वाणिज्यिक दूतावास हैं, जबकि रूस में अब तक दो ही हैं। अब दो और नए वाणिज्यिक दूतावास के खुलने से रूस में हमारी आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ेंगी।

मंगलवार को ऑस्ट्रिया के लिए उड़ान भरने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस आत्मीय माहौल में बातचीत की मेज पर बैठे, वह इस बात की मुनादी थी कि दोनों देशों के बीच सात दशकों पुराना संबंध अब कितना प्रगाढ़ हो चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर बैठक में आतंकवाद के साथ-साथ यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र छेड़ दिया। उल्लेखनीय है, यूक्रेन संकट के कारण रूस पश्चिमी देशों के निशाने पर है, जिसकी प्रतिक्रिया में मॉस्को भी मुखर है। मगर भारत ने बम-बंदूक के बजाय शांति-वार्ता के जरिये समाधान की बात दोहराई। वहीं, आतंकवाद के बहाने रूस को यह एहसास दिलाने की भी कोशिश की गई कि चीन के साथ उसकी नजदीकी परोक्ष रूप से पाकिस्तान को उत्साहित करती है, जो भारतीय जमीन पर आतंकी गतिविधियों को खाद-पानी मुहैया कराने का काम करता है। अच्छी बात यह भी रही कि ईंधन के मामले में भारत को स्थिरता प्रदान करने में रूसी योगदान की प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर सराहना की, जो उचित भी था, क्योंकि अब हम खाड़ी देशों के बजाय सबसे अधिक तेल रूस से ही आयात करने लगे हैं।

इस बैठक से पहले की गई कई अन्य घोषणाएं भी भारतीय हितों के अनुकूल रहीं। मसलन, रूस में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने का एलान किया गया है। यह जरूरी था, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से रूस से कहीं छोटे देश अमेरिका में हमारे पांच वाणिज्यिक दूतावास हैं, जबकि रूस में अब तक दो ही हैं। बीते करीब तीन दशकों से ऐसा कोई दूतावास रूस में नहीं खुला है, जबकि द्विपक्षीय रिश्ते काफी आगे बढ़ चुके हैं। नए वाणिज्यिक दूतावास के बाद रूस में हमारी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी। कारोबार, पर्यटन आदि से जुड़े कामकाज में इजाफा होगा। वहां के बाजार को समझने में कहीं अधिक आसानी होगी और व्यापार को भी फायदा होगा। इसी तरह, यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से हिस्सा ले रहे भारतीय सैनिकों की वतन वापसी पर बनी सहमति भी काफी अहम है। भारत लगातार यह मांग करता रहा है, जिस पर जल्द ही अमल करने का आश्वासन रूसी राष्ट्रपति ने दिया है।

नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के इस पहले द्विपक्षीय दौरे पर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थीं, जो स्वाभाविक ही था। जब रूस और भारत जैसे बड़े देश मिलते हैं, तो द्विपक्षीय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मसलों पर भी बात होती है। विशेषकर यूक्रेन युद्ध को लेकर सबकी उत्सुकता बनी हुई थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख फिर से स्पष्ट कर दिया। सुखद है कि भारत-रूस संबंध को लेकर अब पश्चिमी देश किसी मुगालते में नहीं हैं। 2000 के दशक में भी रूस के साथ हमारा काफी अच्छा रिश्ता था, बावजूद इसके अमेरिका ने भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता किया था। आज भी बेशक पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन साल 2023 में भारत ने 46.5 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल रूस से मंगाए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 2.5 अरब डॉलर था।

रूस के साथ ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं, रक्षा के क्षेत्र में भी हमारी काफी नजदीकी है। रक्षा संबंध करीब 40 साल पुराना है। हम आज भी जितने रक्षा उत्पाद आयात करते हैं, उसका करीब 60-70 फीसदी हिस्सा रूस से ही आता है। ऐसे में, स्वाभाविक है कि इन उपकरणों के रख-रखाव, उन्नतिकरण आदि के लिए भी मॉस्को के साथ लगातार संबंधों को मजबूती दी जाए। फिर, जब कभी हमें जरूरत पड़ी है, रूस हमारी मदद के लिए आगे आया है।

इसी तरह, आपसी कारोबार भी दोनों देशों को काफी करीब ला चुका है। हां, भुगतान एक बड़ा मसला जरूर है, जिस पर इस बार अहम बातचीत हुई है। दरअसल, यूक्रेन युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच डॉलर में ही लेन-देन होता था, लेकिन बाद में रूस पर प्रतिबंध और बदली वैश्विक परिस्थितियों के कारण कभी रूबल, तो कभी रुपये, तो कभी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिहरम में व्यापार होने लगा। चूंकि मॉस्को पर लगा प्रतिबंध हाल-फिलहाल में खत्म होता नहीं दिख रहा, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि भुगतान की कोई स्थायी व्यवस्था बने।

ठीक इसी तरह की चुनौती रूसी संसाधनों को लेकर भी है। रूस चूंकि एक विशाल देश है, इसलिए उसके पास प्राकृतिक ऊर्जा, मिनरल आदि के अपार भंडार उपलब्ध हैं। ऐसे में, हमारे लिए यह जरूरी है कि अपने राजनय संबंधों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए हम अपने हितों की पूर्ति करें। अभी वह बेशक पश्चिमी देशों के साथ उलझा हुआ है, लेकिन यह हमारे लिए एक मौका भी है। हमने पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रूस के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाकर अपनी मंशा स्पष्ट भी कर दी है।

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में परोक्ष रूप से चीन पर भी बात हुई। यह स्पष्ट किया गया कि भारत और रूस के रिश्ते पर किसी तीसरे देश, खासतौर से चीन की तरफ से कोई आंच नहीं आनी चाहिए। चीन से हमें सामरिक तौर पर लगातार चुनौती मिलती रही है और वह पाकिस्तान को भी हरसंभव मदद करता रहता है। ऐसे में, मॉस्को से दशकों पुरानी दोस्ती के नाते यह जरूरी था कि हम उसे यह एहसास दिलाएं कि चीन के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, ताकि बतौर मित्र वह हमारी दिक्कतों को समझे और हमारी मदद करे।

वास्तव में, भारतीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा के तीन पहलू थे। पहला, रूस के साथ रिश्ते बनाए रखना, साथ ही पश्चिमी देशों को स्पष्ट कर देना कि यह कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत नहीं की जा रही। भारतीय हितों की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मानवता की बात करना इसी रणनीति का हिस्सा था। दूसरा पहलू है, इस द्विपक्षीय रिश्ते में कौन-कौन से नए क्षेत्र शामिल किए जा सकते हैं, ताकि यह संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। विज्ञान-प्रौद्योगिकी और 'पीपुल-टु-पीपुल कॉन्टैक्ट' यानी आम लोगों के स्तर पर आपसी संबंध को आगे बढ़ाने पर रजामंदी को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए। और तीसरा पहलू है, पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आने वाली दिक्कतों को दूर करना। भुगतान की टिकाऊ व्यवस्था पर जोर इसकी एक बानगी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सब कुछ बदल गया, पर बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा कम नहीं हुई

यहां स्कैन करें

दिनेश मिश्र | जल विशेषज्ञ

खबर यह है कि 7 जुलाई, 2024 को कोसी नदी का प्रवाह 3.94 लाख क्यूसेक पार कर गया था और बैराज के सारे फाटक उठा देने पड़े थे, ताकि पानी की सहज निकासी हो सके और बैराज को कोई खतरा न होने पाए। प्रभावित गांवों के लोग अपनी रक्षा के लिए तटबंध पर शरण लेने जा रहे हैं और जब तक नदी का पानी अंतिम रूप से शांत नहीं हो जाता, तब तक उनको वहीं रखने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। आज तो कोसी का जल-स्तर कम हो गया है, पर यह कब इतना घटेगा कि लोग वापस अपने घर को लौट सकेंगे, कह पाना मुश्किल है। उस समय तक उनका घर बचा भी रह पाएगा या नहीं, यह भी संदेह के दायरे में है।

कोसी क्षेत्र की यह प्रायः हर साल की घटना है, जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, जब पहली बार कोसी बैराज के सारे फाटकों को एक साथ उठा देना पड़ा था। उस साल नदी में सर्वाधिक प्रवाह 9.13 लाख क्यूसेक पानी आ गया था। यह एक रिकॉर्ड है, जो अभी तक बना हुआ है। नदी में इतना पानी आ जाने की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस साल तटबंधों के बीच रहने वालों ने सामूहिक मृत्यु की एक तरह से तैयारी कर ली थी। कोसी तटबंधों के बीच लिलजा, मजरही, कोठिया आदि गांवों के लोग कचनारी कुंवर के डीह आरापट्टी में इकट्ठा हो गए थे, जहां भारी चीख-पुकार मची हुई थी। यहां दूर से घरों के नदी के पानी में गिरने की आवाजें सुनाई पड़ती थीं और लोग अंदाजा लगाते थे कि किसका घर गिरा होगा।

कोसी-तटबंधों के बीच सुपौल, सहरसा, मधुबनी व दरभंगा जिलों के 380 गांवों में रह रहे करीब 15 लाख लोग आज भी स्थायी हल तलाश रहे हैं।

कितने जानवरों का नुकसान हुआ, किसी को पता नहीं, कितने खूंटे से बंधे मर गए, उसका भी कोई हिसाब नहीं। कितना अनाज नष्ट हुआ, कितने बेघर हो गए, यह सब धीरे-धीरे पता लगा। हम आशा करते हैं, ऐसा इस साल नहीं हुआ होगा और जितना यह मौसम अभी बाकी है, उसमें कोई अनिष्ट न होगा। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं, क्योंकि 1984 में लगभग इसी परिस्थिति में कोसी का पूर्वी तटबंध टूटा था और 1987 में भी टूट गया था, मगर एकदम आखिरी किनारे पर कोई विशेष क्षति नहीं हुई थी। 2008 में कुसहा (नेपाल) में जो पूर्वी तटबंध में दरार पड़ी थी, वह 18 अगस्त के दिन पड़ी थी। इसलिए हम अभी भी खतरे के बीच फंसे लोगों के प्रति सहानुभूति के कारण ऐसा कह पा रहे हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि तटबंध टूटने की शुरुआत भारतीय सीमा से लगे नेपाल के डलवा गांव से 1963 से हो चुकी थी।

वर्तमान स्थिति यह है कि गत 20 जून को कोसी का प्रवाह 2.39 लाख क्यूसेक था, जिससे लोगों के घरों में नदी का पानी पहुंच गया था और यह आशा की जाती थी कि इसकी पूर्व सूचना प्रशासन द्वारा दी गई होती, तो लोगों को सुरक्षित स्थान तक जाने में मदद मिल जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ। तटबंधों के बीच फंसे अनेक घर कटाव के शिकार हो गए हैं। अब बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन को यह स्मरण कराना पड़ रहा है कि 3 सितंबर, 2016 को बाढ़ पीड़ितों को उसने कुछ आश्वासन दिए थे और कुछ शर्तें रखी थीं। यह आश्वासन पूरा करने का अब समय आ गया है। उस पत्र में कहा गया है, 'जहां तक उन परिवारों का संबंध है, जिनका घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह या क्षतिग्रस्त हो गया है अथवा एक सप्ताह से अधिक दिनों तक जल-प्लावित रहा है, उसे वस्त्र व बर्तन और घरेलू सामान हेतु देय अनुदान भी दिया जाएगा।' इसलिए सभी बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन दिया जाए तथा तटबंधों के भीतर जहां-जहां गांव कट रहे हैं, वहां आवश्यकतानुसार सामूहिक रसोई की व्यवस्था की जाए। कटाव पीड़ितों के आवागमन के लिए सरकारी नाव की व्यवस्था हो और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकारी जमीन पर तत्काल की जाए। इसी तरह, तत्काल सहायता के रूप में प्रस्तावित धनराशि उन्हें मुहैया कराई जाए। इसके अलावा तटबंधों पर मोबाइल डिस्पेंसरी की व्यवस्था करके डॉक्टरी सहायता गांवों तक पहुंचाई जाए।

बिहार के कोसी पीड़ितों के पुनर्वास के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तटबंधों के बीच सुपौल, सहरसा, मधुबनी और दरभंगा जिलों के 380 गांवों में रह रहे लगभग 15 लाख लोग सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संत और पापी का फर्क

इस धरती पर अपराधी, समाज विरोधी, विद्रोही और नकारात्मक व्यक्तित्व भी आधा है। निषेध और विरोध करने वाले ये नकारात्मक लोग वे हैं, जो कभी महान राजनेता, तो कभी क्रांतिकारी बन जाते हैं और संसार में निषेध और विरोध का जहर उगलते हैं। हिटलर हो या स्तालिन अथवा मुसोलिनी या माओ, ये नकारात्मक लोग हैं। ये संतों के ठीक उल्टे हैं, पर एक मामले में दोनों लगभग एक जैसे हैं। ये भी संतों की तरह आधे-अधूरे हैं। अंतर केवल एक है- संत ने अपने अचेतन में जो छिपाया है, उससे ही अपने चेतन का निर्माण किया है।

इस संसार में सामान्यतः दो तरह के लोग होते हैं- संत और पापी। मगर ये दोनों एक साथ चलते हैं। एक ऐसे संसार में, जहां कोई पापी न हो, तो वहां कोई संत भी न होगा। और उस संसार में जहां कोई संत न हो, वहां कोई पापी भी नहीं होगा। ये दोनों एक ही धंधे के दो साझेदार हैं। ये दोनों एक साथ रहते हैं, वे एक-दूसरे की सहायता करते हैं। बिना एक के दूसरा भी जीवित नहीं रह सकता। इस अस्तित्व में ही नहीं रह सकता। पापी संत को परिभाषित करता है और संत पापी की परिभाषा देता है।

एक ऋषि या फकीर के पास भिन्न तरह की चेतना होती है। वह अखंड होती है। वह न तो विधायक होती है और न नकारात्मक, उसने दोनों के गुणों को अवशोषित कर लिया होता है। वह सर्व-स्वीकार होता है। जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है, उसी को एक इकाई में रूपांतरित करना है। मनुष्य को चुनाव नहीं करना, बल्कि स्वीकार करना है। स्मरण रहे, स्वीकार भाव से मेरा तात्पर्य सहनशीलता से नहीं है। जब तुम किसी चीज को सहन करते हो, तो इसका अर्थ है, तुमने उसे स्वीकार नहीं किया है। तुम कहते हो, 'क्या किया जा सकता है? उसे छोड़ा नहीं जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, तो मुझे उसे सहना ही पड़ेगा।' मगर स्वीकार भाव एक प्रसन्नतापूर्ण स्वागत है, 'जो कुछ परमात्मा ने दिया है, जरूर उसका कुछ अर्थ होगा, यद्यपि हो सकता है कि ठीक अभी मैं उसे समझने में समर्थ न हो सकूं। मुझे उसे खोजना होगा।' इसमें यह समझ निहित है कि जो कुछ हमें दिया गया है, उसका अर्थ है, अन्यथा वह मुझे दिया ही नहीं गया होता।

संत का स्वीकार भाव एक प्रसन्नतापूर्ण स्वागत है, 'जो कुछ परमात्मा ने दिया है, जरूर उसका कुछ अर्थ होगा। यद्यपि हो सकता है, अभी मैं उसे समझने में समर्थ न हो सकूं। मुझे उसे खोजना होगा।'

एक ऋषि या फकीर धार्मिक व्यक्ति होता है, क्योंकि वह अखंड होता है। वह अपनी काम-वासना से इनकार नहीं करता, अपने क्रोध से इनकार नहीं करता, वह किसी भी चीज से मना नहीं करता। वह प्रत्येक चीज को गहरी समझ, कृतज्ञता और स्वागत भाव से स्वीकार करता है। और उस पूरी समझ, उस स्वागतपूर्ण दृष्टिकोण से चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। एक महान रासायनिक परिवर्तन होता है। यह चमत्कार एक फकीर या ऋषि में ही घटता है। उसका क्रोध करुणा बन जाता है। काम-वासना ध्यान, समाधि बन जाती है।

ओशो

कमला हैरिस | अमेरिकी उप-राष्ट्रपति

अमेरिका के हरेक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह बंदूक हिंसा के खौफ से आजाद जिंदगी जिए। हमें इसका हल पता है। कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को इस दिशा में कदम उठाने का साहस दिखाना चाहिए!

अनुलोम-विलोम
डिजिटल हाजिरी

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में कैसा ऐतराज

उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति का मामला गरम होता जा रहा है। सोमवार को यह आदेश लागू हुआ है, लेकिन इससे पहले से ही विरोध की आवाजें मुखर हैं। शिक्षक काली पट्टी बांधकर अपने दायित्व को निभा रहे हैं। शिक्षकों के इस विरोध का शायद ही कोई मतलब है। उनको समझना चाहिए कि ऑनलाइन प्रक्रिया से सिस्टम में पारदर्शिता आती है और रियल टाइम, यानी वास्तविक समय पर उनकी उपस्थिति जांची जा सकेगी। इतना ही नहीं, शिक्षकों व छात्रों का पूरा विवरण ऑनलाइन होगा, जिससे सुविधाओं की पहुंच व कमियों को दूर करने का मौका मिल सकेगा। शिक्षकों की यह शिकायत भी रही है कि हाजिरी के नाम पर उनको बेवजह प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए यदि डिजिटल हाजिरी लगेगी, तो किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ेगी और शिक्षकों का उत्पीड़न बंद हो सकेगा।

साफ है, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का स्वागत किया जाना चाहिए। पूर्व में ऐसी घटना भी सामने आ चुकी है, जिसमें स्कूल के प्रधानाचार्य से शिक्षक मिलीभगत करके स्कूल गए बिना अपनी हाजिरी लगवा लिया करते थे। इससे स्वाभाविक ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। स्कूल में ही शिक्षकों की हाजिरी लगेगी और वह भी एक तय वक्त पर। शिक्षकों का विरोध इसी बात को लेकर ज्यादा है। उनका कहना है कि बारिश या अन्य मौसमी आपदाओं में या किसी अन्य कारण से कभी-कभी स्कूल आने में विलंब हो सकता है। ऐसी सूरत में यह एप उनको अनुपस्थित दिखा सकता है। शिक्षकों का यह डर वाजिब है, लेकिन जब मौसम खराब हो, तो वे कुछ देर पहले घर से निकलें। छात्र भी यदि सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं, तो उनको डांट लगती है। कहीं-कहीं तो उनकी उपस्थिति भी काट दी जाती है। तो फिर शिक्षकों को क्या दिक्कत है? उनको सोचना चाहिए कि क्या होगा यदि डॉक्टर भी मौसम खराब की बात कहते हुए कुछ देर बाद मरीज तक पहुंचे? इससे क्या मरीज की जान सांसत में नहीं आ जाएगी? इसलिए, जब डॉक्टर तय वक्त पर पहुंच सकते हैं, तो शिक्षक क्यों नहीं?

शिक्षकों को अपना यह विरोध-प्रदर्शन वापस ले लेना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। जब सभी विभागों में डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य की जा रही हो, तो शिक्षकों को इसमें छूट देने का कोई मतलब नहीं है। उनको तो कहीं अधिक खुशी से इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समाज के असल मार्गदर्शक तो शिक्षक ही होते हैं।

विकास कुमार झा, टिप्पणीकार

शिक्षकों को इस व्यवस्था से दूर रखना चाहिए

यह सही है कि इन दिनों कमोबेश हर जगह अथवा हर विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का चलन है, जिसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। मगर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं, जिनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। विशेषकर तकनीकी व अन्य व्यवस्थागत खामियों की वजह से कम के कम शिक्षकों के लिए इस व्यवस्था का सुचारू संचालन संभव नहीं है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक डिजिटल हाजिरी के खिलाफ विरोध पर उतारू हैं। इसके पीछे उनके तर्क वाजिब हैं। एक ओर शिक्षकों को दूर-दराज के विद्यालयों में पठन-पाठन के कार्यों को संपादित करने जाना पड़ता है। रास्तों में नदी, नाले, जलभराव व जाम जैसी अनेक समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि इन शिक्षकों से पठन-पाठन के अलावा भी कई तरह के काम कराए जाते हैं। इससे उनका ध्यान अपने मूल काम से बंट जाता है। लिहाजा, सरकार यदि सोचती है कि शिक्षकों की महज ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करके वह सरकारी विद्यालयों की सेहत सुधार लेगी, तो यह एकांगी सोच है। इसकी मूल वजह यह है कि आज भी ज्यादातर सरकारी विद्यालय भौतिक व मानव संसाधनों के घोर अभाव का सामना कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि दूर-दराज के इलाकों में आज भी नेटवर्क की समस्या रहती है। भारत संचार निगम लिमिटेड की खस्ताहाल स्थिति से तो सभी वाकिफ हैं। मगर इन दिनों निजी क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं कही जा सकती है। ऐसे में, शुचिता को किसी खास खांचे में बांधना उचित नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि नैतिकता व्यक्ति के भीतर से आती है। अगर इन शिक्षकों की नियुक्ति-प्रक्रिया पारदर्शी है और प्रशिक्षण उचित ढंग से हुआ है, तो निस्संदेह बिना डिजिटल हाजिरी के भी वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करेंगे। यकीन मानिए।

मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार

बुनियादी ढांचा सुधारिए

शिक्षकों पर तो सबकी नजर है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों, बदहाल स्कूलों और कमजोर बुनियादी ढांचे पर किसी की नजर नहीं है। आज भी कई शिक्षकों को कई किलोमीटर लंबा सफर तय करके स्कूल आना होता है। रास्ते में जाम की आशंका होती है, गांव की सड़कें भी हरसंभव दुश्वारियां पैदा करती हैं, इसलिए शिक्षकों की मुश्किलों को समझे बिना उन पर डिजिटल हाजिरी के नियम थोप देना गलत है। लगता यही है कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं।

समिधा, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 10 जुलाई, 2024

दैनिक जागरण

मौन कई अप्रिय स्थितियों से बचा लेता है

रूस में भारत की बात

तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा में मास्को जाकर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी इस यात्रा में उन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जिस तरह यह कहा कि बम-बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती, उससे उनके उस चर्चित कथन का स्मरण हो आया, जिसमें उन्होंने पुतिन से दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच यह भी कह दिया कि युद्ध या संघर्ष अथवा आतंकी हमलों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है। भले ही भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के अवसर पर यूक्रेन में रूस का जोरदार हमला वाशिंगटन में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो की बैठक को देखते हुए पश्चिमी देशों को संदेश देने के लिए किया गया हो, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रूसी राष्ट्रपति को यह संदेश देना आवश्यक हो गया था कि भारत इस तरह के हमलों का समर्थन नहीं करता। देखना यह है कि यूक्रेन युद्ध पर भारतीय प्रधानमंत्री की फिर से खरी बात पर रूसी राष्ट्रपति कितना ध्यान देते हैं, लेकिन भारत को रूस के साथ अपनी मित्रता जारी रखते हुए यह स्पष्ट करते रहना होगा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त होते हुए देखना चाहता है। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के भी हित में है।

यह समझना कठिन है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत का पूरा विवरण सामने आने के पहले ही अपनी नाराजगी क्यों जता दी? उन्होंने एक तरह से कूटनीतिक अपरिपक्वता और उतावलेपन का ही परिचय दिया। उनके इस अपरिपक्व व्यवहार के बावजूद भारत के लिए यही उचित होगा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को खत्म कराने के लिए हरसंभव प्रयास करे। इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे आने से एक तो भारत के हित सधेंगे और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका कद बढ़ेगा। भारत के लिए यह भी आवश्यक है कि वह रूस से अपने संबंध आगे बढ़ाते हुए इस पर ध्यान दे कि उसे जिस चीन से खतरा है, उस पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारत को रूस को यह संदेश देना ही होगा कि उसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चीन को अपनी हद में रहने के लिए कहना होगा। इस सबके बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारत रूस को उसकी जरूरत की सामग्री का निर्यात नहीं कर पा रहा है।

जन जागरूकता जरूरी

उत्तराखंड में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कसरत दिखने लगी है। हर साल मानसून बरसने के साथ ही इन बीमारियों की आशंका गहराने लगती है। इनसे हर वर्ष कई लोगों की जान चली जाती है। पिछले वर्ष प्रदेश में डेंगू के चार हजार से अधिक मामले सामने आए थे, इसमें 1200 से अधिक देहरादून के थे। तब यहां तेरह लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। चूंकि, अभी मानसून काल शुरू हुआ है, ऐसे में अगले तीन महीने तक डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बना रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए समुचित कदम उठाए। इसके प्रति जन को भी जागरूक होना होगा। देखने में आता है कि छोटी-छोटी लापरवाही इन बीमारियों के विकराल होने का कारण बन जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के स्तर से चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम में लार्वा नष्ट करने के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह चिंता में डाल रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे घर मिल रहे हैं, जहां मच्छरों का लार्वा मिल रहा है। यह इस बात का संकेत है कि लोग अभी उतने जागरूक नहीं हैं, जितनी अपेक्षा की जा रही है। इस दिशा में और अधिक सक्रियता के साथ काम करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन की यह अच्छी पहल है कि उसने स्कूली बच्चों को डेंगू के खतरे से बचाने के लिए यूनिफार्म को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी अपनी तैयारियां चल रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में दस प्रतिशत बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित रखने को कहा गया है। यह सब ठीक है, लेकिन इसका अनुपालन प्रभावी ढंग से हो, इस पहलू पर भी गौर किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह आदेश कागजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समय रहते सभी की जवाबदेही तय कर दी जानी चाहिए। क्योंकि जब स्थितियां नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। जान का जोखिम भी बढ़ जाता है। पिछले अनुभव तो यही कहानी बयां करते हैं।

परस्पर हितों वाली मैत्री

श्रीराम चौलिया

मोदी-पुतिन शिखर बैठक में हुई घोषणाओं में कई ऐसे मुद्दे सुलझने के स्पष्ट संकेत दिखे, जो पिछले कुछ समय से अटके हुए थे

अवधेश राजपूत

पांच वर्षों के अंतराल के पश्चात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूस दौरे ने खासी उत्सुकता जगाई है। कुछ समीक्षकों के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मोदी का भव्य स्वागत और कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के उनके निर्णयों ने सिद्ध कर दिया कि भारत पश्चिम समर्थक विदेश नीति का पालन न करते हुए गुटनिरपेक्ष रुख अपना रहा है। कुछ ने यह भी अटकलें लगाई हैं कि मोदी ने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए रूस को अपना गंतव्य ठीक उसी समय चुना, जब अमेरिका में नाटो गठबंधन के सदस्य देश रूस विरोधी शिखर वार्ता के लिए इकट्ठे हो रहे थे। यानी भारत ने मानो कोई संकेत दिया है कि वह पश्चिमी शक्तियों द्वारा सुझाई गई लकीर पर नहीं चलने वाला। इन अटकलों के बीच भारत ने रूस के साथ पुरानी मित्रता को बरकरार रखकर अपनी जानी-पहचानी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन किया है। हालांकि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि भारत रूस के साथ लंबे अर्से से चली आ रही सामरिक साझेदारी से पश्चिम को ललकार रहा है। रूस समर्थकों ने भले ही यह दर्शाना चाहा हो कि मोदी की यात्रा से भारत ने पश्चिम को चुनौती दी है और इससे पश्चिमी देश 'ईर्ष्या से जल रहे हैं', परंतु असल में भारत ऐसा कोई मंतव्य नहीं रखता है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने स्पष्ट किया है कि 'हम रूस के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से द्विपक्षीय संदर्भ के ढांचे से देखते हैं' और इस भागीदारी के माध्यम से हमारा पश्चिम के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने का कोई इरादा नहीं है।

वर्ष 2022 में जबसे रूस-यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ है, तबसे दुनिया विपरीत खेमों में बंटी हुई है। इस संदर्भ में रूस के प्रति हमारा रवैया वास्तविकता और व्यावहारिकता के आधार पर टिका है। इसमें वैश्विक विचारधारा के द्वंद्वों का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत और रूस की मैत्री वक्त की कसौटियों पर जांची-परखी और खरी है। भारत के 60 प्रतिशत सैन्य प्लेटफार्म रूसी मूल के हैं। भारत के तेल आयात में रूसी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। रक्षा हो या ऊर्जा सुरक्षा, रूस अब भी हमारे लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इन ठोस कारकों को देखते हुए भारत रूस से मित्रता जारी रखना चाहता है और आपसी लेनदेन में उत्पन्न हो रही बाधाओं और असंतुलन का हल निकालना चाहता है। मोदी-पुतिन शिखर बैठक के बाद की गई घोषणाओं में कई ऐसे मुद्दे सुलझने के स्पष्ट संकेत देखने को मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस भारत के मुख्य सामरिक साझेदारों की सूची में आज भी ऊपरी पायदान पर है। इसके बावजूद भारत रूस की कमजोरियों और परेशानियों से वाकिफ है।

यूक्रेन युद्ध से जुड़े पश्चिमी आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने रूस के उज्ज्वल भविष्य पर प्रश्न चिह्न लगाया है। युद्ध से जुड़ी गतिविधियों के चलते रूस की आर्थिक वृद्धि तेज हुई है, लेकिन यह विकास टिकाऊ एवं सतत नहीं होने वाला। रूस की अर्थव्यवस्था भारत से काफी छोटी है और वह फिलहाल विश्व में ग्यारहवें स्थान पर है। इसके साथ ही, सैन्य नवाचार और अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण में रूस जितना माहिर हुआ करता था, आज इस मामले में वह उतना महारथी नहीं रह गया। यही कारण है कि पिछले एक दशक में रक्षा आयात के क्षेत्र में भारत ने विविधीकरण की नीति के अंतर्गत रूस से सैन्य सामग्री की खरीदारी काफी घटाई है। एक समय भारत की सैन्य सामग्री की 70 प्रतिशत तक पूर्ति रूस से होती थी, जो अब करीब आधी घटकर 36 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान फ्रांस जैसे सामरिक सहयोगियों की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक एवं आत्मीय कारणों से भारत रूस को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन वह उसकी मौजूदा स्थिति से भलीभांति अवगत है। यही कारण है कि रूस की उपयोगिता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं आंका जा रहा है।

भूराजनीति के दृष्टिकोण से रूस एक समय भारत के लिए चीन की काट बना हुआ था। उस समय रूस वैश्विक महाशक्ति था तो चीन के विस्तारवाद और आक्रामक व्यवहार पर अंकुश लगाए रखता था। दुर्भाग्यवश आज पश्चिमी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव से मुक्ति के लिए रूस चीन पर सर्वाधिक निर्भर हो गया है। ऐसे में भारत की अपेक्षा है कि हम रूस के साथ मित्रता को आगे बढ़ाएं, ताकि चीन पूरी तरह से रूस पर हावी न हो जाए। पुतिन स्वयं भी चाहते हैं कि भारत की दोस्ती के आधार पर रूस चीन के सामने पराधीन और बेबस न नजर आए। हालांकि जिस तादाद में चीन रूस के साथ व्यापार और सैन्य सहयोग कर रहा है, उतनी क्रय शक्ति फिलहाल भारत के पास नहीं है कि वह रूस के लिए दूसरा विकल्प बन सके। भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के नौसैनिक दबदबे की काट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति में हमें शायद ही रूस का साथ मिल सके, क्योंकि चीन की तरह रूस भी हिंद-प्रशांत की अवधारणा को अमेरिकी षड्यंत्र मानता है। रूस-भारत सैन्य सामग्री (लाजिस्टिक) समझौते पर भी कुछ बात आगे बढ़ी है, लेकिन लगता नहीं कि रूस किसी भी स्थिति में चीन से प्रतिस्पर्धा वाले प्रत्यक्ष गठबंधन का हिस्सा बनेगा। भारत-रूस संबंधों का सार यही है कि रूस चाहता है कि भारत पश्चिम का मुकाबला करने में उसकी मदद करे, जबकि भारत चाहता है कि चीन से मुकाबले में रूस उसके साथ आगे आए। इन विरोधाभासों के मद्देनजर भारत जानता है कि रूस के साथ उसकी 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' की सीमाएं हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन सीमाओं को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोग को जितना बढ़ाया जा सकता है, उतना बेहतर है। तेजी से बदलती और कठिन होती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इतिहास, भूगोल और आपसी विश्वास पर आधारित रूस-भारत साझेदारी अपनी धुरी पर टिकी हुई है। यह तय है कि दोनों देश इसे कायम रखने के लिए अपने स्तर पर प्रतिबद्धता दिखाते रहेंगे।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

कमीशनखोरी की कीमत चुकाता देश

राजीव सचान

इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि देश में दोयम दर्जे के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो रहा है

आधारभूत ढांचे की खुलती पोल। प्रेट्र

इन दिनों देश के कई हिस्सों से पुलों के गिरने, सड़कों के धंसने, हाईवे में गड्ढे होने और रेल पटरियों के क्षतिग्रस्त होने के समाचार आ रहे हैं। बरसात में ऐसे समाचार आते ही हैं। यह तय है कि जब कहीं कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते प्रायः होने लगी है तो वहां जलभराव होगा। इसका उदाहरण कुछ समय पहले उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे वाले शहर दुबई में भी मिला था, जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था, लेकिन अपने देश में थोड़ी सी अधिक और कई बार तो मामूली बरसात में जगह-जगह जलभराव ही नहीं हो जाता, बल्कि आधारभूत ढांचे की पोल भी खुल जाती है। इससे इन्कार नहीं कि पिछले कुछ समय से देश में आधारभूत ढांचे का निर्माण तेजी से हो रहा है। देश भर में हाईवे, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, सबवे के साथ हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन बन या संवर रहे हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय है। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए इस आधारभूत ढांचे की मजबूती की पोल खुलती रहती है, लेकिन हमारे नीति-नियंता चेत नहीं रहे हैं। जब कहीं कोई सड़क, पुल या आधारभूत ढांचे से जुड़ा कोई अन्य निर्माण टूटता-फूटता है तो विरोधी दल सत्ताधारी दल पर टूट पड़ते हैं। यह बात और है कि कोई नहीं कह सकता कि अमुक दल द्वारा शासित राज्य में आधारभूत ढांचे के निर्माण में किसी तरह की खामी नहीं। सत्य यह है कि केंद्र या राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, उसके समय में बनाए गए आधारभूत ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठते ही रहते हैं।

पिछले दिनों जब दिल्ली में भारी बरसात के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एक हिस्से की छत गिरी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो विरोधी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। इसके जवाब में सत्तापक्ष के नेताओं की ओर से कहा गया कि इस छत का निर्माण तो मनमोहन सरकार के समय 2009 में कराया गया था। क्या महज 15 वर्ष पुराने निर्माण कार्य का ढह जाना स्वीकार्य है? क्या उसकी देखरेख इसलिए नहीं हो रही थी कि उसका निर्माण पिछली सरकार ने कराया था? इन प्रश्नों के बीच यह खबर आई कि जबलपुर हवाईअड्डे की छत गिर गई। जबलपुर के बाद राजकोट हवाईअड्डे की भी छत गिरने की खबर आ गई। इन दोनों हवाईअड्डों का लोकार्पण हाल में ही किया गया था। आधारभूत ढांचे की पोल खोलने वाली इन घटनाओं को महज दुर्योग नहीं कहा जा सकता। ये घटनाएं कहीं न कहीं यही बताती हैं कि सरकारी एजेंसियों की ओर से दोयम दर्जे का निर्माण कराया जा रहा है। इसका पता बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने से भी चलता है। ये सभी बहुत पुराने पुल नहीं थे। इनमें से कुछ 10-20 साल पुराने भी थे। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जब अंग्रेजों के बनाए तमाम पुल अभी सही सलामत हैं, तब 10-20 साल पुराने पुल भी ढह जा रहे हैं? सड़कों और यहां तक कि हाईवे की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। अपने देश में ज्यादातर सड़कें पहली बरसात का भी सामना नहीं कर पातीं। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि अपने देश में दोयम दर्जे के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माण में मानकों की अनदेखी का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। कई बार यह भ्रष्टाचार नेताओं और नौकरशाहों की ओर से मिलकर किया जाता है और कई बार उसके लिए केवल नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। रिश्वतखोर नौकरशाह भ्रष्ट ठेकेदारों को तैयार करते हैं और फिर दोनों मिलकर दोयम दर्जे का निर्माण करते हैं। हर तरह के निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी यानी दलाली एक अलिखित नियम है। अलग-अलग राज्यों में इस दलाली की भिन्न-भिन्न दरें हो सकती हैं, लेकिन निर्माण कार्यों के एवज में खर्च धनराशि का भुगतान बिना कमीशन हासिल करना आसान नहीं। ऐसा नहीं है कि शासकगण इससे परिचित न हों, लेकिन वे नौकरशाही में सुधार की दिशा में बढ़ने के बजाय उससे इन्कार कर रहे हैं। यह तब है जब नौकरशाही के भ्रष्टाचार की कीमत प्रायः उन्हें ही चुकानी पड़ती है।

नेतागण इससे अनजान नहीं कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार अथवा जन समस्याओं के प्रति उसकी बेरुखी के चलते जनता की नाराजगी का सबसे अधिक सामना उन्हें ही करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे नौकरशाही में सुधार की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते? अपने देश में प्रशासनिक सुधार एक लंबे समय से लंबित हैं। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जिस दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, उसकी रपट मनमोहन सरकार के समय भी ठंडे बस्ते में पड़ी रही और मोदी सरकार के समय भी। निःसंदेह किसी भी सरकार का काम नौकरशाही के बिना नहीं चल सकता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसे मनमानी करने दी जाए। देश में फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। जो सरकारें कठोर फैसलों के लिए जानी जाती हैं, वे भी प्रशासनिक सुधारों से बचती हैं। इससे भी खराब बात यह है कि कई बार वे अपने ही दल के जनप्रतिनिधियों से अधिक नौकरशाहों पर भरोसा करती हैं। करीब-करीब सभी यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले, उसका एक बड़ा कारण नौकरशाही की मनमानी रही, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि उसे जवाबदेह बनाने की कोई ठोस पहल होगी। क्या हमारे नेता यह बुनियादी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बेलगाम नौकरशाहों की मनमानी के कारण वे तो बदनाम होकर सत्ता से बाहर हो जाते हैं, लेकिन नौकरशाह मजे करते रहते हैं?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विरासत

विरासत शब्द सुनते ही हमें अपने अतीत का स्मरण होने लगता है। विरासत से किसी भी व्यक्ति की पहचान जुड़ी रहती है। विरासत का स्वाभिमान व्यक्ति को अपने पूर्वजों पर गौरव का भाव जगाता है। ये वही पूर्वज हैं जिन्होंने अपनी विरासत को स्थापित किया और उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते गए। विरासत एक भाव है, जो भाव उससे जुड़े व्यक्ति को कुछ विशेष होने का अनुभव कराने का निमित्त बनता है।

सकारात्मक और लोक कल्याणकारी विरासत पूजनीय होती है। उसे सदैव स्मरण किया जाता है। उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। जबकि बुरे भाव से जुड़ी विरासत स्वीकार्य नहीं होती। उसके प्रति द्वेष का भाव स्वतः प्रकट होने लगता है। दुर्दांत एवं विनाशकारी प्रवृत्ति के लोगों के कृत्यों के प्रति मानवता का भाव नकारात्मक रहता है। समाज उससे स्वयं को जोड़ना नहीं चाहता। उससे छुटकारा पाना चाहता है। विरासत एक पहचान की तरह सदैव हमारे साथ चलती है। पिता की विरासत स्वतः उसके पाल्यों के साथ चलने लगती है। अब पाल्यों का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों की विरासत को संजोए रखें।

श्रीराम का लोककल्याणकारी भाव भारत की विरासत है। श्रीकृष्ण का गीता ज्ञान भारत की विरासत है। बुद्ध, गुरुनानक देव और महावीर स्वामी का चिंतन भारत की विरासत है। ऐसी महनीय विरासत को भी जीवन में आत्मसात करना हमारा परम कर्तव्य है। विरासत केवल भौतिक वस्तुएं, महल या इमारतें मात्र ही नहीं होती, बल्कि विचार और उदात्त चिंतन भी स्वर्णिम विरासत की अभिव्यक्ति होते हैं, जो हमें हमारे महापुरुषों ने प्रदान किए हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी बौद्धिक विरासत को समृद्ध करने में संलग्न रहना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है और एक अनुकरणीय विरासत सदैव प्रेरित करने वाली होती है।

ललित शौर्य

जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय संकट

सुधीर कुमार

जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। बढ़ती जनसंख्या का पारिस्थितिकी-तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से कई सामाजिक-आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरणीय गिरावट के कारण सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करना भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। जनसंख्या में वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव का मुख्य कारण है। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है, भूमि, भोजन, जल, जीवाश्म ईंधन और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खपत अनियंत्रित हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के बढ़ते उपभोग की प्रवृत्ति इसकी मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन भविष्य की पीढ़ियों को कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों से वंचित कर सकता है।

जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है, भूमि, भोजन, जल, जीवाश्म ईंधन और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खपत अनियंत्रित हो जाती है

जनसंख्या में वृद्धि अनियोजित शहरीकरण और अंधाधुंध उद्योगीकरण को भी बढ़ावा देती है। ये दोनों आर्थिक प्रक्रियाएं, जिन्हें अक्सर आर्थिक विकास का पर्याय माना जाता है, पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बढ़ती आबादी की भोजन और आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी वनोन्मूलन, कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण, कल-कारखानों की स्थापना तथा भूजल दोहन, ऊर्जा उपभोग में वृद्धि और पानी की निर्मम बर्बादी से पारिस्थितिकी-तंत्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। औद्योगिक और शहरी विस्तार के लिए जंगलों का सफाया करने से जैव विविधता में कमी और जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह तापमान में वृद्धि और वर्षा में कमी के लिए भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ अनियोजित शहरीकरण और उद्योगीकरण के लिए बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों तथा विभिन्न घरेलू आवश्यकताओं में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है। इससे भूजल स्तर में गिरावट आती है। वहीं औद्योगिक प्रक्रियाओं और शहरी जीवनशैली में पानी के सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी आम है।

बढ़ती जनसंख्या उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों पर भी दबाव बढ़ाती है। गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अंधाधुंध इस्तेमाल भावी पीढ़ी की जरूरतों को प्रभावित कर सकती है। जीवाश्म ईंधन का दोहन पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण बन चुका है। जाहिर है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की स्थिरता को प्रभावित करती है। अतः जीवन के सुचारु संचालन के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

आतंक का स्थायी समाधान आवश्यक

'आतंक का सामना' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उचित ही लिखा गया है। पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां एक बड़ी चिंता के रूप में उभरी हैं। हाल के संसदीय चुनावों में राज्य की जनता ने बढ़-चढ़कर मतदान कर पिछले कई वर्षों के रिकार्ड ध्वस्त किए थे। इससे राज्य की जनता के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसे की व्यापक रूप से पुष्टि हो रही थी और इस पर्वतीय राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनावों की उम्मीद जगने लगी थी। इतना ही नहीं, उसके पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी बातें सामने आ रही थीं कि नीतिगत गलियारों में इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

हालांकि, जिस प्रकार से बीते दिनों में जम्मू संभाग में भी आतंकी हमलों की आवृत्ति बढ़ी है उसे देखते हुए चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जे का मुद्दा शायद ठंडे बस्ते में चला जाए। आतंकी राज्य में हालात बिगाड़ने पर आमादा हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब मिले। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान की तबीयत छोटी-मोटी गोली से नहीं, बल्कि तगड़े इंजेक्शन या सर्जरी से ही सुधरती है और फिर वह कुछ समय शांत रहता है। बेहतर तो यही होगा कि इस बार कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का स्थायी समाधान हो जाए। आखिर हम कब तक क्षति उठाते रहेंगे।

केशव तिवारी, आजमगढ़

बायोमीट्रिक हाजिरी का विरोध अनुचित

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए आनलाइन बायोमीट्रिक से हाजिरी दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। इसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से शिक्षा सेवा में लगे लाखों लोगों की उपस्थिति का वास्तविक ब्यौरा सरकार तक पहुंच जाएगा। आज के युग में तकनीकी के माध्यम से दुनिया में लोगों के जीवन में आमूल बदलाव आ रहा है। बहुत हद तक यह नई तकनीकी अधिक पारदर्शी एवं कुशल है, जिसके चलते तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार द्वारा प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की इस पहल का सेवा में लगे लोगों द्वारा एक सिरे से विरोध हो रहा है। इसी तरह का एक विरोध प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से वर्ष 2017 में तब किया गया था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी कर्मियों को सुबह नौ बजे तक कार्यालय पहुंचने को कहा था। उत्तर प्रदेश सरकार का केवल बेसिक शिक्षा का बजट 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इतना अधिक धन खर्च होने के बाद भी यदि अधिकांश प्राइमरी शिक्षक बायोमीट्रिक हाजिरी के खिलाफ जाकर जवाबदेही से बचना चाहते हैं तो इस घाघ मानसिकता का इलाज खोजना होगा। ऐसे लोग बच्चों में किस तरह की नैतिकता का विकास कर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की नींव रख सकेंगे?

प्रखर द्विवेदी, गोरखपुर

न हो झूठ की राजनीति

'झूठ की राजनीति का असर' शीर्षक से लिखे आलेख में ए. सूर्यप्रकाश का कहना सही है कि संविधान और आरक्षण को खत्म करने के असत्य को इतने सुनियोजित रूप से फैलाया गया कि एक बड़े तबके को यह सच प्रतीत होने लगा, जबकि वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और मोदी सरकार ने आरक्षण की सीमा को कई बार बढ़ाया। और तो और वाजपेयी सरकार ने प्रोन्नति में एससी, एसटी वर्ग को राहत देने वाले कई फैसले लिए। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। बावजूद विरोधी का दुष्प्रचार कामयाब रहा, लेकिन झूठ फैलाए जाने की प्रवृत्ति से जो जनमत तैयार होगा उससे काम करने वाली सरकारों का मनोबल टूटेगा। लिहाजा राजनीति में झूठे प्रचार-प्रसार का खेल खत्म हो, यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पर आधारित हो, अन्यथा लोकतंत्र कमजोर होगा। इस बात की आशंका है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष इस तरह का दुष्प्रचार करेगा।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

मौन कई अप्रिय स्थितियों से बचा लेता है

रूस में भारत की बात

तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा में मास्को जाकर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि भारत के लिए रूस की मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी इस यात्रा में उन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जिस तरह यह कहा कि बम-बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती, उससे उनके उस चर्चित कथन का स्मरण हो आया, जिसमें उन्होंने पुतिन से दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के मौके पर ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बच्चों के अस्पताल को भी निशाना बनाया, इसलिए उन्होंने बिना किसी संकोच यह भी कह दिया कि युद्ध या संघर्ष अथवा आतंकी हमलों में जब मासूम बच्चों की मौत होती है तो हृदय छलनी हो जाता है। भले ही भारतीय प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा के अवसर पर यूक्रेन में रूस का जोरदार हमला वाशिंगटन में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो की बैठक को देखते हुए पश्चिमी देशों को संदेश देने के लिए किया गया हो, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के लिए रूसी राष्ट्रपति को यह संदेश देना आवश्यक हो गया था कि भारत इस तरह के हमलों का समर्थन नहीं करता। देखना यह है कि यूक्रेन युद्ध पर भारतीय प्रधानमंत्री की फिर से खरी बात पर रूसी राष्ट्रपति कितना ध्यान देते हैं, लेकिन भारत को रूस के साथ अपनी मित्रता जारी रखते हुए यह स्पष्ट करते रहना होगा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त होते हुए देखना चाहता है। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व शांति के भी हित में है। यह समझना कठिन है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच बातचीत का पूरा विवरण सामने आने के पहले ही अपनी नाराजगी क्यों जता दी? उन्होंने एक तरह से कूटनीतिक अपरिपक्वता और उतावलेपन का ही परिचय दिया। उनके इस अपरिपक्व व्यवहार के बावजूद भारत के लिए यही उचित होगा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को खत्म कराने के लिए हरसंभव प्रयास करे। इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे आने से एक तो भारत के हित सधेंगे और दूसरे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसका कद बढ़ेगा। भारत के लिए यह भी आवश्यक है कि वह रूस से अपने संबंध आगे बढ़ाते हुए इस पर ध्यान दे कि उसे जिस चीन से खतरा है, उस पर रूस की निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारत को रूस को यह संदेश देना ही होगा कि उसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए चीन को अपनी हद में रहने के लिए कहना होगा। इस सबके बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारत रूस को उसकी जरूरत की सामग्री का निर्यात नहीं कर पा रहा है।

पौधारोपण में जनभागीदारी

अपने आवास में एक पौधा लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यस्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने अपील की है कि हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो, अपने आसपास पौधा लगाए। राज्य के हर व्यक्ति और संस्था को इस पवित्र कार्य में शामिल होना चाहिए। और हां, पौधा लगाकर भूल नहीं जाना है। संकल्प यह भी हो कि हम उस पौधे की सेवा वृक्ष बनने तक करें। परिवार के सदस्य की तरह हम उसकी देखरेख करें। राज्य सरकार का यह वृहत आयोजन है। प्रत्येक जिले में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएंगे। सरकारी तंत्र तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन तभी बेहतर ढंग से फलीभूत होगा, जब हम सब इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हर साल लाखों पौधों लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से काफी कम वृक्ष बन पाते हैं। यह इसलिए कि इसमें जनभागीदारी की कमी है। अगर हर व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द लगने वाले पौधे को गोद ले ले, उसकी रक्षा करे तो कोई कारण नहीं कि पौधे सूख जाएं। बस, हमें संकल्प को दृढ़ करना होगा। यह वक्त की जरूरत भी है। वृक्षों के लगातार कटने का नतीजा है कि तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है। राहत तभी मिल सकती है जब वन क्षेत्र बढ़ें। अभी बिहार में महज सात प्रतिशत वन क्षेत्र है, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 25 प्रतिशत का है। साल दर साल वृहत पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाकर ही इस अंतर को पाटा जा सकता है। वैसे तो हर खाली जमीन पर पौधारोपण किया जाना उपयुक्त है, लेकिन तालाबों व नदियों के किनारे यह और भी मुफीद है। यहां पौधों को फलने-फूलने का तो उचित माहौल मिलेगा ही, तालाब और नदियों को भी इससे लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पौधे ऐसे लगाए जाएं जो या तो फलदार हों या प्रचुर मात्रा में आक्सीजन देने वाले।

पौधारोपण में सब अपनी भागीदारी निभाएं, साथ ही इसकी रक्षा का भी संकल्प लें।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या हाथरस कांड में बाबा सूरजपाल की गिरफ्तारी की मांग सही है?

आज का सवाल
क्या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई आवश्यक है?

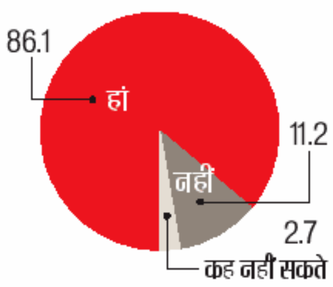

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

परस्पर हितों वाली मैत्री

श्रीराम चौलिया

मोदी-पुतिन शिखर बैठक में हुई घोषणाओं में कई ऐसे मुद्दे सुलझाने के स्पष्ट संकेत दिखे, जो पिछले कुछ समय से अटके हुए थे

पांच वर्षों के अंतराल के पश्चात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूस दौरे ने खासी उत्सुकता जगाई है। कुछ समीक्षकों के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मोदी का भव्य स्वागत और कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के उनके निर्णयों ने सिद्ध कर दिया कि भारत पश्चिम समर्थक विदेश नीति का पालन न करते हुए गुटनिरपेक्ष रुख अपना रहा है। कुछ ने यह भी अटकलें लगाई हैं कि मोदी ने तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए रूस को अपना गंतव्य ठीक उसी समय चुना, जब अमेरिका में नाटो गठबंधन के सदस्य देश रूस विरोधी शिखर वार्ता के लिए इकट्ठे हो रहे थे। यानी भारत ने मानो कोई संकेत दिया है कि वह पश्चिमी शक्तियों द्वारा सुझाई गई लकीर पर नहीं चलने वाला। इन अटकलों के बीच भारत ने रूस के साथ पुरानी मित्रता को बरकरार रखकर अपनी जानी-पहचानी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन किया है। हालांकि यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि भारत रूस के साथ लंबे अर्से से चली आ रही सामरिक साझेदारी से पश्चिम को ललकार रहा है। रूस समर्थकों ने भले ही यह दर्शाना चाहा हो कि मोदी की यात्रा से भारत ने पश्चिम को चुनौती दी है और इससे पश्चिमी देश 'ईर्ष्या से जल रहे हैं', परंतु असल में भारत ऐसा कोई मंतव्य नहीं रखता है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने स्पष्ट किया है कि 'हम रूस के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से द्विपक्षीय संदर्भ के ढांचे से देखते हैं' और इस भागीदारी के माध्यम से हमारा पश्चिम के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने का कोई इरादा नहीं है।

वर्ष 2022 में जबसे रूस-यूक्रेन युद्ध आरंभ हुआ है, तबसे दुनिया विपरीत खेमों में बंटी हुई है। इस संदर्भ में रूस के प्रति हमारा रवैया वास्तविकता और व्यावहारिकता के आधार पर टिका है। इसमें वैश्विक विचारधारा के द्वंद्वों का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत और रूस की मैत्री वक्त की कसौटियों पर जांची-परखी और खरी है। भारत के 60 प्रतिशत सैन्य प्लेटफार्म रूसी मूल के हैं। भारत के तेल आयात में रूसी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। रक्षा हो या ऊर्जा सुरक्षा, रूस अब भी हमारे लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इन ठोस कारकों को देखते हुए भारत रूस से मित्रता जारी रखना चाहता है और आपसी लेनदेन में उत्पन्न हो रही बाधाओं और असंतुलन का हल निकालना चाहता है। मोदी-पुतिन शिखर बैठक के बाद की गई घोषणाओं में कई ऐसे मुद्दे सुलझने के स्पष्ट संकेत देखने को मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस भारत के मुख्य सामरिक साझेदारों की सूची में आज भी ऊपरी पायदान पर है। इसके बावजूद भारत रूस की कमजोरियों

अवधेश राजपूत

और परेशानियों से वाकिफ है।

यूक्रेन युद्ध से जुड़े पश्चिमी आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंधों ने रूस के उज्ज्वल भविष्य पर प्रश्न चिह्न लगाया है। युद्ध से जुड़ी गतिविधियों के चलते रूस की आर्थिक वृद्धि तेज हुई है, लेकिन यह विकास टिकाऊ एवं सतत नहीं होने वाला। रूस की अर्थव्यवस्था भारत से काफी छोटी है और वह फिलहाल विश्व में ग्यारहवें स्थान पर है। रूस और भारत के बीच भारी व्यापार घाटे को कम करने के लिए जो विदेशी निवेश रूस से भारत में आना चाहिए, उतनी पूंजी रूस के पास है ही नहीं। प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश के हिसाब से भारत को रूस के मुकाबले पश्चिमी देशों से कई गुना अधिक लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही, सैन्य नवाचार और अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण में रूस जितना माहिर हुआ करता था, आज इस मामले में वह उतना महारथी नहीं रह गया। यही कारण है कि पिछले एक दशक में रक्षा आयात के क्षेत्र में भारत ने विविधीकरण की नीति के अंतर्गत रूस से सैन्य सामग्री की खरीदारी काफी घटाई है। एक समय भारत की सैन्य सामग्री की 70 प्रतिशत तक पूर्ति रूस से होती थी, जो अब करीब आधी घटकर 36 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान फ्रांस जैसे सामरिक सहयोगियों की हिस्सेदारी काफी बढ़ी है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक एवं आत्मीय कारणों से भारत रूस को अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन वह उसकी मौजूदा स्थिति से भलीभांति अवगत है। यही कारण है कि रूस की उपयोगिता को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं आंका जा रहा है।

भूराजनीति के दृष्टिकोण से रूस एक समय भारत के लिए चीन की काट बना हुआ था। उस समय रूस वैश्विक महाशक्ति था तो चीन के विस्तारवाद और आक्रामक व्यवहार पर अंकुश लगाए रखता था। दुर्भाग्यवश आज पश्चिमी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव से मुक्ति के लिए रूस चीन पर सर्वाधिक निर्भर हो गया है। ऐसे में भारत की अपेक्षा है कि हम रूस के साथ मित्रता को आगे बढ़ाएं, ताकि चीन पूरी तरह से रूस पर हावी न हो जाए। पुतिन स्वयं भी चाहते है कि भारत की दोस्ती के आधार पर रूस चीन के सामने पराधीन और बेबस न नजर आए। हालांकि जिस तादाद में चीन रूस के साथ व्यापार और सैन्य सहयोग कर रहा है, उतनी क्रय शक्ति फिलहाल भारत के पास नहीं है कि वह रूस के लिए दूसरा विकल्प बन सके। भारत के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के नौसैनिक दबदबे की काट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति में हमें शायद ही रूस का साथ मिल सके, क्योंकि चीन की तरह रूस भी हिंद-प्रशांत की अवधारणा को अमेरिकी षड्यंत्र मानता है। पीएम मोदी के दौरे पर रूस-भारत सैन्य सामग्री (लाजिस्टिक) समझौते पर कुछ बात आगे बढ़ी है, लेकिन लगता नहीं कि रूस किसी भी स्थिति में चीन से प्रतिस्पर्धा वाले प्रत्यक्ष गठबंधन का हिस्सा बनेगा। भारत-रूस संबंधों का सार यही है कि रूस चाहता है कि भारत पश्चिम का मुकाबला करने में उसकी मदद करे, जबकि भारत चाहता है कि चीन से मुकाबले में रूस उसके साथ आगे आए। इन विरोधाभासों के मद्देनजर भारत जानता है कि रूस के साथ उसकी 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' की सीमाएं हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इन सीमाओं को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय व्यावहारिक सहयोग को जितना बढ़ाया जा सकता है, उतना बेहतर है। तेजी से बदलती और कठिन होती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इतिहास, भूगोल और आपसी विश्वास पर आधारित रूस-भारत साझेदारी अपनी धुरी पर टिकी हुई है। यह तय है कि दोनों देश इसे कायम रखने के लिए प्रतिबद्धता दिखाते रहेंगे।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

कमीशनखोरी की कीमत चुकाता देश

राजीव सचान

इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि देश में दोयम दर्जे के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो रहा है

आधारभूत ढांचे की खुलती पोल ● पेट्र

इन दिनों देश के कई हिस्सों से पुलों के गिरने, सड़कों के धंसने, हाईवे में गड्ढे होने और रेल पटरियों के क्षतिग्रस्त होने के समाचार आ रहे हैं। बरसात में ऐसे समाचार आते ही हैं। यह तय है कि जब कहीं कम समय में बहुत अधिक वर्षा हो जाएगी, जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के चलते प्रायः होने लगी है तो वहां जलभराव होगा। इसका उदाहरण कुछ समय पहले उत्कृष्ट आधारभूत ढांचे वाले शहर दुबई में भी मिला था, जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था, लेकिन अपने देश में थोड़ी सी अधिक और कई बार तो मामूली बरसात में जगह-जगह जलभराव ही नहीं हो जाता, बल्कि आधारभूत ढांचे की पोल भी खुल जाती है। इससे इन्कार नहीं कि पिछले कुछ समय से देश में आधारभूत ढांचे का निर्माण तेजी से हो रहा है। देश भर में हाईवे, सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, सबवे के साथ हवाईअड्डे और रेलवे स्टेशन बन या संवर रहे हैं, लेकिन यह कहना कठिन है कि उनकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय है। चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए इस आधारभूत ढांचे की मजबूती की पोल खुलती रहती है, लेकिन हमारे नीति-नियंता चेत नहीं रहे हैं। जब कहीं कोई सड़क, पुल या आधारभूत ढांचे से जुड़ा कोई अन्य निर्माण टूटता-फूटता है तो विरोधी दल सत्ताधारी दल पर टूट पड़ते हैं। यह बात और है कि कोई नहीं कह सकता कि अमुक दल द्वारा शासित राज्य में आधारभूत ढांचे के निर्माण में किसी तरह की खामी नहीं। सत्य यह है कि केंद्र या राज्य में किसी भी दल की सरकार हो, उसके समय में बनाए गए आधारभूत ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठते ही रहते हैं।

पिछले दिनों जब दिल्ली में भारी बरसात के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एक हिस्से की छत गिरी और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो विरोधी दलों ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। इसके जवाब में सत्तापक्ष के नेताओं की ओर से कहा गया कि इस छत का निर्माण तो मनमोहन सरकार के समय 2009 में कराया गया था। क्या महज 15 वर्ष पुराने निर्माण कार्य का ढह जाना स्वीकार्य है? क्या उसकी देखरेख इसलिए नहीं हो रही थी कि उसका निर्माण पिछली सरकार ने कराया था? इन प्रश्नों के बीच यह खबर आई कि जबलपुर हवाईअड्डे की छत गिर गई। जबलपुर के बाद राजकोट हवाईअड्डे की भी छत गिरने की खबर आ गई। इन दोनों हवाईअड्डों का लोकार्पण हाल में ही किया गया था। आधारभूत ढांचे की पोल खोलने वाली इन घटनाओं को महज दुर्योग नहीं कहा जा सकता। ये घटनाएं कहीं न कहीं यही बताती हैं कि सरकारी एजेंसियों की ओर से दोयम दर्जे का निर्माण कराया जा रहा है। इसका पता बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने से भी चलता है। ये सभी बहुत पुराने पुल नहीं थे। इनमें से कुछ 10-20 साल पुराने भी थे। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि जब अंग्रेजों के बनाए तमाम पुल अभी सही सलामत हैं, तब 10-20 साल पुराने पुल भी ढह जा रहे हैं? सड़कों और यहां तक कि हाईवे की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। अपने देश में ज्यादातर सड़कें पहली बरसात का भी सामना नहीं कर पातीं। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि अपने देश में दोयम दर्जे के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माण में मानकों की अनदेखी का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। कई बार यह भ्रष्टाचार नेताओं और नौकरशाहों की ओर से मिलकर किया जाता है और कई बार उसके लिए केवल नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। रिश्वतखोर नौकरशाह भ्रष्ट ठेकेदारों को तैयार करते हैं और फिर दोनों मिलकर दोयम दर्जे का निर्माण करते हैं। हर तरह के निर्माण कार्यों में कमीशनखोरी यानी दलाली एक अलिखित नियम है। अलग-अलग राज्यों में इस दलाली की भिन्न-भिन्न दरें हो सकती हैं, लेकिन निर्माण कार्यों के एवज में खर्च धनराशि का भुगतान बिना कमीशन हासिल करना आसान नहीं। ऐसा नहीं है कि शासकगण इससे परिचित न हों, लेकिन वे नौकरशाही में सुधार की दिशा में बढ़ने के बजाय उससे इन्कार कर रहे हैं। यह तब है जब नौकरशाही के भ्रष्टाचार की कीमत प्रायः उन्हें ही चुकानी पड़ती है।

नेतागण इससे अनजान नहीं कि नौकरशाही के भ्रष्टाचार अथवा जन समस्याओं के प्रति उसकी बेरुखी के चलते जनता की नाराजगी का सबसे अधिक सामना उन्हें ही करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे नौकरशाही में सुधार की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ते? अपने देश में प्रशासनिक सुधार एक लंबे समय से लंबित हैं। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जिस दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था, उसकी रपट मनमोहन सरकार के समय भी ठंडे बस्ते में पड़ी रही और मोदी सरकार के समय भी। निःसंदेह किसी भी सरकार का काम नौकरशाही के बिना नहीं चल सकता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उसे मनमानी करने दी जाए। देश में फिलहाल ऐसी ही स्थिति है। जो सरकारें कठोर फैसलों के लिए जानी जाती हैं, वे भी प्रशासनिक सुधारों से बचती हैं। इससे भी खराब बात यह है कि कई बार वे अपने ही दल के जनप्रतिनिधियों से अधिक नौकरशाहों पर भरोसा करती हैं। करीब-करीब सभी यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले, उसका एक बड़ा कारण नौकरशाही की मनमानी रही, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि उसे जवाबदेह बनाने की कोई ठोस पहल होगी। क्या हमारे नेता यह बुनियादी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बेलगाम नौकरशाहों की मनमानी के कारण वे तो बदनाम होकर सत्ता से बाहर हो जाते हैं, लेकिन नौकरशाह मजे करते रहते हैं?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विरासत

विरासत शब्द सुनते ही हमें अपने अतीत का स्मरण होने लगता है। विरासत से किसी भी व्यक्ति की पहचान जुड़ी रहती है। विरासत का स्वाभिमान व्यक्ति को अपने पूर्वजों पर गौरव का भाव जगाता है। ये वही पूर्वज हैं जिन्होंने अपनी विरासत को स्थापित किया और उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते गए। विरासत एक भाव है, जो भाव उससे जुड़े व्यक्ति को कुछ विशेष होने का अनुभव कराने का निमित्त बनता है।

सकारात्मक और लोक कल्याणकारी विरासत पूजनीय होती है। उसे सदैव स्मरण किया जाता है। उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। जबकि बुरे भाव से जुड़ी विरासत स्वीकार्य नहीं होती। उसके प्रति द्वेष का भाव स्वतः प्रकट होने लगता है। दुर्दांत एवं विनाशकारी प्रवृत्ति के लोगों के कृत्यों के प्रति मानवता का भाव नकारात्मक रहता है। समाज उससे स्वयं को जोड़ना नहीं चाहता। उससे छुटकारा पाना चाहता है। विरासत एक पहचान की तरह सदैव हमारे साथ चलती है। पिता की विरासत स्वतः उसके पाल्यों के साथ चलने लगती है। अब पाल्यों का कर्तव्य है कि वह अपने पूर्वजों की विरासत को संजोए रखें। उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। उसके संरक्षण के लिए सदैव प्रयासरत रहें।

श्रीराम का लोककल्याणकारी भाव भारत की विरासत है। श्रीकृष्ण का गीता ज्ञान भारत की विरासत है। बुद्ध, गुरुनानक देव और महावीर स्वामी का चिंतन भारत की विरासत है। ऐसी महनीय विरासत को भी जीवन में आत्मसात करना हमारा परम कर्तव्य है। विरासत केवल भौतिक वस्तुएं, महल या इमारतें मात्र ही नहीं होती, बल्कि विचार और उदात्त चिंतन भी स्वर्णिम विरासत की अभिव्यक्ति होते हैं, जो हमें हमारे महापुरुषों ने प्रदान किए हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी बौद्धिक विरासत को समृद्ध करने में संलग्न रहना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है और एक अनुकरणीय विरासत सदैव प्रेरित करने वाली होती है।

ललित शौर्य

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

आतंक का स्थायी समाधान आवश्यक

'आतंक का सामना' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उचित ही लिखा गया है। पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां एक बड़ी चिंता के रूप में उभरी हैं। हाल के संसदीय चुनावों में राज्य की जनता ने बढ़-चढ़कर मतदान कर पिछले कई वर्षों के रिकार्ड ध्वस्त किए थे। इससे राज्य की जनता के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भरोसे की व्यापक रूप से पुष्टि हो रही थी और इस पर्वतीय राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनावों की उम्मीद जगने लगी थी। इतना ही नहीं, उसके पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर भी बातें सामने आ रही थीं कि नीतिगत गलियारों में इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि, जिस प्रकार से बीते दिनों में जम्मू संभाग में भी आतंकी हमलों की आवृत्ति बढ़ी है उसे देखते हुए चुनाव और पूर्ण राज्य का दर्जे का मुद्दा शायद ठंडे बस्ते में चला जाए। आतंकी राज्य में हालात बिगाड़ने पर आमादा हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब मिले। अब सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तान की तबीयत छोटी-मोटी गोली से नहीं, बल्कि तगड़े इंजेक्शन या सर्जरी से ही सुधरती है और फिर वह कुछ समय शांत रहता है। बेहतर तो यही होगा कि इस बार कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का स्थायी समाधान हो जाए। आखिर हम कब तक क्षति उठाते रहेंगे।

केशव तिवारी, आजमगढ़

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सराहनीय

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट यूजी 2024 के प्रश्नपत्र लीक के विषय पर दिया गया निर्णय अत्यंत सराहनीय है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किया और कहा कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, जहां गेहूं और भूसे को अलग करना संभव नहीं होता, तो पुनर्परीक्षा की संभावना पर विचार किया जा सकता है। यह निर्णय देश भर में 20 लाख से अधिक छात्रों के करियर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक था। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि योग्य और मेहनती छात्रों को उनके उचित स्थान पर पहुंचने में कोई बाधा नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को करेगा। प्रतीक्षित निर्णय ना केवल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और न्याय को भी बढ़ावा देगा।

डा. पवन कुमार, गया, बिहार

व्यर्थ न जाए बलिदान

संपादकीय आलेख 'आतंक का सामना' (नौ जुलाई) पढ़ा। गत कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में वृद्धि चिंताजनक है। कश्मीर के राजौरी जिले में प्रादेशिक सेना के शिविर पर आतंकी हमले में सेना का एक जवान घायल हो गया, आतंकी भागने में सफल हो गए। कठुआ में सेना के वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में पांच सैनिक बलिदान हो गए। आतंकी यहां भी भागने में सफल हो गए। सेना पर हमला आतंकियों के बढ़ते दुस्साहस एवं सूचना तंत्र की नाकामी है। जब तक पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलते रहेंगे एवं घुसपैठ की समस्या जारी रहेगी, तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां समाप्त नहीं हो सकती है।

ई हिमांशु शेखर, कसपा, गया

नेपाल में बढ़ती चीनी दखल

'फिर भारत की चिंता बढ़ाता नेपाल' शीर्षक आलेख में डा. ऋषि गुप्ता ने नेपाल में सत्ता पर काबिज होने के लिए हो रही उथल-पुथल से अवगत कराते हुए भारत को इस पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता बताई है। संभावित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के समर्थक बताए जाते हैं। वे पूर्व में भी नेपाल के प्रधानमंत्री थे और भारत से दूरी बनाए रखी थी। माओवादी सेंटर के पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार अल्पमत में आ गई है। प्रचंड के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। नेपाल भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण विदेश नीति में विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल दोनों देश हिंदू बहुल हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी के साथ दोनों देश संबंध साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच न केवल खुली सीमा है, बल्कि दोनों देश के नागरिक निर्बाध आवाजाही करते हैं। विवाह और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से भी घनिष्ठ संबंध हैं। हाल के वर्षों में नेपाल भारत के प्रभाव से दूर हो गया है। चीन ने धीरे-धीरे इस स्थान को निवेश, सहायता और ऋण से भर दिया है। यह भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत-नेपाल सीमा वस्तुतः खुली है, जिसका दुरुपयोग भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के आतंकवादी संगठन और विद्रोही समूह करते रहे हैं। नकली भारतीय मुद्रा आपूर्ति के मामले पकड़े गए हैं।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

विद्यार्थियों के हित में अध्यापकों से केवल अध्यापन का ही कार्य कराया जाना चाहिए। अध्यापक को रसोइया, चौकीदार, लिपिक, बीएलओ और तहसील का बाबू मत बनाइए। अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

कभी सैनिकों के मुंह से काम के बहाने सुने हैं? कभी सैनिक भी अगर हाजिरी को लेकर आंदोलन करने लगें तो क्या होगा? सैनिक भी गांव और सामान्य घरों से आते हैं। उनकी ड्यूटी के तो घंटे भी तय नहीं होते।

शरद@sharadoffice

शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने हिंदी में बात की तो पुतिन के लिए उसका अनुवाद रूसी भाषा में किया गया। ऐसा ही होना चाहिए। अधिकांश भारतीयों की भाषा हिंदी है और रूसी तो रूस की भाषा है ही। जब अपनी-अपनी भाषा है तो किसी अन्य भाषा का सहारा क्यों लिया जाए?

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

भारतीयों के लिए ईंधन से लेकर उर्वरकों की कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए पीएम मोदी ने रूसी आपूर्ति के लिए आभार जताया। रूस के साथ गर्मजोशी को लेकर पश्चिम भले ही मुंह बनाता रहे, लेकिन मोदी ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर एक उदाहरण ही प्रस्तुत किया।

मोनिका वर्मा@TrulyMonica

जनपथ

दोस्त पुराना है बहुत दें उसको सम्मान,
पर मानेगा बात वह मत रखिए अरमान।
मत रखिए अरमान पुतिन हैं बहुतै जिद्दी,
वो समझें यूक्रेन सामने उनके पिद्दी।
ऐसों को बेकार समझिए कुछ समझाना,
कितना भी हो बंधु आपका दोस्त पुराना।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 89

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बुधवार, 10 जुलाई 2024

चुनाव हमें न केवल अधिकारों की, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों की जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। - रॉबर्ट कैनेडी

जम्मू-कश्मीर में बचे हुए आतंकी नेटवर्क के खात्मे के लिए सरकार जिस बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है, उसके मद्देनजर कठुआ में सेना पर हमले के पीछे आतंकियों की बौखलाहट दिखती है। हाल के दिनों में जम्मू-कश्मीर में जिस तरह आतंक ने फिर से सिर उठाया है, उसे देखते हुए सतर्कता और सख्ती बेहद जरूरी है।

सतर्कता और सख्ती

बीते रविवार को जम्मू के राजौरी में सेना के कैंप पर हमले के अगले ही दिन कठुआ जिले में गश्त पर निकले सेना के वाहन पर आतंकियों ने जिस तरह से घात लगाकर हमला किया है, वह उनके दुस्साहस और बौखलाहट, दोनों को ही दर्शाता है। इससे पहले, कुलगाम में भी सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें छह आतंकी मारे गए थे। ताजा हमला जिस जगह हुआ, वह क्षेत्र कठुआ शहर से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर मचेड़ी और लोहाई मल्हार के बीच पड़ता है। मचेड़ी वही इलाका है, जो नब्बे के दशक में आतंकवाद का गढ़ हुआ करता था। पूरा इलाका जंगलों से घिरा है, यही वजह है कि जब सेना के जवानों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो आतंकी आसानी से भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखौटा संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने नौ जून को, जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब रियासी में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था। इसी तरह, ग्यारह जून को आतंकियों ने चत्तरगला में सेना की एक चौकी पर हमला किया था, तो 26 जून को डोडा जिले में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। दरअसल, अनुच्छेद-370 हटाए जाने और लोकसभा चुनावों में कश्मीर के लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया, उससे आतंकियों और सीमा पार बैठे उनके आकाओं में बौखलाहट है। और, जब वे यहां के हालात की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से करते हैं, जहां लोग स्थानीय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में भी संकेत दे चुके हैं कि जम्मू-कश्मीर में बचे हुए आतंकियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा आतंकियों की बेचैनी अकारण नहीं है। लेकिन इस वर्ष के अंत में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह इसलिए भी

जरूरी है कि आतंकियों के तगड़े स्थानीय नेटवर्क होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिनके जरिये उन तक सभी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। शायद यही वजह है कि हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की बरसी पर हाई अलर्ट और हमला होने की पूर्व सूचनाओं के बावजूद कठुआ हमले को रोका नहीं जा सका। फिलहाल मिल रही सूचनाओं के अनुसार, भारतीय सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और अब पूरे इलाके की सफाई की तैयारी है, जो आतंकियों के बढ़े हुए दुस्साहस को कुचलने के लिए जरूरी भी है। लेकिन कठुआ जैसे हमलों को रोकने के लिए खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

चुनौतियां तो अब शुरू होती हैं

पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले फ्रांस में चुनावी नतीजों ने एक गतिरोध तो पैदा कर ही दिया है। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन प्रणाली के कारण गठबंधन की कोई संस्कृति नहीं है। ऐसे में, मैक्रों को अब भिन्न विचारों वाले दलों के बीच व्यापक सहमति वाले एजेंडे पर श्रमसाध्य बातचीत की बारीकियों को समझना होगा।

सोमवार की सुबह फ्रांस दक्षिणपंथियों के प्रभुत्व वाले देश के रूप में नहीं, बल्कि इटली की तरह एक ऐसे देश के रूप में जगा, जहां मुश्किल जोड़-तोड़ के जरिये ही सही, आखिरकार एक व्यावहारिक गठबंधन सरकार बन सकती है। फ्रांस ने संसदीय चुनाव में मरीन ली पेन की प्रवासन-विरोधी पार्टी नेशनल रैली को नकार दिया है, जो राष्ट्रवादी कारनामों के प्रति उनके गहरे प्रतिरोध का एक और प्रदर्शन था। फ्रांस की जनता ने अपनी पहली पसंद के रूप में फिर से उठ खड़े हुए वामपंथ को चुना जरूर है, लेकिन वह भी सरकार बनाने से काफी दूर है। इन स्थितियों ने मैक्रों को मजबूर कर दिया है कि वे सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति के बजाय संसद की भी सुनें। पेरिस ओलंपिक का बिगुल बजने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है। अगस्त में समुद्र तटों या पहाड़ों पर जाना फ्रेंच जीवन-शैली की पहचान है। ऐसे में, यही लगता है कि सरकार के गठन की बातचीत शरद ऋतु तक खिंच सकती है, जब फ्रांस को बजट पारित करने के लिए सरकार की जरूरत होगी।

रोजर कोहेन
द न्यूयॉर्क टाइम्स

फिलहाल फ्रांस में चुनाव के नतीजों ने एक गतिरोध तो पैदा कर ही दिया है। एक उभरता हुआ और विवादास्पद वामपंथी गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट नेशनल असेंबली में 180 सीटें जीतकर पहले स्थान पर है। उसने तुरंत ही मांग की कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को उसे सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। साथ ही उसने यह भी कहा है कि वह अगले हफ्ते अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री का नाम सामने रखेगा।

संविधान के अनुसार, मैक्रों ही प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। 577 सदस्यीय नेशनल असेंबली में न्यू पॉपुलर फ्रंट को बहुमत से करीब 100 सीटें कम हैं। उसकी जीत के पीछे सिर्फ वामपंथी गठबंधन नहीं था, बल्कि दूसरे चरण के मतदान में मध्यमार्गियों और वामपंथियों द्वारा नेशनल रैली के खिलाफ 'रिपब्लिकन मोर्चा' बनाने के निर्णय का असर भी दिखा था। इसके बावजूद, जुझारू वामपंथी नेता जीन-ल्यूक मेलेनचॉन ने कहा

है कि वह संभावित गठबंधन सहयोगियों से बातचीत नहीं करेंगे, न ही वामपंथी कार्यक्रम में जरा भी बदलाव करेंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के कारण गठबंधन बनाने संबंधी समझौते की कोई संस्कृति नहीं है। मैक्रों को अब राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर भिन्न विचारों वाले दलों के बीच व्यापक रूप से सहमत एजेंडे पर श्रमसाध्य बातचीत की बारीकियों को समझना होगा। उदाहरण के लिए, न्यू पॉपुलर फ्रंट सेवानिवृत्ति की उम्र को 64 से घटाकर 60 करना चाहता है, जबकि एक साल पहले ही मैक्रों ने काफी संघर्ष के बाद इसे 62 से बढ़ाकर 64 कर दिया था।

मैक्रों बजट घाटे को कम करने को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जबकि न्यू पॉपुलर फ्रंट न्यूनतम वेतन बढ़ाना चाहता है और ऊर्जा व गैस की कीमतों को स्थिर रखना चाहता है। मैक्रों की सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक आव्रजन विधेयक पारित किया था, जिसके तहत विदेशियों को फ्रांस में काम करने, रहने और पढ़ने की अनुमति देने वाले नियमों को सख्त बनाया गया था। जबकि, वामपंथियों ने शरण प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाने का संकल्प लिया है।

नेशनल असेंबली का तीन बड़े गुटों-वामपंथी, मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी-में विभाजन, किसी व्यावहारिक गठबंधन के लिए तत्काल कोई आधार प्रदान नहीं करता। मैक्रों के मध्यमार्गी गुट के पास लगभग 160 सांसद हैं, जो पहले 250 थे, तथा नेशनल रैली और उसके सहयोगियों के पास लगभग 140 सांसद हैं, जो पहले 89 थे। फ्रांस ने एक बार फिर अति दक्षिणपंथियों को सत्ता से दूर रखा, लेकिन आप्रवासन और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के प्रति गुस्से के कारण दक्षिणपंथियों को सिरे से खारिज भी नहीं किया है। प्रधानमंत्री गैब्रियल अट्टल के साथ सोमवार को बातचीत के बाद मैक्रों ने उनसे देश की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए फिलहाल पद पर बने रहने के लिए कहा है।

मैक्रों का कार्यकाल सीमित है और उन्हें 2027 में पद छोड़ना होगा। वह पिछले कुछ दिनों से ज्यादातर चुप हैं, जो असामान्य बात है। हालांकि उनकी पार्टी एक-तिहाई सीटें गंवा चुकी है, लेकिन उनकी वैसी हार नहीं हुई, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। अपमानित होने से वह बच गए। यह कोई छोटी बात नहीं है। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह किसी गठबंधन की संभावनाओं को तलाशने के लिए विभिन्न दलों से आराम से परामर्श करेंगे। राष्ट्रपति के समक्ष दो चुनौतीपूर्ण विकल्प हैं। एक तो नेशनल रैली के साथ शासन करना, जिसके युवा पार्टी नेता जॉर्डन बार्डेला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और दूसरे मेलेनचॉन की पार्टी के साथ सरकार बनाना, जिस पर मैक्रों ने यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया है। वह समाजवादियों और ग्रीन्स के साथ-साथ मुख्यधारा के रूढ़िवादियों सहित उदारवादी वामपंथियों को गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे।

पिछले महीने यूरोपीय संसद के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के सफल अभियान का नेतृत्व करने वाले ग्लक्समैन ने कहा, 'हम एक विभाजित असेंबली में हैं, और इसलिए हमें बचकाने व्यवहार से बचना होगा। इसका मतलब है कि हमें बात करनी होगी, संवाद में शामिल होना होगा और यह मानना होगा कि नेशनल असेंबली सत्ता का केंद्र है।' उन्होंने इसे 'राजनीतिक संस्कृति में एक मौलिक परिवर्तन' बताया। न्यू पॉपुलर फ्रंट की 180 सीटों में से अनुमानतः 75 सीटें फ्रांस अनबोड को मिलेंगी, जबकि लगभग 65 सीटें सोशलिस्टों को, लगभग 33 ग्रीन्स को तथा 10 से भी कम सीटें कम्युनिस्टों को मिलेंगी। जैसा कि ग्लक्समैन की टिप्पणियों से साफ है, गठबंधन को एक साथ बनाए रखना कठिन होगा।

सिद्धांत रूप में, यूरोपीय संसद में गठबंधन बनाने वाले उदारवादी ग्लक्समैन समाजवादियों, ग्रीन्स, कम्युनिस्टों, मैक्रों के मध्यमार्गी गुट और रिपब्लिकन के लगभग 60 मुख्यधारा के रूढ़िवादी सांसदों के गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन ग्लक्समैन का दृष्टिकोण मेलेनचॉन से टकराता है, जो संभावित साझेदारों के साथ बातचीत से इन्कार करते हैं, और वे मैक्रों के भी विरोधी हैं। इसलिए फिलहाल समझौते की कोई संभावना नहीं है। चुनाव के बाद फ्रांस में छाए धुंध से बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है, जबकि ओलंपिक मशाल 14 जुलाई को बास्तील दिवस पर फ्रांस की राजधानी पहुंचने वाली है।

©The New York Times 2024

जीवन धारा

आचार्य रामचंद्र शुक्ल

जब गति सफल होती है, तभी इसमें सुंदरता आती है। गति में सुंदरता रहती है; आगे चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही सौंदर्य होता है।

विफलता में भी होता है निराला सौंदर्य

लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंदकला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता है। इस सामंजस्य का और कई रूपों में भी दर्शन होता है। किसी कोट-पतलून-हैटवाले को धाराप्रवाह संस्कृत बोलते अथवा किसी पंडित-वेशधारी सज्जन को अंग्रेजी की प्रगल्भ वक्तृता देते सुन व्यक्तित्व का जो एक चमत्कार-सा दिखाई पड़ता है, उसकी तह में भी सामंजस्य का यही सौंदर्य समझना चाहिए। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोकधर्म का सौंदर्य है। कवि वाल्मीकि की वाणी इसी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है। सौंदर्य का यह उद्घाटन असौंदर्य का आवरण हटाकर होता है।

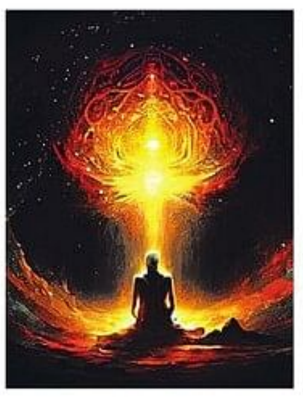

धर्म और मंगल की यह ज्योति अधर्म और अमंगल की घटा को फाड़ती हुई फटती है। इससे कवि हमारे सामने असौंदर्य अमंगल, अत्याचार, क्लेश इत्यादि भी रखता है; रोष, हाहाकार और ध्वंस का दृश्य भी लाता है। पर सारे भाव, सारे रूप और सारे व्यापार भीतर-भीतर आनंद-काल के विकास में ही योग देते पाए जाते हैं। यदि किसी ओर उन्मुख ज्वलंत रोष है, तो उसके और सब ओर करुणा दृष्टि फैली दिखाई पड़ती है। यदि किसी ओर ध्वंस और हाहाकार है, तो और सब ओर उसका सहगामी रक्षा और कल्याण है। वह वृत्ति, जिससे लोक के मंगल का विधान होता है, अभ्युदय की सिद्धि होती है, धर्म है। अधर्म वृत्ति को हटाने में धर्म वृत्ति की तत्परता, चाहे वह उग्र और प्रचंड हो, चाहे कोमल और मधुर हो, भगवान की आनंदकला के विकास की ओर बढ़ती गति है। यह गति यदि सफल हुई, तो धर्म की जय कहलाती है। इस गति में सुंदरता और सफलता दोनों सम्मिलित हैं। जब यह गति सफल होती है, तभी इसमें सुंदरता आती है। गति में सुंदरता रहती है; आगे चलकर चाहे यह सफल हो, चाहे विफल। विफलता में भी एक निराला ही सौंदर्य होता है। तात्पर्य यह है कि यह गति के अंत तक सुंदरता होती है। चाहे सफलता के रूप में हो, चाहे विफलता के। यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण की सहायता से जरासंध और कौरवों का दमन न हो सकता, तो भी राम और कृष्ण की गति विधि में पूरा सौंदर्य रहता, पर उनमें भगवान की पूर्ण कला का दर्शन न होता, क्योंकि भगवान की शक्ति अमोघ है। मंगल-अमंगल के द्वंद्व में कवि लोग अंत में मंगल शक्ति की जो सफलता दिखा दिया करते हैं, उसमें सदा शिक्षावाद या अस्वाभाविकता की गंध समझकर नाक-भौं सिकोड़ना ठीक नहीं।

लोकमंगल की कामना

सूत्र

भावों की छानबीन करने पर मंगल का विधान करने वाले दो भाव ठहरते हैं-करुणा और प्रेम। करुणा की गति रक्षा की ओर होती है और प्रेम की रंजन की ओर। कई कवियों ने अपने-अपने हिसाब से रचनाएं की हैं। भगवान की लीलाओं का भी तरह-तरह से बखान किया है। 'रामायण, रामचरित मानस, महाभारत, रघुवंश, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश' आदि में देख लीजिए सभी में लोकमंगल की कामना की गई है।

दूसरा पहलू

ओशो के निधन के बाद 2000 तक पुणे में उनके आश्रम में हर वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते थे, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया।

क्या गुरु और विचारों का ट्रेडमार्क होता है?

गुरु चरणदास की एक सुप्रसिद्ध शिष्या सहजो पर ओशो की एक अनूठी प्रवचनमाला 'बिन घन परत फुहार' में सहजो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति में अनुग्रहीत होकर कहती है: *राम तजूं पै गुरु न बिसारूं। गुरु को सम हरि को न निहारूं।* गजब की बात है। परमात्मा को भी, सहजो कह रही हैं कि मैं गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी।

भारत तथा विश्व भर में ओशो के लाखों-करोड़ों शिष्य और प्रेमी हैं, जो आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाली पूर्णिमा को ओशो पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। वर्ष 1990 तक, ओशो जब तक देह में थे, तो ओशो के शिष्य और प्रेमी पुणे में उनके आश्रम में आकर इस उत्सव में सम्मिलित होते थे। यह क्रम वर्ष 2000 तक अनवरत चलता रहा, लेकिन बाद में पुणे में इस उत्सव को मनाना बंद कर दिया गया। तब से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित ओशो के सैकड़ों ध्यान केंद्र हैं, जहां इस उत्सव को मनाया जाता रहा है।

स्वामी चैतन्य कीर्ति

ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन साठ से अधिक भाषाओं में प्रकाशित ओशो की पुस्तकों पर रॉयल्टी बटोरता है। इसका उद्देश्य ओशो को एक कमोडिटी की भांति बेचना है।

फेसबुक पर ओशो के नाम से जुड़े 200 पृष्ठों को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की प्रबंधकीय टीम ने हटवा दिया है, ताकि ऐसे उत्सवों की सूचना ओशो के सभी शिष्यों तक न पहुंचे।

शिष्य और प्रेमी फेसबुक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य ओशो प्रेमियों को इस उत्सव में सम्मिलित होने की सूचना प्रकाशित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। इस वर्ष 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन उसके दो सप्ताह पहले, सात जुलाई को फेसबुक पर ओशो के नाम से जुड़े 200 पृष्ठों को पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो स्विट्जरलैंड की ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के अधीन कार्य करती है, की प्रबंधकीय टीम ने हटवा दिया है, ताकि ऐसे उत्सवों की सूचना ओशो के सभी शिष्यों तक पहले की तरह न पहुंचे। ये स्विट्जरलैंड की ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो ओशो नाम पर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के एकाधिकार की समय-समय पर घोषणा करती रहती है, की साजिश है। इस फाउंडेशन ने जूरिख में अपने नाम को पंजीकृत करवाया हुआ है, जहां यह विश्व की साठ से अधिक भाषाओं में प्रकाशित ओशो की पुस्तकों पर रॉयल्टी बटोरती है। वह धन भारत में नहीं आता है। इसका उद्देश्य ओशो को एक कमोडिटी की भांति बेचना है, इसलिए आए-दिन यह ओशो के संदेश के स्वतंत्र प्रसारण में अनगिनत बाधाएं खड़ी करती है। इसके ऐसे क्रूर व्यवहार से ओशो के भारतीय शिष्य जल्दी ही न्यायालय के द्वार पर दस्तक देंगे। ओशो का ध्यान, प्रेम, भक्ति और आनंद-उत्सव का संदेश मनुष्य जाति के लिए उपहार स्वरूप है। ये ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के जाल में बांधने के लिए नहीं है; जैसा कि कभी एक वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह ने ओशो के बारे में लिखा था: समुद्र की हवा को आप अपने जाल में कैसे बांध सकते हैं?

-लेखक ओशो वर्ल्ड मासिक पत्रिका के संपादक हैं।

आंकड़े

जीएनपीए में कमी

भारतीय वाणिज्य बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) 12 वर्षों में पहली बार तीन फीसदी से नीचे आई है।

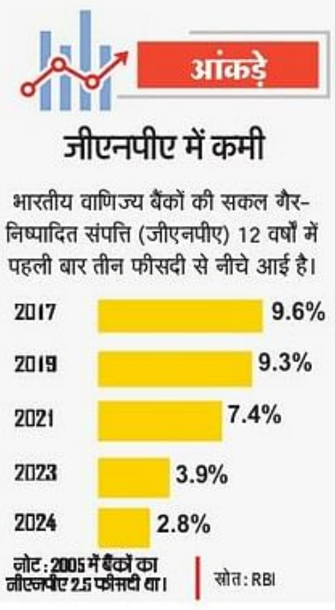

नोट: 2005 में बैंकों का जीएनपीए 2.5 फीसदी था। | स्रोत: RBI

लाक्षागृह में आग लगने के बाद माता कुंती पांडवों को लेकर जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने ब्राह्मण के बेटे की रक्षा के लिए राक्षस के पास भीम को भेजा।

दयावती माता कुंती

अंतर्यात्रा
संकलित

माता कुंती को भगवान का अनन्य भक्त माना जाता है। सांसारिक रूप से वह जीवन भर हमेशा विपत्ति में रहीं, लेकिन मानसिक रूप से उन्हें कभी विपदा नहीं व्यापी। वह सदैव मानती थीं कि 'सबसे बड़ी विपत्ति तो भगवान का विस्मरण होना है। वह दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आया।'

माता कुंती भगवान की भक्त होने के साथ ही बड़ी दयावती भी थीं। लाक्षागृह में जब दुर्योधन ने आग लगवाई, तो उस वक्त पांडवों के साथ उनकी माता कुंती भी थीं। वह बचकर जंगलों में चली गईं। इस दौरान वह एक ब्राह्मण के यहां रहती थीं। लेकिन उस ब्राह्मण का परिवार बड़ा ही चिंतित रहता था। माता कुंती ने उसकी मनोदशा जानकर उसके दुख का कारण जानने का प्रयास किया, तो उसने बताया कि यहां से कुछ ही दूरी पर एक राक्षस रहता है। वह नरभक्षी है। वह बारी-बारी से लोगों को खा जाता है।

अब बारी उसके इकलौते बेटे की थी। उसका बेटा राक्षस के पास जा रहा था। ब्राह्मणी रो रही थी। उससे धीरज बंधाते हुए कुंती ने कहा कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरे पांच बेटे हैं। तुम्हारे बेटे की जगह पर मेरा पुत्र जाएगा और आज के बाद वह राक्षस किसी भी इन्सान को नहीं खा सकेगा। माता कुंती ने राक्षस के पास भीम को भेजा। भीम ने राक्षस का वध कर दिया। इस तरह माता कुंती ने ब्राह्मण के बेटे के साथ ही समस्त वनवासियों की रक्षा की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 अगस्त, 1954

ट्यूनीशिया को आंतरिक आजादी देगा फ्रांस

योजना वे के सामने पेश
प्रधानमंत्री मेन्डेस ट्यूनिस में

फ्रांस के प्रधानमंत्री मुशिये मेंदेस फ्रांस ने कल ट्यूनीशिया वे (शासक) से मुलाकात की और उन्हें बताया कि फ्रांस ने उनके देश को स्वायत्त शासन का अधिकार यानी आंतरिक आजादी देने का निश्चय किया है।

चीन तो चीन ही है

1958 में पं. नेहरू ने सेना के लिए संसाधनों की मांग को उस पंचशील समझौते की आड़ में ठुकरा दिया, जिसे चीन ने कभी नहीं माना।

शिवदान सिंह

सीमा विवाद

पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि भारत और चीन के बीच में स्थायी शांति के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान सबसे पहले जरूरी है। वर्ष 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद से ही पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। टकराव बढ़ने पर युद्ध भी हो सकता है।

इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि सभी देशों को एक-दूसरे के क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। उनका इशारा चीन की तरफ था, जिसने 1955 से भारत का पूरा अक्साई चिन क्षेत्र अपने कब्जे में ले रखा है। भारत और चीन के बीच हुए 2010 के समझौते में साफ लिखा है कि दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता का आदर करेंगे, लेकिन चीन की करनी और कथनी में बहुत

अंतर है। एस. जयशंकर ने भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने को अपनी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा है।

भारत और चीन के बीच तनाव का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं होना है। 1916 में सीमा निर्धारण के लिए ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के बीच एक बैठक शिमला में हुई थी। भारत और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण हो गया था, जिसे मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया था। हालांकि चीन सीमा निर्धारण पर सहमत नहीं हुआ था, उसने भारत-तिब्बत सीमा को भी अब तक मान्यता नहीं दी है। इसी कारण लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा को चीन विवादित मानता है। चीन के साथ विवाद सुलझाने के लिए जयशंकर को अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक, जो सेना की उत्तरी कमान के जीओओ सीएनसी रह चुके हैं, के विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने हाल ही में कहा था कि चीन के साथ भारत के सीमा संबंधी समझौतों में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव की जरूरत है। अन्यथा चीन बार-बार सीमा उल्लंघन करता रहेगा और गलवान जैसी झड़पें होती रहेंगी।

चीन 1951 से ही भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है। 1951 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने एक सड़क जी-21 का निर्माण किया। इसका काफी हिस्सा लद्दाख के अक्साई चिन से होकर गुजरता है। इसकी सूचना भारत सरकार को 1954 में मिल गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद भी 1954 में पं. जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, जिसका नारा था *हिंदी चीनी भाई-भाई*। भारत सरकार इस समझौते का पालन करती रही, लेकिन चीन ने इसे कभी नहीं माना। 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया, जिसके कारण चीन की सेना अक्साई चिन से आगे भारतीय क्षेत्र में आ गई। चीनी घुसपैठ को देखते हुए 1958 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल थिमैया ने पं. नेहरू से सेना की तैयारी के लिए संसाधनों की मांग की, जिसे उन्होंने पंचशील समझौते की आड़ में ठुकरा दिया। देश की रक्षा के प्रति नेहरू के इस रवैये को देखते हुए जनरल थिमैया ने इस्तीफा दे दिया था। फिर चीन ने 1967 में सिक्किम पर कब्जा करने के लिए नाथुला पर हमला कर दिया, लेकिन उस समय मेजर जनरल संगत सिंह ने अदम्य साहस से चीनियों को पीछे धकेल दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें दिल्ली से सहमति नहीं मिली थी।

वर्ष 1996 में सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि सैनिक सीमाओं के बीच में नोमैंस लैंड पर बिना हथियारों के रहेंगे, लेकिन चीन ने इस समझौते की शर्तों को नकारते हुए गलवान में भारतीय सैनिकों पर कंटीले तार लगे हुए लाठी-डंडों से हमला किया। पड़ोसी के साथ शांति पूर्वक रहने के सिद्धांत को धता बताकर चीन ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों-मणिपुर, नगालैंड इत्यादि में आतंकवादी संगठनों को तैयार किया। हालांकि सेना ने उनका सफाया कर दिया। चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश पर है। यदि चीन के साथ स्थायी शांति स्थापित करनी है, तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करना होगा। संयुक्त राष्ट्र को भी सीमा निर्धारण की बातचीत में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण नहीं होने तक दक्षिण एशिया की इन दोनों शक्तियों के बीच में शांति स्थापित नहीं हो सकती।

edit@amarujala.com

ईर्ष्या से सावधान रहें, क्योंकि ये वह हरी आंखों वाला दैत्य है जो उसी शरीर का तिरस्कार करता है और धोखा देता है, जिस पर वह पलता है।

– विलियम शेक्सपियर

मुसीबत की बरसात

बरसात में जलजमाव और उससे शहरों का अस्त-व्यस्त जीवन अब हर वर्ष का स्थायी दृश्य हो गया है, मगर इसके मद्देनजर सरकार को पूर्व तैयारी करने की जरूरत शायद कभी महसूस नहीं होती। सामान्य से थोड़ा अधिक पानी बरसते ही शहरों की सड़कें लबालब हो जाती हैं, मुहल्ले तालाबों में तब्दील हो जाते हैं। लोगों का दफ्तर, स्कूल, व्यवसाय आदि के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। खासकर मुंबई के लोगों को हर वर्ष बरसात में ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अभी बरसात का मौसम शुरू ही हुआ है और मुंबई में सड़कों पर पानी भर गया, रेल की पटरियां डूब गईं, कई रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ीं, बसें रुक गईं, कई दफ्तरों और स्कूलों में कामकाज बंद करना पड़ गया। यहां तक कि सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों का कामकाज स्थगित करना पड़ गया। भारी बारिश की वजह से समंदर में ज्वार उठने के संकेत दे दिए गए। बरसात का असर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी पड़ता है। अक्सर इस मौसम में फलों, सब्जियों के दाम इसलिए आसमान छूने लगते हैं कि माल ढुलाई में बाधा आती है। जिन इलाकों में भारी बरसात होती है, वहां फसलें चौपट हो जातीं और सब्जियों का उत्पादन घट जाता है। दिल्ली में बारिश की वजह से थोक मंडियों में सब्जियां नहीं पहुंच पाने से लोगों को ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है।

हर वर्ष बरसात में जलभराव को लेकर विधानसभाओं में सवाल उठाए जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर कर आंदोलन करते देखे जाते हैं। हर बार आश्वासन दिया जाता है कि जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, मगर स्थिति फिर भी जस की तस बनी रहती है। पिछले वर्ष दिल्ली में बाढ़ आई और यमुना उफन कर लाल किले तक पहुंच गई, तो काफी शोर मचा था। तब दिल्ली सरकार ने कहा था कि हरियाणा ने बिना चेतावनी दिए पानी छोड़ दिया, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हुई। इस वर्ष दावा किया गया था कि पिछले वर्ष जैसी समस्या नहीं आएगी। मगर पहली ही बारिश में जिस तरह कई इलाकों में जलजमाव देखा गया, उससे लगता नहीं कि समस्या का समाधान हो गया है।

शहरों में जलजमाव की बड़ी वजह बरसात से पहले नालों की समुचित सफाई न होना पाना है। जिन नालों और नालियों की गाद निकाली जाती है, उसे किनारे पर छोड़ दिया जाता है, जो बरसाती पानी के साथ बह कर फिर से नालियों में भर जाता है। कई जगहों पर जलनिकासी का समुचित प्रबंध न किया जाना भी बड़ी वजह है। जिन इलाकों में अनियोजित तरीके से बस्तियां बसा दी गई हैं, वहां जलनिकासी के इंतजाम नहीं किए गए। जो नालियां बनी भी हैं उनकी पर्याप्त क्षमता नहीं है, जिसके चलते सामान्य से जरा भी अधिक पानी बरसता है, तो उसे निकलने में काफी वक्त लग जाता है। समझना मुश्किल है कि शहरों की नगर पालिकाएं हर वर्ष इस समस्या का सामना करती हैं, फिर भी वे कोई स्थायी समाधान निकालने का प्रयास क्यों नहीं करतीं। महाराष्ट्र विधानसभा में जलभराव को लेकर हंगामा हुआ, दिल्ली में भी इसे लेकर सियासी रस्साकशी हई। जब-जब समस्या गंभीर होगी, सब इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास करेंगे। मगर जलभराव जैसी समस्या का समाधान इतना जटिल क्यों बना हुआ है, यह समझ से परे है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर भी लापरवाही बरती जाती है। इसका नतीजा हर वर्ष लोगों को जलजनित बीमारियों के रूप में भी भुगतना पड़ता है।

युद्ध में नैतिकता

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन के रिहाइशी इलाकों में भी बम और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। मगर विडंबना है कि इस युद्ध में वैसी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जहां किसी भी हाल में हमला नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कीव में गत सोमवार को बच्चों के एक अस्पताल समेत शहर की कुछ अन्य इमारतों पर हमले हुए, जिनमें कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन का दावा है कि बच्चों के अस्पताल पर रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया। हालांकि, रूस ने कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली से छोड़ी गई मिसाइल ही अस्पताल पर गिरी है। दोनों देशों के ये दावे-प्रतिदावे अपनी जगह हैं, लेकिन क्या युद्ध के दौरान अस्पताल जैसे संस्थानों पर हमले करना वाजिब है? अस्पताल बीमार और घायलों को नया जीवन देने का काम करते हैं। यहां तक कि युद्ध में घायल सैनिकों की आखिरी उम्मीद भी उपचार के लिए इन्हीं जगहों पर टिकी होती है।

गौरतलब है कि कीव में यह हमला अमेरिका में होने वाले तीन दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले हुआ। इस सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान आम नागरिकों के हताहत होने का अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी कड़ाई से विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि युद्ध में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और जेनेवा समझौते के अनुसार युद्ध के दौरान आम नागरिकों और रिहाइशी इलाकों, खासकर अस्पतालों और पनाहगाहों पर जानबूझकर हमला करना प्रतिबंधित है। ऐसी कार्रवाइयों को युद्ध अपराध की श्रेणी में माना जाता है। सवाल है कि क्या युद्ध के दौरान इन अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है? जिन देशों ने मिलकर ये नियम तय किए हैं, अगर वे खुद इनका खयाल नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी इस तरह की कवायदों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायदे-कानून बनाने का मकसद वैश्विक समाज की सुरक्षा और बेहतरी पर केंद्रित होता है। यह मकसद तभी सफल हो पाएगा, जब तमाम देश आम सहमति से हुए फैसलों का सम्मान करेंगे।

महामारी का नया खतरा

हाल में दुनिया के कई देशों में इंसानों तक 'बर्ड फ्लू' विषाणु पहुंचने के उदाहरण मिल चुके हैं। तीन मामले तो अमेरिका में मिले हैं। इनमें इंसान अपने मवेशियों (गायों) के संपर्क में आए थे, जिन्हें 'बर्ड फ्लू' था।

अभिषेक कुमार सिंह

जब से खबर आई है कि 'बर्ड फ्लू' विषाणु का एक नया प्रकार महामारी का रूप ले सकता है, लोग भयभीत हो उठे हैं। इसलिए कि अब यह तेजी से इंसानों में फैल रहा है। हालांकि यह पक्षियों में फैलने वाला विषाणु है, लेकिन उत्परिवर्तित (म्यूटेंट) हुए इसके नए स्वरूप अब स्तनधारी जीवों से इंसानों में फैलने लगे हैं। यों तो 'बर्ड फ्लू' के विषाणु एच5एन1 का एक पुराना इतिहास रहा है। मगर 2020 में इसके जिस नए 'म्यूटेंट' का उभार हुआ है, उसने कोरोना विषाणु की तरह इसके भी पूरी दुनिया में फैल जाने का खतरा उत्पन्न कर दिया है। दुनिया के कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों और पेन्सिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के दर्जन भर राज्यों में मौजूद मवेशियों की जांच में इस उत्परिवर्तित विषाणु की मौजूदगी पाई है। उनकी चिंता है कि स्तनधारियों को अपनी चपेट में लेने वाला यह विषाणु अपना स्वरूप कहीं इतना न बदल ले कि यह इंसानों से इंसानों में फैलने लगे।

वैसे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अभी तक 'बर्ड फ्लू' विषाणु के इंसानों से इंसानों में फैलने की आशंकाओं से इनकार किया है। मगर ये स्थितियां कब बदल जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसलिए कि महामारियां अक्सर बेहद खामोशी से आती हैं। वे धीरे-धीरे एक देश से दूसरे देश में प्रसरित होती और अचानक खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं। हाल में दुनिया के कई देशों में इंसानों तक 'बर्ड फ्लू' विषाणु पहुंचने के उदाहरण मिल चुके हैं। तीन मामले तो अमेरिका में मिले हैं। इनमें इंसान अपने मवेशियों (गायों) के संपर्क में आए थे, जिन्हें 'बर्ड फ्लू' था। मैक्सिको, चीन, आस्ट्रेलिया और भारत में भी बर्ड फ्लू के इंसानों में पहुंचने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इन सारे मामलों में पंछी के विषाणु एक-दूसरे से अलग थे। चिंताजनक बात यह है कि इसी साल अप्रैल में केरल में बर्ड फ्लू का एक मामला प्रकाश में आ चुका था। कुछ ही अरसा पहले कोलकाता से आस्ट्रेलिया गए एक व्यक्ति में यह विषाणु मिला था और झारखंड के रांची में एक बच्चे में इसकी मौजूदगी पाई गई थी।

हालांकि कोरोना से पहले वाले दौर में भी बर्ड फ्लू (एवियन इंफ्लूएंजा) के खतरों को कोई कम बड़ी चेतावनी नहीं माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र की ओर से काफी पहले ही बर्ड फ्लू के बारे में कहा जा चुका है कि जिस तरह दुनिया में आवागमन की रफ्तार तेज हुई है और लोगों के खानपान की आदतें बदली हैं, उन्हें देखते हुए बर्ड फ्लू का विषाणु एच5एन1 एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। अगर किसी विषाणु में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) की क्षमता पैदा हो जाए, तो वह अचानक और ज्यादा संहारक बन जाता है। म्यूटेशन का आशय है कि ऐसी स्थिति में कोई विषाणु एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे तक महज खांसी या छींक के जरिए भी पहुंच सकता है, उसके लिए संक्रमित पंछी का मांस खाना जरूरी नहीं होता।

विशेषज्ञों का मानना है कि बर्ड फ्लू के विषाणु ने एंटीजेनिक छलांग (यानी एक जीव प्रजाति से दूसरी जीव प्रजाति तक फैलने वाला

संक्रमण) लगा ली है और इसने इंसानों तक पहुंच का वह अंतिम दरवाजा पार कर लिया है, जो इसे सामान्य इन्फ्लूएंजा की तरह फैलने से रोके हुए था। समस्या उन विषाणुओं के इंसानों तक आ पहुंचने की है जिनका संबंध असल में पशु-पक्षियों को होने वाली संक्रामक

> **बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, डेंगू और एचआइवी-एड्स से होने वाली मौतों में बीते तीन-चार दशक में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 1973 के बाद से दुनिया में विषाणुजनित तीस नई बीमारियों ने मानव समुदाय को घेर लिया है। धरती पर फैले सबसे घातक रोगाणुओं ने एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ रखी है और बीमारियों के ऐसे उत्परिवर्तित विषाणु आ गए हैं, जिन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यानी मौका पड़ने पर विषाणु अपना स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे उनके प्रतिरोध के लिए बनी दवाइयां और टीके कारगर नहीं रह पाते हैं।**

बीमारियों से है, लेकिन खानपान की बदलती आदतों (खासकर मांसाहार), वनों की अवैध कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों ने इंसानों को अन्य जीवों के विषाणुओं के करीब पहुंचा दिया है।

बर्ड फ्लू हो, कोविड-19 या इबोला, स्वाइन फ्लू, निपाह और सार्स आदि कोई अन्य संक्रामक बीमारी, हाल के वर्षों में दुनिया भर में इनके उभार ने साबित किया है कि इंसान यह मानकर निश्चिंत नहीं हो सकता कि जो बीमारियां पशु-पक्षियों को होती हैं, वे उसे नहीं हो सकतीं।

मगर सवाल है कि इंसानों तक नए-नए विषाणु आखिर पहुंचते कैसे हैं। विषाणु कुछ और नहीं, बल्कि बैक्टीरिया में पनपने वाले परजीवी ही हैं। जब ये कुछ की कोशिकाओं से किसी कारणवश बाहर निकल आते हैं या बैक्टीरिया का खोल तोड़ देते हैं तो उनकी चपेट में आने वाला कोई भी जीव आसानी से संक्रमित हो जाता है। मनुष्यों तक पशु-पक्षियों के विषाणु पहुंचने की दो बड़ी वजहें हैं। एक है, उन जीवों के साथ इंसानों का संपर्क। आमतौर पर इंसान को वही विषाणु नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरे जीव-जंतुओं से उस तक पहुंचते हैं। इस बारे में किए गए शोधों का निष्कर्ष है कि अस्सी फीसद विषाणु मनुष्य तक पालतू जानवरों, मुर्गियों, जंगली जानवरों के जरिए या फिर उन नए इलाकों की खोज के दौरान पहुंचते हैं, जहां वह पहले कभी न गया हो। हालांकि यह सही है कि विषाणुओं का एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के जीव तक पहुंचना बहुत दुर्लभ घटना है, और अगर ऐसा हो भी जाए तो इनके कोरोना विषाणु जैसा असर दिखाने की संभावना तो लाखों में एक बार ही हो सकती है। मगर मांसाहार की बदलती प्रवृत्तियां इंसानों को अन्य जीवों के विषाणु की चपेट में लाने का एक अन्य बड़ा कारण अवश्य हैं।

वैसे तो सभी जीवों में किसी न किसी तरह या कई तरह के विषाणुओं का संक्रमण हमेशा मौजूद होता है और उनका शरीर इससे लड़कर जीवन को बनाए रखने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में भी कई ऐसे विषाणु होते हैं जो या तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते या फिर कुछ घातक बीमारियों से बचाते हैं। बीमारी से बचाने वाले विषाणुओं को मित्र विषाणु कहा जाता है। मगर विषाणुओं के बढ़ते हमलों ने साबित कर दिया है कि इस मामले में अगर इंसान डाल-डाल है, तो वे पात-पात हैं। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, डेंगू और एचआइवी-एड्स से होने वाली मौतों में बीते तीन-चार दशक में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 1973 के बाद से दुनिया में विषाणुजनित तीस नई बीमारियों ने मानव समुदाय को घेर लिया है। धरती पर फैले सबसे घातक रोगाणुओं ने एंटीबायोटिक और अन्य दवाओं के खिलाफ जबरदस्त जंग छेड़ रखी है और बीमारियों के ऐसे उत्परिवर्तित विषाणु आ गए हैं, जिन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यानी मौका पड़ने पर विषाणु अपना स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे उनके प्रतिरोध के लिए बनी दवाइयां और टीके कारगर नहीं रह पाते हैं। दरअसल, ज्यादातर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने माइक्रोब्स (रोगाणुओं) के जीवन चक्रों को समझने की कोशिश नहीं की या संक्रमण की कार्यप्रणाली को नहीं जाना।

साफ है कि जब तक इंसान अपने रहन-सहन और खानपान की खराब आदतों पर अंकुश नहीं लगाएगा और जब तक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में दखलंदाजी से बाज नहीं आएगा, एक से एक खतरनाक विषाणु उभरते और दुनिया को इसी तरह संकट में डालते रह सकते हैं।

अभ्यास का आनंद

अमिताभ स.

सच है कि मंजिल हासिल करने के लिए अभ्यास सबसे बड़ी कुंजी है। अभ्यास की बड़ी खूबी है कि इसे करने से अनाड़ी से अनाड़ी भी खिलाड़ी बन जाता है। अभ्यास करते-करते भी जब तक मंजिल न मिले, तब तक बेशक सब असंभव लगे, लेकिन देर-सवेर मंजिल शर्तिया हासिल हो जाती है। इसीलिए तीसरी तक की प्राथमिक कक्षाओं में श्रुतिलेख में त्रुटियों के सुधार के लिए हर गलत शब्द को कई बार लिखवा कर अभ्यास करवाया जाता है। वास्तव में, इस तरह अभ्यास करने से हर गलती को सुधारने और फिर हर काम को करने की महारत हासिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। बड़ा या छोटा, हर कुछ पाने के लिए अभ्यास करना ही पड़ता है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी अक्सर बताते हैं कि 'मेरी बारहवीं की परीक्षा और मेरे मैच भी साथ-साथ चल रहे थे। मुझे परीक्षा देनी थी, फिर ट्रेन पकड़ कर मैच खेलने जाना था और मैच खेल कर लौटना था। लेकिन दुविधा थी कि पिताजी को कैसे बताऊं! बड़ी हिम्मत बटोर कर पिताजी को बताया, तो उन्होंने सहजता से समझाया कि अगर साल भर मेहनत की होगी, तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा और अगर साल भर मेहनत नहीं की होगी तो भी एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।'

बच्चों और बड़ों की मनपसंद लूडो और सांप-सीढ़ी जैसे खेल की तरह जिंदगी भी अभ्यास का खेल है। इनका पासा कभी मनचाहा अंक नहीं देता, तो कभी जरूरत के अंकों की बौछार कर देता है। फिर भी अगला पांसा फेंकना जारी रखना पड़ता है। अगर हम उड़ नहीं सकते, तो दौड़ें। अगर दौड़ नहीं सकते, तो चलें। अगर चल भी नहीं सकते, तो रेंगते-रेंगते बढ़ें। यानी कुछ भी हो, हमेशा आगे बढ़ते रहा जाए, बढ़ने का अभ्यास जारी रखा जाए। जब कभी लगे कि हार गए, तो भी एक उम्मीद फिर भी बची रह जाती है कि थोड़ा और अभ्यास कर लिया जाए। महज इतने भर से बाजी पलट जाती है।

यानी जीवन में मंजिल हासिल करने का एक ही रास्ता है- अभ्यास जारी रखा जाए। सबसे खुशकिस्मत वह है, जिसे जिंदगी में जब-जब अवसर मिले, वह अभ्यास करते रहने के लिए तैयार रहे। केवल ऐसे कर्मशीलों के लिए ही राहें खुलती जाती हैं। नीदरलैंड के महान विद्वान डेसिडेरियस इरेजमस कहते हैं, 'इंसान के सिवा सभी प्राणी अपने में संतुष्ट रहते हैं, केवल इंसान ही आगे बढ़ने के प्रयास और अभ्यास करता है।'

जब इंसानी फितरत ही अभ्यास करना है, तो फिर अभ्यास क्यों छोड़ना? इसलिए अभ्यास का दामन थामे रहने में ही भलाई है। निस्संदेह हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है। छोटे से छोटे अवसरों का समय पर उपयोग किया जाए, तो बड़े अवसर खुद सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कोई भी शुरू में बड़े काम नहीं करता, छोटे-छोटे काम करता हुआ आगे बढ़ता है। बस, केंद्रित रह कर करते जाना ही हर सफलता की चाबी है। कोई किसी भी क्षेत्र में जुटा हो, उसे खास अवसर के लिए तैयार रहना है और अवसर हाथ लगते ही अपनी पूरी शक्ति झोंक देनी है। ऐसा करने वाला कतई असफल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है, जब करत-करत अभ्यास के सिद्धांत को निरंतर अपनाया जाए, और उस पर पूरी तरह अमल किया जाए। करने की नीयत, खुद पर भरोसा और कड़ी मेहनत हमेशा बेहतर मौके मुहैया कराती है। लेखक सैम्युएल स्माइल्स मिले अवसर गंवाने पर दो टूक कहते हैं- 'कम इसलिए हासिल हुआ, क्योंकि उसे करने के प्रयत्न कम हुए।' यानी सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए अभ्यास कम हुए।

कुछ साल पहले एक जानी-मानी अभिनेत्री ने एक टीवी रियलिटी शो में जाहिर किया था कि 'हर माता-पिता की तरह मेरी मां ने मेरे जन्म से पहले न केवल नाम तय किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया कि मुझे चोटी की नर्तकी और अभिनेत्री बनाएंगी। फिर वे इसे मुमकिन करने में जुट गईं और ऐसा ही कर दिखाया।' यानी अभ्यास कुछ हासिल करने के लिए योग्यता से बढ़ कर है। योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के तभी मायने हैं, जब करने की इच्छा से आगे बढ़ें और सही नीयत से अभ्यास करते रहें। जब तक अभ्यास को सक्रिय न रखा जाए, तब तक काबिलियत का कोई मूल्य नहीं है।

मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया है- 'खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।' सच ही है कि जीवन में वही लोग सफल होते हैं, जो जानते हैं कि वे सफल होंगे। आविष्कारक थामस एडिसन की राय में, 'कतई मत कहिए कि मैं निन्यानबे बार हारा हूं, बल्कि कहें कि मैंने हारने की निन्यानबे वजहें ढूंढ़ी हैं।' फिर उन्हीं वजहों को पार कर, अभ्यास जारी रख, जीत की राह खुलती है। जाहिर है कि अभ्यास और कोशिशें करना सबसे बड़ी बात है। सदा सीखने और हासिल करने की आदत तमाम कामों में सुधार लाती जाती है। तय है कि इंसान अभ्यास से जिस हद तक खुद को सक्षम बनाता है, निपुण बनाता है, कुशल बनाता है और संभावना को जितना विकसित करता है, वह उतनी ही सफलता पाता जाता है।

दुनिया मेरे आगे

> **हर इंसान के भीतर असीम शक्ति है। छोटे से छोटे अवसरों का समय पर उपयोग किया जाए, तो बड़े अवसर खुद सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कोई भी शुरू में बड़े काम नहीं करता, छोटे-छोटे काम करता हुआ आगे बढ़ता है। बस केंद्रित रह कर करते जाना ही हर सफलता की चाबी है।**

नाकामी के पुल

बारिश का मौसम आते ही गंगा के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सड़क मार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने वाली सड़क पर विभिन्न क्षेत्रों में पुल के माध्यम से लोगों का आवागमन होता है। मगर वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पुलों के गिरने की खबरें लगातार आ रही हैं। लोग गांव से निकलकर शहर की ओर रोजाना इसलिए आते थे कि दैनिक जीवनचर्या की आवश्यकता की वस्तुएं लाना, बच्चों का स्कूल जाना, रोगी का अस्पताल जाना, रोजी-रोटी के तलाश में मजदूर को गांव से दूसरे गांव में निकल कर मजदूरी करने का विकल्प बंद हो गया है। सरकार किसी दल की भी हो, आरोप-प्रत्यारोप यह दर्शाता है कि सरकार की नाकामी, प्रशासन की लचर व्यवस्था, पुलों के बनने में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार को समस्या के निदान के लिए सोचना चाहिए, न कि आरोप-प्रत्यारोप के मकड़जाल में बहस करके जनता के वास्तविक मुद्दों को भटकाया जाए। लोकतंत्र में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। जनता सरकार इसलिए चुनती है कि हमारी आवश्यकता और मांगों को सरकार पूरा करे। किसी भी मुद्दे को बहस और आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र बनाने के लिए नहीं।

– तारामुनी देवी, लालगंज, वैशाली

शिकायत के सिरे

निजी स्कूलों की कई तरह की शिकायतें खबरों में आती रहती हैं। कभी मनमानी फीस बढ़ाने की शिकायत आती है तो कभी भवन कोष या किसी दूसरे तरीके से पैसा वसूलने की। कभी इस बात पर सवाल उठते हैं कि स्कूल प्रबंधन स्कूल से ही वर्दी और किताबें खरीदने के लिए मजबूर करता है। स्कूल में वर्दी और किताबों की कीमतें बाजार की कीमतों से अधिक होती हैं और यह भी शिकायत की वजह होती है। इस बात पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में जितने अध्यापक होने चाहिए, उतने नहीं हैं। कभी सरकारी स्कूलों में बच्चों से साफ-सफाई करवाने की तो कभी लड़कियों के लिए शौचालय न होने की शिकायत आती है। आजकल एक और शिकायत आ रही है। जब भी चाहे स्कूल वाले वर्दी बदल देते हैं और वर्दी के रंग और डिजाइन ऐसा बना देते हैं जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं होता। शिक्षा मंत्रालय को इन सब शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

– चरनजीत अरोड़ा, नरेला, दिल्ली

दायरों में तकनीक

आज बच्चों का बदलता व्यवहार अभिभावकों एवं समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। आजकल कम उम्र में ही बच्चे अकेलापन और गुस्से का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान विलुप्त होता जा रहा है और उनका बचपन घर और तकनीकी खिलौनों के दायरे में सिमटता जा रहा है। जबकि बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाने में टेलीविजन, आनलाइन खेल और मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। आनलाइन गेम की वजह से कई बार बच्चों ने अपने माता-पिता का बैंक खाते को खाली कर दिया है और कभी-कभी अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पूर्व में हमारे समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता थी, जिससे बच्चों की देखभाल में सहूलियत होती थी। आज के दौर में माता-पिता दोनों के कामकाजी होने की वजह से बच्चे परिवार से दूर होते जा रहे हैं। बच्चों के बचपन को बचाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर प्रयास करने चाहिए।

– हिमांशु शेखर, केसपा, गया

बिगड़ते हालात

मणिपुर में जारी नस्ली हिंसा आज भी जिस हालत में है और जैसे स्वरूप में आ रही है, अगर उसे तत्काल नहीं रोका गया और जल्दी कोई सर्वमान्य ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो स्थितियां जटिल हो सकती हैं। सवाल है कि आखिर किन वजहों से सरकार पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। क्या यह सरकार की बेबसी है या फिर भेदभाव का रुख कि एक वर्ष में कुछ सुधार नहीं हुआ? कुकी और मैतेई समुदाय में जारी नस्ली हिंसा न थमने और न्याय नहीं मिलने पर हाल ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दुख जाहिर किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की नाकामी पर रोष प्रकट किया है। नस्ली हिंसा के सामने असहाय बनने के बजाय सम्मानजनक समाधान खोजना ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र में मांग मनवाने में हिंसा अपनाना ठीक नहीं।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

www.readwhere.com

मेडिकल कॉलेज खोलने में चिंताजनक लापरवाही

इस साल की मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' के विवाद के बीच मेडिकल शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के सरकारी प्रयासों की पोल खोलने वाली खबर आई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने देश भर में नए खुलने वाले 113 मेडिकल कॉलेजों के आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिए हैं कि इनमें निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं हुए हैं। खारिज किए गए आवेदन पत्रों में से पांच राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों से संबंधित हैं। दूसरी ओर, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के लिए और अधिक मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सकों की जरूरत निरंतर महसूस की जाती है।

नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बुनियादी ढांचे के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं के मापदंड भी निर्धारित हैं। सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणाएं तो हो जाती हैं पर इन मापदंडों की अनदेखी आम बात है। ऐसा भी देखने में आता है कि निरीक्षण टोली को दिखाने के लिए कुछ समय के लिए दूसरे मेडिकल कॉलेजों से शिक्षकों को प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है। जिन कॉलेजों के आवेदन खारिज हुए वहां आयोग की टीम को किसी कॉलेज में फैकल्टी अधूरी मिली तो किसी में संसाधनों की कमी दिखाई दी। वैसे भी कई बार मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए समय पर मानक पूरा नहीं कर पाना सरकारी तंत्र और संबंधित कॉलेज प्रशासन के ढीले रवैये को दर्शाता है। यह ढीला रवैया भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा करता है वरना कोई वजह नहीं कि सरकार इनकी नाक में नकेल न डाल सके। अब ये मेडिकल कॉलेज खुल पाएंगे या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान लग गया है। एनएमसी के मुताबिक, देश में करीब 13.08 लाख चिकित्सक हैं।

सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता को केंद्रीय नियामक प्राधिकरण और एनएमसी नियंत्रित करते हैं। सरकारी मेडिकल सीटों की संख्या सीमित रहती है तो निजी कॉलेजों को मनमानी फीस वसूलने का मौका भी मिल जाता है। नए मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए बिना तय शर्तों को पूरा किए ही आवेदन करना तो और भी गंभीर विषय है। इस घालमेल के लिए जिम्मेदारों का पता लगाया जाना चाहिए। आयोग को इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारों को चेतावनी देते हुए मापदंड पूरे करने का एक अवसर और देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मेडिकल कॉलेज खोलने में साल भर की देरी देश में बेहतर चिकित्सा सेवाओं के अभाव की समस्या को और बढ़ाने वाली ही होगी।

सामयिक: भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना का प्रस्ताव है 'मिग-47'

'मेक इंडिया ग्रेट-47' से बढ़ेगा देश का गौरव

अजीत रानाडे
लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

भारत में पग-पग पर विविधता दिखाई देती है और विविधता में एकता ही हमारी विशेषता है। भारत का विश्व को स्पष्ट संदेश है–'समन्वय', यानी सहिष्णुता नहीं बल्कि स्वीकार्यता, सिर्फ सह-अस्तित्व नहीं, फलना-फूलना भी।

मिग विमानों का अधिग्रहण और उनका संचालन भारत-रूस संबंधों के बहुत से आधारों में से एक महत्त्वपूर्ण आधार हैं। मिग-21 विमान 1960 के प्रारंभिक वर्षों से ही भारतीय वायु सेना का मेरूदंड बन चुका है और यह सोवियत संघ द्वारा भेजा जाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण विमान था। 1971 के भारत-पाक युद्ध में मिग-21, तो 1999 के करगिल युद्ध में मिग-27 की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण रही। मिग विमानों के संचालन और रखरखाव का अनुभव भारत के स्वदेशी विमान कार्यक्रम में काम आया। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का तेजस इसी विकास का परिणाम है। अब मिग-29 पर काम चल रहा है जो उत्कृष्ट वैमानिकी, राडार और हथियार प्रणाली से लैस है। हालांकि मिग-47 को लेकर कोई योजना नहीं है और कुछ लोग सुखोई-47 को मिग-47 समझ बैठते हैं। इसके अलावा भारत तेजस और रफाल विमान पर फोकस कर रहा है।

हम यहां बात करेंगे महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'मिग-47' (मेक इंडिया ग्रेट बाइ 2047) के प्रस्ताव की, जो 2047 तक भारत को महान शक्ति संपन्न राष्ट्र बना सकता है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 की संकल्पना से मेल खाता है। मिग-47 हमारे देश का गौरव बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में है। इससे पहले एक मूलभूत प्रश्न – क्या राष्ट्रवाद का चलन खत्म हो रहा है या फिर इसका पुनरुत्थान हो रहा है? भौगोलिक स्थितियों से जुड़े राष्ट्रों की अवधारणा संभवतः तीन शताब्दियों पुरानी है, इसलिए राष्ट्र राज्य अपेक्षाकृत नई अवधारणा है। राष्ट्रवाद का प्रभाव कम होने के कई कारक हो सकते हैं, जैसे वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी व बहुराष्ट्रीय संघों का अस्तित्व जैसे यूरोपीय संघ, सीमा शुल्क संघ, सैन्य गठबंधन, व्यापार ब्लॉक आदि। राष्ट्रवादी भावनाएं अंतरराष्ट्रीय व बहु-सांस्कृतिक प्रभावों के बीच कम प्रभावी हो सकती हैं। यूके में हाल ही आए चुनाव परिणाम हो सकता है ब्रेग्जिट को पुनः निष्प्रभावी करने के लिए पड़े वोट का नतीजा हों। शरणार्थियों की आवाजाही व बड़ी संख्या में प्रवासियों की मौजूदगी भी राष्ट्रवाद को प्रभावित करती हैं, तो कुछ जगह शरणार्थी व आव्रजक विरोधी रवैया अपना कर भी राष्ट्रवाद का प्रदर्शन किया जाता है।

बेरोजगारी भी चिंता का विषय है, जिसकी वजह बाहरी लोगों को माना जाता है (जैसे भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए)। याद कीजिए अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक अभियान चलाया था कि कैसे बफैलो से बेंगलूरु तक नौकरियां चुराई जा रही हैं? या चीन द्वारा चुराई जा रही हैं? इसके अलावा भू-राजनीति, सीमा पर संघर्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा व युद्ध भड़काने जैसी बयानबाजी भी राष्ट्रवादी भावनाओं को आहत करती हैं। सोशल मीडिया इसमें अतिरिक्त भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रवाद का चलन खत्म हो जाएगा या यह और भी अधिक मजबूत हो जाएगा। इसलिए पुनः 'मिग-47' पर लौटते हैं। इसके कुछ आर्थिक आयाम भी हैं। इनमें से एक है भारत की प्रति व्यक्ति आय को 20,000 डॉलर प्रति व्यक्ति तक पहुंचाना। इसके लिए अगले 25 वर्षों में राष्ट्रीय आय दस गुना हो जानी चाहिए। यानी प्रति वर्ष 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर (डॉलर में)। चूंकि रुपया एक मुद्रा के नाते स्थायी रह सकता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में रहते मजबूत भी हो सकता है, यह वृद्धि दर असंभव नहीं है।

'मिग-47' का एक आयाम है 'ईज ऑफ लिविंग' यानी 'सुगम जीवन'। इसका संबंध सुरक्षित व पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्धता, पर्यावरण अनुकूल संसाधनों से मकान निर्माण, शहरों में सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण वायु से है। चूंकि आय वृद्धि ऊर्जा से प्रेरित होगी, इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि नवीकरण ऊर्जा विकास दो गुनी या तीन गुनी तेजी से हो। भारत सौर सहयोग का वैश्विक नेतृत्वकर्ता देश है। हमें लाखों छोटी ऑटोमोटिव रिचार्जेबल बैटरियों का उपयोग कर सौर ऊर्जा के रात्रि में संग्रहण की योजना बनानी चाहिए। इस तरह हम कार और स्कूटर बैटरियों की भूमिका को उलट सकते हैं। रात में उनसे घर की ऊर्जा जरूरतें पूरी हों और दिन में उन्हें सौर ऊर्जा से रिचार्ज किया जाए। हवा की गुणवत्ता मोटर व भवन निर्माण क्षेत्र में स्थायी रणनीति अपना कर सुधारी जा सकती है। भवन निर्माण क्षेत्र में सीमेंट का उपयोग होता है, जो कैल्शियम कार्बनेट से बनती है। यह कार्बन डाइ ऑक्साइड का बड़ा स्रोत है। इसलिए भवन निर्माण क्षेत्र को कार्बन फुटप्रिंट कम करने की दिशा में काम करना होगा।

'मिग-47' का तीसरा आयाम है–शिक्षा, कौशल व प्रशिक्षण से मानव पूंजी का निर्माण तथा उत्पादकता एवं नवाचार क्षमताएं बढ़ाना। शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र सुधारों से अछूते हैं। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में उठाया गया उचित कदम है। यहां एक प्रयोग किया जा सकता है। कैसा रहे, यदि वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मियों के लिए अपने बच्चों को पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा पंचायत या नगरपालिका के स्कूलों में दिलवाना अनिवार्य कर दिया जाए, क्यों न हर सरकारी स्कूल में शिक्षक-अभिभावक संघ सालाना शिक्षकों की कार्यकुशलता का जायजा ले। चौथा आयाम है–सत्ता का अनवरत विकेंद्रीकरण, सरकार के तीसरे टियर तक। यही वह स्तर है जो लोगों के सबसे नजदीक है। पर निर्णय लेने की स्वायत्तता, फंडिंग व कार्यान्वयन मामले में इसके पास सबसे कम शक्ति होती है। सत्ता जितनी केन्द्रीकृत होती है, उतने ही हम राजनीति में उलझने लगते हैं। इसलिए प्रशासन व सत्ता का विकेंद्रीकरण ही एकमात्र दीर्घगामी मार्ग है। पांचवां आयाम सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक है। हमारे देश को हर दृष्टि से अकल्पनीय विविधता का वरदान मिला है, और फिर भी हम दुनिया में सद्भाव और विविधता में एकता के प्रतीक हैं। यही 'समन्वय' भारत का दुनिया को सबसे महत्त्वपूर्ण संदेश है।

यूएस चुनाव: उम्मीदवार बदलने पर लाभ-हानि का आकलन जरूरी

यों ही कमला हैरिस को किनारे नहीं कर सकते डेमोक्रेट्स

जेनिफर रुबिन
'रीजिस्टेंस: हाउ वीमन सेव्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम डॉनल्ड ट्रंप' की लेखिका
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

राष्ट्रपति जो बाइडन की डिबेट को देखकर आमजन और मीडिया में एक धारणा स्पष्ट तौर पर बनती दिखाई दे रही है, यह कि 'उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एकमात्र मुमकिन विकल्प हैं।' उपराष्ट्रपति की भूमिका भी यही है - उस वक्त आगे आना, जब अस्थायी या स्थायी तौर पर राष्ट्रपति को बदले जाने की जरूरत हो। एक पार्टी जो लंबे समय तक अश्वेत अमरीकियों, विशेष रूप से अश्वेत महिलाओं, के वोटों पर निर्भर रही, वह बिना किसी उग्र प्रतिक्रिया के और बड़े पैमाने पर दलबदल को बढ़ावा दिए उपराष्ट्रपति हैरिस को एक ऐसे श्वेत राजनेता के लिए किनारे नहीं कर सकती जो यादृच्छिक हो और जिसे भलीभांति जांचा-परखा भी न गया हो।

यह लेख लिखे जाने तक बाइडन ने सार्वजनिक तौर पर ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि वे रेस से बाहर हो रहे हैं। इसके विपरीत उन्होंने उम्र और स्वास्थ्य पर चिंताओं के बीच उन्हें फिर से चुनाव मैदान में उतरने से रोकने के आह्वान को खारिज कर दिया है, क्योंकि वाइट हाउस ने भी इस बात से इनकार किया है कि बाइडन का पार्किन्संस रोग के लिए इलाज किया जा रहा है। हालांकि, यदि बाइडन के इस रुख में बदलाव होता है, तो कई मीडियाकर्मियों, डेमोक्रेटिक पार्टी कार्यकर्ताओं और निर्वाचित डेमोक्रेट्स को मुंह की खानी पड़ सकती है। यदि हैरिस राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होती हैं, तो अब तक उनकी विशेषज्ञता और उनके राजनीतिक कौशल को कमतर आंकने वाले आलोचक तुरंत उनकी तारीफों के पुल बांधने लग जाएंगे। यह मानते हुए कि चुनाव अनिवार्य रूप से बाइडन या हैरिस के बीच हैं, मतदाताओं, डेमोक्रेटिक अधिकारियों और प्रगतिशील समूहों को बदलाव की स्थिति में लाभ और हानि का आकलन करना ही चाहिए।

एक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति के तौर पर मैंने हैरिस का साक्षात्कार लिया है। जिस हैरिस को मैंने देखा है वह बिल्कुल भी उस छवि से मेल नहीं खाती जो उनके आलोचकों ने तैयार की है। हैरिस के सकारात्मक गुणों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है।

पहला, यदि बाइडन युवा मतदाताओं को उत्साहित नहीं कर पाते और गैर-श्वेत मतदाताओं के रुख में बदलाव को जोखिम उठाते हैं, तो हैरिस मतदाताओं के इस आधार को उत्साहित करने के लिए जरूरी प्रेरणा साबित हो सकती हैं। हाल ही में सीएनएन-एसएसआरएस के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हैरिस महिला मतदाताओं के बीच बाइडन को हुए तीन पॉइंट के घाटे को सात पॉइंट की लीड में बदलने की क्षमता रखती हैं। कमला बहुत अच्छी वक्ता हैं, जो महिला समर्थकों, अश्वेत छात्रों और हिस्पैनिक श्रोताओं में जोश भर देती हैं। पहली महिला अश्वेत राष्ट्रपति की संभावना भी जरूरी ऊर्जा का संचार कर सकती है। दूसरा, डेमोक्रेट्स के प्रचार अभियान में जो विषय केंद्र में होने चाहिए, वे हैं–गर्भपात, सुप्रीम कोर्ट का मनमानीपूर्ण रवैया और आरोपों का सामना कर रहे पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का इस पद के लिए फिट न होना। ये भी हैरिस के पक्ष में जाता है। वे विरोधियों पर हमलावर होने में मुखर हैं। हैरिस, ट्रंप की नस्लीय टिप्पणियों का जवाब देने के लिए डेमोक्रेट्स का नेतृत्व कर सकती हैं।

तीसरा, हैरिस ही हैं जो रिपब्लिकन्स से उनके पसंदीदा मुद्दे 'आयु' को हाईजैक कर सकती हैं। ग्रांड ओल्ड पार्टी डिबेट्स में बाइडन की आयु को ही प्रमुख मुद्दा बनाए हुए है। अगर हैरिस उम्मीदवार होंगी तो रिपब्लिकन्स के पास आयु को लेकर कोई मुद्दा शेष नहीं रहेगा। साथ ही मीडिया भी ट्रंप की खामियों को उजागर करने पर फोकस करेगी।

फ्रांस: कैंटिलीवर बालकनी जैसे पेड़ की पत्तियां

फ्रांस के शहर मोंटपेलियर में मिश्रित उपयोग वाली वास्तुकला की इस अनुपम कृति का नाम है एल'अर्बर ब्लैंक टॉवर। इसकी बालकनियां पत्तियों की तरह फैली हुई हैं। इसे सू फुजिमोतो ने निकोलस लैसने, दिमित्री रूसेल और ओएक्सओ आर्किटेक्ट्स के साथ मिलकर 2019 में पूरा किया था। एक पेड़ के आकार में बनी, इस घुमावदार 17-मंजिला इमारत में 113 अपार्टमेंट हैं, जिनमें कैंटिलीवरिंग बालकनियां हैं, साथ ही भूतल और छत पर सार्वजनिक सुविधाएं सुलभ हैं।

https://t.me/NewspaperPaid

ये भी जानें सीमा-पार डिजिटल ट्रांजेक्शन को तेज करने के लिए देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा

क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसमें रिजर्व बैंक भी हुआ शामिल

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। यह प्रोजेक्ट भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) और अन्य देशों के डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) के माध्यम से तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाएगा। जब यह प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएगा तो यह भारतीयों द्वारा किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेनदेन का चेहरा बदल सकता है। प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल यूपीआइ और मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के एफपीएस को नेक्सस के जरिए आपस में जोड़ा जाएगा। इन देशों के नागरिक यूपीआइ से पैसों का डिजिटल ट्रांजेक्शन करने में सक्षम होंगे। भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को दूसरे कई देशों तक बढ़ाया जा सकता है।

2026 *तक इस प्लेटफॉर्म के लाइव होने की उम्मीद है आरबीआई को। तेज गति से भुगतान होने के कारण सीमा पार लेनदेन में लगे व्यवसाय लाभान्वित होंगे जिससे उनका नकदी प्रवाह और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।*

30 *जून 2024 को बीआइएस और केंद्रीय बैंकों– रिजर्व बैंक (भारत), बैंक नेगारा मलेशिया, बैंक ऑफ थाइलैंड, बंगको सेंट्रल नग फलीपींस (फिलीपींस का केंद्रीय बैंक) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने हस्ताक्षर किए।*

क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस

प्रोजेक्ट नेक्सस की संकल्पना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआइएस) के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भाग लेने वाले देशों के घरेलू इंस्टेंट पेमेंट्स सिस्टम्स (आइपीएस) को आपस में जोड़कर सीमा पार से भुगतान को सक्षम बनाना और बढ़ावा देना है। यह भुगतान क्षेत्र में लाइव कार्यान्वयन की ओर बढ़ने वाला पहला बीआइएस इनोवेशन हब प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नेक्सस का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इस कारण सीमा-पार भुगतान बहुत तेज तो होगा ही कम खर्चीला भी हो जाएगा। सीमा-पार डिजिटल ट्रांजेक्शन को तेज करने के लिए विभिन्न देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्यादा बढ़ेगा। सीमा पार भुगतान के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट की आवश्यकता महसूस की गई थी।

रिजर्व बैंक ने इसे कैसे गति दी

प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 जून को स्विट्जरलैंड के बेसल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के साथ ही इस पहल के संस्थापक सदस्यों के रूप में मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में भारत भी शामिल हो गया। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी समझा जा रहा था क्योंकि अन्य देशों के साथ सुचारू लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए देशों के व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर प्रणाली धीमी, महंगी और बोझिल बनी हुई है। कल्पना करें, अगर भारत पांच अन्य देशों के साथ क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स से जुड़ना चाहता है तो उसे पांच अलग-अलग देशों से द्विपक्षीय बातचीत करनी होती। नेक्सस के बहुपक्षीय होने से ऐसी पाबंदियों से बचा जा सकता है।

प्रोजेक्ट में शामिल होने के लाभ

प्राथमिक लाभों में से एक लेनदेन के समय में कमी आना है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों में जहां पहले कई दिन या घंटे लगते थे, उसकी तुलना में एफपीएस के माध्यम से घरेलू भुगतान प्रक्रिया आमतौर पर कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाती है। देशों के केंद्रीय बैंकों की भुगतान प्रणालियों के विपरीत, यह प्रणाली कम लागत के साथ चौबीसों घंटे और सात दिन काम करती है। इसके साथ ही बैंकों के लिए उन देशों में भी अपनी सेवाओं की पेशकश करना अधिक व्यावहारिक हो जाता है जहां उनकी भौतिक उपस्थिति या प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है।

विश्वसनीयता में वृद्धि

पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्थाओं से सीमा पार भुगतान में विभिन्न स्तरों पर देरी और खतरे की आशंका बनी रहती है जिससे समस्या हल होने तक अक्सर प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है। प्रोजेक्ट नेक्सस यह सुनिश्चित करके विश्वसनीयता को बढ़ाता है कि भुगतान या तो कुछ सेकंड के भीतर पूरा हो जाता है या विफल होने पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इससे लेनदेन में जोखिम कम हो जाता है। यह प्रोजेक्ट तत्काल भुगतान सेवाओं की पहुंच का विस्तार करता है।

फैक्ट फ्रंट

येल्तसिन ने राष्ट्रपति पद की ली थी शपथ

रूसी राजनीतिज्ञ बोरिस येल्तसिन ने देश के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में 10 जुलाई 1991 को शपथ ली थी। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्तियां रूस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन को सौंप दी। उस रात क्रेमलिन पर फहरा रहे सोवियत झंडे को उतार दिया गया और क्रेमलिन पर रूसी तिरंगा लहराने लगा। अगले दिन सुप्रीम सोवियत ने यूएसएसआर का औपचारिक रूप से विघटन कर दिया।

प्रसंगवश

हरियाली बढ़ाने में सामाजिक संकल्प की भागीदारी जरूरी

वन नीति को कागजों से बाहर लाकर और धरातल पर लागू करने से ही हम धरा को हरा-भरा कर पाएंगे

मानसून की सक्रियता के साथ ही प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने के प्रयासों को गति देने का वक्त आ गया है। यह इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि राज्य के 10 प्रतिशत भू-भाग पर भी वन नहीं हैं, जबकि आदर्श रूप में 33 फीसदी भूमि वन आच्छादित होने चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि प्रदेश में वन क्षेत्र तो पिछले तीन साल में 19 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा है, लेकिन शहरों में हरियाली घट गई है। शहरों में घनी हरियाली का प्रतिशत 15 से घटकर 8 प्रतिशत रह गया है। इससे करीब 2 करोड़ आबादी प्रभावित हो रही है। एक समस्या यह भी है कि विकास की आड़ में हरियाली लगातार चौपट होती जा रही है। कहीं सड़कें बनाने तो कहीं उद्योग-धंधे लगाने के नाम पर हर साल हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है। सड़क निर्माण में तो काटे गए पेड़ों की क्षतिपूर्ति के लिए पौधरोपण का प्रावधान होता भी है लेकिन इस दिशा में ज्यादा काम हो नहीं पाता। जामनगर-अमृतसर भारतमाला परियोजना के ग्रीन कॉरिडोर से जरूर सीख ली जा सकती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में ड्रिप इरिगेशन से भी कम पानी में मरु प्रदेश को हरा-भरा बनाने की योजना है। परियोजना के तहत प्रदेश में 4 लाख 63 हजार 336 पौधे लगेंगे।

पिछले साल 5 जून को राजस्थान वन नीति 2023 जारी की गई थी। इसमें आगामी बीस वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वन नीति कई बार जारी हो गई, लेकिन इसे कागजों से बाहर धरातल पर लाकर लागू करने से ही धरा को हरा-भरा कर पाएंगे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में प्रधानमंत्री के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की शुरुआत करते हुए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को देश का सबसे हरा-भरा संसदीय क्षेत्र बनाने के संकल्प की पहल की है। देश में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण अभियान को जनआंदोलन बनाना होगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका काफी अहम है। सांसद से लेकर पंच-सरपंच तक संकल्पित होकर अपने क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के काम में आगे आएं तो गांव-शहर हरियाली से आच्छादित नजर आएंगे। इस लिहाज से पत्रिका का 'हरयाळो राजस्थान' अभियान भी ऐसे ही प्रयासों को आगे बढ़ाने वाला है। सरकारी स्तर पर हरियाली बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयास भी तब ही परवान चढ़ सकेंगे जब उसमें सामाजिक संकल्प की भागीदारी नजर आएगी।

- आशीष जोशी
ashish.joshi@epatrika.com

आपकी बात

योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो

उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया जाए और शोध के नाम पर खानापूर्ति न की जाए।

-लता अग्रवाल, चित्तौड़गढ़

आज का सवाल

भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश क्यों जाते हैं?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/xu6ed

चिंतन

रूस को भारत का युद्ध छोड़ शांति का संदेश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दो दिवसीय रूस दौरे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता के दौरान मंझे हुए कूटनीतिज्ञ राजनेता की तरह बात की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बहुत सहजता से कहा कि बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती और किसी संघर्ष का कोई समाधान युद्धक्षेत्र में संभव नहीं है। पीएम ने यह बात यूक्रेन से युद्ध के संदर्भ में कही है। रूस को भारत का संदेश साफ है कि युद्ध बंद कीजिए, वार्ता से मसले सुलझाइए। अब अगर रूस युद्ध समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी। कुछेक दिन पहले रूसी राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म करने की सशर्त इच्छा जताई थी। अमेरिका व यूरोप की अपेक्षा रही है कि भारत रूस से बात कर युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन को राजी करे। इस अपेक्षा के अनुरूप ही भारत रूस व यूक्रेन से पहले भी अपील कर चुका है कि यह युद्ध का दौर नहीं है, वार्ता से ही मसले सुलझाए जा सकते हैं। हालांकि रूस व यूक्रेन वार्ता टेबल पर नहीं आए, युद्ध तीसरे वर्ष में है। इसका बड़ा कारण है कि अमेरिका व नाटो से जुड़े यूरोपीय देशों ने कभी भी यूक्रेन को युद्ध खत्म करने के लिए नहीं मनाया। अमेरिका व नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और यूक्रेन के कंधे से रूस को साधने की चेष्टा कर रहे हैं। अमेरिकी जिद के बरक्स रूस ने पश्चिम के बिना सर्वाइव का साधन खोज लिया है। इस प्रयास में रूस के लिए चीन व भारत बड़ा मददगार साबित हुए हैं। अभी एक दिन पहले ही चीन ने रूस व यूक्रेन संग युद्ध खत्म कराने के लिए वार्ता पर जोर देते हुए सहमति से मध्यस्थता की पेशकश की है। हालांकि इस पर रूस व यूक्रेन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने भारत से अपील की है कि रूस के साथ वार्ता में युद्ध के मुद्दे पर चर्चा हो और राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान हो। अमेरिका की मंशा साफ है कि रूस यूक्रेन से जंग खत्म कर चले जाएं और यूक्रेन की पूर्व स्थिति रहे। रूस ने जंग के बाद यूक्रेन के कुछेक भूभाग पर कब्जा जमा लिया है। पीएम मोदी के इस रूस दौरे पर जहां चीन की नजर है, वहीं अमेरिका व यूरोप की भी निगाहें हैं। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मोदी के रूस दौरे को तटस्थ व संतुलित विदेश नीति के तौर पर उद्धृत किया है, तो अमेरिका मीडिया ने भी इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में देखा है। अमेरिकी थिंकटैंक की भाषा में थोड़ी तल्खी है, लेकिन पश्चिम खेमे के दबाव से इतर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए भारत की सराहना भी है। पीमए की रूस यात्रा ऐसे समय हुई है, जब चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ी है। अभी भारत को लेकर चीन की भाषा भी मर्यादित है। इस दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित कर भारत से रूस की गहरी दोस्ती का परिचय दिया और चीन, अमेरिका व यूरोप को संदेश दिया। ऊर्जा, असैन्य परमाणु, डिफेंस, अस्त्र-शस्त्र आदि क्षेत्र में भारत व रूस के बीच सहयोग और मजबूत होंगे। भारत ने रूस के सामने ग्लोबल आतंकवाद के खतरों का मुद्दा भी उठाया। रूसी सेना में भारतीय जवानों के लड़ने का लड़ने का मुद्दा भी उठा, अब रूस भारतीय की भर्ती अपनी सेना में नहीं करेगा। भारतीय समुदाय के साथ भी पीएम ने जोशीले संवाद किया। पीएम ने रूस को सुख-दुख का साथी बता कर भारत के लिए रूस की अहमियत को रेखांकित कर दिया है। भारत-रूस विश्व में नई भूमिका निभाने को तैयार है।

भविष्य
शिशिर शुक्ला

अंतरिक्ष में डाटा की सुरक्षा

हाल ही में यूरोप की कंपनी एसेंड ने 21 लाख डॉलर खर्च करके एक अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि भविष्य में बढ़ते हुए डाटा को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में डिजिटल गोदाम खोलने पर विचार करना पड़ेगा। इस योजना के पीछे कारण यह बताया गया है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर इस कदर हावी हो जाएगी कि अथाह मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपने उपयोगी डाटा को सुरक्षित रख पाना हमारे लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तकरीबन 16 महीने तक इस मुद्दे पर हुए अध्ययन के बाद नतीजा यह निकला है कि इस चुनौती से निपटने के लिए पृथ्वी से 1400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यूरोपीय कंपनी एसेंड के अनुसार अंतरिक्ष में वर्ष 2036 तक ऐसे 13 डाटा सेंटर खोले जाएंगे जिनकी क्षमता लगभग 10 मेगावाट होगी। प्रत्येक डाटा केंद्र की सतह का क्षेत्रफल 6300 वर्ग मीटर होगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2050 तक ऐसे 1300 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। एक अन्य विशेष बात यह है कि ये डाटा सेंटर सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। देखा जाए तो आज हमारे जीवन में डिजिटलीकरण ने पूर्णतया अपना दखल स्थापित कर लिया है। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक हम पूर्णरूपेण डिजिटल तकनीकी की गिरफ्त में जकड़े हुए हैं। कारण यह है कि डिजिटलीकरण ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए अनेक सुविधाओं का समावेश भी किया है। इन सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसका जिक्र करना उचित होगा, वो है समय की बचत। निस्संदेह डिजिटलीकरण ने प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए समय की बचत करने में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है, किंतु डिजिटल तकनीकी के कुछ पार्श्व प्रभाव भी उभरकर सामने आए हैं, जो कहीं न कहीं हमारे जीवन पर ही असर डाल रहे हैं अथवा भविष्य में गंभीर असर डालने वाले हैं। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 402.74 मिलियन टेराबाइट डाटा पैदा हो रहा है। इसके साथ ही यह भी निश्चित है कि समय के साथ प्रतिदिन पैदा होने वाले इस डाटा की मात्रा में निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने पास कीमती सामान ज्यादा हो तो उसकी सुरक्षा को लेकर मन में सवाल उठेगा ही। डाटा के उत्पन्न होने से लेकर डाटा की सुरक्षा तक प्रत्येक कार्य में ऊर्जा का खर्च होना ही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पृथ्वी के डाटा सेंटरों पर वर्ष 2026 तक प्रति घंटा एक हजार टेरावॉट बिजली की खपत होगी। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होने से हम शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को किसी भी दशा में हासिल नहीं कर पाएंगे। यूरोपीय कमीशन के सहयोग से किए गए इस शोध का मुख्य लक्ष्य भी भविष्य में पृथ्वी को अनावश्यक ऊर्जा खपत से बचाते हुए कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने की अवधारणा पर ही आधारित है। चूंकि अंतरिक्ष में सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत होगा, लिहाजा अंतरिक्ष में डाटा सुरक्षा के लिए हम सौर ऊर्जा पर ही निर्भर होंगे। डेनमार्क के डाटा सेंटर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भविष्य में दुनिया के सामने डाटा सुनामी का दौर आने वाला है। पृथ्वी पर एक बड़ी मात्रा में डाटा उत्पादित होगा और उस डाटा की सुरक्षा के लिए एक बड़ी मात्रा में बिजली और पानी की आवश्यकता होगी। नतीजा यह होगा कि बिजली एवं पानी जो धीरे धीरे संकट के दायरे में आने के कगार पर हैं और अधिक तीव्र गति से इस ओर बढ़ जाएंगे। ऐसी दशा में बहुमूल्य डाटा की सुरक्षा कर पाना नितांत मुश्किल होगा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रतिदिन 1.145 ट्रिलियन मेगाबाइट डाटा उत्पन्न हो रहा है। इस हिसाब से वर्ष 2028 तक भारत को 3.6 गीगावाट क्षमता वाले डाटा सेंटर की जरूरत होगी। भारत में मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई, ये चारों डाटा सेंटर के मुख्य हब हैं। भारत के लगभग 90 फीसदी डाटा सेंटर इन्हीं चार महानगरों में हैं। समस्या का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि हम अपने मोबाइल फोन में प्रतिदिन 1.5 गीगाबाइट अथवा 2 गीगाबाइट डाटा प्रदान करने वाले प्लान का रिचार्ज करते हैं। इस हिसाब से हम लगभग 60 गीगाबाइट डाटा प्रतिमाह खर्च करते हैं। अगर औसतन बात की जाए, तो एक भारतीय प्रतिमाह 19 गीगाबाइट डाटा का उपभोग कर रहा है। यहां पर एक अन्य बात का उल्लेख करना उचित होगा कि जनसंख्या वृद्धि की द्रुत दर भी किसी से छिपी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जनसंख्या अगर इसी दर से बढ़ती रही तो डाटा उपभोग की मात्रा भी उतनी ही तेज गति से बढ़ेगी। पृथ्वी पर डाटा के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए भविष्य में दुनिया के सभी देशों को अंतरिक्ष में डिजिटल गोदाम बनाने के विकल्पों पर विचार करना ही पड़ेगा और साथ ही ऊर्जा के स्वच्छतम विकल्प सौर ऊर्जा पर केंद्रित रहते हुए चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना होगा।

(लेखक स्वामी शुकदेवानंद महाविद्यालय में भौतिकी के विभागाध्यक्ष हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

बजट उम्मीद
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

बजट के ऐतिहासिक होने की आस

> 23 जुलाई को वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आर्थिक सुधारों, आर्थिक कल्याण और तेज विकास के आधारों के आगे बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक बजट होगा। यह एक ऐसा बजट भी होगा, जिसमें वित्तमंत्री 2024-25 के तहत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1 फीसदी और 2025-26 में 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। साथ ही वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनने के सपने को साकार करने की डगर पर आगे बढ़ाने वाला बजट भी होगा।

इन दिनों पूरे देश की निगाहें 23 जुलाई को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट की ओर लगी हुई। उम्मीद की जा रही है कि यह बजट विकास और सुधारों से सजा हुआ ऐतिहासिक बजट होगा। इस बजट को तैयार करने के मद्देनजर वित्तमंत्री सीतारमण ने 19 जून से 5 जुलाई तक उद्योग-कारोबार, श्रम, कृषि, एमएसएमई, टैक्सेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता, आधारभूत ढांचा, वित्त क्षेत्र सहित बजट से संबंधित विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित की हैं।

गौरतलब है कि गत 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के तीसरे कार्यकाल में वर्ष 2024-25 का बजट ऐतिहासिक होगा और इसमें आर्थिक तथा सामाजिक मोर्चे पर बड़े ऐलान किए जाएंगे। इस बजट से सरकार सुधारों की प्रक्रिया को और तेज करेगी। यह बजट नई गठबंधन सरकार की नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश में विभिन्न सुधारों से भारतीय बैंकिंग विश्व के सबसे मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में शुमार हो गई है। टैक्स संग्रहण ऊंचाई पर है। गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से इन वर्गों का उत्थान हुआ है। मुर्मू ने कहा कि पिछले दस वर्षों में सरकार के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म ने भारत को विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया है और भारत ने 2021 से 2024 के बीच 8 प्रतिशत सालाना की दर से वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि नए बजट के माध्यम से अटके पड़े सुधारों, वित्तीय व श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, वैश्विक बाजार में भारतीय खाद्यान्नों की मांग बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने तथा रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने के बड़े कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष एक फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट एक लेखानुदान की तरह था तथा इसमें कोई लोक लुभावन योजना नहीं थी। ऐसे में इस अंतरिम बजट ने 23 जुलाई को प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के लिए अच्छे आर्थिक और वित्तीय आधारों की विरासत सौंपी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पूर्ण बजट 2024-25 की तैयारी को अंतिम रूप देते समय वित्तमंत्री सीतारमण के पास अच्छे व ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के कई मजबूत आधार हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्त मंत्रालय को 2.11 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम लाभांश सौंपा गया है, वह भी नए बजट का मजबूत आधार होगा। इस लाभांश से सरकार को राजकोषीय सहायता मिलेगी और व्यय अपेक्षाओं का प्रबंधन होगा। आयकर परिदृश्य पर सकारात्मक बदलाव होने का अनुकूल परिदृश्य मौजूद है। पिछले 10 वर्षों में आयकरदाताओं की संख्या और

आयकर की प्राप्ति में छलांगें लगाकर वृद्धि हुई है। आयकर रिटर्न रिकॉर्ड 8 करोड़ के स्तर को पार कर चुका हैं। जहां पिछले 10 वर्षों में आयकर रिटर्न भरने वाले दोगुने से भी अधिक हुए हैं, वहीं, आय की असमानता में भी कमी आई है। वित्तमंत्री की मुठ्ठियों में देश में कर सुधारों से आयकरदाताओं और आयकर संग्रहण के साथ-साथ जीएसटी में लक्ष्य से भी अधिक वृद्धि की बड़ी अनुकूलताएं है। इसके अलावा पिछले वर्षों में वित्तमंत्री सीतारमण वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए अब तक राजकोषीय घाटे को बजट लक्ष्य के मुताबिक उपयुक्त रूप से नियंत्रित रखते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ी हैं।

निःसंदेह नया बजट 2024-25 गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर केंद्रित होते हुए दिखाई दे सकता है। नए बजट में वित्तमंत्री वृद्धि और रोजगार पर फोकस करते हुए दिखाई दे सकती हैं। किसान सम्मान निधि सालाना 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये की जा सकती है। कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई वेयरहाउसिंग को प्रोत्साहन नए बजट में बढ़ाएं जा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहनमूलक राहत दी जा सकती है। जहां विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार नए बजट से पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे नए क्षेत्रों तक विस्तृत कर सकती हैं और श्रम साध्य क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन के पथ पर आगे बढ़ सकती हैं, वहीं रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को भी प्रोत्साहनमूलक राहत दे सकती हैं। नए बजट में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ाने से संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाताओं सहित विभिन्न उत्पादों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए अधिक पूंजीगत व्यय के प्रावधान भी दिखाई दे सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि इन दिनों वेतनभोगी (सेलरिड) वर्ग के लाखों छोटे आयकरदाता और मध्यम वर्ग के लोग यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पिछले विभिन्न बजटों में उन्हें टैक्स संबंधी कोई उपयुक्त राहत नहीं मिली है। साथ ही अब महंगाई वृद्धि और उनके बढ़ते जरूरी खर्चों के कारण उन्हें कुछ आयकर राहत की अपेक्षा है। वित्तमंत्री नए बजट में खपत को बढ़ावा देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के उपाय भी कर सकती हैं, जिसमें कर राहत के उपाय भी शामिल हैं। ऐसे में नए बजट में आयकर के पुराने तथा नए स्लैब दोनों के तहत छोटे आयकरदाताओं को राहत के प्रावधानों का ऐलान किया जा सकता है। निःसंदेह वेतनभोगी वर्ग के द्वारा नए बजट में राहत की अपेक्षा इसलिए भी न्यायसंगत है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग के द्वारा दिया गया कुल आयकर पेशेवरों और कारोबारी करदाताओं के वर्ग द्वारा चुकाए गए कुल आयकर से काफी अधिक होता है। वेतनभोगी करदाताओं के कर की कटौती अर्जित आय पर की जाती है। इसे टीडीएस के रूप में जाना जाता है। टीडीएस के कारण वेतनभोगी ईमानदारी से आयकर चुकाते हैं और आमदनी को कम बताने की गुंजाइश नगण्य होती है। ऐसे में टीडीएस की वर्तमान 50,000 रुपये की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये की जा सकता है।

हम उम्मीद करें कि 23 जुलाई को वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा पेश होने वाला वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट आर्थिक सुधारों, आर्थिक कल्याण और तेज विकास के आधारों के आगे बढ़ाने वाला एक ऐतिहासिक बजट होगा। यह एक ऐसा बजट भी होगा, जिसमें वित्तमंत्री 2024-25 के तहत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 5.1 फीसदी और 2025-26 में 4.5 फीसदी तक लाने का लक्ष्य आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। साथ ही वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनने के सपने को साकार करने की डगर पर आगे बढ़ाने वाला बजट भी होगा।

(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं?

संकलित
दर्शन

जब ईश्वर का वास हृदय में माना गया है, तो मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं? मंदिरों की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि पूजा, अर्चना और यज्ञ आदि द्वारा पवित्र तन्मात्रओं यानी पंचभूतों के सूक्ष्म रूप की सृष्टि की जाए। किसी साधु हृदय व्यक्ति को पूजा का कार्यभार सौंपा जाए। स्थान का मन पर अदृश्य प्रभाव पड़ता है। चिकित्सालय में व्यक्ति को हर तरफ रोग और रोगी ही दिखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी वहां अशक्त महसूस करने लगता है। हमारे शरीर से प्रतिदिन शुभ या अशुभ अदृश्य सूक्ष्म शक्ति-राशि का उत्सर्जन होता रहता है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध और आलस्य बाहर छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से जाता है। यह सामूहिक भक्ति या उपासना शुभ तन्मात्रओं व तरंगों का सृजन करती है। अतः यहां आगमन दुर्बल मन वाले मनुष्यों में ऊर्जा का संचार करता है। सज्जनों से ही प्रार्थना स्थलों की पवित्रता बनी रहती है। यदि मंदिर में असाधु व्यक्तियों का आवागमन बढ़ जाए तो स्थान अपनी पवित्रता खोने लगता है। पवित्र श्रवण मास में शिवलिंग पर दुग्ध, बेलपत्र, फल-फूल आदि चढ़ाकर पुण्य अर्जित करने की होड़ लगी रहती है। यदि ईश्वर है और वह हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होता है तो वह एक बेलपत्र, अंजुली भर दूध या एक पुष्प से भी प्रसन्न हो जाएगा। सावन के महीने से इतर भी ये दृश्य आमतौर पर मंदिरों में आम होते हैं। यदि यह व्यवस्था सुचारु न हो तो अव्यवस्था स्वाभाविक है। इसी कारण कई मंदिरों में व्यक्तिगत रूप से भोग-अर्पण की मनाही है।

सत्कर्मों में सदैव आस्था रखें

संकलित
प्रेरणा

एक नदी के तट पर एक शिव मंदिर था, एक पंडितजी और एक चोर प्रतिदिन अपनी-अपनी आस्था के अनुरूप मंदिर आया करते थे। जहां पंडितजी फल फूल, दूध चंदन आदि से प्रतिदिन शिवजी की पूजा करते। वहीं वह चोर रोज भगवान को खरी-खोटी सुनाता और अपने भाग्य को कोसता रहता। एक दिन पंडितजी और चोर एक साथ मंदिर से बाहर निकले। निकलते ही चोर को स्वर्णमुद्राओं से भरी एक थैली मिल गई। जबकि ठीक उसी समय पंडितजी के पैर में एक कील घुस गई। चोर स्वर्ण मुद्राओं से भरे थैले को पाकर अत्यंत प्रसन्न था। जबकि पंडितजी पीड़ा से परेशन थे, लेकिन पंडितजी को कील की पीड़ा से अधिक इस बात का कष्ट था कि मेरे पूजा पाठ करने के बाद भी बदले में भगवान ने मुझे कष्ट दिया। जबकि इस चोर के कुकर्मों के बदले में उसे स्वर्णमुद्राओं के रूप में पुरस्कार मिला। तब मंदिर से आवाज आई- हे पंडित! आज तुम्हारे साथ एक बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों के कारण तुम केवल कील लगने की पीड़ा पाकर ही मुक्त हो गए। जबकि इस चोर के भाग्य में आज अपार धन संपत्ति प्राप्ति का योग था। लेकिन अपने कुकर्मों के कारण उसे केवल कुछ मुद्राएँ ही मिली हैं। अच्छे कर्म से ही मनुष्य का भविष्य एवं भाग्य बनता बिगड़ता है। इसलिए सदैव सत्कर्मों में आस्था बनाए रखना चाहिए।

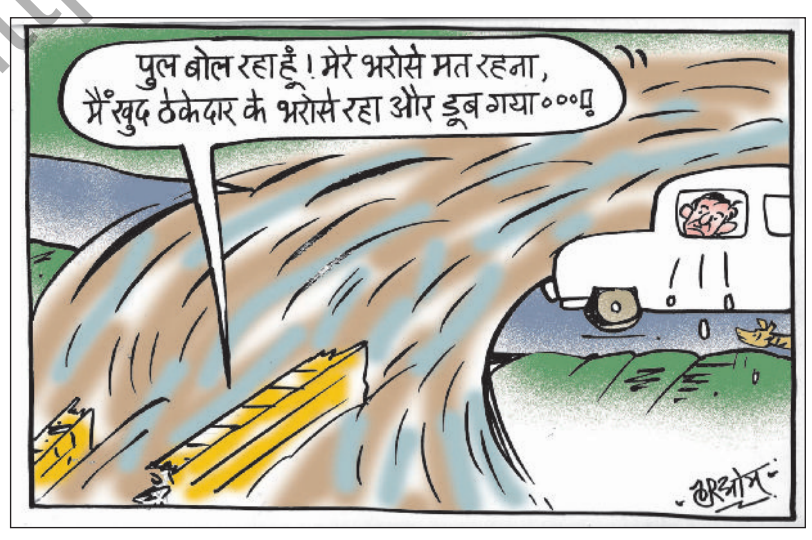

अंतर्मन

आज की पाती

सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी क्यों

बारिश न हो तो सूखे के कारण सब्जियों के दाम में वृद्धि हो जाती है और अगर बारिश हो जाए तो भी सब्जियों के खराब होने के कारण दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका क्या हल निकाला जाए, यह शायद कोई नहीं सोचता है। देश में उगाई जाने वाली खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखकर तो यह लगने लगा है कि यह कहीं दूर विदेशों से आई हैं। देश के कुछ राज्यों में आजकल टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। यह किसी एक सब्जी की आसमान छूती कीमत की बात नहीं है। कभी प्याज तो कभी अन्य सब्जियों के मूल्य आसमान छू जाते हैं। कृषि प्रधान देश में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी और फिर भी किसानों की दयनीय दशा सचमुच शर्मनाक है। सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। *– प्रकाश जैन, दुर्ग*

ट्रेंड

शिक्षा सामूहिक जिम्मेदारी

एनईपी का संपूर्ण कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर सीखने के परिणामों में सुधार भारत को एक ज्ञान महाशक्ति में बदलने और समान और समावेशी पहुंच को सक्षम करने के लिए केंद्रीय है। जड़युक्त, भविष्यवादी, बहुभाषी और 21वीं सदी की शिक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
-धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री

समाधान का रास्ता

जैसे ही मैंने मध्य एशिया की अपनी यात्रा समाप्त की, मैं पूरे क्षेत्र में मिली एकजुटता की भावना से प्रोत्साहित होकर निकला। बिखरी हुई दुनिया में, यह खुशी की बात है कि मध्य एशिया अलग रास्ता चुन रहा है- सहयोग और सामान्य समाधान का रास्ता।
-एंटोनियो गुतरेस, यूएन महासचिव

मन से आत्मा की ओर मुड़ें

परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त और मार्गदर्शन करने वाली मार्गदर्शक चेतना है। अहं-मन भौतिक स्तर पर उस आंतरिक प्रकाश का एक सीमित प्रतिबिंब है। जब तक हम मन से आत्मा की ओर नहीं मुड़ते, हम नहीं जान पाएंगे कि हम कौन हैं या अस्तित्व का अर्थ क्या है।
-डॉ डेविड फ्रॉली, अमेरिकी हिंदू लेखक

आश्चर्यजनक प्रतिभा

पृथ्वी पर क्या चल रहा है? पिछले दो सप्ताह के भीतर दूसरी बार, भारतीय मूल की एक युवा महिला ने मंच पर धूम मचाई है। प्रतिभा जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। संगीत की स्वदेशी अमेरिकी शैलियों में अर्जित कौशल के साथ। रॉक एंड गॉस्पेल।
-आनंद महिंद्रा, उद्योगपति

करंट अफेयर

नाटो में सबसे कम योगदान देने वाला देश बना कनाडा

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की मेजबानी में आयोजित हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया संगठन ने कहा कि कनाडा 32 सदस्यीय इस सैन्य गठबंधन में सबसे कम योगदान देने वाले देशों में से एक बन गया है। प्रमुख अमेरिकी मीडिया संगठन 'पॉलिटिको' ने कहा, 'पिछले कई वर्षों में ओटावा 32 सदस्यीय गठबंधन में सबसे कम योगदान देने वाले देशों में से एक बन गया है। वह घरेलू सैन्य खर्च के लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम रहा है, नए उपकरण खरीदने के लिए वित्त पोषण देने में नाकाम रहा है और उसके पास इस संबंध में कोई योजना भी नहीं है।' कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो इस साल के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाशिंगटन पहुंच गए हैं जिसकी औपचारिक शुरुआत आज होगी। ट्रुडो के कार्यालय ने बताया कि यहां बैठकों के दौरान वह पूरे यूरोप में नाटो के सामूहिक रक्षा प्रयासों में कनाडा के योगदानों पर प्रकाश डालेंगे। 'पॉलिटिको' ने कहा कि नाटो के 12 संस्थापक सदस्यों में से एक कनाडा ने रक्षा पर दो प्रतिशत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) खर्च करने के संकल्प पर 2014 में हस्ताक्षर किए थे।

ऑफ बीट

पृथ्वी के गर्म होने पर तूफानों में कैसे बदलाव आएंगे

जब एक जुलाई को तूफान बेरिल ने ग्रेनेडाइन द्वीप समूह पर हमला किया, तो इसकी 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और भयानक तूफान ने इसे उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में आएं श्रेणी 5 का तूफान (सैफिर-सिम्पसन तूफान पवन पैमाने पर सबसे विनाशकारी ग्रेड) बना दिया। 2024 में सक्रिय तूफान के मौसम की भविष्यवाणी काफी पहले ही कर दी गई थी। हालाँकि, जिस गति से बेरिल तीव्र हुआ, उसने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह तूफान केवल 24 घंटों में 70 मील प्रति घंटे की औसत हवाओं के साथ उष्णकटिबंधीय-तूफान की ताकत से 130 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ प्रमुख-तूफान की स्थिति में पहुंच गया। अल्बानी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क में वायुमंडलीय विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर ब्रायन टैंग कहते हैं, 'बेरिल जून की बजाय तूफान के मौसम में आने वाला विशिष्ट तूफान है, और इसकी तीव्रता और ताकत असामान्य रूप से गर्म पानी के कारण होती है।' जैसे-जैसे रिकॉर्ड जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन के कारण दुनिया तेजी से गर्म हो रही है, शोध से पता चलता है कि अभी और भी अप्रिय आश्चर्य आने वाले हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।